Page No.1

राजस्थान विधान सभा

२१वीं बैठक, सोमवार, दिनांक २ अप्रैल, सन् १९५६ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ११ बजकर ७ मिनट पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या २४१

राजस्थान में राष्ट्रीयकरण की गई पुस्तकें एवं उनके लेखकों को पुरस्कार इत्यादि

श्री चाँदमल मेहता—क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में राष्ट्रीयकरण की गई कौन कौन सी पुस्तकें चालू हैं ?

(ख) उक्त पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण कब कब किया गया ?

(ग) उक्त पुस्तकें किन किन लेखकों द्वारा लिखी गई हैं व उन्हें क्या पुरस्कार दिया गया है एवं उनका राष्ट्रीयकरण किस आधार पर किया गया है ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनिवाल (उप शिक्षामंत्राणी) —सदस्य महोदय की जानकारी के लिये ....

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है।

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—(क) सदस्य महोदय की जानकारी के लिये ऐसी पुस्तकों की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) जुलाई सन् १९५४ में

[श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल]

(ग) सदन की मेजपर रखी गई तालिका में लेखकों के नाम अंकित हैं। लेखन शुल्क अभी तक नहीं दिया गया है। इन पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण मुख्यत: इस आधार पर किया गया कि राष्ट्रीयकरण की नीति का अवलम्बन क्रमश: किया जाय।

(कृपया परिशिष्ठ १ देखिये)

श्री चांदमल मेहता—क्या लेखकों को पुरस्कार देना निश्चित किया गया है?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जी हां।

श्री चांदमल मेहता—कितना कितना पुरस्कार देना निश्चत किया गया है?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनिवाल—या तो पुस्तक के मूल्य का १।१० भाग रोयल्टी के रूप में या १००० रु० नकद।

श्री चांदमल मेहता—जो पुरस्कार निश्चित किया गया है वह अभी तक नहीं दिये जाने का कारण क्या है?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनिवाल—इस सम्बन्ध में रकम आई हुई है ए. जी. के यहां से अभी तक हिसाब पास होकर नहीं आया है इसलिये नहीं दिया गया।

श्री चांदमल मेहता—राष्ट्रीयकरण की गई पुस्तकों को किन लेखकों द्वारा लिखाई जाय इसका किसने फैसला किया?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—इसके लिये एक कमेटी बनाई गई है।

श्री चांदमल मेहता—उसके सदस्य कौन कौन हैं?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—उनकी सूची मेरे पास नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस कमेटी ने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला जिससे कि सब लेखक अपनी अपनी पुस्तकें भेज सकते?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा था कि किस आधार पर उक्त

Page No.3

[श्री चांदमल मेहता]

पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस प्रश्न के अंतर्गत पूरक प्रश्न उठना स्वाभाविक है। इस पूरक प्रश्न की जानकारी नहीं है कह कर टाला जाना उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष—Half-an-hour discussion may be raised.

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मेरे पास अभी सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष—If the replies are inadequate and not proper, half-an hour disussion can be raised.

प्रश्न संख्या २४२

इन्सपेक्टर, डिप्टी इन्सपेक्टर एवं सब डिप्टी इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स के अधिकार

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स, डिप्टी इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स और सब डिप्टी इन्सपेक्टर ऑफ स्कूलस के क्या २ अधिकार हैं?

(ख) राजस्थान में ऐसे कौन कौन इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स हैं जिन्हें प्रारम्भिक पाठशालाओं के अध्यापकों की नियुक्तियों के अधिकार हैं?

(ग) ऐसे कौन २ इन्सपेक्टर हैं जिन्हें ऐसे अधिकार नहीं हैं?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल (उप शिक्षा मंत्राणी)—(क) इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स व डिप्टी इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स इन्चार्ज डिस्ट्रिक्ट को अध्यापकों की नियुक्ति करने के समान अधिकार दिये हुये हैं। डिप्टी इन्सपेक्टर व सब डिप्टी इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

(ख) राजस्थान के समस्त इन्सपेक्टर्स ऑफ स्कूल्स व डिप्टी इन्सपेक्टर्स आफ स्कूल्स, इन्चार्ज डिस्ट्रिक्ट को मेट्रिक ग्रेड तक के अध्यापकों की नियुक्ति करने के अधिकार हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—यह अधिकार कब दिये गये हैं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—अभी कुछ अर्सा हुआ है, ऐसे पॉवर्स तय होकर उन्हें दिये गये ।

श्री चांदमल मेहता—क्या इस प्रश्न को भेजने के बाद में ऐसे पॉवर्स दिये गये हैं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—यह पहले ही हो चुका है ।

श्री अध्यक्ष—If the replies are inadequate and not proper, half-an hour discussion can be raised.

प्रश्न संख्या २४३

राजस्थान में पुनग्रहण की गई जागीरें एवं उनके जागीरदारों को अन्तर्कालीन मुआवजा

श्री केसरीसिंह (वि० स० ७५)—क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) राजस्थान में आज तक कितनी जागीरें पुनग्रहण की जा चुकी हैं, जिलावार बताया जावे ?

(ख) पुनग्रहित जागीरों में से कितनी जागीरों के जागीरदारों को अन्तर्कालीन मुआवजा दिया जा चुका है और कितने जागीरदारों को पूरा मिल चुका है ?

(ग) जिला बूंदी में ऐसे कितने जागीरदार हैं जिनको आज तक अन्तर्कालीन मुआवजा नहीं दिया है और उनके नाम क्या हैं ?

(घ) क्या कारण है कि इनको मुआवजा अब तक नहीं मिल सका है ? अब सरकार इनको मुआवजा कब तक दिलायेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(क) कुल ५,४४३ जागीरें खालसा हुई हैं जिनकी जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(ख) ११२० जागीरदारों को अन्तर्कालीन मुआवजा मिल गया है इनमें से १०७४ जागीरदारों को पूरा दिया जा चुका है।

(ग) अन्तर्कालीन मुआवजे के लिए २१ आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से १४ जागीर-

[श्री दामोदरलाल व्यास]

दारों को अन्तर्कालीन मुआवजा दिया जा चुका है, केवल सात जागीरदारों को देना बाकी है जिनके नाम निम्न हैं—

१. श्री धनुषधारी सिंह
२. श्री रेवाशंकर
३. श्री नरेन्द्रसिंह
४. श्री द्वारिका दास
५. श्री कनोडअली
६. श्री अब्दुल मजीद खां
७. श्री कृष्ण दाधीच

'घ' दावों में खामियां होने के कारण व समय पर नियमानुसार आवेदन पत्र पेश न करने के कारण विलम्ब हुआ है।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति के पश्चात शीघ्रातिशीघ्र दिये जाने का प्रबन्ध किया गया है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

महाराज श्री केशरी सिंह—क्या यह सही है कि बूंदी जिले में जो १२३ जागीरें खालसा हुई हैं उनमें से कुछ जागीरें ऐसी हैं जो २०० रुपये से कम हैं?

श्री दामोदर लाल व्यास—इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

(महाराज श्री केशरीसिंह के अनुपूरक प्रश्न पूछने खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—हाफ एन अवर डिस्कशन आ रहा है, उसमें पूछ लेना। नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २४४

जनवरी १९५५ के पश्चात् नायब तहसीलदारों को कार्यवाहक तहसीलदार बनाने के आधार

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) १ जनवरी, १९५५ के बाद कितने नायब तहसीलदारों को कार्यवाहक तहसीलदार बनाया गया?

[श्री चांदमल मेहता]

(ख) उक्त नायब तहसीलदारों का सीनियोरिटी लिस्ट में कौनसा स्थान है ?

(ग) ऐसे कौन कौन नायब तहसीलदार हैं जो अधिक सीनियर होते हुए भी कार्यवाहक तहसीलदार नहीं बनाये गये हैं ?

(घ) ऐसे कौन कौन कार्यवाहक तहसीलदार हैं जो १ जनवरी, १९५५ के बाद नायब तहसीलदार बना दिये गये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(क) १ जनवरी, १९५५ के बाद ४२ नायब तहसीलदारों को कार्यवाहक तहसीलदार बनाया गया।

(ख) इनमें से एक तो ग्रुप 'ए' के हैं, बाकी सब १५ लगायत ९८ ग्रुप 'सी' के हैं इनमें से जो १३ व्यक्ति कार्यवाहक तहसीलदारी के पद पर नहीं हैं वे या तो किसी दूसरे विभाग में तहसीलादारी के अनुरूप पद पर लगे हुए हैं, छुट्टी पर हैं, या रिटायर हो चुके हैं। एक श्री मोहम्मद रसूल पाकिस्तान चले गये हैं।

(ग) केवल एक श्री बलवीरसिंह, उनका नाम ग्रुप ए. के सीनियोरिटी नं० ४६ पर होते हुए भी इनके खिलाफ कुछ अभियोग होने के कारण इन्हें कार्यवाहक तहसीलदार नहीं बनाया गया।

(घ) कोई नहीं।

श्री चांदमल मेहता—(ख) में यह जवाब नहीं मिला कि सीनियोरिटी लिस्ट में कौन कौन सा स्थान है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—लिखित सूची उपलब्ध नहीं हुई

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि बी. ग्रुप के ऐसे नायब तहसीलदार मौजूद हैं जो कार्यवाहक तहसीलदार नहीं बनाये गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास—बी. ग्रुप का कोई ऐसा नहीं है। 'ए.' ग्रुप के एक श्री बलवीरसिंह ऐसे हैं जिनका सीनियोरिटी लिस्ट में ४६ वां नम्बर होते हुए भी उनको कार्यवाहक तहसीलदार नहीं बनाया गया, इसके विशेष कारण अभी मैंने बताये हैं।

श्री चांदमल मेहता—तो क्या 'बी.' ग्रुप के सब नायब तहसीलदारों को तहसीलदार बना दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—कन्फर्म्ड तहसीलदार हो गये।

श्री चांदमल मेहता—आपने सी. ग्रुप का सीनियोरिटी का नम्बर बताया, बीच में कुछ नम्बर छूटे हुए हैं तो क्या यह सही है कि उनको कार्यवाहक तहसीलदार नहीं बनाया गया?

श्री दामोदर लाल व्यास—मैंने अर्ज किया कि कार्यवाहक तहसीलदार तो नहीं बनाया पर ऐसी जगह पर पोस्टेड हैं जो कि तहसीलदार के बराबर का पद है, या रिटायर होगये हैं या पाकिस्तान चले गये हैं।

श्री चांदमलमेहता—जो तहसीलदारों के समकक्ष स्थान पर काम करते हैं वे कहां कहां पर हैं?

श्री दामोदर लाल व्यास— लिखित उत्तर उपलब्ध नहीं हुआ।

प्रश्न संख्या २४५

श्री सदाशिवम् एस. डी. ओ. राजगढ़ का अलवर से शीघ्र स्थानान्तर के कारण

श्री भवानी सहाय—क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) एस. डी. ओ. राजगढ़ श्री सदाशिवम् अलवर जिले में, किस तारीख को भेजे गये और उनका स्थानान्तरण अलवर से किस तारीख को किया गया?

(ख) इतने अल्प समय में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं?

(ग) क्या उनका यह स्थानान्तरण इसलिये हुआ कि उनकी अदालत में श्री भरतलाल नामक सी. आई. डी. के भू. पू. इन्फार्मर, जिसे लड़की उड़ाने के कारण नौकरी से अलग किया था, का और दूसरी लड़की उडाने का एक और मुकदमा ३७२ ताजीरात हिंद का चल रहा था?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(क) श्री सदाशिवम् का एस. डी. ओ. राजगढ़ (अलवर) के पद पर नियोजन १० मई, सन् १९५४ को हुआ। उनका स्थानान्तरण उस जगह से ७ जनवरी, १९५६ को हुआ।

(ख) प्रशासनिक कारण।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भवानी सहाय—क्या यह सही है कि वे वहां पर बहुत अच्छा काम करते थे पर किसी गुंडे द्वारा शिकायत करने पर उनका ट्रान्सफर कर दिया गया?

श्री दामोदरलाल व्यास—कार्य तो उनका अच्छा था पर यह कहना गलत है कि ट्रांस्फर किसी की शिकायत पर किया गया था।

श्री भवानी सहाय—क्या यह सही है कि एक गुन्डे द्वारा शिकायत करने पर उनकी ट्रांस्फर के लिए बार बार टेलीफोन किये गये थे?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह बिल्कुल झूंठ है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २४६

राजस्व विभाग के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों का शिघ्र फिक्सेशन करने सम्बन्धी

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्व विभाग के मातहत किन किन श्रेणी के कर्मचारियों का फिक्सेशन अभी तक नहीं हुआ है?

(ख) उक्त कर्मचारियों के फिक्सेशन नहीं होने के क्या करण हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास—(राजस्व मंत्री) (क) राजस्व विभाग के मातहत निम्न श्रेणीयों के कर्मचारियों का फिक्सेशन अभी बाकी है।

१. रेवेन्यु इन्स्पेक्टर्स २. कानूनगो ३. सदर कानूनगो ४, पटवारियान।

(ख) इनकी वरिष्टता क्रम सूची को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, यह अध्यक्ष राजस्व मंडल के विचाराधीन है।

श्री चांदमल मेहता— अब कब तक सरकार विचार करती रहेगी?

श्री दामोदरलाल व्यास—उनकी सीनियोरिटी लिस्ट अन्तिम रूप से तय होने वाली है।

श्री चांदमल मेहता—इसके अन्तिम रूप से तय होने की क्या कोई अवधि भी नियत है?

श्री दामोदरलाल व्यास—अवधि तो नियत नहीं की जा सकती पर जितना जल्दी हो सकेगा किया जायगा।

Page No.9

प्रश्न संख्या २४७

हरिजनों की शासकीय सेवा में निश्चित कोटा के अनुसार नियुक्तियां

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) हरिजनों का नौकरियों में प्रस्तावित कोटा पूरा करने के लिये इस समय राज्य सरकार क्या क्या नीति अपना रही है ?

(ख) हरिजनों के लिये रिक्त स्थानों पर इस समय क्या दूसरे लोगों की भर्ती करली जाती है अथवा वे स्थान रिक्त रखे जाते हैं ?

(ग) यदि अन्य लोगों की नियुक्तियां की जाती हैं तो वे टेम्परेरी होती हैं या परमानेन्ट और यदि टेम्परेरी होती हैं तो कितने समय तक के लिये ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(उद्योग मंत्री) (क.) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के सचीव, समाज कल्याण विभाग से विभागों को आदेश जरिये नं० एफ. २२-बी. एफ (२) जी. ए. (२) ५३ दिनांक ७/७/५४ के दिये गये हैं तदनुसार संचालक, समाज कल्याण विभाग, जयपुर के कार्यालय में एक रजिस्टर रहता है जिसमें उम्मी[illegible] अनुसूचित जाति अथा अनुसूचित जन जाति के प्राथियों के नाम योग्यता आदि [illegible] अन्य अधिकारी अपने विभाग के रिक्त स्थानों की सूचना भेजते हैं तब इस विभा[illegible] उनको उक्त स्थानों पर भर्ती करने के लिये भेज दी जाती है।

(ख) योग्य व्यक्ति न मिलने पर दूसरे लोगों की भर्ती करली जाती है।

(ग) नहीं।

(घ) इस तरह की नियुक्तियां अधिकतर अस्थाई ही की जाती हैं।

(ङ) आवश्यकता व नियमानुसार।

(च) यह सवाल ही नहीं उठता।

श्री हरिशंकर—कब तक के लिये अस्थाई व्यक्तियों को हरिजनों के रिक्त स्थान पर रखते हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैने उत्तर दिया कि योग्य व्यक्ति जब तक नहीं मिलते तब तक रखा जाता है।

श्री हरिशंकर—६ महीने तक या ६ महिने तक।

श्री भोगीलाल पंड्या—किसी में छ महीने होते हैं और किसी में ६ महीने होते हैं।

श्री हरिशंकर—क्या यह समझा जावे कि इस समय के बाद हरिजनों को नहीं लिया जावेगा

श्री भोगीलाल पंड्या—हरिजनों में योग्य व्यक्ति नहीं मिलेगा तो उसकी जगह दूसरा भर्ती किया जावेगा।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या सरकार को यह विदित है कि जो आदेश इस सम्बन्ध में दिये गये हैं उनका सब जगह पालन होता है क्या ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट,

प्रश्न संख्या २४८

जनवरी, १९५५ के पश्चात राजस्थान (विशेषतया किशनगढ़) में खोले गये संस्कार केन्द्र

श्री चांदमल मेहता—क्या योजना मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

[illegible]री, १९५५ के बाद राजस्थान में कहां कहां संस्कार केन्द्र खोलने की स्वीकृति [illegible]

(ख) कहां कहां संस्कार केन्द्र चालू किये जा चुके हैं ?

(ग) किशनगढ़ में संस्कार केन्द्र कब से किस स्थान पर चालू किया गया और उसमें कब२ किन२ कार्यकर्ताओं को नौकर रखा गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (योजनामंत्री) (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) निम्न ७ स्थानों के अतिरिक्त सूची में वर्णित सभी स्थानों पर केन्द्र चालू किये जा चुके हैं—(१) सीकर, (२) सवाई माधोपुर (३) करौली (४) गंगानगर (५) बाड़मेर (६) जैसलमेर (७) जालोर।

(ग) किशनगढ़ में दिनांक २७-११-५५ से संस्कार केन्द्र चालू किया गया। विस्तृत जानकारी सदन की मेजपर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ की संस्कार सेन्टर में एक महिला को रखने की योजना थी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इसके लिये प्रार्थनापत्र मांगे गये थे और उन पर कोई कार्यवाही नही हुई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जिन के लिये प्रार्थनापत्र मांगे गये कार्यवाही हुई होगी।

श्री चांदमल मेहता—किशनगढ़ में कितने कार्यकर्ता रखने की स्वीकृति है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—दो।

श्री चांदमल मेहता—दो में एक महिला कार्यकर्ता होनी चाहिये।

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार इसकी आवश्यकता नहीं मानती ?

प्रश्न संख्या २४६

श्री अध्यक्ष—श्री सरदार सिंह।

(अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

प्रश्न संख्या २५०

राजस्थान में हरिजन गजटेड अधिकारी

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) राजस्थान में गजेटेड ऑफिसर्स की कुल संख्या कितनी है ?

(ख) गत ४ वर्ष में हरिजनों में से कितने गजेटेड ऑफीसर्स बनाये गये और इनका अब तक क्या प्रतिशत है ?

Page No.12

[श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री]

(ग) हरिजनों में से जो लोग गजेटेड ऑफीसर्स बनाये गये उनके नाम, जाति क्या क्या हैं और वे किस किस पद पर कहां कहां काम कर रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(क) ३,१४०।

(ख) ८ करीब, ०.२५ प्रतिशत।

(ग) इस समय सिर्फ दो व्यक्ति जो गजेटेड पदों पर कार्य कर रहे हैं, उनके नाम जाति आदि यह हैं—

१. श्री रामचन्द्र मीणा, आर. ए. एस. असिस्टेन्ट सेटिलमेंट ऑफिसर, (अन्डर ट्रेनिंग) जोधपुर।

२. श्री शंकरलाल पंचाल, असिस्टेन्ट इन्जिनियर, इलेक्ट्रिकल एन्ड मैकेनिकल विभाग, जयपुर।

श्री हरिशंकर—क्या यह सही है कि रामचन्द्र मीणा शिडयूल कास्ट का नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इस संबन्धमें आपत्ति उठाई गई थी जिसकी जांच की जा रही है।

श्री हरिशंकर—हरिजनों में से किन किन को लिया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—शंकरलाल पंचाल हैं।

श्री हरिशंकर—कोनसी जाति से आया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—पिछड़ी हुई जाति से आया है।

श्री हरिशंकर—इस साल में कितनों की नियुक्ति की थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—८ की नियुक्त की गई थी।

श्री हरिशंकर—वे उनको किन किन पदों पर लिये गये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—एसिस्टेन्ट कस्टोडियन आदि।

श्री हरिशंकर—क्या वह पोस्ट गजेटेड पोस्ट है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने जो बताया है वे गजेटेड पोस्ट हैं। एसिस्टेन्ट कस्टोडियन की भी गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट

प्रश्न संख्या २५१

जागीर पुनर्ग्रहण (प्रथम संशोधन) अधिनियम के लागू होने से अब तक जागीरदारों को खुद काश्त भूमि देने हेतु बेदखल हुए कृषक

श्री भैंरू सिंह—क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण कानून के प्रथम संशोधन के लागू होने के पश्चात से अब तक जागीरदारों की खुद काश्त के लिये भूमि प्रदान करने हेतु कितने काश्तकारों को बेदखल करना पड़ा है ? काश्तकारों की संख्या जिलेवार क्या है ?

(ख) इन काश्तकारों के अधीन किस किस प्रकार की भूमि थी जिसके कारण उन्हे खुद-काश्त के लिये बेदखल करना पड़ा ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(क) राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण एक्ट के अनुसार बेदखल करने की आज्ञा नहीं दी जा सकती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैंरू सिंह—आज्ञा दी जा सकती है।

श्री दामोदरलाल व्यास—आज्ञा नहीं दी गई। मैं करेक्ट करता हूँ।

श्री भैंरू सिंह—क्या जागीरदारों को खुद काश्त करने के लिये जमीन देने के लिये किसी काश्तकार को बेदखल करने की जरूरत नहीं आई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जो सूचना अभी तक आई है उसके अनुसार कह सकता हूँ कि किसी काश्तकार को बेदखल नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष—नेक्सट ।

प्रश्न संख्या २५२
छोटे उद्योगों के प्रोत्साहनार्थ स्वीकृत धन राशि

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगें—

(१) छोटे उद्योगों को ऋण देने के लिये चालू वर्ष में कितने रुपये स्वीकृत किये गये हैं ?

(२) ऐसे कौन कौन व्यक्ति या फर्म हैं जिनको स्वीकृति दी जाने पर भी लोन नहीं दिया गया है ।

(३) उक्त स्वीकृति कितने समय से पेन्डिंग है ।

(४) भारत सरकार द्वारा इस काम के लिए कितने रुपये प्रदान किये गये हैं ?

(५) लोन के लिये कितने प्रार्थनापत्र सरकार के पास कितने समय से विचाराधीन हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(उद्योग मन्त्री)—(१) छोटे उद्योगों को ऋण देने के लिये चालू वर्ष में छः लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति किये गये हैं ।

(२) इसकी सूची टेबल पर रखदीं गई है ।

(३) विगत की क्रम संख्या १ से १६ तक की स्वीकृति ता० १३—१०—५५ से क्रम संख्या १७ का ता० २—२—५६ से व क्रम संख्या १८ से ७१ तक की ता० ६—२—५६ से पेन्डिंग है ।

(४) अब कोई नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि स्वीकृत रकम में से भी रकम विभागीय स्वीकृति न मिलने की वजह से नहीं दी गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने बताया कि पैसे नहीं थे । पैसों के लिये सेन्टर से कोशिश की गई और आपको खुशी होनी चाहिये कि ज्योंही रूपया प्राप्त हुआ सारा का सारा दे दिया गया ।

प्रश्न संख्या २५३

सीकर के डूंगरमल सर्राफ एण्ड सन्स द्वारा शेखावाटी में अनेक प्रकार के खनिज पदार्थों की खोज एवं शासकीय सहायता

श्री भैंरू सिंह—क्या वाणिज्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या यह सही है कि सीकर के डूंगरमल सर्राफ एण्ड सन्स ने शेखावाटी में कई प्रकार के खनिज पदार्थ सीसा, केल्साइट, फ्लूराइट, हेमेटाईल तथा हलमेनाईट आदि खोज निकाले हैं ?

(ख) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में डूंगरमल एन्ड सन्स को क्या सहयोग दिया गया और इन खनिज पदार्थों को निकालने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (वाणिज्य मन्त्री)—(क) नहीं, प्रोस्पेक्टिंग हो रहा है।

(ख) सरकार द्वारा खनिज का प्रमाणपत्र न्यूनतम दर पर दिया गया है।

श्री भैंरू सिंह—प्रमाणपत्र देने के अलावा और भी कोई सहायता दी गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं।

श्री भैंरू सिंह—क्या यह सही है कि डूंगरमल सर्राफ ने खनिज के लिये सरकार से सहायता की मांग की थी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं। उन्होंने जो मांग की वे सारी पूरी कर दी गई। वे मेरे से अभी मिले थे उनको सेन्टर से कुछ काम करवाना था उसके लिये सिफारिश कर दी गई है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २५४

श्री अध्यक्ष—श्री सोहनलाल भटनागर

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

प्रश्न संख्या २५५

शांतिलाल, असिस्टेन्ट वेलफेयर ओफिसर, समाज कल्याण विभाग, जयपुर की ग्रेड में वृद्धि करने के आधार

श्री भैंरूसिंह—क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या यह सही है कि श्री शांतिलाल, असिस्टेन्ट वेलफेयर ऑफिसर, समाज कल्याण विभाग, जयपुर को इस विभाग में आने से पूर्व सप्लाई विभाग में २०० रू० से ३०० रू० की ग्रेड में थे और अब वह २०० से ४०० रू० के ग्रेड में काम कर रहे हैं ?

(ख) यदि हां, तो उन्हें यह तरक्की किस आधार पर दी गई ?

(ग) क्या यह सही है कि श्री शांतिलाल की इस विभाग में आने के पश्चात नई सर्विस शीट बनाई गई है।

(घ) यदि हां, तो क्यों और इस नई सरविस शीट में उनके सप्लाई विभाग में काम करते समय की बांसवाड़ा, उदयपुर, सवाई माधोपुर, अलवर आदि स्थानों की भ्रष्टाचार की शिकायतें और उन पर की गई कार्यवाईयों का भी इन्द्राज किया गया है या नहीं ?

(ङ) श्री शांतिलाल ने अपना स्थायी पता क्या बताया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (समाज कल्याण मन्त्री)—(क) हां।

(ख) श्री गुप्ता को ग्रेड का मिनिमम २००)रू० दिया गया है जो सामान्यता नियमानुसार अस्थाई कार्यवाहक कर्मचारियों को भी दिया जाता है। तरक्की नहीं दी गई है ग्रेड का न्यूनतम दिया गया है १७०) प्लस २५) ।

(ग) हां, सर्विस बुक नहीं बनाई गई।

(घ) श्री शांतिलाल का सर्विस रिकार्ड सप्लाई में प्राप्त न होने के कारण नई सर्विस बुक बनाई गई जिसमें भ्रष्टाचार की शिकायतों का इन्द्राज नहीं किया गया, कारण कि समाज कल्याण विभाग इन शिकायतों के बारे में अनभिज्ञ है।

(ङ) यह सागवाड़ा जिला डूंगर पुर के रहने वाले हैं।

श्री भैंरूसिंह—क्या इसकी सूचना पब्लिक सर्विस कमीशन को दी जा चुकी है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नियमानुसार भेजनी पड़ती है, भेज दी होगी।

श्री भैंरूं सिंह—कब भेजी गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—तारीख मालूम करने के बाद बता दूंगा ।

श्री भैंरूं सिंह—क्या पब्लिक सर्विस कमिशन ने सरकार को सूचना दे दी है कि यह आज्ञा दुरुस्त नहीं है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री भैंरूं सिंह—क्या सरकार को यह मालूम है कि डूंगरपुर ग्रेन-प्रोक्योरमेंट के मामले में इनको सजा मिली है और उनका रेकार्ड जानबूझ कर खो दिया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह बिल्कुल गलत है । मेरे ख्याल से इन्होंने डूंगरपुर में नौकरी नहीं की है । अगर फिर भी आज सूचना दे रहे हैं तो जानकारी प्राप्त की जावेगी ।

श्री भैंरूं सिंह—क्या यह नई सर्विस शीट बनी है उससे पहले की जो शिकायतें हैं उनकी जांच करेंगे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार ने सर्विस बुक देखी उसमें कोई शिकायत नहीं थी ? कोई अर्जी देता है तो रूटीन में उसकी जांच होती है । अगर उसके खिलाफ कोई शिकायत हुई होगी तोउसकी जांच हुई होगी ।

श्री भैंरूं सिंह—क्या यह सही है कि इन कीसर्विस बुक स्वयं श्री शान्तिलाल ने बनाई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—विभाग में किसने बनायी यह मैं नहीं बता सकता विभाग के अध्यक्ष तो वही रहते हैं ।

श्री भैरोंसिंह—क्या सरकार ने उनकी नई सरविस बुक बनाने की कोई आज्ञा जारी की थी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसमें आज्ञा देने की क्या जरूरत नियमानुसार सभी की बनती है ।

श्री भैंरूं सिंह—क्या उनकी सरविस बुक नयी बनायी गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जरूर ।

श्री भैंरूसिंह—यह सर्विस बुक नई क्यों बनाई गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आपको यह मालूम होना चाहिये कि वे पहले गजेटेड ऑफिसर थे उनके बारे में सप्लाई डिपार्टमेन्ट को पूछा था, उसमें ऐसी कोई बात नहीं पाई जिसको

[श्री भोगीलाल पंड्या]

उनकी सरविस बुक में एन्टर करना ठीक प्रतीत हो। आप जैसी कि सूचना दे रहे हैं कि वे जिस समय डूंगरपुर में थे उस समय उन्होंने कुछ अनाज के सिलसिले में गडबड़ी की मैं जहां तक जान सका हूं वे कभी भी डूंगरपुर में रहे नहीं फिर भी आप कह रहे हैं मैं जानकारी प्राप्त करूंगा।

श्री भैंरूंसिंह—जब उनकी सरविस बुक नई बनाई गई तो सप्लाई डिपार्टमेन्ट से जानकारी प्राप्त करके कोई भी बात उनकी सरविस बुक में शामिल नहीं की गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—कोई बात हो तो शामिल की जाय, पहले का कोई भी इन्द्राज नहीं है।

श्री भैंरूंसिंह—अभी जैसा कि आपने बतलाया कागज देखकर मालूम किया कि कोई शिकायत नहीं है इसलिये कुछ भी इन्दराज नही किया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने कागज शब्द ही नहीं कहा, मैंने कहा कि उनकी सर्विस बुक में कोई इन्द्राज नहीं है जिसे हम नयी सरविस बुक में रखें।

श्री भैंरूंसिंह—मेरा यह प्रश्न है कि सप्लाई डिपार्टमेंट में जो उनकी सर्विस शीट के कागजात थे वे इस नई सर्विस बुक में शामिल किये गये या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जब कोई सर्विस बुक थी ही नहीं तो क्या इन्दराज करते, नोन गजड स्टाट की जिस प्रकार सरविस बुक बनती है वैसी ही बनाई गई है।

श्री भैंरूंसिंह—क्या यह आवश्यक है कि गजटेड आफिसर अगर किसी नोन गजटेड पोस्ट पर नियुक्त होता है तो उसका पुराना सरविस रेकार्ड उसमें शामिल नहीं किया जाय ?

श्री भोगीलाल पंड्या—गजटेड आफिसर की सर्विस बुक रहती ही नहीं जो कि एन्टर की जा सके।

श्री भैंरूंसिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न साफ है पहले जो सर्विस शीट के उनके कागजात थे वे क्या उनकी नई सर्विस बुक में शामिल किये गये या नहीं, अगर नहीं किये गये तो क्यों नहीं किये गये ?

श्री भोगी लाल पंड्या—विभाग ने जब अपनी सर्विस बुक तैयार की तो उन्होंने सप्लाई डिपार्टमेन्ट से उनकी पहले की सर्विस बुक मांगी थी वह आई उसमें ऐसा कोई इन्दराज नहीं था कोई बात ऐसी नहीं थी जिसको दर्ज करना आवश्यक हो।

श्री भैंरूंसिंह—मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जब सर्विस बुक उनकी तैयार थी चाहे किसी रूप में हो गजटेड के रूप में हो या नोन गजटेड के रूप में जब उनकी नई सर्विस बुक बनाई

[श्री भैरुसिंह]

गई तो वे पुराने कागज शामिल किये या नहीं ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—शामिल करने जैसी कोई चीज ही नहीं थी तो क्या शामिल किया जाय मेरा जबाब बिल्कुल साफ है।

श्री भैंरू सिंह्—क्या यह सही है कि जब कोई व्यक्ति गवर्नमेन्ट सर्विस में आता है तो उस दिन से उनके प्रमोशन आदि सरविस संबन्धी जितने भी कागजात होते हैं एक जगह किये जाते हैं ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—जैसा भी नियम होता है उसके अनुसार काम होता है ।

श्री भैंरू सिंह्—क्या श्री शान्तिलाल के मामले में तमाम रूल्स लागू किये गए हैं जो एक व्यक्ति के सर्विस में एन्टर होने पर किए जाते हैं ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—श्री शान्तिलाल के मामले में ही नही जो भी व्यक्ति सर्विस में आता है तमाम सर्विस रूल्स लागू होते हैं, हुए हैं, और होते रहेंगे ।

श्री भैंरू सिंह्—क्या यह सही है कि भूतपूर्व सप्लाई कमिश्नर ने श्री शान्तिलाल के खिलाफ जांच की थी कि उन्होंने सवाई माधोपुर में अनाज के सिलसिले में गड़बड़ी की थी जो उनकी सप्लाई की सर्विस शीट में शामिल है ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—मेरी जानकारी में तो ऐसी कोई चीज नहीं है ।

श्री भैंरू सिंह्—श्री शान्तिलाल को ग्रेड इनक्रीमेन्ट किस कारण से दिया गया ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—कोई इनक्रीमेन्ट नहीं दिया गया, पहले ही उनको १७० और २५ रुपये इस प्रकार १९५रु० माहवार मिलते थे अब उनको २०० रु० पर फिक्स किया गया है जैसा कि आम तौर पर हुआ करता है, पहले वे १२०-१०-३०० के ग्रेड में थे अब उनको २०० से ४०० के ग्रेड में रखा है ।

श्री भैंरू सिंह्—इस विभाग से इनको लिया गया क्या कम्पेटीटिव एक्जामिनेशन के आधार पर लिया गया या किसी और आधार पर ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—न्यूनतम योग्यतायें इस पोस्ट के लिये होनी चाहिये, वे सब पूरी करते हैं, उन सब को लिया गया है। इसके बाद पब्लिक सरविस कमीशन में जायेंगे। अगर

[श्री भोगीलाल पंड्या]

पब्लिक सर्विस कमीशन वालों को ठीक नहीं जंचेगीं तो उनको हटा सकते हैं, लेकिन सरकार ने जो भी न्यूनतम योग्यता इस जगह के लिए रखी शान्तिलाल उनको पूरी करते हैं।

श्री भैंरू सिंह—क्या यह सही है कि ये अभी अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—अस्थायी रूप से कर रहे हैं।

श्री भैंरू सिंह—स्थायी रूप से बिना पब्लिक सर्विस कमीशन के स्वीकृति के कैसे नियुक्ती करदी ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—मैं कह रहा हूं, अस्थायी तौर पर नियुक्ति हुई है, यह पोस्ट ही अस्थायी तौर पर क्रीएट हुई है।।

श्री भैंरू सिंह—क्या यह सही है कि श्री शान्तिलाल के संबन्ध में एप्रूवल के कागजात पब्लिक सर्विस कमीशन को करीब एक साल से भेज रहे हैं उनकी ओर से किसी भी प्रकार का जवाब अभी तक नहीं आया है ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—पब्लिक सर्विस कमीशन के जवाब का मुझे पता नही ?

श्री भैंरू सिंह—सरकार इनकी यादाहनी करती है या नहीं ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—कोई आवश्यकता नहीं पब्लिक सर्विस कमीशन नियत समय पर अपना काम करता है, विशेष आवश्यकता महसूस हो तो यादाहनी भी करवा देते हैं।

श्री भैंरू सिंह—क्या सरकार ने श्री शान्तिलाल के नाम की इस पद के लिए शिफारिश की है।

श्री भोगीलाल पण्ड्या—मैं जानकारी प्राप्त करके बता सकता हूं। आप अलग से यह प्रश्न पूछिये।

श्री भैंरू सिंह—क्या सरकार यह आवश्यक नहीं समझती कि इस पद के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा प्रार्थना पत्र आमिन्त्रित करवाये जांय और कम्पीटिटिव टेस्ट के आधार पर व्यक्ति का सिलेक्शन किया जाय ?

श्री अध्यक्ष—Next, Question number 256.

प्रश्न संख्या २५६

श्री अध्यक्ष—श्री सज्जनसिंह—(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित परिशिष्ट ५ देखिये)

प्रश्न संख्या २५७

जसवन्त कालेज, जोधपुर के द्वितीय वर्ष में असफल छात्रों से अधिक फीस लेना

श्री **भैंरू सिंह**—क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि गत वर्ष से जसवन्त कालेज, जोधपुर में दूसरे वर्ष के असफल छात्रों से ८. रू. माहवार फीस ली जाती है?

(ख) क्या यह भी सही है कि महाराजा कालेज, जयपुर में ऐसे छात्रों से सिर्फ साढे तीन रूपया माहवार फीस ली जाती है ?

(ग) क्या जसवन्त कालेज में इन छात्रों से अप्रेल, मई व जून के महीने की फीस के भी २४ रूपये लिये जाते हैं ?

(घ) क्या इन महीनों में ये छात्र कालेज में नहीं पढ़ते हैं ? यदि हां, तो फिर यह फीस उनसे क्यों ली जाती है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—(उप शिक्षा मंत्राणी) (क) जी हां स्पेशल क्लास वाले छात्रों से।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) प्रत्येक कालेज में पूरे सेशन के लिये ली जाती है।

श्री भैंरू सिंह—मेरा यह भी प्रश्न है कि लड़कों से ज्यादा फीस क्यों ली जाती है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—इसलिये ली जाती है कि इनको बैठने की जगह कम होती है इसलिये रात्रि में क्लासें चलानी पड़ती हैं, उसका प्रोफेसर्स को अलाउन्स देना पड़ता है।

श्री भैंरू सिंह—क्या यह सही है कि प्रोफेसर्स को गर्मियों की छुट्टियों का भी अलाउन्स दिया जाता है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल--फीस तो जितनी भी ली जाती है पूरे सेशन की ली जती है ।

श्री भैंरू सिंह—गर्मियों की छुट्टियों में प्रोफेसर्स पढ़ाते तो नहीं है फिर फीस क्यों ली जाती है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—गर्मियों की छुट्टियों का वेतन तो देना पड़ता है, हालां कि स्कूल और कालेज बन्द रहते हैं ।

श्री भैंरू सिंह—स्पेशल फीस ली जाती है वह क्यों ली जाती है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—फीस तो पूरे सेशन की ही ली जाती है किसी को किसी प्रकार का कन्सेशन नहीं है ।

श्री भैंरू सिंह—क्या यह सही है कि कुछ छात्रों के आवेदन पत्र पर सरकार ने यह आदेश दिया है कि इस वर्ष के बाद में यह स्पेशल फीस बन्द कर दी जायगी ?

श्रीमती बेनीवाल—मुझे तो पता नहीं, ऐसा होगा तो विचार हो रहा होगा ।

श्री भैंरू सिंह—जयपुर और जोधपुर के छात्रों में इतना फर्क क्यों रखा गया ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जोधपुर में रात्रि को क्लासें लेनी पड़ती है जयपुर में नहीं:—

श्री भैंरू सिंह—नाइट क्लासेज में बिजली का प्रबन्ध करने का काम सरकार का है या छात्रों का ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—लेकिन जहां विशेष सुविधा की आवश्यकता होती है वहां तो प्रबन्ध करना ही पड़ता है !

श्री भैंरू सिंह—जब कि जयपुर में नाइट क्लासें चलती हैं तो यहां तो फीस नहीं ली जाती फिर जोधपुर में यह क्यों ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—यह मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री भैंरू सिंह—अगर जयपुर में नाइट क्लासेज के लिये स्पेशल फीस नहीं ली जाती होगी तो क्या जोधपुर में भी नहीं ली जायगी ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जायगी अगर दोनों का मामला एक सा है तो डिफरेन्स नहीं किया जायगा ।

प्रश्न संख्या २५६

पुरानी बस्ती स्थित (जयपुर) गोपीनाथ जी के मन्दिर का प्रबन्ध सरकार द्वारा लिया जाना

श्री भैरूं सिंह—क्या देवस्थान मंत्री निम्न लिखित प्रश्नका उत्तर देंगे :—

(क) क्या यह सही है कि जयपुर में पुरानी बस्ती स्थित गोपीनाथ जी के मन्दिर पर जनवरी, सन् १९५६ में सरकार द्वारा अधिकार कर लिया गया है ?

(ख) यदि हां, तो क्यों

(ग) सरकारी अधिकार में लेने के पश्चात मन्दिर की व्यवस्था का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

(घ) क्या यह सही है कि इसकी व्यवस्था के लिए एक कामदार नियुक्त किया गया है, यदि हां, तो किसको और किस आधार पर ?

श्री दामोदरलाल व्यास (देवस्थान मंत्री)—(क) जी हां । तारीख १३।१।५६ को मन्दिर श्री गोपीनाथ जी पर सरकारी इन्तजाम करने का हुक्म जारी हुआ ।

(ख) इसके कारण निम्न प्रकार हैं—

१. गोस्वामी जी द्वारा मन्दिर व उसकी जायदाद का कुप्रबन्ध ।

२. लगभग १५, ००० रुपये की कीमत की मन्दिर की सम्पत्ति की चोरी ।

३. स्वयं गोस्वामी जी और उनके भाई के संबन्ध में अनेक प्रकार की शिकायतें जिसमें चालचलन की काफी शिकायतें थी ।

४. गांव की आमदनी में से नाजायज फायदा उठाना ।

(ग) इस सम्बन्ध में श्री गोस्वामीजी ने उच्च न्यायालय में रिट एपलीकेशन प्रस्तुत की वहां से हुक्म इम्तनाई प्रचलित हुआ । इसी बीच गोस्वामी ने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का

[श्री दामोदरलाल व्यास]

अवसर चाहा और प्रार्थना पत्र तारीख १७-१-५६ को प्रस्तुत किया, इस पर प्रबन्ध में लेने की आज्ञा को मन्सूख कर दिया गया ?

(घ) जी हां, गोस्वामीजी की तरफ से जो कामदार सरकारी प्रबन्ध होने से पहले थे उन्हें कामदार रखा गया।

श्री भैंरू सिंह (१६)—क्या यह सही है कि अधिकार करने से पूर्व गोस्वामी जी को कोई सूचना नहीं दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया अपने उत्तर के भाग में। पहले बिना नोटिस दिये ही अधिकार लेने की बात आई इस पर गोस्वामीजी का आवेदन मिला, इस पर देवस्थान कमिश्नर को आज्ञा दी गई कि बाकायदा नोटिस देकर बाद में अधिकार किया जाय।

श्री भैंरू सिंह—बिना नोटिस दिये सरकार के जिन अधिकारियों ने उस पर अधिकार कर लिया और जिसके कारण गोस्वामीजी को सरकार को नोटिस देना पड़ा, उन अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने क्या एक्शन लिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अधिकार पूरा किया नहीं गया और इस बीच ही गोस्वामीजी का रिप्रेजेन्टेशन मिला। जिस पर बाकायदा नोटिस देकर कार्यवाही करने के आदेश दिये।

श्री भैंरू सिंह—क्या यह सही नहीं है कि देवस्थान विभाग के अध्यक्ष ने बिना सरकार की उचित आज्ञा के ही उस मन्दिर पर अधिकार पहले कर लिया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी नहीं, यह सही नहीं है।

श्री भैंरू सिंह—क्या यह सही है कि सरकार ने ऐसे आदेश दिये थे कि बिना पहले गोस्वामी जी को नोटिस दिये ही मन्दिर पर अधिकार कर लिया जावे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—नीचे से सिफारिश आई थी कि अधिकार कर लिया जावे इस पर गोस्वामीजी ने रिप्रेजेन्टेशन दिया इस पर आदेश दिया गया कि गोस्वामी जी को बाकायदा नोटिस देकर उनका जवाब भी शामिल कर लिया जावे।

श्री भैंरू सिंह—बिना नोटिस इस मन्दिर पर अधिकार करने की गलती विभागीय अध्यक्ष के द्वारा हुई या उस मन्दिर के लिए मनोनीत अध्यक्ष के द्वारा हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया देवस्थान विभाग के अध्यक्ष ने सरकार को सिफारिश की थी इसको ले लेने की पर बाद में गोस्वामीजी का रिप्रेजेन्टेशन आने से बाकायदा नोटिस देकर और उनका जवाब शामिल करके बाद में अधिकार करने का आदेश दिया गया।

श्री भैंरू सिंह—क्या यह सही है कि मन्दिर की शिकायतें बताई गई थी पर उनकी किसी भी अधिकारी से जांच नहीं करवाई गई और बिना जांच कराये ही उस पर अधिकार कर लिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जांच करवाई गई थी और उसमें गोस्वामी जी को भी बराबर जानकारी में रक्खा गया था।

श्री भैंरू सिंह—जांच किस अधिकारी से कारवाई गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—असिस्टेन्ट कमिश्नर, देवस्थान विभाग।

श्री भैंरू सिंह—क्या यह सही है कि इस जांच में गोस्वामीजी को शामिल नहीं किया ?

श्री दामोदर लाल व्यास—वक्त २ पर शामिल किया गया।

श्री भैंरू सिंह—पहले जांच करवाई गई उसमें शामिल उनको नहीं किया गया और अधिकार करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई। इस पर उन्होंने नोटिस दिया सरकार को, तो क्या यह सही नहीं है कि इस जांच में उनको शामिल नहीं रक्खा गया शुरू से आखिर तक बराबर ?

श्री दामोदरलाल व्यास—वक्त वक्त पर जरूर शामिल किया गया। यह मैं कह चुका हूं।

श्री भैंरू सिंह—मेरे कहने का आशय यह है कि उनको अपनी सफाई का मौका पूरा पूरा नहीं दिया गया !

श्री दामोदरलाल व्यास—तभी तो उनको नोटिस देकर उनसे जवाब हासिल करने का और सफाई देने का मौका दिया गया।

श्री भैंरू सिंह—वह तो मौका इस बात का दिया गया कि चूंकि आपने बिना नोटिस दिये ही अधिकार कर लिया था। मैं पूछ रहा हूँ जांच में गोस्वामी जी को अपने बयान देने का मौका दिया गया या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह महज कानून का सवाल है। प्रलिमिनेरी एन्क्वायरी हुई। उसकी जानकारी वक्त २ पर उनको दी जाती रही पर उनके बयान लेना उस वक्त जरूरी नहीं समझा

[श्री दामोदरलाल व्यास]

गया। पर बाद में उन्होंने जब रिप्रेजेन्टेशन किया इसलिये नोटिस देकर सफाई देने का उनको मौका दिया गया।

अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री हंसराज।

प्रश्न संख्या २६०

धौलपुर सब डिविजन में आठवीं कक्षा में फीस का लिया जाना

श्री हंसराज जटिया—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या यह सत्य है कि धौलपुर सब डिविजन में ८ वीं कक्षा को फीस ली जाती है?

(ख) क्या राजस्थान में अन्य स्थानों में भी यह फीस ली जाती है?

(ग) यदि नहीं, तो फिर केवल धौलपुर सब डिविजन में ही क्यों ली जाती है?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनिवाल (उप शिक्षा मन्त्राणी)—(क) जी हां।

(ख) अन्य स्थानों पर भी कहीं २ ली जाती है।

(ग) फीस की दरें सब राजस्थान में समान करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रहो है।

श्री हंसराज जटिया—सब जगह इस वक्त एक फीस क्यों नहीं है?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—यह पहले की चली आ रही है। अब कोशिश कर रहे हैं एक करने की।

श्री हंसराज जटिया—यह कब तक एक हो जावेगी?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जल्दी ही करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। श्री भैंरूसिंह।

प्रश्न संख्या २६१

नाथद्वारा मन्दिर का प्रबन्ध वर्तमान सरकार द्वारा नई प्रबन्ध समिति को दिया जाना और गुसांई जी के अधिकारों में वृद्धि किया जाना

श्री भैंरू सिंह (१६)—क्या देवस्थान मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या नाथद्वारा की सेवा पूजा सम्पत्ति व व्यवस्था का सम्पूर्ण अधिकार भूतपूर्व सरकार द्वारा एक प्रबन्ध समिति को सौंपा गया था ?

(ख) क्या यह सही है कि वर्तमान सरकार द्वारा इस प्रबन्ध समिति को भंग करके नाथद्वारा के गुंसाईं जी को मन्दिर का अधिकार दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) मन्दिर की सम्पत्ति, आय व व्यवस्था के सम्बन्ध में गुंसाईंजी को सरकार द्वारा क्या २ अधिकार दिये गये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) वस्तु स्थिति इस प्रकार है कि गोस्वामी जी व वैष्णवों में आपस में मन्दिर की तथा सम्पत्ति के प्रबन्ध की स्थायी योजना तैयार करने के लिये कई बैठकें होकर एक योजना बनाई गई जिसमें वैष्णवों के १२ सदस्य थे और श्री गोस्वामी जी सभापति थे। सरकार ने कोई योजना अपनी तरफ से नहीं बनाई बल्कि जो अन्तर्कालीन प्रबन्ध था वह एक पावर आफ एटोरनी के जरिये से था जिसको भी श्री गोस्वामी जी ने रद्द कर दिया और सरकार के समक्ष एक योजना पेश की जो वैष्णवों और श्री गोस्वामी जी दोनों की सहमति से तैयार की गई बताई, उसको सरकार ने स्वीकार कर लिया। मगर जब वैष्णव समाज के लोगों ने इसका विरोध किया तो सरकार द्वारा अपनी स्वीकृति वापिस ली गई।

श्री भैंरू सिंह—जो अन्तर्कालीन व्यवस्था थी उसको समाप्त करने के लिए महन्त जी को क्या अधिकार है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—गोस्वामी जी ने वहां की व्यवस्था चलाने के लिए पॉवर आफ एटोरनी द्वारा १२ आदमियों को मुकर्रर किया था और उनको वहां की व्यवस्था चलाने का अधिकार दिया था जिस पावर आफ एटोरनी को रद्द करने का उनका अधिकार था और वही उन्होंने किया।

श्री भैंरूं सिंह—क्या यह सही नहीं है कि इस प्रकार की अन्तर्कालीन व्यवस्था को रद्द करने से पहले गोस्वामी जी का इस मन्दिर की प्रोपर्टी पर अधिकार नहीं था ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इस पर तो उनका अधिकार न पहले था, न बाद में रहा और न आज है।

श्री भैंरूं सिंह—क्या यह सही है कि उस प्रकार की अन्तर्कालीन व्यवस्था को समाप्त करने के बाद जो नई व्यवस्था की गई उसमें जो रुपया गोस्वामी जी को मिलता था वह रुपया ज्यादा बढ़ा दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह बिल्कुल गलत है।

श्री भैंरूं सिंह—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अन्तर्कालीन व्यवस्था में उनको कितना मिलता था और आज कितना मिलता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अन्तर्कालीन व्यवस्था में कुछ नहीं लिया पर इसके लिये झगड़ा चलता रहा कि कितना मिलना चाहिये। इस झगड़े का फैसला नहीं हो सका और आखिर राजस्थान सरकार के भूतपूर्व माननीय मुख्य मन्त्री ने चार हजार देने की आज्ञा दी और बाद में उनको महज तीन हजार दिलवाया गया है।

श्री भैंरूसिंह—क्या यह सही नहीं है कि महाराज को सरकार ने बम्बई से केवल इसीलिए बुलाया गया था कि उनके एलाउन्स में वृद्धि की जायगी और दूसरी व्यवस्था प्रबन्ध समिति की जायगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—सरकार ने महाराज को नहीं बुलाया। महाराज खुद ही आये और जिसका उनको अधिकार भी है।

श्री भैंरूं सिंह—अब क्या व्यवस्था कर रक्खी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—वर्तमान प्रबन्ध समिति और महाराज के दरमियान परमानेन्ट व्यवस्था की एक स्कीम बना ली गई है और जो भी मेम्बर हैं वे एक मैनेजिंग कमेटी के रूप में वहां का प्रबन्ध कर रहे हैं। इधर सरकार ने दफा ९२ C.P.C. में डिस्ट्रिक्ट जज उदयपुर की कोर्ट में दावा दायर कर दिया है जो चल रहा है।

श्री भैंरूं सिंह—कोई प्रतिनिधि सरकार का भी है इस अन्तर्कालीन प्रबन्ध समिति में ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अर्तन्कालीन से आपका क्या मतलब है ? वर्तमान प्रबन्ध समिति से या पहले वाली से ?

श्री भैंरूंसिंह—वर्तमान से।

श्री दामोदरलाल व्यास—इसमें कमिश्नर, उदयपुर एक सदस्य हैं सरकार की ओर से।

श्री भैंरूंसिंह—क्या यह सही है कि आज भी सरकार का नियन्त्रण वहां की सम्पति पर नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—ठीक है, वहां की कुल सम्पत्ति पर अधिकार कमेटी का है।

श्री भैंरूंसिंह—मेरा प्रश्न सरकार के नियन्त्रण का है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसका कोई सवाल नहीं पैदा होता। वह मन्दिर की सम्पत्ति है और उस के प्रबन्ध का अधिकार प्रबन्ध समिति की है।

श्री भैंरूंसिंह—इस प्रबन्ध समिति की स्वीकृति सरकार की ओर से मिल गई है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यही तो मैंने अर्ज किया कि दफा ९२ में दावा दायर कर रक्खा है।

श्री भैंरूंसिंह—तो जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक प्रबन्धक कमेटी का मन्दिर की प्रोपर्टी पर कैसे अधिकार हो गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसके लिए सरकार की स्वीकृति का सवाल नहीं है। तिलकायत महाराज ने और प्रबन्ध समिति के सदस्यों ने मिलकर एक स्कीम पेश की है और उन्होंने प्रबन्ध का अधिकार उस समिति को सौंपा है। सरकार ने अपनी तरफ से दावा दायर करवा दिया है।

श्री भैंरूंसिंह—यही तो मेरा प्रश्न है कि जब तक फैसला नहीं होता है तब तक प्रबन्धक समिति को काम करने का अधिकार कैसे होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसके लिये इन्टेरिम पावर आफ एटोर्नी फिर ले लिया गया है तिलकायतजी महाराज से।

श्री भैंरूंसिंह—सरकार की शक्ति से या महाराज की इच्छा से ?

श्री दामोदरलाल व्यास—दोनों के आपसी फैसले के अनुसार।

श्री भैंरूंसिंह—क्या यह सही है की उस फैसले में इस वेष्णव कमेटी को प्रबन्धक नहीं बनाकर पावर आफ एटोर्नी का लैटर किसी और के नाम से दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह गलत है।

श्री भैरूंसिंह—यह सही है कि पावर आफ एटोर्नी का लैटर लिया गया पर इसकी जो पृष्ठभूमि है उसमें इस पर वेष्णवों के बिलकुल दस्तखत नहीं हैं, उन का इस पर नोट आफ डिसेन्ट भी है।

श्री दामोदरलाल व्यास—पावर आफ एटोर्नी महज तिलकायत महाराज ही एग्जीक्यूट करते हैं। यह तो एक कानूनी मसला है। इसको अगर आप देख कर आया करें तो ज्यादा अच्छा हो। सवाल कम हो सकते हैं और समय बच सकता है।

श्री शम्भूसिंह—क्या यह तिलकायत महाराज का निजी मन्दिर है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—नेक्सट।

प्रश्न संख्या २६२

चित्तौड़ जिले की कुछ तहसीलों में दुबारा बन्दोबस्त की कार्यवाहियें एवं काश्तकारों से बेगार

श्री जगतसिंह झाला—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या चित्तौड़ जिले की कुछ तहसीलों में दुबारा बन्दोबस्त का कार्य शुरु कर दिया गया है ? यदि हां, तो कहां कहां ?

(ख) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा बेगार बन्द होने के बावजूद भी इस विभाग के कर्मचारियों द्वारा काश्तकारों से खेतों में जरीब वगैरा डालने का कार्य जबरन लिया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—चित्तौड़ जिले की तहसील कपासन में तरमीम बन्दोबस्त का काम आरम्भ किया गया है।

(ख) बेगार की प्रथा नहीं है।

श्री जगतसिंह झाला—क्या यह सही है की इस बारे में शीकायतें पेश हुई हैं आपके पास कपासन से ?

श्री दामोदरलाल व्यास—आप कोई स्पेसिफिक शिकायत करेंगे या कोई भी स्पेसिफिक शिकायत मेरे सामने लाई जावेगी तो मैं अवश्य उसकी जांच कराऊँगा। वैसे मेरे पास अभी तक कोई शिकायत नहीं आई।

प्रश्न संख्या २६३

श्री अध्यक्ष—श्री श्रीदास गोयल।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर वाद विवाद

श्री अध्यक्ष—Discussion on the Draft outlines of the Second Five Year Plan.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम यह पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप है उस पर विचार करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर दूं कि आज जिस चीज़ पर इस सदन में हम विचार कर रहे हैं, वह राजस्थान की द्वितीय पंचवर्षीय योजना ही नहीं लेकिन सारे भारतवर्ष का जो ड्राफ्ट प्लान है, उस पर हमें विचार करना है और उस दृष्टि से विचार करने में खास उद्देश्य यही है कि प्लानिंग कमीशन और गवर्नमेंट आफ इंडिया इस मसौदे पर जल्दी ही चर्चा करने वाले हैं और निर्णय करने वाले हैं तो इसके पहले वे यह चाहते थे कि अलग अलग जो विधान सभाएं हैं, उनके अन्दर इसके बारे में जो कि सारे भारतवर्ष का प्लान है, क्या २ अलग अलग रायें हैं वह भी उनको मालूम हों तो ज्यादा अच्छा हो, कि उस दृष्टि से हम यहां विचार करने के लिए इस प्रश्न को लें। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता था कि हमारी बहस में ऐसा न हो कि हम बजाय सारे भारतवर्ष के प्लान के राजस्थान के प्लान के ऊपर डिसकशन की बात को ज्यादा आधारित कर दें। जब हम सेकिन्ड फाइव इयर प्लान को डिसकस कर रहे हैं यहां पर तो एक महत्वपूर्ण चीज पर हम विचार करने जा रहे हैं, जिस चीज का असर आने वाले ५ वर्षों तक ही नहीं बल्कि उस के आगे भी सारे देश के ऊपर पड़ने जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद इस प्लान के बारे में देश में अलग २ स्तर पर काफी चर्चाएं आपस के अन्दर हुई हैं। नेशनल डेवलपमेंट कौन्सिल, उसकी स्टेंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट के मेम्बर्स, कलकत्ते के अन्तर स्टेटिस्स के लिए खास तौर से आयोजित संगठन और अलग २ मेम्बर्स और दूसरी जो संस्थाएं है, अखबार हैं, उन्होंने इस पर काफी चर्चाएं की हैं और काफी वादविवाद के बाद जो वर्तमान प्रारूप हमारे सामने है। वह आया है। इस प्लान को बनाने के अन्दर सबसे पहले यह आवश्यक होगा कि हम इस चीज को सामने रखें कि हमारा आब्जेक्टिव क्या है? हम किस लक्ष्य को लेकर देश के प्लान को देखना चाहते हैं? स्पष्ट है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

बनाई गई थीं, उस समय आर्थिक विकास और सामाजिक विकास का दृष्टिकोण जो हमारे सामने था, लेकिन बीच में जो वर्ष गुजरे उसके साथ साथ हमारा दृष्टिकोण भी स्पष्ट हो ही गया और इस समय जब की हम इस प्लान को स्वीकार करने की बात कर रहे हैं, देश में समाजवादी आधार को अपने सामने रखा और यह निश्चित बात है कि सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान जैसी बड़ी चीजों को हम तय करने जा रहे हैं तो उसका असर उस उद्देश्य पर क्या पड़ता है ? उस दृष्टिकोण से देखना होगा। लेकिन उसको देखने में यह हमें स्पष्ट तौर पर मानकर चलना होगा कि हम किसी एक डॉक्ट्रिन के तौर पर सोशलिज्म की चर्चा के अन्दर इस प्लान के मामले को रखें तब यह आवश्यक है कि बहस में ज्यादा पड़ जांय और वास्तविकता से दूर हो जायं। इसलिए जहां तक सोशलिस्टिक पेटर्न के अपने लक्ष्य की बात कहते हैं, वहां पर हमें देश की परिस्थितियों, देश की आवश्यकताओं, को सामने रखकर विचार करना होगा। केवल डॉक्ट्रिन्स, स्लोगन्स या और बातों के उपर इन चीजों के ऊपर आने वाला प्रश्न स्पष्टतः सामने नहीं आता।

पिछले प्लान और इस प्लान के बीच में हमारा जो स्ट्रेस है, मतलब जोर हमारा है, वह इस बात पर ज्यादा रहा है कि इस प्लान के अन्दर हम हेवी इन्डस्ट्रीज़ या बेसिक इन्डस्ट्रिज़, जिन्हें आप कहें, या मशीन मेकिंग इन्डस्ट्रिज़ जिन्हें आप कहें, या स्टील प्लान्टस जिनको कहें, इस प्रकार की जो योजना है, उसके ऊपर आने वाली पंच वर्षीय योजना में अधिक से अधिक ध्यान केन्द्रित करें। और उस बात को सोचने के पीछे स्पष्ट है कि हमारा लक्ष्य यह रहा है कि जहां प्राइवेट सेक्टर के अन्दर बहुत सी स्ट्रेटेजिक इन्डस्ट्रीज हैं या प्राइवेट का इकोनोमिक असर सोशल ऑर्डर पर इतना हो कि जिस असर की वजह से हमारी सोसाइटी के अन्दर जो हम परिवर्तन करना चाहते हैं, उस परिवर्तन करने के अन्दर बाधक हो या उस बेलेन्स को और तरह का करने वाला साबित हो तो उसको रोका जाना चाहिए। और जब रोकने की बात कहते हैं तो स्वाभाविक परिणाम यह उठता है कि हम पब्लिक सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा बड़ा बनायें। उस पब्लिक सेक्टर को बड़ा बनाने के संबंध में देश में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं हुई हैं। कई व्यक्तियों ने इस बात पर काफी जोर दिया कि देश में पहले कन्जूमर्स गुड्स का उत्पादन ज्यादा करें, और कन्जूमर्स गुड्स के उत्पादन से जो बीच में प्राफिट हो, उसका इन्डस्ट्रियेलाइजेशन ज्यादा हो। लेकिन सही बात तो यह है कि अगर हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं तो कुछ फेक्ट्रीज या इन्डस्ट्रीज जो कन्जूमर्स गुड्स के अन्दर डील करती हैं, उन कन्जूमर्स गुड्स पर ध्यान दें तो हमारा देश भविष्य के लिए बड़ी चीजों के लिए तैयार नहीं हो सकता। अगर हमें बड़ी चीजों के लिए तैयार होना है, जैसा कि एक स्वतन्त्र देश को तैयार होना चाहिए, तो निश्चित बात है कि इन्डस्ट्रियलाइजेशन की जब बात कहें पब्लिक सेक्टर में, तो सिवाय इसके दूसरा हो नहीं सकता कि हम अपने यहां हेवी इन्डस्ट्रीज़ को ज्यादा से ज्यादा बड़े पैमाने के ऊपर कामयाब करें। और इस प्लान को देखने से जाहिर होता है कि स्टील प्लान्ट्स के ऊपर विशेष तौर से ध्यान दिया गया है, क्यों कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के के अन्दर भी उस कमी को हमने महसूस किया, हम बराबर इस बात का अनुभव करते रहे कि रात दिन मशीनरी के मामलों में अब भी विदेशों पर बहुत ज्यादा आधारित रहना पड़ता है, और

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

बड़ी योजना या बड़ा काम जिस तरह का हम आगे चाहते हैं, वह करना हमारे लिये बड़ी मुश्किल हो जाता है। फिर, अध्यक्ष महोदय, जब प्लान पर डिसकस करना है तो मैं समझता हूं, एक पक्ष या साईड को लेकर प्लान को नहीं देखा जा सकता। उसको सही रूप से समझने के लिए यह आवश्यक होगा कि हमें विभिन्न सेक्टर जो अलग अलग हैं, उन सब के ऊपर विचार करना होगा, चाहे वे रुरल सेक्टर हों, अरबन सेक्टर हों, लेबर सेक्टर हों या लैण्ड पालिसी का सवाल हो, इन्डस्ट्रियलाइजेशन का सवाल हो, सोशल अपलिफ्ट का सवाल हो, वे सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। किसी साइड को छोड़कर प्लान पर विचार नहीं कर सकते। और जो प्लान जिसके बारे में हम चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, इस प्लान के अन्दर इन सारी चीजों के अन्दर ध्यान दिया गया है और इस बात का प्रयत्न किया गया है कि इस प्लान को डेमोक्रेटिक तरीके से चलाया जाय। अध्यक्ष महोदय, इस बात पर काफी चर्चा देश के अन्दर हुई है और अब भी काफी चर्चा होती रहती हैं। इतना बड़ा प्लान जिसमें ४८ करोड़ पब्लिक सेक्टर के लिए है। हम इस देश में पूरा करना चाहते हैं वह क्या देश के अन्दर डेमोक्रेटिक तरीके से बिना कन्ट्रोल्स के बिना, स्टेट कन्ट्रोल, जिसे कहना चाहिए, अधिक बढाये हम सफल कर सकेंगे ? अब तक जो बड़े बड़े प्लान हैं ज्यादातर पूरे किये गये हैं; एक प्रकार से उनमें एक डिक्टेटर शिप के तरीके से सारे प्लान को पूरा किया। काफी स्टेट कन्ट्रोल रहा, और कन्जम्पशन के अन्दर, एक्सपेन्डीचर के अन्दर, उन सारी चीजों के अंदर इस तरह की बातें पैदा हुई हैं देश के अंदर। लेकिन इस चीज में इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखने का प्रयत्न किया गया है कि जो प्लान हम देश में लागू करना चाहते हैं, उसमें डेमोक्रेटिक वरकिंग का एलीमेंट जो है वह समाप्त न हो जाय, उसको कायम रखते हुए तेजी के साथ उस ओर बढ़ सकें। सारे प्लान का उद्देश्य यही है कि आम तौर से नेशनल इनकम बढे और जो अनएमप्लोयमेंट बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ऐसा ख्याल किया जाता है, वह अनएमप्लोमेंट न बढे, लोगों को एम्पलोयमेंट मिले और इस प्रकार स्टेंडर्ड आफ लिविंग आम तौर से लोगों का ऊंचा हो। ख्याल यह किया जाता है कि जो प्लान अब सामने रखा गया है उसके द्वारा करीब २५ परसेंट नेशनल इनकम के अंदर इनक्रीज़ हो, और यह भी ख्याल किया जाता है कि २५ परसेंट नेशनल इनकम के इनक्रीज के साथ जो एम्प्लोयमेंट के फेक्टर को केल्क्यूलेट किया गया है उसमें अनएमप्लोयमेंट रूरल, अरबन और अंडर एमप्लोयमेंट है उनको एमप्लोयमेंट मिलता है, सारे फेक्टर्स को अगर कंसीडर करते हैं, तो करीब करीब जिसे यह कहा जाय कि ८ मिलयन यानी ८० लाख लोगों के करीब को काम मिले, ऐसा इसमें एक आधार मानकर चला गया है।

यह स्पष्ट है अध्यक्ष महोदय, कि आने वाले पांच वर्ष के बाद जो रेट ऑफ इंक्रीज इन पोपुलेशन है, जिसे पोपुलेशन की बढोतरी कहें उसको सामने रख कर और जो हमारे यहां कि स्थिति है उसको सामने रख कर चलें तो बहुत मुमकिन है जो अन एमप्लोयमेंट के जो पर सेन्टेज आज हैं इनमें बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कर पायें लेकिन इस प्लान से,

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

जो अनएम्पलोयमेंट आज है और फ्यूचर पोपुलेशन का जो एडीशन होगा और उससे जो अधिक अनएम्प्लोयमेंट बढ़ सकता है वह नहीं बढ़ सकेगा और ५६,५७ की जो पोपुलेशन है; का सवाल है उसको फेस करना पड़े। कई बातों की इस मौजूदा प्लान में कमी मालूम पड़ सकती है। उसके कारण स्पष्ट हैं। एक तो इन सारी चीजों को अपने साधनों के अनुसार पूरा करना चाहते हैं। जो ४८०० करोड़ रूपयों का प्लान हमारे सामने है, उसको किस प्रकार पूरा कर सकते हैं इस पर एक दृष्टि डालूं तो अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि हमारे सामने स्पष्ट होगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना को पूरा करने का एक हिम्मतवरी का काम प्लानिंग कमीशन ने और भारत सरकार ने अपने हाथ में लिया है, अपने साधनों को देखते हुए। जो हमारे वर्तमान देश की रेवेंनूज है, उसमें से ख्याल है ३५० करोड रूपया उपलब्ध होंगे और एडीशनल टेक्सेज से ४५० करोड़ रूपये एकत्रित करना पड़ेगा और फिर रेलवे से १५० करोड़ रूपये अधिक आने का अनुमान है और २५० करोड़ रूपयों की आमद प्रोविडेन्ट फन्ड से, लोंस और स्माल सेविंग्स से १२०० करोड़ का अंदाज लगाया जा सकता है और उन सब को जोड़ कर देखें तो २४०० करोड़ आ सकते हैं। बाकी २४०० करोड़ का प्रश्न रहता है। उसके लिए यह ख्याल किया जाता है कि एक्स्टर्नल एसिस्टेंस, फौरिन कंट्रीज से, ८०० करोड़ रूपयों के करीब मिल सकती है और उसके बाद डेफिसिट फाइनेंस १२०० के लिए एक्स्ट्रा रुपया सरकुलेट करने की बात जुड़ती है और बाकी का रूपया हमारे यहां के इनटरनल रिसोर्सेज से ख्याल करें तो इस तरह ४८०० करोड़ रूपया हो सकता है। इन ४८०० करोड़ रूपयों में से जहां एक्सटरनल एसिस्टेंस का ८०० करोड़ आने का का जैसा कि ख्याल है जब कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में ५०० करोड़ के आस पास की औसत रहती है जिसका मतलब यह है कि पांच साल में यह औसत रही और अब ८०० करोड़ को सामने रख कर इस को फेस करना चाहते हैं। इन फीगर्स को सामने रखने का मतलब यह है कि आपको हमको सोचना पड़ेगा कि और ज्यादा काम किये जाते तो ज्यादा एम्प्लोयमेंट होता और नेशनल इनकम ज्यादा हो सकती थी, ज्यादा बड़े प्लान की बात जब हम करते हैं तो रिसोर्सेज की बात को नजर अन्दाज नहीं कर सकते हैं और इसकी डिटेल्स को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे साधन क्या है और हमें क्या करना है? इसमें जो कुछ भी कहा गया है उसके लिए भी बड़े एफर्ट्स की जरूरत होगी और उसमें कामयाब होंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने बताया कि जो आयोजन किया गया है इसमें है, इस हद तक संभव हो सकता है।

एक और खास बात इस प्लान की है और मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, कि वह वाजिब भी है। हमारा दृष्टि कोण यह है कि हमें इस प्लान को एक रिजिड प्लान की तरह सोच कर नहीं चलना चाहिये, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का यह आयोजन है यह सोचने की बात नहीं है कि जो कुछ लिखा हुआ है वह अन्तिम है। हर वर्ष इसपर विचार किया जावेगा अपने साधनों के अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार और अपने अनुभवों को सामने रखते हुए और एक ब्राड, एक बड़ा ब्राड फ्रेम वर्क्स हैं हमारे सामने हैं, जिसको लेकर चले। इस ब्राड फ्रेम वर्क के अन्दर बड़ी बड़ी चीज़ हैं नदी घाटी योजना, पावर की योजना, जिसको आप शुरू करना चाहते हैं, या शुरू हो

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

वे तो स्वभाविक हैं, शुरू रहेंगी। हर वर्ष इस प्लान पर चर्चा की जावेगी और देश की परिस्थिति के अनुकूल इसमें आवश्यक परिवर्तन किया जावेगा, क्यों कि बहुत से परिवर्तन आज देश में, विदेशों में इतनी तेजी के साथ हो रहे हैं, हो सकता है कि वर्ष भर बाद इन परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ और हम समझें कि इस प्लान में अमुक परिवर्तन करना चाहिए, जहां यह आवश्यक है कि इसको इयर टू इयर रिवाइज करें, रिवाइज करने का मतलब यह नहीं कि जो डाफ्ट हमारे सामने है वह कोई बेसिक नहीं रखता है। वह बेसिस रखेगा। उसमें जो चेन्जेज होंगी या जो परिवर्तन करना आवश्यक हुआ, उन चीजों पर विचार किया जावेगा परिस्थिति समान हो या न हो, लेकिन यदि परिस्थिति में परिवर्तन होता है तो इसमें भी परिवर्तन हो सकता है। तो रिजिडिटी इसमें नहीं हैं। फ्लेक्सिटी का अंश मौजूद है।

तीसरी चीज इसमें यह है कि इस प्लान को कन्सीडर करते हुए इस बात को लक्ष्य में रख कर चलना होगा कि जहां हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो तृतीय या चतुर्थ भी कहें। आज से पंद्रह साल, बीस साल आगे का जो प्लान हो उसको स्पष्ट करके चलना चाहिए। जब देश के सामने एक लक्ष्य निर्धारित होता है, हमें कहां पहुंचना हैं, क्या करना है ? चाहे एक वर्ष का प्लान हो, चाहे दस वर्ष का १५ वर्ष का प्लान हो, वह एक दूसरे के साथ फिट इन होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज जो हम काम करें और उसमें आगे परिवर्तन करना पड़े। इस दृष्टिकोण से प्लानिंग कमीशन ने सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट और डेवलपमेंट कौंसिल इन चीजों पर विचार कर रहे हैं कि एक लोंग टर्म तैयार रखें कि जिस पर विचार किया जा सके।

मैं इस समय अधिक चर्चा के अन्दर न जाकर कुछ मुद्दे की बातें थीं वे आपके सामने निवेदन की। इसमें लैंड पोलिसी के सम्बन्ध में एक चेप्टर है, जो आपने देखा होगा और सीलिंग के बारेमें जिक्र किया गया हैं। सिलिंग कायम किया जाना चाहिए और उसका आधार क्या होना चाहिये जिसको आगे लेकर चलें। मैं समझता हूं कि बहुत से माननीय सदस्यों ने इन चीजों को देखा होगा और बाद में वे देखें तो स्पष्ट होगा कि हम क्या कल्पना लेकर चलते हैं। अध्यक्ष महोदय, इन चेप्टर्स में हेवी इन्डस्ट्रीज और पब्लिक सेक्टर के डेवलपमेंट, हेवी इन्डस्ट्रीज के साथ साथ छोटी इण्डस्ट्रीज का भी है। पूरी तरह उनको आगे बढ़ाया जाय उसके लिये विशेष तौर पर आयोजन किया गया है। कोऑपरेटिव खेती का आयोजन है, छोटी इण्डस्ट्रीज का आयोजन है। इन चीजों को विशेष तौर पर प्लानिंग कमीशन मानता है कि वही लक्ष्य की ओर ले जानी वाली चीजें हैं और उनके लिये प्रयत्न बराबर करना चाहिये।

जहां इस वक्त में हम आल इण्डिया प्लान पर डिस्कस कर रहे हैं, स्टेट प्लान पर पहले किया था, कुछ चीजे इसमें है पार्लियामेंट से फाइनेलाइजेशन हो जाने के बाद स्टेट प्लान को डिस्ट्रिक्ट लेवल में फैलाया जायगा। जिसको कम्युनिटि डेवलपमेंट कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

होंगे । कुछ बड़ी बड़ी चीजें हैं वे स्टेट प्लान की तौर पर अलग होंगी । तो इस तरह से इस प्लान की फरदर डिटेल्स कैसी होनी चाहिए वह जल्दी किया जावेगा ।

अध्यक्ष महोदय, इन चीजों की जहां हम जानकारी कर रहे है, वहां मैं समझता हूँ इस आवश्यकता को भी सदन, मेरा ख्याल है, अनुभव करता होगा कि इस प्लान के अन्दर जहां तक पब्लिक सेक्टर के आधार पर इन्डस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने का सवाल है । इस बारे में कई जगह काफी चर्चाएं हुई हैं, और मैं भी समझता हूं कि अब जब कि देश इस बात को सामने रखकर चलना चाहता है कि मेजर इन्डस्ट्रीज को एस्टब्लिश करना है तो इसका बटवारा देश की आवश्यकता को सामने रख कर किया जाना चाहिये । यदि पब्लिक सेक्टर से जो इन्डस्ट्रीज एस्टब्लिश होने वाली हैं, उनका कंसन्ट्रेशन एक ही जगह अधिक हो जाता है तो कुछ एरियाज बेकवार्ड रह जाते हैं । इन चीजों पर हमने काफी जोर दिया है और आगे भी विचार किया जा सकता है । सदन इस बात से सहमत होगा कि देश में पब्लिक सेक्टर से जो इन्डस्ट्रीज एस्टब्लिश करने का सवाल आता है वहां लैस डेवलप्ड एरियाज में भी इन्डस्ट्रीज इस प्रकार होनी चाहिये कि जिससे वहां के लोगों को भी काम काज मिल सके । यह आधार हम मानते हैं तो यह स्वाभाविक है कि पिछड़े हुए इलाकों में लोगों को काफी तादाद में काम धंधा मिल जाता है । जब बड़ी इंडस्ट्रीज एस्टब्लिश होती हैं और बड़ी इन्डस्ट्रीज के एस्टब्लिश होने के कारण रूरल एरियाज में काम काज शिफ्ट होता है तो वहां के लोगों के स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग में भी बढ़ोत्तरी होती है और उनको रोजगार मिलता है । ये चीजें आगे विचार किया जाकर तय होने वाली हैं । मैं समझता हूँ जब इस का अंतिम निर्णय होगा तब प्लानिंग कमीशन और गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया इन सब बातों पर विचार करेंगे ।

इसी प्रकार रेलवेज की बात आती है । रेलवे के एक्सटेन्शन के लिये वैसे ठीक है और आवश्यक है कि हमारे बड़े प्रोडक्शन सेन्टर्स हैं, स्टील प्लान्टस हैं उनसे लिन्क अप किया जाना आवश्यक है, लेकिन इस के साथ साथ देश के विभिन्न हिस्सों में जो बेकवर्ड हैं उनको भी ओपन करना आवश्यक है । इस लक्ष्य को रेलवे मिनिस्ट्री ने भी अपने सामने रखा है जैसा कि इस साल के बजट स्पीच से और २ बातों से मालूम पड़ता है और सेकन्ड फाइव ईयर प्लान में इसको काफी हद तक कार्यान्वित कर सकेंगे ऐसी आशा है । इतना ही कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं और अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूं कि बजट का दायरा जनरल ड्राफ्ट प्लान है उस पर ही अधिक सीमित रहेगा क्यों कि यहां जो व्यूज वगैरह हैं वे गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया के हैं । इस पर चर्चा होनी चाहिए सारे हिन्दुस्तान के बारे में । ऐसा न हो कि राजस्थान एसेम्बली चर्चा कर बैठे केवल राजस्थान के बारे में ।

श्री हिम्मतसिंह–It is everybodys plan and everybody can speak on it

श्री भोलानाथ—अध्यक्ष महोदय,जो विषय आज हाउस के सामने आया है वह मुख्य मंत्री महोदय के कथनानुसार काफी महत्वपूर्ण है। यह जो प्लान हमारे सामने आया है इसमें कोई शक नहीं कि इसमें काफी गुंजायश है, इस बात की कि समय,समय पर उन्नति की जा सकती है। जो बड़ी बातें इस प्लान में कही गई हैं और जो उद्देश्य बताये गये हैं उनमें सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि अपनी नेशनल इन्कम में बढ़ोतरी की जाय और देश की आय लगभग २५ परसेन्ट बढ़ाना चाहते हैं और साथ ही साथ दूसरा महत्वपूर्ण काम रखा गया है वह यह है, कि लोगों को रोजगार मिले। तीसरा उद्देश्य यह है कि सोशलिस्टिक पेटर्न पर चला जाय और चौथा उद्देश्य यह है किदेश का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो।

इस समय जिस उद्देश्य से हमें विचार करना है, वह यह है कि हम जिस दशा में विचार कर रहे हैं, उस दशा में हमारे जिलों का विकाश हो। इस प्लान में एक खास चेप्टर आया है और उस चेप्टर में जिक्र किया गया है डिस्ट्रिक्ट प्लान्स के बारे में। इसका विकाश बताया है और जो ख्याल रखा गया है, जो विचार रखा गया है उस में खासतौर से कहा है कि हम प्लान का सबसे बड़ा जोर जिलो पर है।

The district has rightly been described as an instructor of democratic planning.

यह एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इस पुस्तक के पेज ५८ पर खास तौर से बात कही गई है। मुझे जो बातें कहनी हैं वे इस पर आधारित हैं। इसके जो चार बड़े उद्देश्य बताये हैं, वे हैं एक रोजगार में बढ़ोतरी, दूसरा नेशनल इन्कम बढ़ाना, तीसरा सोशलिस्टिक पेटर्न का सवाल और जो चौथा सवाल है वह राष्ट्रीय दृष्टि से विचारणीय है। हमारे देश में बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज हों, कारखाने खुले और उन इन्डस्ट्रीज के लिये जो मशीनें चाहिये वे भी यहां बन सकें। इसके बारे में हमारी जो पोलिसी है, वह साफ है। मैं समझता हूँ राष्ट्रीय नीति से हमारी नीति मेल खाती है, हाउसइस बातको पसन्द करेगा। लेकिन जो हमारे सामने नक्शा है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्लान के लिये जो फइनेन्स आयेगा, उसके लिए जनता से बहुत कुछ आशा की गई है। अभी मुख्य मंत्री जी ने बताया था कि लगभग १२ अरब रुपये सरकार को पब्लिक से लेने हैं, कुछ तो बचत योजना के रूप में, कुछ ऋण के रूप में और कुछ टेक्सेज के रूप में। इस तरह से लगभग १२ अरब रुपये पब्लिक से लेने हैं। १२ अरब लेने का मतलब यह है कि प्लान का एक तिहाई हिस्सा पब्लिक से लेना है। इसके लिए हम को जनता में उत्साह और जोश पैदा करना पड़ेगा। हमें जनता को यह समझाना पड़ेगा कि यह डेमोक्रेटिक प्लान है, यह पीपल्स प्लान है आदि बातों का विश्वास जनता में पैदा करना पड़ेगा। लेकिन यदि हम जिलों की योजना बनाने में देरी करते हैं और जिलों का नक्शा और गांव का नक्शा हमारे सामने नहीं रखते हैं, तो जनता को अधिक टेक्स देने के लिये या रुपया लगाने के लिए ज्यादा उत्साहित नहीं कर सकते। इसलिये मेरा यह नम्र निवेदन है कि

[श्री भोलानाथ]

डिस्ट्रिक्टस का प्लान सबसे पहले हमारे सामने होना चाहिये। यदि इसमें देरी लगती है तो कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जो हमने योजना का नक्शा जनता के सामने रखा है, उसे हमें पूरा करना हैं और उसे पूरा करने में दिक्कत आ सकती है और यदि जो रुपया बचत के जरिये ऋण के जरिये या टेक्सेज के जरिये हमारे पास आने में कठिनाई पैदा होती है तो हमको प्लान को लागू करने में कठिनाई पैदा होगी।

इस लिये मैं माननीय अध्यक्ष, निवेदन करना चाहता हूं कि जिले का प्लान बिल्कुल साफ होना चाहिये और जैसा कि मैंने चैप्टर में से पढ़ कर सुनाया, भारत सरकार ने नक्शा बताया है, उस माफिक होना चाहिये।

हमारे राजस्थान में, यह खुशी की बात है कि डेवेलपमेंट कमेटियां हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में डेवेलपमेंट कमेटियों के बारे में भी कहा गया है। पर मालूम होता है कि अभी हमारी डेवेलपमेंट कमेटियां जो काम कर रही हैं, इन इफेक्टिव हैं, इस प्लान को कामयाब करने में जो उत्साह और जोश लोगों के दिलों में पैदा करना पड़ेगा, उस कार्य में ये कमेटियां कमजोर पडेंगी। यदि इन कमेटियों को सफल और मजबूत बनाना है तो मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्टस का प्लान साफ हो जाना चाहिये। जिलों में जब तक कि आम जनता में जोश पैदा नहीं होगा तब तक यह जो पीपुल्स प्लान, डेमोक्रेटिक प्लान कही गई है। उसके लिये हम आम लोगों में जोश पैदा नहीं कर सकेंगे। इसलिये जितना जल्दी से जल्दी हो सके जिले के प्लान, नक्शे को पेश करें, उतना ही अच्छा रहेगा।

अब इस बारे में मेरा यह सुझाव है कि जो तीन बातें रखी गई हैं एक रोजगार का सवाल, दूसरा नेशनल इन्कम बढ़ाने का सवाल, और तीसरा सोसलिस्टिक पेटर्न का। तो इन उद्देश्यों के बारे में डिस्ट्रिक्ट लोकल बोडिज़ सोचें कि जिलों में काम करने होंगे। उनमें यह नेशनल इन्कम बढ़ती है कि नहीं, रोजगार का सवाल हल होता है या नहीं। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिये राजस्थान में खर्चा हो वह सब जिलों में समान रूप से पोपुलेशन के बेसिस पर करना चाहिये।

जो प्लान हमारे सामने हैं, वह राजस्थान की सामुदायिक दृष्टि से, हिन्दुस्तान की दृष्टि से बड़ी उपयोगी है जैसे भाकरा का प्लान है, चम्बल का प्लान है, ये सब जिलों को सूट नहीं कर सकते; पर इनके अलावा जो और काम हैं वे सब जिलों के लिये समान रूप से रखने पडेंगे। जिससे हर जिले के लोगों का इस योजना के प्रति जोश और उत्साह बढ़ाया जा सके, ऐसी सूरत में उन्हें यह कहा जा सकता है कि हर जिले में यह काम हो रहे हैं। सब जिलों में पैसा बराबर खर्च किया जा रहा है, सबको इससे फायदा होगा, इस लिये तुम्हें भी इस योजना में पैसा देना चाहिये। प्रथम पंचवर्षीय योजना में चम्बल प्लान को शरीक नहीं किया गया पर डाक्टर काटजू ने नया तरीका निकाला वह यह कि सरकार को अगर जनता से ज्यादा पैसा मिले तो ज्यादा पैसा खर्च किया जा

Page No.39

[श्री भोलानाथ]

सकता है, इसका अच्छा रेस्पोन्स हुआ, इसके मुताबिक मध्यभारत से और राजस्थान से बहुत पैसा मिला।

जब दूसरा नक्शा आप बना रहे हैं तो इस तरह का बनाना चाहिये कि उसको उन लोगों के सामने रख कर, उन्हें सोचाया जा सके कि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्वल है, आपके लिये व आपकी आने वाली पीढियों के लिये सरकार यह काम कर रही है, तो इससे आम लोगों के दिलों में इस प्लान के प्रति दिलचस्पी पैदा होगी और इसको कामयाब बनाने के लिये आम लोगों के दिलों में जोश और उत्साह पैदा होगा। और लोग इसको कामयाब बनाने के लिये अधिक से अधिक पैसा देंगे। इस लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि डेवेलपमेंट कमेटियों में रिप्रेजेन्टेटिव करेक्टर के लोगों को रखने की कोशिश की है, तो उन्हें और मजबूत बनाने के लिये सब डिस्टिक्ट्स में पोपुलेशन के आधार पर समान रूप से पैसा खर्च किया जाय ताकि वे लोग आम लोगों में उत्साह पैदा करन सकें। फिर यह उन कमेटियों का काम है कि आम लोगों में इस प्लान के प्रति उत्साह पैदा करें। पर इसके लिये आपको यह देखना होगा कि जो रूपये आप खर्च करना चाहते हैं, उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। २५ परसेंट ऐसी योजनाओं के लिये रखिये जो हमारी स्टेट की ओर से या भारत सरकार की योजना के माफिक हैं, बाकी रूपया सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिये। ऐसा नहीं कि एक जिले में लाखों करोड़ों रूपये खर्च हों और दूसरे जिलों में कुछ भी नहीं हो। हमारे यहां रोजगार, प्रोडक्शन और नेशनल इन्कम को बढाने के लिये किसी एक खास इलाके में जोश और उत्साह पैदा करने से काम नहीं होगा। हमें राजस्थान के हर इलाके में रहने वाले लोगों के दिलों में, आम लोगों के दिलों में इसके लिये जोश और उत्साह पैदा करना होगा। इस लिये मेरा यह सुझाव है कि जो आपके सुझाव जांय उनमें जिलेवार प्लान बनाया जा कर भेजना चाहिये। उसमें व्यवस्था हो कि जहां उपजाऊ अच्छी जमीन है पर पानी की कमी है वहां कुए बनवाइये, जहां पथरीली जमीन है और जमीन अच्छी नहीं है वहां सड़कें बनवाइये और जहां सड़कें अच्छी हैं तो ट्रान्सपोर्ट का प्रबन्ध कीजिये, जहां कूए नहीं बन सकते वहां सिंचाई के दूसरे साधन उपलब्ध कीजिये। मतलब यह कि सब जगह जरूरत के काम शुरू किये जायं। हमारा बोर्डर यू. पी. और पंजाब से लगा हुआ है पर राजस्थान सरकार के सामने बिजली के लिये बात रखते हैं तो कहा जाता है कि हमारा कोटा भारत सरकार से फिक्स हो चुका है। परन्तु आज हमारे भारत सरकार से सम्बन्ध दूसरी तरह के हो गये हैं, आज पंजाब और राजस्थान सब एक जोन में आ गये हैं, बोर्डर के इलाकों को बिजली मिल सकती है तो इसके लिये कोशिश करनी होगी। जो पहले स्टेट्स का आपस में कम्पीटिशन था, वह अब खत्म हो गया है, जो सहानुभूति की दृष्टि पहले नहीं थी वह अब हो जानी चाहिये। यह खुशी की बात है कि भरतपुर में यमुना का पानी आने वाला है, दूसरी जगह पानी नहीं आता है तो वहां कूए खुदवाने चाहिये। ऐसा करेंगे तो लोगों में उत्साह पैदा होगा और वे इस योजना में पैसा देंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १६ अरब की मांग जनता के सामने रक्खी है, उसमें पैसा मिलेगा। परन्तु इस रुपये को इकट्ठा कराने के लिये सरकार को इन शिकायतों से बचना चाहिये कि किसी जिले में ज्यादा रूपया खर्च किया जाता है, किसी जिले में उसके मुकाबिले बहुत कम, तो इस तरह की आलोचना का खतरा नहीं पड़ेगा।

[श्री भोलानाथ]

मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा कि यह तो अगली दूसरी योजना के लिये भूमिका तैयार हो रही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर हम अभी से, सही आधार से, कोई योजना को बनाते हैं और लोगों की मांगों को पूरा करके हम वहां की जनता को संतुष्ट कर देते हैं कि इस योजना में उन जिलों में सड़के बांध, कुए बनवाये जायेंगे। यह कह देते हैं कि इस योजना में यह काम नहीं आयेंगे, तो आयन्दा योजना में आयेंगे तो इससे लोगों में उत्साह पैदा हो जाता है।

प्लान के माने हैं, तैयारी, सुव्यवस्थित रूप से सोचने की तैयारी, इसके लिये आप सोचिये और आगे के लिये नक्शा पेश कर दीजिये, इसके लिये जनमत तैयार कीजिये, और जो रुपया खर्च किया जाय वह सही तरीके से खर्च किया जाय। इससे जनता के दिलों में इस प्लान के प्रति पूरा उत्साह पैदा हो सके और वह पूरी तरह से इस योजना में सहायता दे। इसी से रोजी देने, नेशनल इन्कम बढ़ाने और सोसलिस्टिक पैटर्न कायम करने में हम कामयाब हो सकते हैं। सोसलिस्टिक पैटर्न के स्वप्न को पूरा करने के लिये हमें बहुत कुछ करना है। लैंड रिफोर्म्स के कानून पास हो जाने पर भी हमें अभी लैंड पोलिसी के बारे में बहुत कुछ सोचना है। राजस्थान में अभी कन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का सवाल है। कौनसा राजस्थान का हिस्सा किस चीज के लिये तैयार है, कहां कन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग करना है कहां सीलिंग को लागू करना है तो इसके लिये जो डेवेलपमेंट कमेटीज़ हैं, या और जो संस्थायें काम करती हैं, उनमें पब्लिक ओपिनियन पर असर डालने वाले हैं उनको लें ऐसे लोगों को कोन्फिडेन्स में लेकर आम लोगों तक सूचना पहुँचाए तो अच्छा काम होगा।

इस चेप्टर में सरकार ने विचार किया है, पर स्टेट गवर्नमेंट पर छोड़ दिया है, इसमें ज्यादा देर लगाने से वही दशा होगी जैसी कि हमें फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में बाद में बहुत ज्यादा रूपया खर्च करना पड़ा।

लोगों के सामने साफ नकशा जल्दी पेश करने से जो प्लान के लिये आम लोगों से पैसा आने वाला है, उस पर भी अच्छा असर पड़ेगा। सरकार की तरफ से सही आधार पर साफ नक्शा पेश किया गया तो जनता में अभी जोश और उत्साह बढ़ेगा। जब पब्लिक में जोश होगा, लोग काम करेंगे और जब लोग काम करेंगे तो इससे योजना पूरी होगी और हमारे देश की तरक्की होगी। जब लोग यह समझेंगे कि इससे लोगों को काम मिलेगा और आय बढ़ेगी लोग काम करेंगे। लेकिन अगर हम ढिलाई करते रहे तो न तो पैसा आवेगा और न काम होगा और जो पैसा आवेगा वह भी फालतू जावेगा। इसलिये समय रहते हुए इसका प्रबन्ध किया जाना चाहिये। इसलिये मेरा माननीय अध्यक्ष, आपसे और आपके जरिये सदन के सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लानिंग बनाये जावे। और इसकी तरफ जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जावे। मैं सदन के नेता महोदय से भी यही निवेदन करूंगा कि डिस्ट्रिक्टवाइज प्लानिंग की तरफ ध्यान दें और डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लानिंग बनाने के बाद उसे हाउस के सामने पेश किया जावे।

श्री विशम्भरनाथ जोशी—अध्यक्ष महोदय, द्वितीय पंच वर्षीय योजना के प्रारूप पर आज सदन के समक्ष विचार करने के लिये प्रस्ताव पेश हुआ है। मैं भी इस पर दो शब्द कहने के लिये खड़ा हुआ हूँ। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सबसे बड़ी निराशा की बात जो हमको नजर आती है, वह यह है कि जो दावा इन्होंने बेरोजगारी को मिटाने का किया है वह समस्या हल नहीं होगी। बेरोजगारी के निराकरण के विषय में प्लान वालों ने खुद ने यह स्वीकार किया है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना की सारी अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी बेरोजगारी की स्थिति बहुत ज्यादा हद तक सुधर सकेगी ऐसी बात नहीं है लेकिन जो बेरोजगारी की स्थिति आज है, वही करीब करीब बनी रहेगी। वह इसलिये रहेगी कि ८ मिलियन यानि ८० लाख नई जगहें द्वितीय पंच वर्षीय योजना में विभिन्न महकमों में होगी। तो ५ वर्षों में हमारे यहां कालेजों से और स्कूलों से पढ़ कर निकलने वाले लोग जो काम करने योग्य होंगे उनकी तादाद भी २॥ मिलियन हो जाती है। ५ वर्ष में दो करोड २५ लाख आदमियों को रोजगार की जरूरत होगी और इस योजना के अनुसार हमारी सरकार ८० लाख जोब सिक्योर कर सकेगी। इसका परिणाम यह होगा कि या तो नये लोग बेरोजगार रह जावेंगे या जो आज बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल जाएगा और ये पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा या जब उनको रोजगार दिया जाएगा उस समय बिना पढ़े लिखे लोगों को बेरोजगार कर दिया जाएगा। हम यह समझते थे कि इससे बेरोजगारी की समस्या को हल करने में काफी हद तक सफल हो सकेंगे, लेकिन यह बात द्वितीय पंच वर्षीय योजना के प्रारंभ में ही गलत साबित होती नजर आई। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस योजना पर ४८ अरब रूपया खर्च होगा और इतना रूपया खर्च होने के बाद भी और हमारे पास जितने साधन हैं उनको पूरी तरह से एक्सप्लोइट करने के बाद भी, डेफिसिट फाइनेन्स होने के बावजूद भी और मुद्रा स्फीत का इतना बड़ा खतरा मोल लेने के बाद भी बेकारी की समस्या को नहीं सुलझा पाये तो जो ४८ अरब रूपये हम देश में खर्च करने जा रहे हैं, उससे कोई महत्वपूर्ण मसला हल नहीं होने जा रहा है।

इसके अलावा प्लानिंग में सोशियल पेटर्न या सोशियल सोसाइटी की ओर बढ़ने का प्रयास किया जाएगा इसका भी संकेत है। मैं समझता हूँ कि जो हमारा कल्याणकारी राज्य है, उसका ध्येय ही यही है और उसकी ओर बढ़ने का दावा करते हैं तो हर एक नागरिक को जो स्वास्थ हो और जो कोई भी काम करने की योग्यता रखता है उसको काम दिया जावे और उसको जीवन उपार्जन के साधन बताये जावे, यह कल्याणकारी राज्य की प्रथम जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिये मैं यह कहूंगा कि एक बड़ी भारी बात हो रही है और वह यह कि यहां पर हेवी इन्डस्ट्रीज शुरू हो गई हैं। मैं यह कहूंगा कि यह मालिकों की तरक्की के लिये ठीक है लेकिन यह अपने आप में एन्ड इन इटसेल्फ नहीं है। देश के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो, सुख और समृद्धि हो और लोगों की बेकार फौज नहीं पड़ी रहे और ऐसा न हो कि उनके जीवन के साधन न होने से उनका जीवन निराशापूर्ण बना रहे। अगर ऐसा होता है तो इन सारे रूपयों का जो यहां पर खर्च होंगे क्या उपयोग होने वाला है। मेरा इसमें यह ख्याल है कि हेवी इन्डस्ट्रीज पर जरूरत से ज्यादा खर्च किया जा रहा है। ऐसा होना चाहिये कि इस पर इतना ज्यादा रूपया खर्च नहीं किया जावे और इसमें से कुछ रूपया कोटेज इन्डस्ट्रीज में ज्यादा दिया जावे और मैं समझता हूं कि मौजूदा जो कोटेज इन्डस्ट्रीज के लिये रूपया एलोट किया हुआ है, उससे दुगना रूपया दिया जा सकता है तो बहुत ठीक यों कि एक करोड़ रूपयों में हम हैवी इंडस्ट्रीज में बहुत कम लोगों को काम दिला सकेंगे

[श्री विशम्भरनाथ जोशी]

और एक करोड़ रुपयों में हम कुटीर उद्योग या ग्राम उद्योग में लगाएंगे तो १ करोड से २० या २५ हजार आदमियों को रोजगार दिला सकते हैं। हेवी इन्डस्ट्री से हमारे विलेजेज को कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। इस चीज को हमें अपने ध्यान में रखना चाहिये। इसके अलावा हमको यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि लाखों की तादाद में लोग कालेजों से निकलने वाले हैं। उनको काम दिलाना है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक बहुत अहम मसला है और इस पर हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिये। अगर हम इस तरफ ध्यान नहीं देंगे तो लाखों लोगों को बहुत बडा खतरा पैदा करेंगे। यदि हम ग्रामों के लिये कुछ नहीं करेंगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे कि सरकार हमारे लिये क्या कर रही है यदि आप आर्थिक अधिकार और राजनैतिक अधिकार बराबर रखेंगे और हेवी इन्डस्ट्रीज कायम करेंगे तो एक पूंजीपति अपनी फेक्ट्री में हजारों लाखों आदमियों को नौकर रख कर इस बेरोजगारी के जमाने में उन पर अपना दबाव डाल सकेगा और इलेक्शन के समय और मत दान के समय मत ले सकेगा और चुनाव में वे लोग उसके लिये कार्य करेंगे। वह अपने हर काम को अपनी मर्जी के मुताबिक करेगा और हमारे विधान में जो स्वतन्त्र नागरिक के अधिकार लिखे हुए हैं वे सुन्दर अक्षरों में लिखे रह जावेंगे और वह एक एकेडेमिक चीज रह जावेगी और व्यवहारिकता की चीज नहीं रहेगी। जब तक नागरिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं होती, लोगों को जीवन उपार्जन के लिये काम नहीं दिया जावेगा तब तक एक सच्ची सामाजवादी व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती है।

इसके बाद मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक ट्रेन्ड व्यक्तियों का सवाल है, हमारे प्रान्त के लिये जितने ट्रेन्ड व्यक्तियों की जरूरत है, उसके लिये हमारा तजुर्बा रहा है कि बहुत से क्षेत्रों में जहां अनुभवी व्यक्तियों की आवश्यकता थी, नहीं मिल पायें। प्लान को बनानेवालों ने प्लान को समाप्त करने की जिम्मेदारी को महसूस किया है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रही है कि इन ट्रेन्ड व्यक्तियों के अभाव को पूरा करने के लिये कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया गया।

इसमें, ड्राफ्ट आउटलाइन में लिखा गया है कि इन्जीनियर्स की देश में बहुत कमी है। उसको पूरा करने के लिये यह सुझाव दिया गया है कि १४ इन्जीनियरिंग कालेज खोल दिये जांय, कुछ वेटरनरी कालेज भी खोल दिये जांय लेकिन अब तक भी इन प्रस्तावों पर विचार हो रहा है। अभी तक इस पर विचार ही हो रहा है हालांकि प्रथम पंच वर्षिय योजना का काम खत्म भी हो चुका है। दूसरी पंच वर्षीय योजना का काम शुरू होने वाला है : द्वितीय पंच वर्षीय योजना में कार्यों को चालू करने के लिये हम कदम भी बढ़ा रहें हैं लेकिन हमने इन्जीनियरों की पढ़ाई का ओवरसियरों की पढ़ाई का किसी भी प्रकार प्रबन्ध नहीं किया आज भी यदि हम इनको चालू कर देते हैं तो एक इन्जीनियर का कोर्स चार साल का होता है उसका मतलब यह हुआ कि इस द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में हम केवल इन्जीनियर ही तैयार कर सकेंगे जो इस दूसरी योजना के समाप्ति काल में इन्जीनियर बनकर कालेजों से निकलेंगे। इसी तरह डाक्टरों का भी सवाल है, ओवरसियरों का भी सवाल है। इसका मतलब यह हुआ कि

[श्री विश्वम्भरनाथ जोशी]

आज हमारी योजना का ट्रेन्ड पीरियड विचाराधीन चल रहा है इसको कार्यान्वित करने में समय लगेगा। आज हम इन लोगों से फायदा नहीं उठा सकेंगे इस प्रकार के लोगों के तैयार होने में चार पांच साल का समय लगेगा तो जो यह योजना बन रही है उसका फायदा आने वाली तृतीय पंच वर्षीय योजना में हमको मिल सकता है, हम इन लोगों से तृतीय पंच वर्षीय योजना में काम ले सकते हैं।

इसके अलावा भी इसमें एक बहुत बड़ी विवेकहीनता भी रही है जिसे हम थोड़ी सी अदूरदर्शिता भी कह सकते हैं। वह एक प्रकार की भयंकर कमी है। असल में यह जरूरत तो हमें पहले से ही महसूस कर लेनी चाहिये थी कि प्लान के प्रथम सोपान में ही हमें इन्जीनियर्स आदि के लिये कालेज खोल देने चाहिये थे, ओवरसियरों के लिये क्लासें और डाक्टरों के लिये कालेज चालू कर देने चाहिये थे। बीस परसेन्ट से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग देने का कार्य प्रथम पंच वर्षीय योजना में ही हमें शुरू कर देना चाहिये था, ताकि इस द्वितीय पंच वर्षीय योजना में हमें ट्रेन्ड पर्सनल्स मिल सकते। आज हम जब कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना शुरू करने जा रहे है शिक्षित आदमियों की कमी हमें कदम कदम पर महसूस होगी, हमारे कामों में रुकावटें आयेगी; कदम कदम पर हमें इन लोगों की कमी खटकती रहेगी। पहला हमारा ध्येय यह होना चाहिये था कि हम इन योजनाओं के लिये शिक्षित आदमियों की कमी पूर्ति करें, जिनका कि इन योजनाओं में पूरा अभाव रहा है। आज हमें इस प्रकार के अनुभव से फायदा उठा कर तृतीय पंच वर्षीय योजना के लिये अभी से इन्तजाम करना शुरू कर देना चाहिये जो गलती हम पहले कर चुके वह दुबारा नहीं दुहराई जाय।

इसके अलावा हम इस योजना के लिये ५ अरब और ६ अरब रुपया इस देश के जन साधारण से लेना चाहते हैं, स्मॉल सेविंग के रूप में। इसके अलावा ७ अरब रुपया मार्केट के लोगों के जरिये हम प्राप्त करना चाहते हैं, इस तरह से बारह अरब रुपया चाहते हैं, हमको जन साधारण से मिल जाय। जहां तक मैं समझता हूँ यह बारह अरब रुपया जन साधारण से एकत्रित करना कोई आसान बात नहीं है। मैं यह उचित समझता हूं कि इस बारे में देश की जनता से जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। लोगों में इस तरफ जाग्रति पैदा करने की आवश्यकता है। उनमें इन योजनाओं के लिये उत्साह पैदा करने की आवश्यकता है, लोगों में लगाव पैदा करने की जरुरत है, लेकिन जहां तक मैं देख पाया हूँ इस संबन्ध में हमारी तरफ से बहुत कमी रही है, कोई भी काम इस तरफ नहीं हुआ। इसको देखते हुए यह कल्पना नहीं की जा सकती कि १२ अरब रुपया जो जन साधारण से लेना चाहते हैं वह प्राप्त होने वाला है। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस प्लान को जन साधारण का प्लान नहीं कह सकते। प्रत्येक देश और प्रत्येक जिले के लोगों से इसके लिये पूछा गया हो, यह भी बात नहीं। विलेज लेवल पर तैयार हुई हो गांव के लेवल पर तैयार हुई हो तो यह भी बात नहीं है। इसके लिये यह कहा जाय कि झोंपड़े में रहने वाले गरीब से इस बारे में समर्थन प्राप्त किया जायगा। जनता का पूरा सहयोग लिया जायगा

[श्री विश्वम्भरनाथ जोशी]

और उन्हीं के इच्छानुकूल प्लान की रूप रेखा बनाई जायगी। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की पूरे की तो मैं वाकफियत रखता नहीं लेकिन अपने प्रदेश के बारे में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि बड़े बड़े गांवों और कस्बों को और जिलों को तो आप रहने दीजिये विधान सभा के सदस्यों तक को जो कि एक एक लाख के प्रतिनिधि हैं, उनकी इफेक्टिव वोइस को भी इस प्लान के तैयार करने में काम में नहीं ली। इस प्लान की जो रूप रेखा बनायी गई और जब वह बन चुकी तब हमारे सामने आई, विधान सभा में पेश होने से काफी पहले यह रूप रेखा बन चुकी थी। अब इसके लिये यह कहा जा रहा है कि इसमें ज्यादा रद्दोबदल तो नहीं हो सकती और न कहने की गुंजाइश ही है। कोई ऐसी बात हो तो एकाध बात तो बदली जा सकती है,नहीं तो जैसी यह प्लान है वैसी की वैसी ही रहेगी। एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि जैसी की जैसी है; वैसी रहेगी। दूसरी तरफ आप जनता से पूरा सहयोग चाहते हैं। लोगों में उत्साह का वातावरण पैदा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमें १२ अरब रुपया भी मिल जाय, मुझे यह बात पार पड़ने वाली नजर नहीं आती है। आज लोगों में इसके लिये उत्साह नहीं, न उनको पूरी जानकारी ही है। आप किस उम्मीद पर जनता का सहयोग चाहते हैं, आपने जब कि जनता के जो प्रतिनिधि है उनसे भी आपने पूछा नहीं और आप यह आशा करते हैं, कि जनता आपको सहयोग दे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी हालत में जनता आपको सहयोग नहीं दे सकती। आज जब कि यह प्लान हमारे सामने है, इस स्टेज में इसमें परिवर्तन और आवश्यक संशोधन करने की गुंजाइश भी है। इसका हमें पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिये। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, गांव के लेवल पर और कस्बों के लेवल पर जो कुछ भी परिवर्तन करने आवश्यक हों वे किये जाने चाहिये।

इसके अलावा भी हम लोगों से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट कमेटीज़ की तरफ से जो सुझाव मागे थे वह सुझाव भी हम देखते हैं। इस डिटेल्स में नहीं आये। मैं नहीं कह सकता कि वे सुझाव किस स्टेज पर रह गये। प्लानिंग कमीशन को वह सुझाव भेजे गये हैं या नहीं लेकिन जो चीज फाइनल होकर आई है, उसमें तो वह नहीं है। आखिर मैं तो यही कहूंगा कि यह जो प्लान हमारे सामने आया है वह अधिकारियों द्वारा तैयार किया हुआ प्लान है, इसे जनता का प्लान कहना लिटरेली गलत बात है। अक्षरशः गलत नहीं तो बहुत कुछ गलत है। मै सारे हिन्दुस्तान के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता अपने प्रान्त की जानकारी जरूर रखता हूं, जहां तक राजस्थान का इस प्लान से संबन्ध है मैं कह सकता हूँ कि वह राजस्थान की जनता का प्लान नहीं हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि जो रुपया राजस्थान की जनता को इस कार्य के लिये देना है, वह हम कैसे प्राप्त कर सकेंगे ? मैंने फिगर्स केलकुलेट करके देखे हैं पांच अरब रूपया जो स्मॉल सेविंग के रूप में हमें जमा करना जरूरी है। मान लीजिये हमारी एक तहसील की आबादी एक लाख है तो उस हिसाब से हमें ढाई लाख रूपया उस तहसील से वसूल करना होगा और वह भी पाँच साल तक चालू रहना चाहिये। इसी प्रकार मारकेट लोन का क्षेत्रीय विस्तार किया जाय तो करीब चार लाख रुपया प्रत्येक तहसील से वसूल करना होगा। वह भी पांच साल तक चलना चाहिये। लेकिन जो

[श्री विश्वम्भरनाथ जोशी]

स्थिति प्रत्येक तहसील की है जिससे हम लोग वाकिफ हैं, उसे देखते हुए मैं तो यह कह सकता हूँ इतनी रकम बहुत दुष्प्राप्य है। असंभव कहूँ तो कोई बेजा नहीं होगा असंभव नहीं तो असंभव से कुछ कम जरूर है। मैं नहीं समझ सकता हम इस टारगेट को कैसे प्राप्त कर सकेंगे ? जब तक हम लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेंगे, उनकी जरूरतों को मालूम नहीं करेंगे उनको जब तक यह मालूम नहीं होगा कि इस प्रकार के प्लान से उनको क्या फायदा पहुँचने वाला है, तब तक उनमें इस बात की स्फूर्ति पैदा नहीं होगी। हमें इस बात से उन लोगों को परिचित करने के लिये सक्रिय कदम उठाने की जरूरत है ताकि गांव में रहने वाले, कस्बों में रहने वाले, लोगों को इस प्लान के बारे में दिलचस्पी पैदा हो सके। और उनको मालूम हो सके कि यह उनके फायदे के लिये किया जा रहा है, वे अपना कर्तव्य समझें, अपनी जिम्मेवारी समझें और प्लान में पूरा सहयोग दे सकें।

मैं समझता हूं इस पर विद्वान लोगों ने जरूर नज़र रखी होगी। इसको देखने से यह मालूम होता है कि हेवी इन्डस्ट्रीज़ का एक तरह से उन पर भूत सवार होगया हो, इसको देखने से यही पता चलता है, उन्होने इस हेवी इन्डस्ट्रीज को जरूरत से ज्यादा इस तरह का दिखाया....यही मालूम पड़ता है।

अब आप देखिये जो १५ करोड़ रूपया इसमें रखा गया है, वह लोकल डेवलपमेंट के लिये रखा गया है। यह एक चीज़ है जिससे गांवों के रहने वाले लोगों की अपनी आवश्यकता पूरी हो सकें। जहां आप एक पैसा खर्च करते हैं वहां दो पैसे मिलने की संभावना रहती है। इसमें आप यदि एक रूपया लगाते हैं तो दो रुपया आपको मिलने की आशा रहती है, लेकिन इस रकम को देखने से हमें यह पता चलता है कि इसमें जनता का सहयोग सही तौर पर नहीं लिया गया है ताकि हम गांवों की छोटी छोटी जरूरियात और उनकी आवश्यकताओं में दिलचस्पी ले सकें। इस ४८ अरब के प्लान में केवल १५ करोड़ रुपया हम रखते हैं लोकल डेवलपमेन्ट वर्क्स के लिये जो इस रकम का ३०० वां हिस्सा है और जिससे हम लोकल डेवलपमेन्ट वर्क करना चाहते हैं। जिसकी कि उपयोगिता सबसे ज्यादा है, जिसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा है और जनता के सहयोग और समृद्धि की दृष्टि से जिसका महत्व सबसे ज्यादा है, उसमें हमने सारी स्कीम का ३०० वां हिस्सा रक्खा है।

इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि प्लान के पब्लिकेशन का जहां तक सवाल है, उसकी उपयोगिता को कम आंका गया है और उसके लिये केवल ७ करोड़ रुपया ही रखा गया है। जिसका ६०० वां हिस्सा होता है। समझदार लोग, थोड़ा बहुत जानते हैं, पर वह भी मोटी मोटी बातें वे जानते हैं, उसकी विस्तार में जाकर सारी तस्वीर वे भी नहीं जानते। यह मैं दावे के साथ कहता हूँ। हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना को पांच साल हो गये। उसके बारे में भी यह हाल है कि पढ़े लिखे लोग उसकी डिटेल के बारे में नहीं जानते। उन

[श्री विश्वम्भरनाथ जोशी]

बहुत थोड़े लोगों की बात को छोड़ दीजिये जो इन योजनाओं के अन्तर्गत ही काम करते हैं और जिनको वहां से तनख्वाहें मिलती हैं। ऐसी स्थिति में देश के अन्य साधारण नागरिकों की क्या स्थिति है, यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। तो हमारे देश के ऐसे ३५ करोड़ लोगों के बीच और इस विस्तृत भूखंड में जहां वे बसे हुए हैं। हम इन सात करोड़ रुपयों से उन को जानकारी कराना चाहते हैं तो यह सम्भव नहीं होगा। उनको जानकारी कराना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिये इसमें कम रुपया रक्खा गया है। इसमें अधिक रुपया रक्खा जाना जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं कहना चाहूँगा और वह यह है कि एक सिद्धान्त जो इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत किया गया है वह है रीजनल बेलेन्स्ड डवलपमेन्ट का यानि सबका विकास एक साथ होना चाहिये। अगर एक प्रान्त अनावश्यक रूप से पीछे रह जाता है और दूसरा प्रान्त अत्याधिक रूप से आगे बढ़ जाता है, तब भी सामूहिक रूप से देश का भला नहीं होने वाला है। और अगर एक प्रान्त के एक हिस्से में काफी प्रगति हो जाती है और उसी प्रान्त का दूसरा हिस्सा काफी पिछड़ा रह जाता है तो सारे प्रान्त की सर्वांगीण प्रगति की दृष्टि से हम पिछड़ जाते हैं, सारा प्रान्त भी पिछड़ा रह जावेगा। तो इस दृष्टि से सारे देश की प्रगति तभी सम्भव है, जब कि सारे प्रान्त और प्रान्तों के सारे हिस्से एक समान प्रगति करें। रीजनल डवलपमेन्ट बैलेन्स्ड हो। इस लिये मैं कहना चाहूँगा कि प्रश्नों द्वारा, कट मोशनों द्वारा और अन्य साधनों द्वारा आये दिन इस सदन में भी यही कहा जाता है कि बैलेन्स्ड रीजनल डवलपमेन्ट की हमें जरूरत है। तो इस दृष्टि से सारे प्रान्त को और प्रान्त के सारे हिस्सों को समान प्रगति के स्तर पर लाया जाना जरूरी है। जो हिस्से सरकारी कर्मचारियों की असवाधानी से, उनकी भूलों से या कि उनकी लापरवाही से पीछे रह गये हैं उनको जल्दी से समान स्तर पर लाया जाना भी अत्यान्तिक जरूरी है। यह फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल माना गया है कि सबका एकवल बैलेन्स्ड रीजनल डवलपमेन्ट होना चाहिये। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम सारी प्लान को फेल कर देंगे अगर ऐसा नहीं किया तो इस योजना को सफल बनाने के लिये जिस दिशा में हमें जाना चाहिये उस से विपरीत दिशा की तरफ चले जावेंगे।

इसके बाद मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने इसमें आगे चलकर यह कहा कि यह प्लान कोई रिजिड प्लान नहीं है। एक बार जो तय कर दिया वह कर दिया उस में कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा, ऐसी बात नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर, जरूरत महसूस होने पर और अनुभवों के आधार पर इसमें हर स्टेज पर सालाना रिवीजन होगा और आवश्यक परिवर्तन भी किये जा सकेंगे। यानि उस वक्त भी अपनी गलतिओं के अनुभव के आधार पर सुधार करके का मौका रहेगा।

इसके बाद इसमें डवलपमेन्ट वर्क के लिए जो १५ करोड़ की राशि रक्खी गई है, वह भी बहुत अपूर्ण है। कम से कम डेड अरब रुपया इसके लिये रक्खा

Page No.47

[श्री विश्म्भरनाथ जोशी]

जाना चाहिये । और यह रुपया हर तहसील में हर स्थानीय विकास कार्यों के लिए प्राप्त हो सके।

इस निवेदन के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री घीसीसिंह—मैं पांच मिनट बोलूंगा और ऐसी बात कहूंगा कि........

श्री अध्यक्ष—श्री हरिकृष्ण व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्व का मौका है कि हमारे देश की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा हम तैयार कर रहे हैं और यह आवश्यक है कि इस योजना पर विचार करते समय सबसे पहले इस बात को अपने दिमाग में हम साफ कर लें कि आया यह योजना आने वाली योजना का ढांचा बनाने के लिये ही तैयार हुई है अथवा देश में एक विशेष प्रकार की उन्नति का आधार बनने के लिये तैयार की गई है।

अलवर से आये मेरे मित्र कह रहे थे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना ने वे आधार तैयार किये हैं जिन आधारों पर हमने दूसरी योजना बनाई और यह दूसरी योजना वे आधार तैयार करेगी जिन पर हम तीसरी योजना बनावेंगे। मैं समझता हूं कि यह सोचने का तरीका मूलत: गलत है। यह सही है कि किन्हीं मुद्दों पर अथवा किन्हीं सीमों पर एक योजना में कार्य पूरा नहीं हो सकता, यह भी सही है कि औद्योगीकरण अथवा बिजली के साधनों को उपलब्ध कराने का कार्य वह भी निश्चित तौर पर एक योजना काल में पूरा नहीं हो सकता। इसके लिये शायद १५ बीस वर्षों की योजना कल्पना के तौर पर रखनी चाहिये और रखनी भी पड़ेगी। लेकिन यदि पहली पंच वर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना में कोई फर्क है यदि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आधार में और पहली पंचवर्षीय योजना के आधार में कोई बुनियादी तब्दीली है तो वह अध्यक्ष महोदय, यह है कि पहली योजना में दर असल हमने इसके सिवाय कुछ नहीं किया कि आर्थिक कठिनाइयों को ठीक करके देश का आर्थिक स्थिति को बिगड़ने से रोका जावे। इसके अलावा इस पहली योजना ने कुछ नहीं किया। अब वह स्टेज आ गई है कि जब कि हम ऐसे कार्य अपने हाथों में लें, जिससे देश में एक नये प्रकार की अर्थ व्यवस्था बनाने का कार्य हम प्रारम्भ कर लें। इसके लिए एक आधार प्रस्तुत हो जावे और केवल आने वाली योजना की तैयारी के रूप में नहीं, पर एक नयी औद्योगिक आर्थिक स्थिति के निर्माण के कार्य हम शुरू कर चुके हैं ऐसी हालत प्राप्त हो जावे। मैंने इस प्रस्तावना पर जोर इसलिये दिया कि यह द्वितीय पचवर्षीय योजना हमारे देश में विषय बन चुकी है वाद विवाद की और विचारों के आदान प्रदान की। हकीकत तो यह है कि पिछले वर्ष मार्च मास में हमारे देश के सामने एक मसविदा पेश हुआ था जिसको कामनली प्लान फ्रेम कहा जाता है और यह मसविदा इण्डियन स्टेटिस्टिकल इन्सीट्यूट, जिसके सदर श्री पी.

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

सी महालानोबिस थे, उनके नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों ने मिलकर एक मसविदा बनाया था और उन्होंने इस देश के सामने वह मसविदा प्रस्तुत किया था । वह प्लान फ्रेम के नाम से मशहूर है ।

आज जो यह ड्राफ्ट आउट लाइन हमारे सामने आई है, इसमें जहां तक उद्देश्यों के उसूलों का प्रश्न है, वही प्लान फ्रेम हूबहू वर्ड टू वर्ड इसमें मौजूद है । उस प्लान फ्रेम में जो उद्देश्य आये थे उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना मैं इस समय आवश्यक समझूंगा । उसमें चार उद्देश्य दिये हैं ।

इसमें अध्यक्ष महोदय, पेज ७ पर पहला उद्देश्य है । देश के आम लोगों की नेशनल इनकम की स्थिति है उसको बढ़ाना, जिससे कि देश के लोगों की हालत सुधर जावे । और इस ड्राफ्ट को आउट लाइन्स के मुताबिक, जहां तक मैं अध्ययन कर पाया हूँ, हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि २५ परसेंट का अनुमान है और पर केपिटा में मिनिमम १८ परसेंट की वृद्धि का अनुमान है ।

दूसरा उद्देश्य रखा है कि देश को औद्योगीकरण का मार्ग अपनाना पड़ेगा, और औद्योगीकरण के अन्दर बेसिक इन्डस्ट्रीज और हेवी इन्डस्ट्रीज के ऊपर जोर देना पड़ेगा ।

तीसरा उद्देश्य है कि रोजगार में सुधार हो । ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, और चौथा उद्देश्य है कि जो अन्तर है आज देश के विभिन्न लोगों या वर्गों की आमदनी में, उस आमदनी के अन्तर को कम किया जाय ।

इन चारों कार्यों को करते हुए साथ साथ आगे बढ़ें । मैं समझता हूं कि जहां तक उसूलों का ताल्लुक है, जहां तक योजना का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, उसका सवाल है तो उसमें दो राय नहीं हो सकतीं । यह चार उसूल इसमें प्रतिपादित किये गये हैं । वह प्लान फ्रेम में और ड्राफ्ट आउट लाइन्स में एकसे हैं । वह ऐसे उसूल हैं कि अपने मुल्क की उन्नति की इच्छा करने वाला हर नागरिक उसका स्वागत करेगा, और स्वागत करेगा इतनी बात नहीं है कुछ लोग अलबत्ता ऐसे जरूर हैं जिनको उन उसूलों में से कुछ उसूल खटकते हैं । खटकते हो और इतना ही नहीं लेकिन खटके हैं । जब कि प्लान फ्रेम सामने आया तब हमारे देश के कुछ लोग आये जैसे कस्तूर भाई, लाल भाई, लालचन्द किलाचन्द थे जो कि बम्बई में सूती मिलों के एसोसियेशन के सभापति और सेक्रेटरी हैं, देश के एक बहुत बड़े माने हुए नेता श्री बी. सी. राय जो कि बंगाल के मुख्य मंत्री है वे आये और भी लोग आये और उन्होंने दूसरा दृष्टिकोण देश के सामने रखा । उन्होंने यह कहा कि हम पूरे के पूरे प्लान में, प्लान फ्रेम अथवा योजना जो तैयार की जा रही है, इसमें बड़े बड़े उद्योगों की ओर, हेवी इन्डस्ट्रीज की ओर जो बड़े औजार हैं, मुझे ताज्जुब नहीं मालूम

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

हुआ, अध्यक्ष महोदय, जबकि हमारे माननीय नेता खड़े होकर कह रहे थे कि प्लान बनाने के वक्त दिमाग में यह हान्ट कर रहा था कि बेसिक इन्डस्ट्रीज़ पर बहुत जोर दिया जाय। लेकिन मैं बहुत जोर के साथ कहना चाहता हूं कि प्लान बनने के वक्त वह चीज़ हान्ट नहीं कर रही थी, लेकिन देश की उन्नति तो एक तरफ जाय। अपना मुनाफा किसी तरह से एन केन प्रकारेण कायम रखें और बढ़ायें ऐसे माननीय उद्योगपतियों में यह चीज हान्ट कर रही है। आज भी वे जानते हैं कि सारी की सारी स्थिति बड़े उद्योगों में लगेगी तो क्या बनेगा कि वह कल कारखाने देश के अन्दर निर्माण होगें, जिनको बेसिक इन्डस्ट्री कहा गया है। उसमें से इस्पात निकलेगा, जिससे कि मशीनें बनेंगीं। लोगों के प्रयोजन की चीज़ें नहीं लेकिन मशीन और मशीन टूल्स। यदि देश की उन्नति करना है, अपने उद्योगों के आधार को दृढ़ और मजबूत बनाना है तो दो चार सूती कपड़े के मिल बनाने से देश का औद्योगीकरण आगे नहीं बढ़ता है। आज तक इन कारखानों से देश का औद्योगीकरण आगे नहीं बढ़ा है। औद्योगीकरण आगे बढ़ता है जब कि मशीनें बनाने वाले साधन हमारे देश में हों। मेरा हो यह कोई एक सजेशन नहीं है, अध्यक्ष महोदय, बल्कि देश के अन्दर जब राजनैतिक आंदोलन शुरू हुआ है तब से और लोगों ने नहीं बल्कि देश के महान् नेताओं ने हर बार कहा है कि क्या अजीब हालत है कि रेलवे के लोकोमोटिव इन्जिन से लेकर मामूली स्प्रिंग तक विदेशों से मंगानी पड़ती है। इस मामले में हमारा देश आत्म निर्भर नहीं रहेगा, दूसरों पर निर्भर रहेगा तो आत्म रक्षा के लिए, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए यदि कहीं से हमला हो, हम नहीं चाहते हैं कि किसी से लड़ाई झगड़े में पड़ें, तो कोई मुल्क अपनी आजादी की रक्षा नहीं कर सकता, जिस मुल्क के अन्दर हेवी इन्डस्ट्रीज नहीं हैं, दूसरों पर मुनस्सर रहने वाले आर्थिक आधार पर है वह मुल्क पूर्ण रूप से आजाद नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, कि यह मुमकिन हो कि कस्तूर भाई लालभाई अथवा दूसरे लोग हैं उन्हें यह महसूस होता है कि बेसिक इन्डस्ट्रीज में निश्चित व्यक्तिगत पूंजी लगा कर निश्चित जल्दी से जल्दी मुनाफा मिले ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज तो प्लांट डेवलपमेंट का सवाल है, योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का सवाल है, मैं समझता हूं कि जितनी हैवी इंडस्ट्रीज को एलोकेशन दिया गया था प्लान फ्रेम में, मैंने यह सारा, माननीय अध्यक्ष, ड्राफ्ट आउटलाइन है, इसको देखा है तो उसमें उसूल तो वही के वही रखे गये हैं लेकिन एलोकेशन का जहां तक ताल्लुक है वहां हैवी इंडस्ट्रीज का एलोकेशन कम कर दिया गया है। मैं अभी उसका तफसील में जिक्र करूंगा, लेकिन जो कुछ भी स्थिति है, हकीकत है, उससे औद्योगीकरण का प्रस्ताव अपनाना सम्भव नहीं है, भारत के लिये सम्भव नहीं है। जब हम बेसिक इंडस्ट्रीज का, हेवी इन्डस्ट्रीज का, निर्माण नहीं कर पायें तो इसके मायने मैं समझता हूं कि हमारे आने वाले लोगों के लिए भयंकर भूल होगी। भारत सरकार का यह कहना, योजना कमीशन का यह कहना, पार्लियामेन्ट का यह कहना कि बेसिक इन्डस्ट्रीज की जो कमी है उसको दूर करना पड़ेगा। मेरी यह राय है कि प्लानिंग फ्रेम को बदलकर बेसिक इन्डस्ट्रीज पर जो कम कर दिया गया है, उसको रद्द करके कम कर दिया गया है। उस प्लानिंग फ्रेम के हिसाब से क्या आंकड़े होने चाहिए, मैं, अध्यक्ष महोदय, चन्द मिनटों में सदन के सामने रखूंगा यानी उन आंकडों के जरिये से जो बात मैंने कही है उसको साफ करने का प्रयत्न करूंगा। प्लानिंग फ्रेम का विरोध हुआ, और विरोध होने के

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

बाद पेनल आफ इकानामिस्ट जिसमें वाडिया और वकील तथा दूसरे लोग थे मुकर्रर हुआ। उस पेनल आफ इकानामिस्ट ने पुस्तिका तैयार की है, जिसका नाम व्यू बुक है। दोनों नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल के पास जाते हैं और एक अजीब सी चीज होती है और वह चीज यह होती है कि जहां तक औद्योगीकरण की भूमिका का प्रश्न है, उसूलों का प्रश्न है, सिद्धांतों के प्रतिपादन का प्रश्न है। प्लानिंग फ्रेम के सिद्धांत कायम रह जाते हैं और आज इस ड्राफ्ट आउट लाइन में मौजूद हैं, लेकिन जहां टारगेट का प्रश्न है, एलोकेशन का प्रश्न है, फिजीकल टारजेट अथवा मोनेटरी टारगेट का प्रश्न है, प्लानिंग फ्रेम के टारगेट्स रद्द कर दिये जाते हैं और उनमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है, जिसकी ओर मैं सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा।

हुआ क्या? जहां तक प्लानिंग फ्रेम का प्रश्न था, उसके जिम्मे यह था, कि हम कुछ समय के लिए, हमारी जो आवश्यक चीजें हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो मौजूद इन्स्टाल्ड केपेसिटी है उसका पूरा पूरा उपयोग करें तथा जो बाकी रहे उसकी पूर्ति कॉटेज इन्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन देकर। लेकिन देश के उद्योगपतियों और कुछ उद्योगपतियों ने जोर लगाया कि नई फेक्ट्रीज भी खुलनी चाहियें, पुरानी फेक्ट्रीज जो बनी हुई हैं उनकी मशीनरी का रिप्लेसमेंट होना चाहिए, और नतीजा यह हुआ कि इन्डस्ट्रीज के अन्दर लगभग ४५० करोड़ रुपया कॉटन टेक्सटाइल, जूट और शुगर, इन तीनों इन्डस्ट्रीज के लिए प्लानिंग कमीशन ने एलॉट किया है। इस ड्राफ्ट आउट लाइन के अन्दर रिपलैसमेंट, रिनोवेशन और नई इन्डस्ट्रीज के लिए यह चीज़ लगभग ४५० करोड़ की एलॉट की है। उसका नतीजा पड़ा रेलवेज के प्लान पर। आपको मालूम है और सारे देश कोई मालूम है, पार्लियामेंट में जब इस पर बहस हुई थी, नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल में बहस हुई थी तब रेलवे प्लान का प्रश्न आया था। रेलवे मन्त्री और दूसरे लोगों ने कहा था कि रेलवे प्लान का जो हमारा ढांचा है उसको बढ़ाया जाय। और यह सही बात है कि कुछ इलाकों में, कुछ क्षेत्रों में, नई लाइन खोलने के दृष्टिकोण से संभव है कि उसको कुछ एक्सपेन्ड करने की आवश्यकता थी, लेकिन प्रश्न इतना ही नहीं था, प्रश्न यह था कि नये उद्योगों को एलॉटमेंट करना है। यदि आपको मशीनरी अथवा दूसरी चीजों के लिए प्रोविजन करना है तो उस हद तक रेलवे, फ्रेटेज का प्रोवीजन करना ज्यादा लाजमी, और आज हुआ यह कि केवल वह हेवी मात्र रह गये हैं और आज भी कुछ लोगों को हॉन्ट कर रहा है कि बेसिक इन्डस्ट्रीज, हेवी इन्डस्ट्रीज, का जोर है। बाकी हकीकत यह है कि सारी का सारी इन्डस्ट्रीज का जो सेक्टर था वह २६ परसेन्ट से कम होते होते १९ परसेंट पर आ गया है। उसी पब्लिक सेक्टर में जो लगभग ८० परसेंट था वह कम होकर ६२ परसेन्ट आ गया है। इतना ही नहीं लेकिन स्टेट के पब्लिक सेक्टर में १२०० करोड़ का जो प्रोवीजन था वह अब ८९१ करोड़ बन गया है और हेवी इन्डस्ट्रीज का जहां तक सवाल है एक बहुत बड़ा हेवी इन्डस्ट्री का आइटम, मशीन बिल्डिंग का आइटम जिसको हम कह सकते हैं टूल बनाने का; वह इस प्लान को देखने से मालूम हुआ है कि वह आइटम खत्म हो गया। पब्लिक सेक्टर से और प्राइवेट सेक्टर दोनों में से वह इस ड्राफ्ट आउट लाइन में खत्म हो गया है, और मैं समझता हूं कि हमारे देश की उन्नति की दृष्टि से यदि हम इस तरह चलें तो बहुत ही गलत चीज़ हुई है। इस गलत चीज़

Page No.51

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

को करने की जिम्मेवारी मेरे उन दोस्तों पर होनी चाहिये जो कि काफी हेवी इन्डस्ट्रीज को नहीं चाहते हैं। वे केवल राजस्थान में ही नहीं और भी दूसरी जगह हैं उन्हें ज्यादा खतरा है और भी दूसरी जगह और ज्यादा ताकतवर दूसरी जगह उन्होंने जो बवन्डर उठाया है, मशीन बिल्डिंग इन्डस्ट्रीज का नाम गायब हुआ। इतना ही नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय, पब्लिक सेक्टर में फेरो मैग्नीज, एप्लायेन्सेज, ये जो तीन चार बड़ी इन्डस्ट्रीज हैं, जिनके लिए प्रोविजन था उनको पब्लिक सेक्टर से हटा कर प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। फरजर और फाउन्ड्री का दो सौ करोड़ का प्रोविजन था, बल्कि जो तीन छोटे से प्लान्ट है जिनकी आज देश में जरुरत है, आज देश को आवश्यकता है उनको २०० से ८० तक लाकर रख दिया गया और इस प्लान फ्रेम की आउट लाइन हुई, उसमें यह जो परिवर्तन हुआ, वह गलत दिशा में हुआ है और यह परिवर्तन ऐसी दिशा में हुआ है जो देश की उन्नति के मार्ग में तेजी से बढ़ने के बजाय उसमें कमजोरियां आई हैं और मैं समझता हूं कि सबसे पहली राय होनी चाहिए कि प्लान फ्रेम में जो कमी हुई है उसको रद्द किया जाय और वापिस उसी प्लान फ्रेम की ओर बढ़ा दिया जाय।

दूसरी बात की ओर जो मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, वह यह है कि आज हमें वैदेशिक सहायता के ऊपर पहले की बजाय ज्यादा मुनहसर रहना पड़ता है। प्लान फ्रेम वर्क में ४०० करोड़ का डेफिसिट है लेकिन हकीकतन तो ११०० करोड़ का है चूंकि २०० करोड़ तो फोरिन एक्सचेन्ज और १०० करोड़ अपने लग जावेंगे इसलिए ११०० से ८०० आ गये, लेकिन फोरिन डेफिसिट जो बन गया है उसका मूल कारण यह है कि उसको मूल उद्योगों पर लगाने के बजाय हमने दूसरी चीजों पर उसको उपयोग करने के रास्ते खोले हैं और १३०० करोड़ रुपयों की मशीनरी व दूसरा सामान मंगाने के अन्दाज से चल रहे हैं जब कि प्लान फ्रेम में ११०० करोड़ से ज्यादा नहीं था। तो स्थिति यह हुई कि इस योजना के अन्दर भी उतनी स्वतन्त्रता नहीं जितनी कि प्लान फ्रेम में थी। विदेशी सहायता के ऊपर ज्यादा मुनहसर रहना पड़ता है और नहीं मिले तो प्लान को ठेस पहुंचने का खतरा पैदा हो रहा है और जो आप फोरिन एक्सचेन्ज की ओर विदेशी सहायता के रुप में सोच रहे है वह इस योजना को कामयाब बनाने में काफी असंतोषजनक है और इस योजना को गलत रास्ते पर ले जाने का बायस भी हो सकती है।

जहां तक दूसरे प्रश्न हैं, जो दूसरी योजना के महत्वपूर्ण ढंग हैं, देश में वे कौनसे परिवर्तन लाने हैं, देश में वे कौनसी तब्दिलियां लानी हैं, जिनके जरिये एक ओर औद्योगीकरण का रास्ता अपनावें और दूसरी ओर इन्टरनल मार्केट का रास्ता अपनायें? उधर बैठने वाले एक माननीय मित्र ने संकेत किया और संकेत करके ही उसको छोड़ दिया। जहां तक राजस्थान का सवाल है, सारे देश का प्रश्न है आप देखेंगे तो यह उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो कुछ भी यहां निर्माण होगा आन्तरिक मार्केट नहीं बनेंगे, खरीददार नहीं होंगे तो आगे चल कर फुल प्रोडक्शन की समस्या आ जायगी और उस समस्या को न आने देने के लिए उस सम्बन्ध में प्लानिंग कमीशन में प्लान फ्रेम के वक्त से कोशिश चल रही है। जितनी ड्राफ्ट आउट लाइन में कमियें हैं, जहां तक एग्रेरियन

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

सेक्टर का प्रश्न है उसमें यह ड्राफ्ट लाइन तुलनात्मक दृष्टि से संतोष जनक गिनी जा सकती है । प्रश्न है इसको लागू करने का, इम्प्लीमेन्ट करने का । मैं आपका ध्यान पेज ७६ की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ । यह ज्यादा जोर देकर भी इसलिए कहना चाहता हूं कि राजस्थान में प्लानिंग कमीशन के निर्णय का बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, अध्यक्ष महोदय । सबसे ज्यादा जोर इस ओर दिया गया है वह यह है पहले नम्बर में खेती में सुधार, और दूसरे नम्बर में सीलिंग के बारे में और तीसरे नम्बर में पर्सनल कल्टीवेशन । जहां तक लैंड रिफोर्म का प्रश्न है मैं समझता हूं कि वह राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक प्रश्न है । पेज ७६ पर यह कहा गया है :—

"Existing legislation should be re-examined in terms of the definition of personal cultivation set out above, and suitable action taken to confer tenancy rights on individuals who have in the past been treated merely as labourer or as partners in cultivation."

पर्सनल कल्टीवेशन की वहां परिभाषा है जिसका उल्लेख किया गया है जो इस प्रकार है अध्यक्ष महोदय, कि पर्सनल कल्टीवेशन उसी की मानी जावेगी जब उस व्यक्ति का कल्टीवेशन का खुद का रिस्क हो, पर्सनल सुपरविजन हो और उसकी खुद की लेबर हो, स्टेट को प्रोडक्शन में फायदा पहुंचाता हो लेकिन अपनी पैदावारी को बांटे के रूप में देता हो । और आंशिक रूप में, पैसे के रूप में देता हो तो नहीं गिना जावेगा । प्लानिंग कमीशन की ड्राफ्ट आउट लाइन में शर्त लगायी गई है कि पर्सनल कल्टीवेशन वहीं समझी जायगी जो व्यक्ति फिजिकली, एसेन्शयली लेबर कॉन्ट्रिब्यूट करता हो । इतना ही नहीं और भी जोर दिया गया है कि जमीन रिज्यूम की जाय पर्सनल कल्टीवेशन के लिए तो क्या जरूरी होगा देखना कि—

" When land is to be resumed for personel cultivation, however, it is necessary that each of the elements of personal cultivation including labour participation in the main agricultural operations, should be insisted upon. "

यदि हम हमारे यहां के टेनेन्सी कानून को देखें, यदि हमारे यहां के जागीर रिजम्प्शन कानून को देखें और जो जो इस सम्बन्ध में कानून हैं, पास किये गये हैं उनकी ओर नज़र दौडयें तो हमें मालूम होगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का नाम ले लेना काफी नहीं है, दूसरी पंचवर्षीय योजना को दिल से यदि थोडी कामयाब बनाने की ओर अग्रसर होने की इच्छा है और खेती के सम्बन्ध में बड़ी तब्दीली की जो दिशा बतायी गई है उसको कार्य रूप में परिणत करना पड़ेगा । मुझे अफसोस के साथ कहना पडता है कि मुख्य मंत्री महोदय ने इस प्रश्न को दुर्लक्ष्य किया है और उल्लेख मात्र भी नहीं किया जो कि योजना का एक महत्वपूर्ण अंग है । इतना ही नहीं एक फेमिली, पांच मेम्बर की फेमिली, उस फेमिली की होल्डिंग तीन गुना, जहां तक सीलिंग का सम्बन्ध है वह सीलिंग तुरन्त लागू करनी

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

चाहिए। यह दूसरी पंचवर्षीय योजना का बहुत बड़ा आधार है। छोटे २ खेतों को मिला कर बड़ा बनाने की ओर जैसे हम अग्रसर हो रहे हैं वैसे ही सीलिंग मुकर्रर करने, खेतिहर लोगों को जमीनें दे पायें तो खेती में सुधार होगा और अगर सही दिशा के अन्दर औद्योगीकरण होगा, उनको मार्केट मिलेगा, निजी रूप में जो किसान है उनके लिए जमीन का कम्पलीट रिफोर्मेशन होगा तो देश आगे बढ़ेगा लेकिन औद्योगीकरण और खेती के सम्बन्ध में हम तब तक कामयाब नहीं हो सकते हैं जब तक कि इन्टरनल चीजों के लिए बाजार और कृषि सम्बन्धी एग्रेरियन रिफोर्म्स लागू न करें और तीसरा जोर दिया गया है जिस पर मैं समझता हूं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ड्राफ्ट आउट लाइन में वह पूरा नहीं है। दर असल में एग्रेरियन प्लानिंग है। मैं नहीं समझता कि कहां से सूचना मिली मुख्य मंत्रीजी को लेकिन लेन्ड रिफोर्म्स और एग्रीकल्चर के बारे में अभी १०-२० दिन पहले सिफारिश की है। उसका आधार यह है कि रूरल क्रेडिट कमेटी की सिफारिश के बगैर नहीं देना चाहिये। डेट कंसीलियेशन और मौजूदा जितने डेट्स हैं उनको कोओपरेटिव सोसाइटी के जरिये रूरल क्रेडिट का मौका देना चाहिये। इन दोनों पर एग्रेरियन पहलू पर जोर दिया गया है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं, अध्यक्ष महोदय, क्यों मुख्य मंत्रीजी ने, शायद परेशानी हो जाय, इसलिए उसका जिक्र नहीं किया हो; यह बात दूसरी है लेकिन पंचवर्षीय योजना में साफ लिखा है—

" Most voluntary surrenders of tenancies are open to doubt as bonafide transactions and it is desirable that reviews of cases of alleged voluntary surreuders over a period of, say, three years, should be undertaken, and to the extent necessary, action should he taken to restore the tenants."

प्लानिंग कमीशन के ड्राफ्ट एक्सप्लेनेशन का यह कहना है कि पिछले तीन साल में जितनी बेदखलियें हुई हैं, दिखावट में चाहे रजामन्दी से ही हुई हों लेकिन वास्तव में रजामन्दी से नहीं हुई हैं, उनको रीओपन करना चाहिये। मैं कहूँगा कि सही दृष्टिकोण यह होगा कि राजस्थान में पिछले ३ वर्ष से ही नहीं बल्कि सन् ५० से एब्नोरमल स्थिति, टेरर था, मार पीट और खून खराबी का वातावरण था; उस वातावरण में जिन लोगों को बेदखल होना पड़ा है चाहे सरकारी मोहर लगने से हुआ हो, चाहे रजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट के जरिये हुआ हो, डर और झगड़े से हुआ हो लेकिन इस सम्बन्ध में यदि प्लानिंग कमीशन ३ साल के लिये कहता है तो उसको लागू करने के लिये राजस्थान में ६ साल की स्थिति पर जाना पड़ेगा, तभी सही आधार पर हो सकेगा।

देश के औद्योगीकरण की ओर जोर दिया, योजना के दूसरे भाग की ओर जोर दिया, उसमें मतभेद का प्रश्न नहीं है। मैं समझता हूँ लेन्ड रिफोर्म्स हैं वे महत्वपूर्ण हैं। इतना ही नहीं मैं मानता हूं और सारा देश एक राय है, तात्कालिक रूप से ईमानदारी से अमल किया जाय तो हम न सिर्फ किसानों को आजीविका दे सकेंगे, उनको उन्नति के मार्ग पर ला सकेंगे बल्कि देश के सारे लोगों की उन्नति कर सकेंगे। थोड़ा मतभेद है, कंपेनसेशन के प्रश्न पर देना या नहीं देना। इस मतभेद के प्रश्न को एक मिनट के लिये अलग रखा जाय तो अलग रहेगा लेकिन बाकी पर अमल करने का

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

प्रश्न है । इस पर पूरा ध्यान देना चाहिये और उसके लिये एडीकेट मशीनरी होनी चाहिये। ये बातें पूरी होनी चाहिये यदि प्लानिंग कमीशन की सिफारिशों पर ध्यान देना है ।

अब मैं उन बातों की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ जो कमजोर हैं, जो कमजोर ही नहीं बल्कि खतरनाक भी हैं । मुख्य मन्त्री जी कह रहे थे कि यह बहुत बड़ी हिम्मत का काम है कि हमारी ऐसी स्थिति होते हुए भी हमने ४८०० करोड़ रुपयों का प्लान सामने रखा और २३०० करोड़ रूपये और बढ़ा दिये जायेंगे तो ६१ करोड़ का प्लान पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से पूरा होना है । ४८०० करोड़ रूपयों का प्लान अभी जो हमारे सामने है वह हमारी मौजूदा स्थिति को देखते हुए बहुत बडी हिम्मत का काम है । मैं ऐसा मानता हूँ कि वह हिम्मत का नहीं बल्कि घबराहट का काम है । ४८०० करोड़ रूपयों का प्लान भारत के लिये इतनी बड़ी बात नहीं है यदि उसके साधनों की ओर दृष्टिपात करें । जब देश का नव निर्माण हो, नये किस्म के काम हाथ में लेते हों, तब साधन काम में न लें, नये टेक्स न लगावें ऐसी बात नहीं है । मैं रोज सुनता हूँ कि जब उत्तर देने उठते हैं मन्त्री लोग तब इतनी बात उनके समझ में आती है कि विरोध हो रहा है लेकिन यह समझ में नहीं आता कि विरोध इसलिये होता है कि काम ठीक ढंग से नहीं किया जाता । साधन उपलब्ध करते हैं लेकिन सारा मुल्क मिलकर करे तो ठीक होता है। टेक्स लेना चाहिये, लेकिन टेक्स जो दे सकता है उससे लिया जाना चाहिये। जिसकी टेक्स देने की स्थिति नहीं है उससे नहीं लेना चाहिये लेकिन जो दे सकता है परन्तु देना नहीं चाहता तो फिर राज्य को अपनी सत्ता का उपयोग करके उनसे टेक्स लिया जाय । ४८०० करोड़ का प्लान बनाया गया है जिसमें से १२०० करोड़ रूपयों का डेफिसिट दिखलाया गया है । इससे मैं समझता हूँ कि नासिक के छापाखाने को थोड़ा ओवर टाइम काम करना पड़ेगा बाकी लम्बी चौड़ी कोई परेशानी नहीं है डेफिसिट फाइनेन्स को मीट करने के लिये । लेकिन आज परेशानी नहीं तो क्या हुआ, कल हो सकती है । जिस अर्थव्यवस्था में आज आप १२०० करोड़ रूपयों के नये नोट छाप कर सर्कुलेशन में दे देंगे । १६०० करोड़, १७०० करोड़ रूपयों के नोटों का सर्कुलेशन पिछली वार के समय भी था, अब यदि आंकड़ा २१०० करोड़ तक पहुंचेगा । लडाई के समय कितना बडा इन्फ्लेशन हुआ था उससे देश परिचित है । यह जरूरी है कि जो सामान लडाई में उपयोग में नहीं आ सकता था वह बरबाद होता था, वैसी आज स्थिति नही है । आज उद्योग के नव निर्माण की स्थिति है, आज दूसरी तरह की स्थिति है, मुमकिन है डेफिसिट फाइनेन्सेज के कारण कीमतों के भाव अधिक चढने लग जांय और इसकी संभावना भी है तो नतीजा यह होगा कि टेक्सेज के रूप में ३५० करोड रूपये अभी के हिसाब से और ४५० करोड़ रूपये नये करों के हिसाब से, कुल ८०० करोड रूपये जो वसूल किये जारहे है वे कुछ नहीं रहेंगे । यदि कीमतें बढ गई तो इन्डाइरेक्टली, परोक्ष या प्रत्यक्ष रुपये, समय लग सकता है, पर बोझ ज्यादा पड़ेगा और लोगों को कठिनाई होगी तो एक तो डेफिसिट फाइनेन्स वैसे ही है दूसरा पब्लिक डेट और स्माल सेविंग्ज के ऊपर इस बारे में इत्तफाक नहीं करता । उधर बैठनेवाले एक मित्र ने कहा था कि यह टारगेट बढ़ा चढ़ा हुआ है लेकिन इस वर्ष के आंकडे ६० करोड़ हैं । यदि इससे बढ़ाकर १०० करोड़कर दिये जांय तो मेरे ख्याल से बहुत बडा एक्सेस नहीं आना चाहिये । इसीप्रकार प्राइवेट सेविंग

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

७०० करोड़ का है वह भी इतना बड़ा नहीं है। लेकिन बाकी जो आइटम्स हैं वे मुझे कठिनाई के
मालूम पड़ते हैं। ३५० करोड के एग्ज़िस्टिंग टेक्सेज़ और इसके अलावा ४५० करोड़ के और नये
टेक्स लगाकर वसूल करने की योजना की गई है और रेलवे के १५० करोड का जिक्र किया गया
है तो फ्रेट और फेअर जो एग्जिस्टिंग हैं उससे अगर ज्यादा बढ़ा देंगे तो रेलवेको ज्यादा आमदनी होगी।
यदि ज्यादा रोलिंग स्टोक काम से आता हो और ज्यादा पेसेन्जर हो इस कारण से आमदनी ज्यादा हो,
यह दूसरी बात है लेकिन बाकी जो आदमनी होगी वह होगी फेअर और फ्रेट रेट बढ़ाने से; तो इस
तरह से ४५० करोड के नये कर लगने के कारण और १५० करोड रेलवे के कारण; इस तरह से ६००
करोड का नया टेक्सेशन जनता पर लगेगा। यह लागू करने की कोशिश की जाती है। यह हमारे
एन्युअल बजट मे भी ज्यादा पडता है। सालाना आज जितनी आमदनी है उससे ज्यादा आदमनी ५
साल में करना आज की स्थिति में कठिन मालूम पडता है। लेकिन इसको लागू करने के लिये आंख
मूंदकर आगे बढ़ेंगे तो लोगों पर बोझा पडेगा और इसको कामयाब करने की कोशिश करेंगे तो असं-
तोष के वातावरण का हम खुद निर्माण करेंगे। तो फिर क्या किया जाय? साधन हमें
चाहिये, और बड़ी मात्रा में साधन चाहिये। डेफिसिट फाइनेन्स का प्रश्न,
टेक्सेशन का प्रश्न, इनके बारे में हिचकिचाहट का कदम रखा जाय तो क्या किया
जाय। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, कि हमें बहुत हिम्मत के साथ, बोल्डली आना चाहिये नये
साधन पैदा करने के लिये।

अभी कुछ दिन पहले इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया, इसके बाद लाइफ इन्श्यो-
रेन्सेज़ का नम्बर आया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ४५ फी सदी की हैं बाकी की रकम कौनसे उपयोग में
डाली जाय, कौनसे उपयोग में न डाली जाय, इसका कन्ट्रोल सरकार के हाथ मे आ गया, लाइफ इन्श्यो-
रेन्सेज़ के राष्ट्रीयकरण के जरिये सरकार ने ऐसा किया है कि जो सट्टे बाज हैं उनके हाथों से सट्टेबाजी
करने के और इन्फ्लेशन करने के साधन छीन लिये।

देश के बड़े बड़े बैंक हैं जिन बैंकों के जरिये न सिर्फ पैसों का इधर उधर गोल-माल होता
है बल्कि बहुत बड़े साधन हैं जो हमारे काम में नहीं आते। जो विदेशी पूंजी हमारे देश में लगी हुई
है, जो मुनाफा बाहर जाता है, उसके ऊपर रोक क्यों नहीं लगा दी जाती कि इसके ऊपर पाबन्दी हो कि
यह मुनाफा बाहर देशों में नहीं जा सकता।

मैं तो यह कहूंगा कि इस ड्राफ्ट की आउटलाइन्स में हालांकि इसका उल्लेख नहीं किया
गया है फिर भी जिसकी शुरूआत हो गई है, श्री टी. टी. कृष्णमाचारी ने; सोवियत यूनि-
यन के उपप्रधान मंत्री मिकोयान आये थे, तब उनके स्वागत भाषण में उन्होंने कहा कि हम शिपिंग
के मामले में भी नये जहाजों का रास्ता खोल चुके हैं और ६ जहाज भारत के और ६ जहाज सोवियत
यूनियन के माल को लाने ले जाने का काम करेंगे और स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन का निर्माण करने जा
रहे हैं। इसको हाथ में लिया जाय। तो जो माल हमारा बाहर जाता है, ऐसी चीजें कि जिनकी मोनो-

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

पोली है भारत की दुनियां के अन्दर, उनमें से भी साधन उपलब्ध हो सकें। कोल्हार की सोने की खानें हैं, कोयलों की खान है और बहुत सी चीजें हैं जो राष्ट्र के हाथ में है वह राष्ट्र को साधन दे सकती है। उनके प्रति मौजूदा रूख में परिवर्तन किया जाय तो साधनों का हल हो सकता है।

हम देश के सामने जाते हैं, हमारी सरकार जाती है और लोगों से कहती है कि हमारी पंचवर्षीय योजना को कामयाब बनाने के लिये तुम पैसा दो, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमें और साधनों की जरूरत है, इसलिये टैक्स लगाने के मामले पर तुम विरोध मत करो, पर यह कहने से पहले हमारे दिल को टटोलना चाहिये। जिन लोगों को कहते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना को आगे बढ़ाने में मदद दीजिये, उन लोगों को यह अधिकार है और वे पूछ सकते हैं कि ७ करोड़ रुपया जो देश की पब्लिसिटी पर लगा रहे हैं उसे कम करके, पांच करोड़ या तीन करोड़ कर दिया जाय तो इससे देश को नुक्सान नहीं होने वाला है, इसी तरह और कहां कमी की जा सकती है इसका पार्लियामेंट को रिव्यू करना चाहिये। सब से पहले प्रीवी पर्स का प्रश्न क्यों नहीं लिया जाता? मामूली आदमी पर हाथ डालने की कोशिश की जाती है तो प्रीवी पर्स का जो हमारे ऊपर बोझा है, जो हमने कम्पेन्सेशन दिये हैं, इसके बारे में भी एक सीलिंग मुकर्रर की जाय कि १० हजार या २० हजार के ऊपर के मुआवजे को पोस्टपोन किया जाय और उन्हें कहा जाय कि आगे जाकर देश के साधन जब बढ़ जायंगे तब तुम लोगों को यह पैसा दे दिया जायगा। ४०० करोड़ रुपया सारे देश में कम्पेन्सेशन के रूप में दिया जा रहा है उसमें से कुछ हिस्सा पोस्टपोन कर दिया जाय तो आज हम पैसों के लिये फांसियां खा रहे हैं, वह नहीं खायेंगे।

इतना ही नहीं इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो है वह यह है कि यदि राष्ट्रीयकरण के कार्य को तुरन्त हाथ में नहीं ले सकते तो इसमें अगर कठिनाई होती है तो एक ऐसी चीज स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन जिसका उल्लेख इस योजना की ड्राफ्ट लाइन्स में नहीं किया है लेकिन टी. टी. कृष्णमाचारी ने अपने भाषण में उल्लेख कर दिया है नेशनल डेवलपमेंट पूल का निर्माण किया जाय। दूसरे ऐसे साधन हैं जिनसे लोग मुनाफा उठाते हैं, उनको रोका जाय और आगे जा कर व्यक्तिगत इन्कम पर भी काबू किया जाय नेशनल डेवेलपमेंट पूल का निर्माण किया जाय, किसी सीमा तक किसी की इन्कम है वह पोस्टपोन कर दिया जाय; और उन्हें कह दिया जाय कि आगे चल कर जब देश में साधन बढ जायंगे तब १०,२० साल के बाद एक साथ या हिस्सों के रूप में तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जायगा और शायद उतना न मिले जितना है; तब हमारी स्थिति हो जायगी कि हम उन्नति कर सकें।

राजस्थान के लिये मैंने माइका जैसी चीज का जिक्र किया था कि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के जरिये इस काम को हाथ में लें और दूसरी चीजें हैं उन्हें हाथ में लें तो हमारे साधन बढ़ाने के जरिये बन जायंगे।

टैक्स लगाने का अधिकार सरकार को है, इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

परन्तु यह न्याययुक्त होना चाहिये। उन लोगों से लिया जाना चाहिये जो दे सकते हैं और इन्डायरेक्ट टेक्सेशन का रास्ता छोड़ना पड़ेगा और डायरेक्ट टेक्सेशन का रास्ता अख्त्यार करना पड़ेगा। तब न तो १२०० करोड़ के डेफिसिट का खतरा रहेगा और न साधन जुटाने के लिये मुसीबत ही होगी।

मैं इसलिये जोर दे रहा हूँ इस बात पर कि यह एक बुनियादी उसूल की चीज है। हर मुल्क ने योजनाबद्ध रूप में अपने मुल्क को बढाने की कोशिश की है, यह कोई नहीं कह सकता है। एक चीज हर मुल्क में लागू हुई है चाहे वह रूस हो, चाहे चीन हो चाहे बलगेरिया हो, चाहे जेकोस्लोवाकिया हो आज भी जो मुल्क तरक्की कर रहे हैं उनमें लेबर एन्थुजियाज्म पैदा करके काम किया गया है।

आज जो आंकड़े हमने इकट्ठे किये हैं, इस बुनियाद पर इकट्ठे किये हैं कि जो देश की उपार्जित चीजें हैं, उनका स्तर आज क्या है, पर कोई भी देश की तरक्की के लिये यह रास्ता नाकामयाब समझा गया है। इसके लिये लेबर एन्थुजियाज्म पैदा करने की आवश्यकता है। हर एक आदमी देश का रहने वाला यह समझे कि इस कार्य के जरिये हम देश की तरक्की कर रहे हैं, आगे जाकर इसका मुझे फायदा मिलेगा तो वह अपना दिल व दिमाग उस कार्य में लगा देता है। लेबर प्रोडक्टिविटी, यह कोई नई चीज नहीं है। ऐसी बहुत बडी बडी स्कीमें थीं जिनके बारे में इन्जीनियर्स बैठे, इन्जीनियर्स के विशेषज्ञ बैठे, हो नहीं पर बांध बांधने के लिये बैठे और उन्होंने कहा कि इस कार्य में ६ साल लगेंगे। उस इलाके के लोगों की इच्छा यह थी कि बार बार बाढ आती है और नुक्सान होता है इसलिये उसका प्रबन्ध वर्षा से पहले हो जावे ताकि हर साल बाढ से लोग मरते हैं और पशु मरते हैं वे बच जावें। उन्होंने इंजीनियरों से सलाह की और कहा कि यह कार्य वर्षा से पहले समाप्त हो जाना चाहिये। इंजीनियरों ने कहा कि यह कार्य वर्षा से पहले किसी हालत में समाप्त नहीं हो सकता। वहां के सब लोगों ने मिल कर उस पर विचार किया और फिर इंजीनियरों से मिले और कहा कि कोई रास्ता इसके लिये हो सकता हो तो निकलाजाए। तो इन्जिनीयरों ने कहा कि इसके लिये केवल एक ही रास्ता है कि अगर ३० लाख लोग इसके लिये काम करने को तैयार हों तो यह काम ४ महीनों में समाप्त हो सकता है। इस पर जिन इलाकों में बाढ आने वाली थी वहां के सब लोग काम में जुट गये क्योंकि मौसम ऐसा था कि खेती का काम तो था नहीं। इसका नतीजा यह हुआ कि उन लोगों ने मिल कर उस काम को ३॥ महीनों में ही पूरा कर दिया और वे सब लोग बाढ से बच गये और वह एक बहुत बडा कदम जनता ने उठाया। तो इसी तरह से लेबर प्रोड्यूसिंग और काम करने की शक्ति और दिलचस्पी हो तो काम हो सकता है। यहां के लेबर अोथेरिटीज़ किस तरह से काम कर रहे हैं यह भी मालूम है।

आप नये नये टैक्स लगा कर जनता पर नया नया बोझा डाल रहे हैं। मैं यह कहूँगा कि आप अगर आम लोगों पर नया नया बोझा टैक्सों का डाल कर निर्माण का काम कराना चाहते हैं तो यह कोई हितकर नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा कि प्लानिंग करने वालों का

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

बेसिक सिद्धान्त यह होना चाहिये कि वे उन लोगों से पैसा लें जो समृद्धशाली हैं। मगर उन्होंने वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के लोगों को छूआ नहीं। यही कारण है कि रिसोर्सेज आदि के जो साधन हैं वे सबसे ज्यादा कमजोर हैं और यही कमजोरी आगे चलकर इस योजना को कार्यान्वित करने में खतरनाक हो सकती है। आज करोड़ों रुपयों का गबन होता है, यह बात किसी से छुपी नहीं हैं। आज दुनियां जानती है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति क्या है! हमारे देश में पाकिस्तान की फौजों का निर्माण हो चुका है, और देश के बोर्डर पर तरह तरह की घटनाएं हमेशा हुआ ही करतो हैं। मैं नहीं कह सकता कि पकिस्तान के लोगों और हिन्दुस्तान के लोगों में तनातनी हैं। वे भाई भाइ हैं और पाकस्तान के लोग नहीं चाहते कि भारत के साथ किसी प्रकार का टंटा हो। लेकिन एक बात में यह कह देना चाहता हूं कि पकिस्तान के जो रूलर्स हैं वे अपनी नीति से चलते हैं, वे वाशिंगटन की नीति और उसके कहने के अनुसार चलते हैं और पाकिस्तान को उनसे फौजी मदद मिल रही है और जब फौजी मदद मिलती है तो कुछ चुलबुलाहट भी पैदा हो जाती है। ऐसी अन्तराष्ट्रीय स्थिति है।

इसके अलावा आज यह कहा जाता है कि फोरिन एड हमको मिलेगी और वह आज नहीं तो कल। लेकिन मैं यह कहूंगा कि जो फोरिन एड हमको मिलेगी और वह कब मिलेगी, अगर वह सहायता मिलेगी तो वह किसी प्रकार की शर्त से खाली नहीं होगी। आज जो वैदेशिक नीति भारत ने अपनाई है वह परिस्थिति बदलने की हालत में कल कहा जा सकता है कि हम इस नीति में परिवर्तन लेंगे। अगर नीति में परिवर्तन हो जाता है तो इसका असर हमारी योजना पर पड़ता है और इसके कम्पलीशन में असर पड़ सकता है। इसलिए हमारे पास ऐसे साधनों का होना आवश्यक है जिन पर हम कह सकें कि हम आत्म निर्भर हैं। 'रूस और अमेरिका से हमको मदद मिले और वह किसी शर्त पर मिले जैसे कि बम्बई में आइल के मिल को सहायता मिली है अमेरिका से, वह इस शर्त पर मिली है कि उन लोगों को हर डिप्लोमेटिक एनिमिटी हो। अगर कोई जुल्म करे, किसी को मार भी दें तो भले ही मार दें मगर फिर भी हमारे यहां की कोर्ट को उनके केसको सुनने का कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ और न कभी हमने सुना और देखा। अगर हमको करोड़ों रुपयों की सहायता इस प्रकार से मिलती है तो हम उसको सहन नहीं करना चाहते।

(घंटी)

मैं कहना चाहता हूं—

श्री अध्यक्ष—You have taken 45 minutes.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am not Sepeating. I am developing points after points. हमें करोड़ों रुपयों की सहायता के भरोसे नहीं रहना चाहिये। मैं यह अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी यह संभावना है कि हमको एड मिल जायेगी यह हमारी कमजोरी का बायस

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

बनेगी और अगर हम उस पर निर्भर नहीं रहेंगे तो वह हमारी कमजोरी दूर हो जावेगी और लोगों पर जो बोझ की प्रवृत्ति है वह भी दूर हो जावेगी। मैं यह साफ कहना चाहता हूं कि आज हर जिम्मेदार आदमी का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्र की उन्नति में सहयोग दे। यहां पर राष्ट्रीयता का प्रश्न है और चूंकि मैं यहां पर इसका जिक्र कर रहा हूं, कहूंगा कि अगर आम जनता पर इसके लिये कोई बोझा डालकर रुपयों की कमी को पूरा किया जावेगा तो मैं यह कहूंगा कि हमारी सरकार इसमें कामयाब नहीं होगी, हमारी प्रगति रुक जावेगी, कई प्रकार की कठिनाइयें पैदा होंगी। इसलिये राष्ट्रीयता के हित में सारे के सारे विधान सभाई सदस्य प्लानिंग कमीशन को जोर देकर कहेंगे कि आप नये साधनों का सुझाव दें। अन्त में मैं इस पहलू की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा और आपके जरिये सदन के माननीय सदस्यों का भी ध्यान आकर्षित करूंगा जिसका सम्बन्ध है हेवी इन्डस्ट्रीज़ को कार्यान्वित करने से। उद्योगीकरण के सिलसिले में, खेती के सम्बन्ध में लेन्ड रिफोर्म आदि का ध्यान रखा जाता है। यदि हेवी इन्डस्ट्रीज़ से जो काम किया जावे तो इससे राष्ट्र को फायदा होगा। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं और देखता हूं इस योजना में भी कमजोरी है। जहां तक इसको कार्यान्वित करने की बात है मैं यह कहूँगा कि लगभग ढोल में पोल जैसी बात है। मैंने यह कड़ा शब्द जान कर कहा है कि ढोल में पोल जैसी बात है और मैंने जान-बूझ कर इस शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि यह स्थिति सारे देश में है। इस पर हमको सैद्धान्तिक रूप से सोचना पड़ेगा, जितने भी कार्य होते हैं वे सिर्फ दिखावे मात्र के होते हैं वास्तव में कोई काम नहीं होता। पहले साम्राज्यवाद में जो काम होते थे उसके लिये हम कहा करते थे कि काम कुछ नहीं होता लेकिन अभी भी जो काम होते हैं वे केवल दिखावे मात्र के होते हैं। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ और आपसे यह पूछना चाहता हूं कि चम्बल प्रोजेक्ट और भाखरा नांगल के काम जो हो रहे हैं और हाथ में लिए हुए हैं वे आज भी ढीले ही हैं और इससे आपको मालूम हो गया है कि मौजूदा जो ढांचा है वह नाकामयाब हो रहा है।

आज एग्रेरियन रिफोर्म जिस हद तक हो रहे हैं और जिस तरह से हो रहे हैं उससे यह महसूस होता है कि जिस महकमे के अन्दर में यह काम है वह महकमा अभी तक निकम्मा साबित हो रहा है। आपको इस योजना को सफल बनाने के लिये सारा का सारा नया रूप अपनाना पड़ेगा क्योंकि डेवलपमेंट ब्लोक आदि में जो पिछले समय काम हुआ है वह कैसा हुआ है और कितना हुआ है सब जानते हैं। अभी द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई है। इसलिये हमें हमारे देश के ढांचे को उनके अनुकूल बनाना चाहिये। मौजूदा हमारे देश का जो ढांचा है वह नवनिर्माण के लिये सूटेबल नहीं है।

तो हमने इन्डस्ट्रीज के बारे में आत्म निर्भरता के लिये विशेष तौर पर बोल्ड थिंकिंग किया और हमारे स्टेटिस्टीशियन और इकोनोमिस्टों ने यह निर्णय किया कि जो तात्कालिक रूप में हमें कठिनाई अनुभव हुई वह कठिनाई हेवी इन्डस्ट्रीज़ के जरिये हमें दूर करनी

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

है जो कि हमारा विचार कुछ अरसे पहले नहीं था। मुझे याद है भारत सरकार ने उटी में एक सम्मेलन सन १९४९ में बुलाया था। जिस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्री षणमुखम चेट्टी और स्व० डा० श्यामप्रसाद मुखर्जी भी भारत सरकार के मंत्री थे उस समय अमेरिकन राजदूत मि० हेनरी ग्रेडी थे वे भी वहां गये थे। वहां जब इस प्रकार का प्रश्न आया कि भारत बरमा और मलाया दूसरे देशों की तरह अपने देश की उन्नति के लिए कौनसा रास्ता अख्तयार करे तो इस बात पर वहां पर मत भेद हुआ, उनमें से एक की राय थी औद्योगिकरण का रास्ता अख्तयार करना चाहिये। उस समय हैनरी ग्रेडी और हमारे मंत्रियों ने यह कहा कि यह रास्ता गलत है हमारे पास सीमित साधन हैं, इसलिये यह रास्ता अख्तयार नहीं करना चाहिये। यह स्थिति थी हमारे देश में उस समय, यह हमारा दुर्भाग्य ही समझिये। लेकिन भारत सरकार ने और उनके मंत्री षणमुखम चेट्टी और स्व. डा. श्यामप्रसाद मुखर्जी ने जिस चीज को खड़े होकर कहा कि औद्योगिकरण का रास्ता अख्तयार नहीं करना चाहिये लेकिन आज समय आगया कि हमें उनके पांच साल के पहले के निर्णय से जो हानि हुई उस निर्णय में परिवर्तन करना पड़ा, विचारों में तब्दीलियां आई। हमने अपने पडौसी देशों से अनुभव हासिल किये और आज हम उस निर्णय में आमूल परिवर्तन करने जा रहे हैं, आज हमें यदि औद्योगीकरण की ओर बढना है तो इस योजना में जो कार्यान्वित करने का ढांचा है उसमें आमूल परिवर्तन करना होगा। आज का मौजूदा प्रशासनिक ढांचा ब्यूरोक्रेटिक है, इसको बदलना पड़ेगा। लोगों के संगठनों को, आम लोगों के संगठनों को और दूसरे लोगों के नुमायन्दों को सब को मिलकर गांव की पंचायत से लेकर और और भी जो दूसरे जरिये हैं सब जरियों का प्रयोग करके इस योजना को कार्यान्वित करने का बहुत बड़ा जिम्मा है। पब्लिक कोऑपरेशन केवल नाम मात्र दिखावे के रूप में नहीं। जनता का सहयोग, आम लोगों का सहयोग योजना बनाने से लगाकर कार्यान्वित करने तक का लेना है। तो हमें नये मेथड इवोल्व करने पड़ेंगे। यह सब हमें उसूलों के तौर पर तय करने पड़ेंगे। इस समय इनके तफसील में जाने की आवश्यकता नहीं। इस बारे में मेरे कुछ सुझाव हैं। उन सुझावों को मैं बगैर किसी हिचकिचाहट के रखना चाहता हूं। उन पर अमल करना चाहिये। जहां तक साधनों का प्रश्न है इस योजना को कार्यान्वित करना है तो धन की बहुत आवश्यकता है। जब धन दिलाने की हमारी जिम्मेदारी है तो हमें इसके लिये हमारा क्या फर्ज होने चाहिए वह भी हमें तय करना चाहिये। हमारी पंच वर्षीय योजना के लिये हमारे पास नारे होना चाहिये। उन नारों का मेरे माननीय उधर बैठने वाले मित्र भी इसका फायदा उठा सकते हैं और उठाना चाहिये। पहला नारा हमारा यह होना चाहिये कि जो हमने पहला टारगेट रखा है उस पर चलें, जो हमने नकल करदी है उसको रद्द करें, दूसरा नारा यह होना चाहिये नये साधनों का निर्माण किया जाना चाहिये ताकि मामूली आमदनी वाले पर बोझा नहीं पड़ सके।

तीसरा नारा यह होना चाहिये इसको कार्यान्वित करने का हमें डेमोक्रेटिक तरीका अपनाना चाहिये। इसके लिये दुनिया के अंदर जितनी शक्तियां है जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं जिनका रुख भारत के साथ सहानुभूति का है, जो दोस्ताना का बरतवा करते हैं, जो बाइज्जत हमको सहायता करने के इच्छुक हैं, चाहे किसी भी रूप में हों, वह चाहे मशीनरी के जरिये हो,

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

टेकनिशियन्स के जरिये हो; उन सब चीजों का पूरा उपयोग और लाभ उठाना चाहिए । अगर यह मार्ग अपनाया गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अगर गलत रास्ता अपनाया गया तो यह निश्चित है कि इससे असंतोष फैलेगा और उस असंतोष के कारण विरोध होगा और विरोध करना पड़ेगा जो पंचवर्षीय योजना की कामयाबी में बाधा बन जायगी । मैंने जो चीजें कहीं उन पर गंभीरता से विचार करते हुए देश की उन्नति की दृष्टि से माननीय सदस्य उन बातों पर विचार करेंगे और एक मत से जिन उसूलों को मैंने सदन के सामने रखा उसके अनुसार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में परिवर्तन करने की दृष्टि से जो सुझाव मैंने दिये हैं उन पर विचार करेंगे । इन शब्दों के साथ अपने विचार रखता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

डा० श्री मंगलसिंह—अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन मे जो प्रश्न उपस्थित है वह एक ऐसा प्रश्न है उसका संबन्ध इस प्रदेश के साथ २ सारे देश से है जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह पंचवर्षीय योजना, दर असल जो पहली पंच वर्षीय योजना बनी थी वह बहुत जल्दी २ में बनी थी और जिस समय बनी थी उस समय देश के सामने अन्न की विकट समस्या थी । खाने का प्रश्न सब से पहले हल होना चाहिये था । इसी दृष्टि को रखते हुए पहली पंचवर्षीय योजना बनी और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस प्लान का करीब आधे से ज्यादा रुपया खर्च कर दिया गया । खाने का प्रश्न मनुष्य के लिये पहला प्रश्न है, जबतक खाने का प्रबन्ध नहीं तब तक दूसरा प्रबन्ध हो नहीं सकता । यह जो दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारे सामने है दर असल पहली पंचवर्षीय योजना से भिन्न है । जहां पहली पंचवर्षीय योजना में हमने खाने की समस्या का हल किया वहां दूसरी पंचवर्षीय योजना में हम देश के रहने वालों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं और खास तौर से यही मुद्दा नजर में रखकर हमने यह योजना बनाई है । मनुष्य के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए खाना, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा इन पांचों चीजों का होना आवश्यक है । इसमें से पहली चीज को पूरा करने के लिये समुचित सामान है, समुचित धन है, समुचित प्रबन्ध है; यही इस पंचवर्षीय योजना की आधार शिला मालूम पड़ रही है, लोगों की बेरोजगारी और बेकारी को निर्मूल करना है । वैसे देखा जाय तो जितनी भी चीजें एक मनुष्य को चाहिए वे दो चीजों में विभक्त होती हैं । वे दो चीजें हैं उनमें से एक है श्रम और दूसरी है पांच तत्व जिसमें पृथ्वी सबसे प्रधान है । इस हाल में चाहे किसी चीज पर आपकी नजर पड़े वह तो पृथ्वी ही है, उसमें श्रम का मिश्रण होकर इस हाल की चीजें हमारे सामने हैं । लकड़ी के सामान को भी देखिये, वह सब लकड़ी जो पृथ्वी और श्रम के मिश्रण से बनी है । इसी प्रकार यह जो लोहे का सामान है इसी तरह से कपड़े का सामान है वह सब पृथ्वी के गर्भ से निकला है और श्रम के सहयोग से आज इस शक्ल में हमारे सामने है । चाहे चमड़ा लें लीजिये या किसी चीज को ले लीजिये, दो ही चीजों का सम्मिश्रण मिलेगा एक पृथ्वी और दूसरा श्रम । आज हमें जब कि लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना है तो हमें भी इन दो चीजों का आश्रय लेना होगा ।

[डा० श्री मंगलसिंह]

मैं पहला स्लोगन आपके सामने रखना चाहता हूँ वह है श्रम। हमारे देश में श्रम करने के लिये, श्रमके महत्व को समझाने के लिए हमें यह आवश्यक है कि जैसे कि पहली पंच वर्षीय योजना के अन्दर अन्न के ऊपर ज्यादा जोर दिया उसी प्रकार श्रम के ऊपर खास तौर से ध्यान देना चाहिए। जहां हमने यह तय किया है कि पचास प्रतिशत गवनमेंट दे और पचास प्रतिशत जनता दे तो मेरा इसमें निवेदन है कि श्रम को हमें महत्व देना चाहिए जैसा कि हम नहीं दे रहे हैं, वहां भी हमने धन की मांग की है। मैं यह समझता हूं कि हमें श्रम के ऊपर अधिक महत्व देना चाहिए क्योंकि इस देश में जैसा कि मेरे मित्र ने कहा चीन के बीस लाख आदमियों ने जो काम ६ वर्ष में होने वाला था उसे साढ़े चार महीने में कर दिया, जो श्रम की कीमत बताता है। मेरे ख्याल से इस योजना में इस बात की खामी है। इसको जब हम अपने सामने रखकर चलेंगे तो लोगों का जीवनस्तर ऊंचा उठ सकता है। अब इस स्तर को बढ़ाने के लिए सामान की जरुरत है। सामान श्रम और पृथ्वी से पैदा होता है और जितनी भी चीजें हमारे काम में आती हैं वे कल-कारखानों से मशीनों से बनती हैं। पर इन मशीनों को बनाने के लिए दूसरी बड़ी मशीनें चाहिए और उन बड़ी मशीनों को बनाने के लिए भी और बड़ी मशीनों की जरुरत है। इस दृष्टि से इस योजना में सोचा गया कि बड़ी से बड़ी मशीनों के बनाने के कल कारखाने तैयार किये जावें। जिससे बड़ी से बड़ी मशीनें भी हम अपने यहां ही तैयार करने में कामयाब हो जावें और बाहर से मंगाने की जरुरत नहीं रह जावे। यह बड़ी अच्छी और बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आधुनिक काल में कोई भी देश इसके बिना एक दूसरे के कम्पीटीशन में ठहर नहीं सकता। तो इस सूरत में यह योजना नेशनल न कहीं जाकर इन्टर्नेशनल बातों को विचार करके भी हमारे सामने लाई गई है।

पर इससे भी एक सवाल फिर रह जाता है। इतने बड़े बड़े कल कारखाने और इतनी बड़ी से बड़ी मशीनें बन गईं पर इसका मतलब यह लगाया जावेगा कि कम श्रम करना पड़े और ज्यादा फल मिले। आदमियों के श्रम को बचाया जावे यह बात इसमें है। एक तरफ बड़ी मशीनें तैयार करके हम श्रम को बचाना चाहते हैं और दूसरी तरफ बेकारी का प्रश्न भी हम हल करना चाहते हैं तो ये बातें एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी लड़ती हैं। लेकिन बड़े बड़े कारखाने और बड़ी बड़ी मशीनें हमें चाहिये ही, इसलिये हमने बेकारी के प्रश्न को हल करने के लिये दूसरे और रास्ते सोचे। बेकारी मशीनों के बढ़ने से बढ़ती है, घटती नहीं; तो इस तरह बेकारी पहले से भी है और मशीनों से और बढ़ गई तो इस बढ़ी हुई बेकारी को हल करने के लिये फिर हमारे सामने यह आती है कि ग्रामोद्योगों को फिर पांव गांवों में कुछ ऐसे छोटे कल-कारखाने खोल लें जिन पर अधिक आदमी काम पर लग सकें और उनके लिये बिजली का प्रबन्ध किया जावे। इस तरह से छोटे छोटे कल कारखानों की तरफ और ग्रामोद्योगों की तरफ भी हमारा ध्यान जाता है।

तो ये जो चीजें हमारे सामने लाई गई हैं इससे अंशतः हमारी बेकारी की समस्या का हल

[डा० श्री मंगलसिंह]

होगा और देश की सम्पत्ति बढ़ेगी। पर देश की सम्पत्ति तो वास्तव में इस वसुन्धरा में भरी पड़ी है। इसके गर्भ से हमें उसे निकालना होगा। मैं समझता हूँ कि प्रथम योजना में खानों पर बड़ा जोर दिया गया था। पर इस दूसरी योजना में जिस तरह से बड़े बड़े कल कारखानों पर और बड़ी बड़ी मशीनों पर जोर दिया गया है उससे भी ज्यादा जोर इसी खनिज पदार्थों को उपलब्ध कराने पर दिया जाना चाहिये था। जिस पृथ्वी के अन्दर से हम अन्न निकालते हैं उसी वसुन्धरा के गर्भ में अमित और असीम धन भरा पड़ा है वह असीम धन हम इसकी कोख से निकाल सकते हैं। कोलार जैसे दो चार और गोल्ड फील्ड मिल जावें तो आपको धन को ज्यादा इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं कहता हूं कि सोना ही क्या इसके अन्दर तो न मालूम क्या क्या भरा पड़ा हैं, हम अपनी वसुन्धरा की तरफ ऊपर ही ऊपर न देखकर नीचे भी देखें और इसके अन्दर से अमित धन निकालने की कोशिश करें तो न मालूम हमको प्लेटिनम गोल्ड या ऐसी ही दूसरी कितनी चीजें मिल जावें। मुमकिन है कि ऐसी चीज हम निकालने में कामयाब हो जावें, जो पेट्रोल से भी सैंकड़ों गुना अधिक ताकतवर वस्तु हो तो इस ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिये। कल कारखाने तो मनुष्यों के बनाये हुए हैं पर इस पृथ्वी की कोख में जो चीजें भरी हैं वे प्रकृति ने बना बनाकर दी हैं। तो वह बनी बनाई वस्तुएं वह बना बनाया धन न निकाल कर हम दूसरी बातों में धन की लालसा करते हैं। यह खनिज पदार्थों के रूप में अमित धन कुदरत ने और ईश्वर ने हमें दिया है उसको नहीं निकालना उस देन को ठुकराने के बराबर है।

इसमें आगे जो बात कही गई है वह कर द्वारा धन इकट्ठा करने की है। कर लगे इसमें किसी को चिन्ता नहीं होनी चाहिये। आखिरकार तो स्तर बढ़ता है उनका जो कर देते हैं। करों का बोझा भी उन्हीं पर पड़ना चाहिये पर अगर वह बोझा उन लोगों पर पड़ता है जो दोनों वक्त खाना खाने को और पहनने को पूरा कपड़ा भी नहीं पाते हों तो इस योजना का और आगे आने वाली तीसरी चौथी योजनाओं का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ये कर उन्हीं लोगों पर लगाया जावे जिनको आमदनी अधिक और खर्चा कम हो। सेविंग यानि लोगों की बचत पर ही कर लगाये जाते हैं। और लगाने चाहिये और जिसकी आमदनी और खर्च बराबर हैं उससे भी कर अगर लिया जावेगा तो इसमें भी दिक्कत आवेगी। तो इन बातों का भी ध्यान रखना होगा कि करों का बोझा इन और ऐसे लोगों पर नहीं पड़े।

अब बचत वाली भी बात कही गई है। जिनको आमदनी होती है उन्हें ईमानदारी किफायत से खर्च करके जो बचत होती है उस सारी या उसमें से अधिक अंश को इस योजना में लगाना चाहियें क्योंकि इससे उनको रकम का अच्छा ब्याज मिलेगा और रकम की हिफाजत भी रहेगी और देश के निर्माण में भी इससे सबसे अधिक सहायता मिलेगी।

इसमें मुझे एक कसर नजर आई कि पार्लियामेन्ट के मेम्बर थे या जो दूसरे हमारे पदाधिकारी थे जो इस योजना को बनाने के लिये बैठे थे उनको चाहिये था कि वे अपनी आमदनी

[डा० श्री मंगलसिंह]

का पचास प्रतिशत या कम से कम पच्चीस प्रतिशत इस बचत योजना में दे देते। जो दूसरों से रुपयों की मांग करते हैं वे अपनी बचत की बात न करें, यह बात उनके लिये शोभाजनक नहीं है और न उनकी यह अपील किसी को लगने वाली है। तो यह नियम सभी लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों के लिये भी होने चाहिये कि वे अपनी आय में से कम से कम पच्चीस और अधिक से अधिक जितना देना चाहें आवश्य देना चाहिये और यही नियम सभी देश की धारा सभाओं के लिये भी लागू होना चाहिये।

अगर धारा सभा के सदस्य बाहर जाते हैं और लोगों से कहते हैं कि बचत योजना में आप अपना रूपया लगाइये और हम अपने रूपये को गांठ में बांधते जांय और उसमें से कुछ भी लगाने को तैयार नहीं, और किसी ने पूछ लिया कि आपने क्या कन्ट्रीब्यूशन किया है इसमें और हम कह दें कि हमने कुछ नहीं किया तो यह बात हमारी बहुत गहरी असर नहीं करेगी। मैं यह नहीं समझता हूँ कि इस बचत योजना के अन्दर यह ठीक है कि पार्लियामेंट के मेम्बरों और विधान सभाओं के मेम्बरों का जो कन्ट्रीब्युशन आयेगा वह बहुत अधिक होगा, लेकिन यह एमाउन्ट की बात नहीं है, यह उस रकम की बात नहीं है, यह उस भावना की बात है। जब तक आप गुड़ खाते हैं बच्चों को मिठाई के लिए मना नहीं कर सकते। इस बारे में मैं यह कहूंगा कि यह बहुत बड़ी जरूरत है।

अब दूसरी बात जो इस रूपये को इक्टठा करने के लिए की गई है वह बाहर से पैसा लाने के लिए, कर्जे में ८०० करोड़ रूपया बाहर से आ सकता है। मैं यह समझता हूँ कि जो बाहर से कर्जा लेकर अपनी उन्नति करना चाहते हैं यह व्यक्ति के लिए भूल है ही, लेकिन मैं समझता हूँ कि नेशन के लिए कोई बड़ी अक्लमन्दी की बात नहीं है। लेकिन इस वक्त हमको अपने काम के लिए रूपया आपद् धर्म समझ कर, बाहर से भी लाकर अगर उन्नति कर सकते हैं, चाहे समय आने पर वापिस करने का अवसर मिल सकता है, तो भी मैं यह समझता हूँ कि ठीक ही है।

तीसरी बात मैं इसमें यह कहूंगा कि जितनी हमारी बैंक हैं जितना रूपया बचत का है देश के निवासियों का वह निश्चित कहीं न कहीं बैंक में उन्होंने उसको रख छोड़ा है, और बैंक में जितना भी रूपया है, जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें जितना रूपया है और उससे जितना पैसा कमाते हैं सब वे ही लोग कमाते हैं जो कि पैसे से पैसा कमाते हैं और गरीबों से इक्टठा करके धनवान बनते हैं। मैं समझता हूँ यह निजी बैंकों का रूपया इस योजना में प्रयोग होना बड़ा भारी जरूरी है, फौरन करने की चीज है। इन सब बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना आवश्यक है। इसमें समय बीच में देना, उन लोगों के कान खड़े कर देना होगा। इसके मायने यह हैं कि उनकी बचत का रूपया बैंकों से काफूर हो जाय। हम जानते हैं कि वे लोग इतने चतुर हैं कि उनके कान में यह बात पड़ जाय तो बैंकों में उनके हिसाब किताब के अलावा कुछ न मिले जैसा कि जागीरदारों और राजाओं को थोड़ा बहुत समय मिला उसमें उन्होंने क्या क्या कर लिया, यह सबके सामने है। मैं समझता

[डा० श्री मंगलसिंह]

हूँ कि हिन्दुस्तान के अन्दर कोई प्राइवेट बैंक न रहे और सब स्टेट बैंक होने चाहिए और सबके रूपये की बचत जो है जो कि करोड़ों रूपयों की है और उसने रूपया जमा करते आये हैं और आगे भी जमा करते रहेंगे तो डाक खानों के जरिये या दूसरे और जरियों से गवर्नमेंट के पास बचत का रूपया आता है वह बैंक में या और कहीं न कहीं तो आदमी रखेगा। वह सब का सब रूपया गवर्नमेंट के हाथ आता है और वह डेवलपमेंट के कार्य में काम आयेगा। तो सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देना आवश्यक है।

एक और जो बात कही गई है और जो मैं यह देखता हूँ कि इसमें कुछ कमी है। रेलवे के ऊपर बहुत सा रूपया खर्च किया गया बतलाया गया है और आगे भी पचवर्षीय योजना के अन्दर जो बतलाया गया है, लेकिन मैं यह समझता हूं कि फिर भी वह बहुत कम है। रेलवे बहुत आवश्यक चीज है। मेरा ऐसा ख्याल है कि सन १८५० के करीब एक योजना पार्लियामेंट के सामने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रखी गई थी और उसके अन्दर बड़े बड़े बान्ध नदियों पर बांधने की दूसरी स्कीम थी और काफी उस समय को देखते हुए बहुत भारी रकम रखी गई थी और एक स्कीम रखी गई थी रेलवे की। उस वक्त की बात है, आज से करीब १०० वर्ष से भी अधिक हो गये हैं उस वक्त १८५७ आगया विचार करते २ और १८५७ में जिसको कि गदर का नाम दिया जाता है वह देशभक्तों की बहुत बड़ी देश को स्वतन्त्र करने की बड़ी शानदार लड़ाई थी, जिसका नाम लोगों ने गदर रख दिया। अगर उसके अंदर कुछ लोगों की भूल नहीं हुई होती तो देश १०० वर्ष पहले ही स्वतन्त्र हो गया होता, लेकिन आज का विषय वह नहीं है, पर मैं यह कहता हूं कि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से दो स्कीमें रखी गई थीं। सन् ५७ के गदर के बाद दोनों स्कीमों के ऊपर विचार हुआ वहां। यह पर्लियामेंट के डिसकशन के अंदर मौजूद है। उन्होंने कहा कि अगर बान्धों की स्कीमें लेते हैं तो उसमें अरबों रूपया खर्च होता है और नदी यदि बंध जायगी और पानी सब जगह पहुंच जायगा और अन्न ज्यादा ज्यादा पैदा होगा तो हिन्दुस्तान के लोग खाने और कपड़े में स्वतन्त्र हो जायेंगे तो उनके दिमाग में स्वतन्त्रता की बात आने लगेगी इस लिए इनको गरीब रखें, इनको बे कपड़ा रखें और इनको भूखें रखें। अगर इनके ऊपर राज्य करना है तो कमजोर रखें इन्हें तभी हमारा राज्य चल सकता है। इस भावनाको लेकर पार्लियामेंट में बातें कही गई थी। और उन्होंने यह सन् १८५७ के तजुर्बे से, अनुभव को लेकर कि उनको दिल्ली में बहादुर शाह को फिर से हराकर काबू करने के लिए मद्रास से फौज मंगाने में बड़ी देर लग गई थी और उन्होंने यह महसूस किया था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमको फौज लेजानी है, उसके लिए रेलवे बनानी है। इस लिए उन्होंने दूसरी स्कीम जो थी उसको मन्जूर कर लिया। उन्होंने दूसरा फायदा यह देखा था कि बांध वाली स्कीम के अन्दर जितना रूपया खर्च होगा वह हिन्दुस्तान के मजदूरों को मिलेगा। हिन्दुस्तान की जितनी मिट्टी है, जितना सामान है वह यहां का लगेगा। वह सब रूपया यहीं पर लगेगा। इसलिए यहां के मजदूर धनवान होंगे। यहां के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। यहां के लोगों को इसका पानी मिलेगा। यहां के लोगों के लिए अन्न ज्यादा पैदा होगा। लेकिन अगर रेलवे बनती हैं तो यहां के लिए एक एक सामान कील, कांटे डिब्बे और इन्जिन सब विलायत से आयेंगे तो उनके देश के

[डा० श्री मंगलसिंह]

के मजदूर धनवान होंगे, केपिटलिस्टों को इसका फायदा होगा। लिहाजा वह स्कीम रखी गई और उस स्कीम को मंजूर कर लिया। स्वतंत्रता जब हमारे यहां पर आई तो वह स्कीम जो दबी हुई थी १८५० और ६० के बीच में जो बनी थी वह ले ली गई। इसमें तरक्की होने से कितना फायदा हुआ। थोड़े ही दिनों में अन्न के सवाल पर स्वतंत्र हो गये। तो मैं यह कहना चाहता था कि रेलवे यह बड़ी भारी आवश्यक चीज़ है। हिन्दुस्तान के अन्दर से जिस वक्त अंग्रेज यहां से चले गये और जिस हालत में हमने इसको पाया तो यहां के बड़े बड़े कर्णधार थे, मैं मिसाल के तौर पर कह दूं कि एक कमरे में जहां कि उसमें पूरी चारपाई उल्टी पड़ी थी, गद्दा फटा पुराना एक तरफ था, तकिया फटा है, चद्दर मैली पड़ी है इस प्रकार से हिंदुस्तान को छोड़कर अंग्रेज यहां से गये थे, तो हमारे नेताओं ने क्या किया कि पहली पंचवर्षीय योजना में हमने दरी को साफ किया, गद्दे का कपड़ा बदला, चद्दर को धोकर, साफ करके एक होल डोल में बन्द करने को तो कर दिया लेकिन वह बंधता नहीं था। और होल डोल को बांधने के लिए यह आवश्यक है कि हम रेलवे और सड़कें जो फैली हुई हैं जो हमारा धन है, सारे हिंदुस्तान के अन्दर बिखरा हुआ है, इधर उधर पड़ा हुआ है। एक जगह बहुत सा अन्न होता है। दूसरी जगह अन्न नहीं होता है, वहां हम कैसे ले जांय ? इसका प्रबंध करने के लिए हमारे लिए यह आवश्यक है कि इन रस्सियों को, चमड़े के तस्मों को होल डोल के नीचे रखकर उसका एकीकरण करें। हिंदुस्तान को, अपने देश के गद्दे, कपड़ों को एक सूत्र में बांधने के लिए अपना जितना धन है, अपना जितना सामान है उसको इकट्ठा करने के लिए यही एक चीज़ है। होलडोल जिस तरह बगैर बन्धा बेकार है, उसी प्रकार रेलवे और सड़कों के बगैर सारी धन संपत्ति बेकार है, खुला पड़ा है। खतरे में हैं। चाहे कोई भी उसे उठा कर ले जासकता है।

श्रीमन्, सिर्फ मैं एक बात और कहूंगा। पिछली पंचवर्षीय योजना के अन्दर बहुत सा रुपया खर्च हुआ और वह अब भी खर्च हो रहा है। लेकिन जिस मनोवृत्ति से कर्जा लेकर जिस तरह से छोटे छोटे लोगों से बचत कराके, जिस प्रकार से वह धन इकट्ठा किया है उसी पीड़ा के साथ वह धन खर्च नहीं किया जा रहा है। उस पर अंकुश रखना है, उसी खर्च पर अंकुश रखना है। यह एक विशेष आवश्यकता है, हमको इस पंचवर्षीय योजना में और अगली पंचवर्षीय योजनाओं में। हम देखते हैं कि जहां २०) से काम चल सकता है वहां सैंकड़ों रुपया खर्च हो जाता है. बड़ी मुश्किल से सैंकड़ों रुपया इकट्ठा हुआ, उसको पानी की तरह बहा दिया जाय और जो उसका फल मिलना चाहिए वह न मिले। संसार में यह कहा गया है कि रुपया बड़ी मुश्किल से इकट्ठा होता है, बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है लेकिन मेरा यह कहना है कि रुपया कमाना आसान है लेकिन उसको खर्च करना मुश्किल है। खर्चा करने के अन्दर ज्यादा अक्ल चाहिए बनिस्पत कमाने के। मैं आपको जोर से यह बात निवेदन कर देना चाहता हूँ कि हमारे जो कर्णधार हैं, प्रबन्धक हैं, कर्मचारी हैं, सब लोग इस पर विशेष रूप से ध्यान दें और जिस तरह से यह धन इकट्ठा किया है उसी पीड़ा से और हिफाजत से इन रुपयों को खर्च करना चाहिये। मैं इन शब्दों के साथ इस पंचवर्षीय योजना की स्कीम का समर्थन करता हूं।

श्री घीसीसिंह—माननीय सभापतिजी, भारत सरकार ने और राजस्थान सरकार ने इन योजनाओं द्वारा जो हमारे देश के उत्थान के लिए कार्य किया है, वह तो सराहनीय है और जो ८०० करोड़ रुपया खर्च किया जायगा, भारत सरकार ने और उनके एक्सपर्ट्स ने जो आंकड़े रखे हैं। वे काफी सोच समझ कर रखें हैं लेकिन एक बहुत बड़े महत्व की चीज़ है वह न भारत सरकार ने और न राजस्थान सरकार ने रखी वह थी जमुना से जल लाने की योजना। जमुना के जल से भरतपुर और अलवर का बहुत बड़ा फायदा हो सकता है उसके निर्माण के लिए कोई चीज़ नहीं रखी गई। न तो उसके लिए धन राशि रखी गई और न ही उसको योजना में रखा गया। सबसे बड़ी कमी इस योजना के अन्दर है वह यही है। मैं राजस्थान सरकार से और भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि इस पंचवर्षीय योजना में यह बडी भारी कमी रह गई है उसको पूरा करें ताकि अलवर और भरतपुर एक इलाके के रूप में मिल कर जो सरसब्ज हो सकता है वह चीज इसमें नहीं है। हिन्दुस्तान में कई जगह पानी की बड़ी आवश्यकता है और पानी पहुँचाना भूल गये तो जीवन निर्वाह किस प्रकार होगा। हम इस सदन में और बाहर सुनते रहे हैं कि यू पी. सरकार और राजस्थान सरकार में यह तय हो चुका है कि जमुना को नहर भरतपुर और अलवर को पानी देने के लिए निकाल देगें लेकिन अगर इस पंचवर्षीय योजना में देंगे तो उसका कहीं जिक्र नहीं है। इसलिए राजस्थान सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और लम्बी लम्बी स्कीमों से काम नहीं चलेगा। मैं आगे बोलने वाले भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि वे इस पर बोलें यह भूल से रह गया है। इन किताबों को उल्टा सीधा करने से काम नहीं चलता और लम्बे चौडे भाषण देने से काम नहीं चलता। कम रूपया लगायें, और रुपया मंगा कर यह करें, इससे राजस्थान का उत्थान होगा।

श्री शंभूसिंह—माननीय चेयरमेन महोदय, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वास्ते राजस्थान के विषय में जो योजना का प्रारुप हुआ है उसको विशेष रुप से अध्ययन किया। अगर हमने उसका अध्यन किया है और भारतवर्ष की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्लान आउट लाइन है, उन पर विशेष रूप से विचार प्रकट करना है तो सेकिन्ड फाइव इयर प्लान के लिये जो पुस्तक हमें मिली है उसमें दूसरे अध्याय में जो उल्लेख है उसको हमने गौर से पढ़ा है तो उसको देखने से प्रतीत होगा कि ४८०० करोड रुपयों की जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनायी गई है और जिसके वास्ते आमद का इन्तजाम किया गया है, जिसमें से पूरे २४०० करोड़ रुपया इस प्रकार से है जिसके लिए यह कह सकते है कि यह अनिश्चित राशि है। १२०० करोड रुपया डेफिसिट फाइनेन्स से ८०० विदेशी सहायता से और ४०० करोड अनकवर्ड गेप से। उसके बाद भी २४०० करोड रुपयों का जो प्लान रह जाता है, उसमें भी जो एक्जिस्टिंग रेटस है........

(घंटी)

श्री सभापति—There is no quorum.

(गण पूरक घंटी)

(लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री शंभूसिंह—[जारी रखते हुए] जो मौजूदा टेक्सेशन है उसके अलावा ४५० करोड़ रुपया और टेक्सेशन के रुप में, इसमें उसका विधान किया गया है। आज की जनता की जैसी परिस्थिति है उसको देखते हुए इस नये टेक्सेशन का भार जो जनता पर लगाने का तजवीज किया गया है, वह कुछ असंगत प्रतीत होता है। परन्तु प्रश्न यह रहता है कि इतनी बड़ी योजना को कार्य रुप में परिणत करने के वास्ते पैसा कहां से आ सकता है ? तो टेक्सों के प्रावधान का यही बड़ा कारण हो सकता है। मैं समझता हूँ कि टेक्सेज उन्हीं पर लगाये जावें कि जिनके पास सरप्लस इनकम हो। ऐसे लोगों पर टेक्सेज नहीं लगाये जावें जो किसान हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, कम आमदनी के व्यापारी हैं। उन पर टेक्सेज नहीं लगाना चाहिए। इस पर स्पष्ट रुप से नहीं कहां गया कि इस प्रकार के लोगों को टेक्सेज छोड़ दिये जावेंगे।

उद्योगों के दो विभाग किया गये हैं एक पब्लिक सेक्टर और दूसरा प्राइवेट सेक्टर। औद्योगीकरण देश के लिए लाभदायक हो सकता है लेकिन उद्योगों की वजह से कुछ इविल्स भी हो सकते हैं और वे ये हो सकते हैं कि अनएम्प्लोयमेन्ट का बढ़ना और पूंजी का एक जगह संग्रह हो जाना। मान लीजिये कि कुछ हजार व्यक्ति अपना कुछ काम करके अपना भरण पोषण करते थे और औद्योगीकरण से वे उस काम को करना बन्द कर देंगे। इन वस्तुओं का उत्पादन मशीनों द्वारा होगा, इन मशीनों से लाभ तो यह जरुर होता है कि कम इनर्जी खर्च करनी पडती हैं परन्तु ज्यादातर लोग इनसे बेकार हो जाते हैं और इसी वजह से महात्मा गांधी ने भी इस इन्डिस्ट्रियलाइजेशन को ज्यादा पसन्द नहीं किया था। मगर यह संभव नहीं कि हम अपने देश का औद्योगीकरण न करें और देश को इस अवस्था में रहने दे। संसार में औद्योगीकरण इतनी तेजी से हो रहा है और उन्नति की जो घुड़दौड़ लगी हुई है उसमें पीछे रह जावें यह भी सम्भव नहीं। औद्योगीकरण होना चाहिए लेकिन साथ ही कोटेज इन्डस्ट्रीज् हैं उनको भी काफी प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

इसके वास्ते भी इस में व्यवस्था है। लेकिन हमारे देश में जो व्यक्ति कोटेज इन्डस्ट्रीज चला रहे है, वे सब तरह के पेशा और हुन्नर करने वाले लोग हैं तो मैं यह मुनासिब समझता हूं कि ऐसे वर्तमान कोटेज़ इन्डस्ट्रीज को चलाने वाले हैं, छोटे उद्योग करनेवाले व्यक्ति हैं उनका सेसन्स होना चाहिये और वे लोग कैसी कैसी दस्तकारियों का काम करते हैं, जिन जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उनको सुधरे हुए इम्प्लीमेंट्स मिलने चाहिये, उनको सहायता मिलनी चाहिये ताकि नये कुटीर उद्योग यानि काटेज इन्डस्ट्रीज खोली जा सकें। लेकिन इस वख्त जो एग्जिस्टिंग उतपादक हैं या कोटेज इंडस्ट्रीज का काम करने वाले लोग हैं, उनको अलग नहीं करना चाहिये बल्कि उनको रिफाइंड इम्प्लीमेंट्स देने चाहिये और उनको रॉ मेटिरियल उपलब्ध कराना चाहिये और हर तरह से काफी इमदाद देनी चाहिये।

बड़ी इन्डस्ट्रीज का दूसरा दोष यह है कि पूंजी और धन एक ही जगह संग्रह हो जाता है। जिस की इन्डस्ट्रीज होती हैं वह काम करने वाले लोगों के श्रम को खरीद कर फायदा उठाते हैं। लेकिन इस प्लान में ज्यादा इन्डस्ट्रीज् पब्लिक सेक्टर की रखी है इसलिये यह भय कम हो जाता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी काफी इन्डस्ट्रीज रखी हैं। इससे आशंका बनी रहती है। इससे उसी तरह का

[रावत श्री शम्भूसिंह]

पूंजीवाद चलेगा और इसका जो परिणाम होता है धन का एक जगह संग्रह हो जाना, जरूर होगा। यह खास कर वर्तमान परिस्थिति में जब कि मेनेजिंग एजेन्सी वगैरा का कानून या जोइन्ट स्टॉक कम्पनीज़ का कानून है उसमें बहुत कम सुधार हुआ है। मेनेजिंग एजेन्सी सिस्टम में कुछ समय पहले कुछ परिवर्तन हुआ था। लेकिन इस प्लान में ऐसा कोई प्रोवीजन नहीं है कि मेनेजिंग एजेन्सी सिस्टम को सुधारेंगे या इसमें आमूल चूल परिवर्तन करेंगे। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक यह खतरा दूर नहीं होगा। ये बातें मैंने आपके समाने इन्डस्ट्रीज़ के बारे में निवेदन कीं।

इसके बाद एक चेप्टर है लैंड रिफोर्म्स के बारे में। लैंड रिफोर्म्स में सीलिंग वगैरा बहुत सी बातें हैं, जिनका वर्णन इसमें किया गया है। मगर लैंड रिफोर्म्स की वजह से जो बेकारी देश में पैदा हो रही है या जो भविष्य में हो सकती है, उसको मिटाने के लिए जो लोग लैंड रिफोर्म्स की चपेट में आकर डिस्प्लेस्ड परन्सस हो सकते हैं, उनके रिहेबिलिटेशन के वास्ते समुच्चित इन्तजाम इस चेप्टर में कुछ नहीं दिखाया गया है। मैं समझता हूं कि जो लोग लैंड रिफोर्म्स के शिकार हुए हैं या हो सकते हैं उनके वास्ते बहुत कुछ तजवीज होनी चाहिये थी कि वे अपने आपको पूर्ण रूप से रिहेबिलिटेटकर सकें। मेरा यह ख्याल है कि प्राइवेट सेक्टर में जो इन्डस्ट्रीज खोली जाने वाली हैं या जो प्राइवेट एन्टरप्राइजर्स हैं उनमें कुछ परसेन्टेज ऐसे लोगों का होना चाहिये जो कि लैंड रिफोर्म्स के शिकार हुए हैं या जिनको लैंड रिफोर्म्स से नुकसान पहुँचने वाला है। प्राइवेट सेक्टर की इन्डस्ट्रीज ऐसे लोगों के लिए महफूज रखी जावें ताकि वे लोग अपने अपने आप को रिहेबिलिटेट कर सकें।

इसके पश्चात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में खनिज पदार्थों की प्रचुरता है। सब तरह की आबहवा और क्लाइमेट्स हमारे यहां हैं। सब तरह का कृषि जन्य उत्पादन हो सकता है और इन्डस्ट्रीज भी खोली जा सकती है। मेरा यह सुझाव है कि जहां जिस प्रकार का कच्चा माल पैदा होता है उसी सर्किल में मेनुफेक्चिरिंग इन्डस्ट्रीज होनी चाहिये। मसलन उदयपुर के पास जावरा माइन्स हैं वहां पर जिंक, सिलवर,लेड काफी मात्रा में उपलब्ध होता है। यहां से कच्चा माल कलकत्ता भेजा जाता है और उसके के रूप और वहां के प्लान्ट्स के रूप में माल तैयार किया जाता है। यह बिल्कुल अनइकोनोमिक बात है। कच्चा माल किसी जगह पैदा हो और उसको मेनुफेक्चर किसी दूसरी जगह किया जावे, यह नहीं होना चाहिये। होना यह चाहिये कि जहां तक सम्भव हो जिस जगह कच्चा माल उपलब्ध हो, वहीं मेनुफेक्चर होना चाहिये।

अभी हमारे देश में बड़े बड़े प्रोजेक्टस बन रहे हैं। उनकी वजह से बिजली भी यहां काफी मात्रा में उपलब्ध हो सकेगी तो हम इस बिजली की सहायता से जगह जगह कारखाने खोल सकते हैं और बिजली की सहायता से कच्चा माल चाहे खनिज हो चाहे खेत से उत्पन्न होने वाला हो, हम ऐसे माल के लिये वहीं पर कारखाने खोल सकते हैं और कोयला और तेल का प्रश्न बहुत कुछ बिजली की सहायता से हल हो सकता है तो इस पंचवर्षीय योजना में यह बात स्पष्ट होनी चाहिये कि माल तैयार करने के लिये कारखाने उस स्थान में अवश्य खोले जायेंगे, जहां कच्चा माल उपलब्ध हो।

[रावत श्री शम्भूसिंह]

मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इसे अच्छी तरह से देखने पर भी यह नहीं जान पाया कि डिफेन्स पर सरकार क्या खर्च करने जा रही है। हालां कि डिफेन्स रेगुलर एक्स-पेंडिचर है। मैं समझता हूँ कि हमारे देश को सब तरफ से सुरक्षित बनाने के लिये डिफेंस पर काफी खर्च करना चाहिये और इसके लिए आर्सनल इस वख्त मौजूद हैं। ज्यादा आर्सनल जगह जगह खुल सकते हैं शस्त्र अस्त्र अच्छे बन सकते हैं और आधुनिक समय की चीजों की जानकारी पूरी तरह से होनी चाहिये इस लिहाज से हमें दूसरे देशों का मुंह देखना पड़े और अपनी आवश्यकता का समान खुद बना लेवें। इस दृष्टि से भी डिफेंस पर काफी प्रोवीजन रखना चाहिये और भारतवर्ष में जितनी भी सैनिक जातियां (मार्शल रेसेज) हैं उनका संगठन करने के लिए कुछ न कुछ योजना हमारे सामने होनी चाहिये ताकि हमारे देश के लिए जो द्वितीय पंच वर्षीय योजना बनाई गई है वह शांति के साथ पूरी हो सके। यह शांति शस्त्रों से कायम होगी फिर शास्त्रों द्वारा तरह तरह की विद्याओं में निपुण होकर हम काफी उन्नति कर सकते हैं। तो मैं अनुभव करता हूँ कि डिफेंस पर काफी मात्रा में व्यय की तजवीज होनी चाहिये।

इसके बाद मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ सरसरी तौर पर कि सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान है वह संतोषदायक प्रतीत होतो है, पर फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में जिन तरीकों से अपव्यय होने का मौका मिला है उन पर इस सेकिन्ड ईयर प्लान में गंभीर नियन्त्रण होना चाहिये ताकि जो पैसा जिस काम के लिये रखा गया है वह पूरा का पूरा उसी काम पर लगे और उस पैसे का किंचित मात्र भी अपव्यय तथा दुरुपयोग न हो सके।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय उपाध्यक्ष, सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान पर अभी कुछ माननीय मित्रों ने अपने विचार प्रकट किये। फर्स्ट फाइव ईयर प्लान को खत्म करके इस दूसरे दरवाजे के द्वारा हम उस स्वराज्य की ओर जाना चाहते हैं कि जिसकी हम स्वराज्य के बाद कल्पना किया करते थे। जहां तक फर्स्ट फाइव ईयर प्लान का सवाल है वह हमें कई तरह के पाठ पढ़ाती है; जो कुछ वहां भूलें हुई, जो कुछ खामियां रहीं, काम करने में जो देरी हुई, उनके कारण हमें मालूम हैं और जिनके कारण हमें मालूम नहीं हैं उनके कारण हमें मालूम करना है और जितना रुपया खर्च किया गया है, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता माननीय मित्र ने कहा सही तरह से सही जगह खर्च हुआ या उसका वेस्टेज हुआ, ये सब ऐसी चीजें हैं जिन पर सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान पर अग्रसर होते हुए हमें विचार करना है।

फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में सरकारी और गैरसरकारी मशीनरी ने हाथ बंटाया, किस हद तक उस राष्ट्रीय यज्ञ में भाग लेते रहे और आगे चलने वाले सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान में वह किस हद तक सफल होंगे, यह सब विचार करना है। यह एक ऐसी बात है जिसको नहीं भुलाया जा सकता कि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान को पूरा करने के बारे में हमारे आजाद देश के हर एक आदमी को सेनानी के रूप में काम करना है और उसी तड़पन के रूप में काम करना है जैसे एक्च्युअल वार

[श्री श्रीदास गोयल]

फील्ड में एक सिपाही अपने हथियारों के साथ तैयार रहता है। यदि इसके लिये हमें किसी प्रकार की तैयारी करनी हो, यदि किसी प्रकार की कुर्बानी करनी हो तो उसके लिये सर्वस्व देकर भी तैयार रहें। अगर इस लगन के साथ काम किया जाय तो हम ४८०० करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे है, इससे हम भारतवर्ष में दूध की नदियां बहाने का स्वप्न पूरा कर सकते हैं, दूध की नदियां बहा सकते हैं जिस प्रकार कि भगवान् कृष्ण के समय में बहा करती थीं। इससे हम उस राम राज्य का स्वप्न पूरा कर सकेंगे जो कि त्रेतायुग में था। इसके लिये हमें सब को चाहे, मन्त्री महोदयी हों, चाहे इस सदन के एम. एल. एज. हों, सेक्रेटरीज.हों, और किसी प्रकार के सरकारी कर्मचार हों, चाहे जनता के कार्यकर्ता हों, सब को ज्यादा से ज्यादा जुट कर बिना किसी प्रकार की खुदगर्जी की भावना के योग देकर अपने कर्त्तव्य का पालन करें तो हम वही नक्शा पेश कर सकते हे कि बिना किसी प्रकार की गड़बड़ी के, बिना किसी खून खच्चर के हमने आजादी प्राप्त की, उसी तरह बिना किसी प्रकार की गड़बड़ी के लैंड रिफॉर्म्स के एक्ट पास हो जाने पर भी जमीन की समस्या है, यातायात के साधन नहीं हैं, शिक्षा के लिये साधन नहीं हैं और इसी प्रकार की और और समस्याएं हैं, गड़बड़ियां हैं उनको बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। यदि हममें यह भावनाएं पैदा हुई तो हम दिखा देंगे कि रूस ने कमाल दिखाया पर कितने खून खच्चर के बाद, चीन ने कमाल दिखाया पर हिंसा के द्वारा परिवर्तन हो गया, पर हम यहां पर भाई चारे, मित्रता और प्रेम के द्वारा सरकारी और गैरसरकारी मशीनरी को एक करके परिवर्तन ला रहे हैं।

हम आशा करते हैं कि हमारे मन्त्री महोदय इन योजनाओं को पूरा करवाने के लिये जागरूक रहेंगे और इन्हें ए. बर ब्यू.रो मानकर और यह मान कर और यह मान कर कि यह राष्ट्रिय जिम्मेदारी है और यह उस स्वराज्य को ओर ले जाने वाली है, जिसकी कल्पना हम किया करते थे, जिसके स्वप्न हम देखा करते थे, पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। इस ४८०० करोड़ रुपये का अच्छी तरह से खर्चा हो गया तो तृतीय पंचवर्षीय योजना हमारे लिये बड़ी आसान हो सकती है।

मनुष्य के जीवन के लिये कई उसूल हैं जिनके पूरा होने पर सुख प्राप्त कर मनुष्य किसी भी प्रकार गड़बड़ी करने की कल्पना नहीं करता। मनुष्य रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा और सस्ता एवं जल्दी न्याय, इन सात आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये गड़बड़ी करता है, यदि इस योजना के द्वारा मनुष्य की इन सात आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तो मनुष्य गड़बड़ी करने की कल्पना भी नहीं करेगा। फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में जो खामियां रही हैं उन्हें हमें दूर करना होगा तभी हमें कामयाबी मिलेगी और हम मनुष्य की इन सात आवश्यकताओं की पूर्ती कर सकेंगे। इस राजस्थान का इतिहास त्याग और बलिदान का इतिहास रहा है और हम अब भी ऐसा ही उदाहरण पेश करेंगे कि इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो हमें हमारा भाग मिला है उससे हम ज्यादा कर के बतायेंगे।

[श्री ओंकारदास गोयल]

माननीय उपाध्यक्ष, इसके साथ साथ मैं कुछ और बातें अर्ज करना चाहता हूं। मैंने शिड्यूल देखा, सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान में जो भी व्यक्ति इस शिड्यूल को देखे तो उसे प्रसन्नता होनी चाहिये, इस शिड्यूल के पहले बहुत बड़ी भावना है और वह यह है कि सोशलिस्टिक पेटर्न के आधार पर देश का निर्माण करने के लिये इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया है। और इसका खास मतलब है असमानता को मिटाना, भेदभाव को मिटाना, जमीन, दौलत, हर प्रकार की प्रगति के बारे में जो असमानता है, शिक्षा और स्वास्थ्य इन बातों के बारे में जो असमानता है, उसको मिटाना।

मैं अर्ज करू कि इसके ३५ पेज पर अलग अलग तरीके से रुपये रखे हैं, यह हर एक भारतवासी का कर्त्तव्य है कि इस धन राशि का ठीक समय पर सदुपयोग हो और इसके साथ ही बहुत सी धन राशि जनता से इकट्ठी करना है। जिस प्रकार घर में कोई बीमार हो जाता है तो उसको दवा दारू देने के लिये सभी रुपया खर्च करते हैं, अपनी व्यक्तिगत बात के लिये रुपया खर्च करते हैं, ठीक उसी तरह से सब भारतवासियों के दिमाग में यह भावना पैदा हो जाय कि हमारे राष्ट्र की तरक्की तभी होगी जब कि हम पैसा देंगे। हम मीटिंगों में बातें करते हैं पर जिस तेज रफ्तार से गांव गांव में इस लहर को फैलाना है वह नहीं फैला सके हैं। इस लहर को फैलाने के लिये ज्यादा क्रियाशील होना है। जो आदमी इसमें रुपया देगा वह रुपया दे कर यह महसूस करेगा कि इस यज्ञ में रुपया दिया है तो तन मन धन से सहायता करू। इस तरह की भावना हम, इस तरह की लहर हम आम लोगों के दिलों में पैदा कर सकें तो यह सब फंड्स आसानी से इकट्ठे हो जायेंगे।

अब मैं कुछ ऐसी बातें निवेदन कर देना चाहता हूं जिनका कि ग्रामीण लोगों की कठिनाईयों से ताल्लुक है। हमारे सवाई माधोपुर के पास खिलजीपुर कस्बा है जो रणथम्भोर के पास है। वहां आलू की पैदावार बढ़ाने के लिये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने प्रयत्न किये और इसके फलस्वरूप आलू कि बहुत ज्यादा पैदावार हुई पर पैदावार होने के बाद एक आना सेर का आलू का भाव हो गया, पैदावार तो खूब हुई पर मार्केट नहीं था, इससे लोगों को हतोत्साहित होना पड़ा। सवाई माधोपुर इलाके में बीस पच्चीस साल पहले गन्ना बिल्कुल पैदा नहीं होता था पर सरकारी कर्मचारियों ने प्रयास किया और आज वहां सैकड़ों मन गन्ना पैदा होता है पर बहुत सा गन्ना बेकार चला जाता है। गन्ने की उपज के लिये जहां इतना गन्ना पैदा है उसके लिये इन्डस्ट्रीज पैदा करें, मार्केट नही हो तो मार्केट पैदा करें, कूलर्स की व्यवस्था करें ताकि वह माल खराब नहीं हो। खेती में अच्छी उपज होती है पर उनको अच्छा पैसा नहीं मिलता है तो उनको हतोत्साहित होना पड़ता है, तो हमको इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना है। मैं समझता हूं कि एग्रीकल्चर में जो काम होता है उसमें भी इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट का सम्बन्ध हो तो काम ज्यादा अच्छा होगा।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना जरूरी मानता हूं और जैसा मैंने पहले शिक्षा के सुधारों के सिल सिले में अर्ज किया था कि यदि देश को आगे बढ़ाना है तो हम सब को विद्यार्थियों के

[श्री श्रीदास गोयल]

चरित्रों को ऊंचा उठाना चाहिये। और लोंगो के चरित्र को भी ऊंचा उठाना चाहिये जिस देश का चरित्र अच्छा है उस देश का यज्ञ सफल होगा और चरित्र बल के सामने क्या हाईड्रोजन बम्ब और क्या एटम बम्ब किसी की भी ताकत नहीं कि कुछ भी बिगाड़ सकें। और यही हमारे देश का आत्म-बल है जिसने हमारे देश को हजार वर्षों की गुलामी से मुक्त कराया और आज हम अपने देश की उन्नति के लिये, सेवा के लिये सीना तान कर योजनाएं बना रहे हैं और काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि एज्युकेशन में और सोशियल सर्विसेज में खास तौर से चरित्र बल पर ध्यान दिया जाना चाहिये। क्योकि हमको गांवों में रहनेवाले, कस्बों में रहनेवाले, शहरों में और नगरों में रहने वाले विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण करना है और इसके लिये खास तौर थोड़ा रुपया इधर मार्क रख कर देखें कि इसका किस तरह से उपयोग होता है। हम राजस्थान के निवासियों की नब्ज टटोलें कि वास्तव में कितना ऊंचा उठा सकते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि आज के विद्यार्थी कल के नागरिक होंगे और देश की जिम्मेदारियों को संभालेगे । देश की सुरक्षा, देश की उन्नति और देश के हित की बागडोर सब उनके हाथ में आवेगी। इस लिये यदि हम शिक्षा के द्वारा उनके चरित्र को अच्छे ढांचे में ढालने के लिये कोई ठोस कदम उठा सकते हैं तो उठाना चाहिये और यदि हम उस चीज को इगनोर करते हैं तो मैं यह कहूंगा कि हम बहुत बड़ा अन्याय करेंगे। मैं आशा करता हूं कि हमारे माननीय संबन्धित मंत्री कृपया कम से कम इसकी ओर कुछ संकेत करेंगे ताकि हम उस पर सोच सकें और जो हमें द्वितीय पंचवर्षीय योजनामें सफलता की ओर ले जाने वाला है उसकी तरफ ध्यान दें। इतना ही निवेदन करूंगा और आपका अधिक समय नहीं लूंगा। लेकिन मैं यह जरूर कहूँगा कि जिस किसी व्यक्ति ने इस द्वितीय पंचवर्षीय योजन को सफल बनाने में ५० प्रतिशत सहयोग दिया तो उसने साधुता का कार्य किया और जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसके लिए दिया उन्होंने साइलेन्ट वर्कर की तरह आगे बढ़ कर काम किया। लेकिन जब हम उसके आंकड़े देखते हैं, हिस्ट्रीशीट खोल कर देखते हैं तो हम कहेंगे कि हम उन्हें सच्चे नागरिक बनाने के लिए जा रहे हैं, संविधान में उनको सुविधा दी जा रही है। हम उन लोगों को जिनको पहले स्वाधीनता नहीं थी, उनको नागरिक बनाने के लिए कोशिश की जा रही है और इसके लिए हमें खुशी होनी चाहिये। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जो डिपार्टमेंट इस कार्य को इम्पलीमेंट करने जावे और जो एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने वाले है वे भी कदम दर कदम साथ चले और सहयोग दें और अपने को इस ढांचे में डाले कि वे पब्लिक के साथ काम कर सकें तो ज्यादा अच्छा होगा। जनता को मालूम होना चाहिये कि जो काम किया जा रहा है उसमें जनता का पैसा बरबाद नहीं होगा। मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि यहां जयपुर में एक व्यक्ति को मशीन के लिये १६ हजार पर रिलीफ मिला। उसके कोई मशीन वगैरा नहीं मंगाई वह सरकार का १६ हजार रुपया यों ही गया न मालूम कहां गया ? सरकार ने कस्टम ड्यूटी में भी छूट दी। वह लीज भी १६००० का सरकार के पास नहीं आया। वह इन्डस्ट्री आज बन्द पड़ी है। इससे कुछ आदमियों का रोज-गार चलता। मैं उस व्यक्ति का नाम बताना नहीं चाहता। राजस्थान सरकार का पैसा ला पता। तो ऐसी स्थिति में सरकार को यह देखना है कि जो रकम खर्च करने वह जा रही है वह वास्तव में

[श्री श्रीदास गोयल]

खर्च होती है या नहीं जिसके लिये वह दी जा रही है। हमको यह देखना है कि हमको कोई बेवकूफ तो नहीं बना रहा है। अगर ऐसा करता है तो फिर पैसा तो फालतू जाएगा ही और तेल तो तिल्लों से ही निकलेगा और रुपया तो हमको पब्लिक से ही लेना है और अगर हमारा क्रेडिट ठीक होगा तो हमें ज्यादा से ज्यादा रुपया जनता से मिल जावेगा और अगर पब्लिक यह सोचेगी कि रुपया इस तरह से रुक जाता हैं और बरबाद हो जाता है तो हमको रुपया लानें में मुश्किल आएगी।

इसके अलावा सभी लोगों को इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने में श्रमदान, संपत्तिदान और शारीरिक दान देना चाहिये। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री धूलजी भाई भावसार—माननीय उपाध्यक्ष, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में विचार करने के लिये जो प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। यह पंचवर्षीय योजना भारत सरकार ने इसलिये बनाई है कि हमारे देश में जब गुलामी थी, हमारे देश के उद्योग धन्धों को जिस गवर्नमेंट ने प्रायः नष्ट कर दिया था और हमारे देश में उससे बेरोजगारी और बेकारी बढ़ गई उसको मिटाने के सिद्धान्त को ध्यान में रख कर इस देश के निर्माण के लिये कदम भारत सरकार ने उठाया है और इसी लिये पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया है। पंचवर्षीय योजना का मतलब यह है कि देश में जो असमानता बढ़ी हुई है जिससे गरीबी और अमीरी में भेदभाव है उनके बीच में जो शोषण होता है, मजदूरों और उनके मालिकों में भेद भाव होता है उसको मिटाने का है। अगर आप देखेंगे तो देश में जरुरी काम जो हमारे लिये लाभदायक हैं पंचवर्षीय योजना में होने जा रहे हैं। मौजूदा समय में देश में असमानता इस हद तक पहूंच गई है कि जो महनत करनेवाले हैं वे भूख से तडफते हैं उनके लिये पढ़ने और पहने को और यो कहिये कि उनके लिये किसी तरफ की सुविधा नहीं और यहां तक कि पिछड़े हुए इलाकों में यह विशेष कर देखा जाता है कि उनको कोई सुविधा प्राप्त नहीं है। कस्बों और शहरों में सब तरह की सुविधा आम जनता को मिल सकती है। इसलिये इस सारी स्थिति को समान स्तर पर करने के लिये यह पंचवर्षीय योजना देश को ऊंचा उठाने के लिये इसका निर्माण हो रहा है।

इस योजना को लेकर देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश के अन्दर समान स्तर कायम हो सके और लोगों का सुखी जीवन बनाया जा सके। हम जब इसी दृष्टिकोण से राजस्थान के उन पिछड़े हुए इलाकों को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह दृष्टिकोण सम्पूर्ण नहीं हो पाया है। इसलिये आदिवासी एरिया के लियेजैसा कि मुख्य मंत्रीजी ने बताया बेकवर्ड एरिया की ओर विशेष ध्यान देने की बात बताई है इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे पिछड़े हुए इलाके में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा भील लोग और आदिवासी

[श्री धूलजीभाई भावसार]

जो उदयपुर डिवीजन में निवास करते हैं उनके स्वास्थ्य के लिये, उनकी शिक्षा के लिये आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति के लिये, कितनी दिक्कतें पड़ती हैं, उनके आवागमन के साधन अपने एक दूसरे के गाँवों में जाने के लिये उपलब्ध नहीं है, सड़कों का हाल आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सड़कों का काम हुआ है वह बहुत ही कम हुआ है, एक एक वर्ष में एक एक माइल सड़क बनी है जैसे बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ रोड बनाई गई है वह पांच वर्ष में केवल पांच, छ माईल ही बन पाई है। दूसरी बांसवाड़ा से सागवाड़ा तक जो रोड बनाई जा रही है वह भी पांच साल में केवल पांच मील ही बन पाई है, इस तरह का रोड का कार्य प्रथम पंचवर्षिय योजना में धीमी प्रगति करता रहा है खास कर के आदिवासी इलाके में। जिन आदिवासी किसानों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, दूसरों के समान स्तर पर लाना चाहते हैं, जिस रफ्तार से आज कार्य की प्रगति हो रही है उसको देखते हुए पांच दस वर्ष में नहीं बल्कि पचासों वर्षों में जाकर उनका जीवन इस स्तर पर आ सकेगा इसलिए मैं सरकार को निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछड़े हुए इलाके में और आदिवासियों के लिये उनके स्वास्थ्य के लिये उनकी शिक्षा के लिये उनके यातायात के मार्गों की ठीक व्यवस्था के लिये, शिक्षा भवन निर्माण कार्य आदि किये जावेंगे। यह सरकार की योजना है कि जो कुछ भी ग्रामीण इलाके में खर्च किया जाय उसका एक तिहाई हिस्सा ग्रामीण लोगों से लिया जाय केश के रूम में। इस संबन्ध में मेरा यह निवेदन है कि जो ज्यादा इलाके गरीब हैं जो अपने खाने तक के लिये मुहताज हैं जिनको पूरे पेट भर खाने तक को नहीं मिलता वे निर्माण कार्यमें किस प्रकार लगेंगे ? आज जिस किसी कस्बे से दो हजार या पांच हजार रुपया वसूल करना है तो यह इनकी गरीबी को देखते हुए उस कस्बे से इतनी रकम वसूल करना मुश्किल है, और खासतौर से ऐसे एरिया जिसे बेकवर्ड एरिया कहते हैं वहां के लोगों के लिये हमें भारत सरकार से निवेदन करना है कि पैसा न लगा सके उन्हें सब साधन उपलब्ध किये जायं उनके लिये शिक्षा के साधन उपलब्ध किये जायं खेती के साधन बनाये जांय डिस्पेन्सरीज और जीवन के लिये जो उपयुक्त सामग्री हो वह उनके लिये जुटाई जाय। जब तक यह व्यवस्था नहीं होगी वहां का कार्य आगे बढ़ने में कठिनाई रहेगी। मैं देखता हूँ कि प्रथम पंच वर्षीय योजना में देहातों में जो काम हुआ है यह वहां के आदिवासी भाइयों में जो कुछ काम हुआ है उनमें कुओं के निर्माण का कार्य हुआ है, इसके अलावा स्कूल का काम भी हुआ है। यह ठीक है कि बड़े बड़े कस्बों में किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक है, वहां सन्तोष हो सकता है लेकिन आदिवासी क्षेत्र में अब तक वे गरीब नहीं पनप पाये हैं, वे अभी तक गरीब हैं, और वहां की हालत भी बहुत शोचनीय है इसलिये मेरा यह निवेदन है कि बेकवर्ड एरिया में ऐसे लोगों का स्तर ऊंचा उठाने के लिये सरकार के लिये यह आवश्यक है कि पूरी सहायता देकर निर्माण कार्य और विकास कार्य ठोस रूप में किये जा सकें।

आप देखेंगे कि इन लोगों को हर तरह से दिन रात आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध करने के लिये, उनको बेचने के लिये, कितनी कठिनाई होती है। एक गांव से दूसरे गांवमें जाना उनके लिये सुलभ नहीं होता है, उनको इसके लिये कई तरह की यातनायें सहनी पड़ती हैं। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि जहां हम बड़े बड़े कस्बों के लिये लाखों और करोड़ों रुपया व्यय कर रहे हैं, बडी बडी योजनाओं में खर्च कर रहे हैं, वैसे ही बड़े बड़े शहरों की जनता शिक्षित है, वह इन रुपयों

[श्री धूलजी भाई भावसार]

का आसानी से लाभ उठायेगी और तरक्की पर पहुँचेगी। लेकिन मैं देखता हूं आदिवासी जो लोग हैं वे पिछड़े हुए हैं, वे ऐसे इलाकों में रहते हैं जिस ओर कभी भी पहले ध्यान नहीं गया उनके लिये सरकार को एक विशेष प्रकार से विचार करना चाहिये जिससे वे लोग किस तरह से जल्दी से जल्दी दूसरे लोगों के समान स्तर पर अपने आपको ला सकें। इसके लिये सरकार को विचार करना चाहिए। और इसके लिये भारत सरकार के समक्ष सुझाव पेश करने चाहियें। ताकि बेकवर्ड एरिया में रहने वाले लोगों को समान स्तर पर लाया जा सके। और जो कुछ भी बेकवर्ड एरिया के लिया खर्च किया जाय वह पूरा का पूरा सरकार द्वारा ही खर्च किया जाय, इस में से कुछ भी इन इलाकों से रहने वालों से न लिया जाय। वहां पर ग्रामोद्योग एवं कुटीर उद्योग चल सकते हैं, वहां पर खनिज पदार्थों की बहुतायत है इसलिये वहां पर यह उद्योग चालू हो सकते हैं, शिक्षा दी जा सकती है वहां के लोग खेतीहर हैं काम अपना खुद कर लेते हैं इस तरह से साल भर में छ महिने बेकार रहते हैं, यदि कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाय तो वहां के किसान हमेशा के लिये स्वावलम्बी बन सकते हैं। हमेशा के लिये अपने पांवों पर खड़े हो सकते हैं और अपना जीवन यापन ठीक प्रकार से कर सकते हैं। उन लोगों को न बड़ी मशीनरी की आवश्यकता है और न बड़े २ उद्योगों की ही आवश्यकता है। उनको अपनी आजीवीका चलाने के लिये छोटे छोटे कुटीर उद्योग और जीवन के लिये आवश्यक साधन आवश्यक वस्तुओं को उपलब्धी हो जाय तो वे अपने आप को स्वावलम्बी बना सकते हैं और इस तरह से राजस्थान के निर्माण और देश के निर्माण में वे बहुत कुछ हिस्सा ले सकते हैं। मैं राजस्थान सरकार का इस ओर विशेष कर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आदिवासी जो एरिया है उसके लिये किसी प्रकार का पैसा उन लोगों से न लेकर भारत सरकार को इस बारे में वे सुझाव पेश किये जांय, जहां हम लाखों करोड़ों रुपया आदिवासियों के लिये खर्च कर रहे हैं उसमें विशेष ध्यान रक्खा जाना चाहिये। उसके साथ साथ एक ऐसा टोस सुझाव पेश किया जाय, एक ऐसी टोस प्रणाली बना ली जाय जिससे उनके लिये शिक्षा का प्रबन्ध, स्वास्थ्य का प्रबन्ध और जीवन के लिये जितनी भी आवश्यक वस्तुयें हैं उन सब के लिये भारत सरकार अपनी ओर से अधिक पैसा खर्च करे ताकि इन लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा सके और दूसरों लोगों के जीवन स्तर पर लाया जा सके।

श्री भैरोंसिंह—[दांता रामगढ़] माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी पंच वर्षीय योजना हमारे सम्मुख कई दिनों से आई हुई है। इस संबन्ध में इस सदन में अबतक जो चर्चा हुई सदन के बाहर भी कई बार इस दूसरी पंच वर्षीय योजना के संबन्ध में कई चर्चायें सुनने को मिलीं। एक प्रजातन्त्री आधार पर चलने वाली सरकार भविष्य के लिये कोई योजना तैयार करती है वह इस प्रकार की योजना तैयार कर सकती है या नहीं यह प्रश्न इसके मूल में विचाराधीन रहता है। इस देश के कई अच्छे अच्छे नेताओं ने इस बात की राय जाहिर की है जिस डेमोक्रैसी में पांच साल के लिये एक सरकार आती है वह सरकार अगले पांच वर्ष के लिये कोई योजना निर्धारित कर सकते हैं या नहीं। आज कोई यह कहे वह सरकार इस प्रकार की योजना नहीं बना सकती या इस प्रकार की योजना बना सकती है, ये दोनों पहेलू ऐसे हैं जिन पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक है।

[श्री भैंरू सिंह]

पहली पंचवर्षीय योजना बनी उस समय चुनाव होने के पहले ही जो सरकार विद्यमान थी उसने उसका ड्राफ्ट बनाया। इसके बाद में आम चुनाव हुए और ३१ तारीख को उस योजना का समय समाप्त हुआ। एक तारीख से दूसरी योजना लागू हुई और यह योजना आगे के पांच वर्षों के लिये लागू होती है वैसी सूरत में आज की सरकार को आगे के पांच वर्षों के लिये कोई योजना बनाने का अधिकार है या नहीं यदि इस पहलू को हम ठीक ढंग से सोचें तो दोनों परिस्थितियां हमारे सामने हैं। एक यह भी बात है कि कोई भी प्रकार की देश में कोई सामूहिक कार्यवाही की जाती है जनता के और देश के उत्थान के लिये तो इसके लिये एक योजना भी आवश्यक है और वह योजना अगर थोड़े थोड़े समय के लिये होगी तो बहुत मुमकिन है कि बड़े बड़े कार्य शायद सम्पूर्ण न हों। दूसरा पहलू आता है कि क्या एक समय में चलने वाली डेमोक्रेटिक सरकार आगे की सरकार के लिये कोई योजना बनाकर उस पर वह योजना जबर्दस्ती थोपने का भी कोई काम कर सकती है। मैं समझता हूं कि इसमें एक प्रकार की आपत्ति है और वह यह है कि आज की सरकार अपने जितने भी विरोधी दल के सदस्य हैं या विरोधी पक्ष की संस्थाएं हैं, विरोधी भावनाओं को लेकर चलने वाली संस्थाएं हैं, प्रदेश के निर्माण के सम्बन्ध में कोई भी योजना हम बनावें तो उसके अन्दर उनकी भी पूरी सलाह लें और उनसे भी जानकारी हासिल करें। पूरी जानकारी हासिल करने के बाद यदि यह सरकार और इस सरकार के जितने भी विरोधी दल हैं वे सब देश के निर्माण के लिये योजना बनावें तो वह वास्तव में डेमोक्रेटिक सरकार के लिये शोभाजनक बात होगी। और यहां इस बात का अभाव है। यह आज की सरकार अगली सरकार के लिये योजना बनावे और उसमें विरोधी दल के सदस्यों की या कि विरोधी दल के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व नहीं हो तो इस प्रकार का स्टैप अनडेमोक्रेटिक है; ऐसा मैं समझता हूं।

इसका सबसे बड़ा नुक्स यह होगा कि इस काम में, राष्ट्र के इस निर्माण कार्य में जितना जनता का सहयोग अपेक्षित होता है वह नहीं मिलता और इस के अभाव के कारण कई स्कीमें ऐसी रह जाती हैं अधूरी जिनको हमें यहां समय में पूरी करना है।

इसका दूसरा पहलू भी है। आज की सरकार कोई योजना बनावे, टैक्सों के प्रोपोजल रक्खे और वे पांच साल तक निरन्तर चलते रहें और हो सकता है कि आज की सरकार ऐसा समझती हो कि उन आगामी वर्षों में भी हमारा ही राज रहेगा पर यह कोरी कल्पना ही है। इस कोरी कल्पना के आधार पर हम मूल सिद्धान्त के आधार पर ही जानबूझ कर कुठाराघात करें तो यह तो अप्रजातांत्रिक बात होगी। ऐसी सूरत में हमारा परम कर्तव्य हो जाता है कि डेमोक्रेसी के नाम पर डेमोक्रेटिक शासन को चलाने के नाते इस प्लान में विरोधी दल के नेता को और विरोधी दल की संस्थाओं की राय को पूरा पूरा मौका दें प्रकट होने का और उनको स्वीकार करने का। पूरा दुर्भाग्य है कि जो स्वरूप इस योजना का हमारे सामने आया उसको पहले भी इस सदन में डिस्कस किया गया था और आज जो ड्राफ्ट आया वह भी ऐसा कि जिसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते वह ड्राफ्ट आज हमारे सामने वाद विवाद के लिये आया है। अगर हम एक

[श्री भैरूंसिंह]

अच्छा सुझाव भी देते हैं जिससे राष्ट्र के निर्माण कार्य में अच्छी सहायता प्राप्त हो वह भी स्वीकार नहीं होने वाला है क्योंकि वह भी मजबूर हैं, ड्राफ्ट बन गया है, टारगैट्स तैयार हो गये हैं। कहा यह जाता है कि यह सारी योजना फ्लेक्सिबिल है। एक एक साल के बाद में जो खामियां अनुभव के आधार पर नजर आवेंगी उनको एक एक साल के बाद में एडजस्ट कर देंगे पर जो मोटा रूप आपने अख्तियार कर लिया उसमें कोई परिवर्तन कर नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में कहूंगा कि बिना विरोधी दल के लोगों की राय के अगर आप इस योजना को बनाते हैं तो यह चीज अनडेमोक्रेटिक है। आगे के इन पांच वर्षों में फ्लेक्सिबिल होने के नाते उन स्कीमों का को एडजस्टमेन्ट हो उनमें विरोधी दल के जो भी सदस्य हैं या जो संस्थाएं हैं उनको अपनी जानकारी देने का पूरा अवसर दें।

यह योजना ४८०० करोड़ रुपयों को है। जितनी करोड़ की बनी है उसमें हर आदमी की यह इच्छा होती है कि आपने देश के निर्माण कार्य में जितना धन लगाया जावे उतना लगाया जावे लोगों का स्टैन्डर्ड आफ लिविंग जितना ऊंचा किया जा सके किया जावे, पर सारी की सारी चीजें हमारे रिसोर्सेज पर निर्भर करती हैं। जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनके आधार पर हम कोई यप्लानिंग करते हैं तो वह जनता के सहयोग को, प्राप्त कर सकने में सफल हो सकेगी। जनता का सहयोग उस स्थिति में अधिक से अधिक मिल सकेगा। पर इन ४८ सौ करोड़ का जो टारगैट है उनके रिसोर्सेज का पता लगाते हैं कि यह सारी योजना किस आधार पर बनी है, यह सारा पैसा कहां से आवेगा, तो पता लगता है कि यह सारी योजना ऐसे आधार पर बनी है जिसमें बिलकुल ही किसी प्रकार का कोई स्थापित्व नहीं है।

जहां ४८ सौ करोड़ की पूर्ति के बारे में टेक्सेशन का सवाल आता है कि स्माल सेविंग की बात आती है या कि जनता से लोन लेने की बात आती है, विदेशी सहायता की बात आती है फिर भी एक ऐसा अनकवर्ड गैप रहता है जिसके बारे में अभी तक कोई व्यवस्था नहीं कर सके, आगे कर लेंगे इसकी सम्भावना रह सकती है पर आज कोई निश्चित चीज नहीं जिसके आधार पर हम कह सकें कि जो रूप बन रहा है वह पूरा कर सकेंगे। लोन्स के बारे में माननीय उपाध्यक्षजी, इन चार वर्षों में हम जनता से १५० करोड़ का लोन ले चुके हैं और नई योजना में सात सौ करोड़ रक्खा है। यदि ठीक ढंग से सोंचे तो मैं समझता हूं कि इसके पीछे कोई लोजिक नहीं है। यदि जनता की ऐसी स्थिति हो गई है कि योजना के कारण से काफी समृद्धिशाली बन गई हो, उसका इकोनोमिक स्टेन्डर्ड काफी ऊंचा हो गया हो और इस कारण से उसके पास कोई सरप्लस मनी हो गया हो कि जो वह सारा सरकार को उधार दे देगी तो बात दूसरी है। पर मैं समझता हूं कि दिन ब दिन राजस्थान की ही नहीं देश भर के लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। ऐसी स्थिति में हम १५० करोड़ की ही सहायता दे सकने वाली जनता से यह ७०० करोड़ रुपये की सहायता पाने की उम्मीद करते हैं और इस आधार पर इस योजना की सफलता के स्वप्न लेते हैं तो यह आधार हमारा कमजोर ही साबित होगा।

[श्री भैंरूसिंह]

इसी प्रकार का हाल स्माल सेविंग के बारे में है। २०० करोड रुपये इकट्ठे किये पहली योजना के सारे अभियान में। अब हम आशा करते हैं कि ५०० करोड़ रुपये अगले पांच सालों में इकट्ठे कर सकेंगे। इस निरी कल्पना को देखकर आश्चर्य होता है और आश्चर्य के साथ दुख तो तब और हमारा बढ़ जाता है, जब हम यह देखते हैं, कि इन दो बातों के बारे में कोई विशेष प्रकार की टिप्पणी भी इस में नहीं देखने को मिलती है कि जिसके कारण हम यह समझें कि जनता में कोई विशेष प्रकार का इन्स्पायरेशन (प्रेरणा) हो गई है अपने देश की प्रगति करने के हित में और जिससे प्रेरित होकर वह जितना धन उसके पास है वह सारा का सारा धन सरकार को सौंप देगी। तो ऐसी स्थिति में मैं यही कहूंगा कि हम इस प्रकार की आशा से कि पैसा जनता दे देगी ऐसी बड़ी योजना बनावें तो आगे चलकर उसमें सफल हो सकेंगे कि नहीं इसमें हमें तो सन्देह उत्पन्न होता है।

इसी प्रकार से फॉरिन एड को आधार बनाया है। आजतक जो अमेरिका से एड मिलती रही है वह २०० करोड रुपयों की है। आज कल हम पत्रों में पढ़ रहे हैं आइजनहावर की स्पीच हुई है भारत को मदद देने के लिये चालीस करोड़ डालर की मांग की है। अब हम उम्मीद करते हैं कि वह पांच वर्षों में २०० करोड़ से बढ़कर ८०० करोड़ हो जावेगी। और उस हालत में जब कि आज के पहले पांच वर्षों में अगर मैं यह कहूँ कि भारत और अमेरिका की टर्म्स आज के मुकाबले में काफी अच्छी था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक तरफ तो हम विदेशी सहायता के ऊपर बड़ी आशा लगाये यह योजना बनावें और दूसरी तरफ आज जो टर्न्स रिलेशन्स हमारे इन विदेशी रिसोर्सेज के साथ चल रहे हैं उनको देखते हुए यह उम्मीद करें कि वह अधिकांश सहायता अब भी मिल जावेगी तो यह समझदारी का काम नहीं होगा।

अभी अभी अमेरिका के श्री डलेस पाकिस्तान जाकर आये। पाकिस्तान के बाद हिन्दुस्तान में भी वह आये। इस संबंध में भी बात चीत हुई। इस बात चीत के आधार पर उनके जाने के बाद पाकिस्तान की ओर से हिन्दुस्तान की सीमा के ऊपर जितने हमले हुए वह इस बात का संकेत हैं कि अमेरिका की फौजी सहायता के आधार पर पकिस्तान की इस प्रकार की हिम्मत हो सकती है कि उस हिम्मत के कारण हिन्दुस्तान को काफी परेशानी उठानी पड़े, और वह परेशानी दो तरीकों से होगी। उस परेशानी से बचने के लिए अमेरिका की तरफ से जिन बातों के आधार पर नीति निर्धारण करना है उन बातों की चकाचौंध में अमेरिका की सहायता द्वारा उसी प्रकार से गवर्नमेंट उनके सामने यील्ड करे और करना होगा या यह होगा कि अमेरिका की फौजी ताकत के ऊपर पाकिस्तान की सेना के सामने खड़ा रहकर अपने आपको समाप्त कर दें। हम शान्ति चाहते हैं। हम यह भी चाहते हैं कि हमारी नीति दोस्ती की रहे और कोई भी देश इस संसार में एक दसरे के ऊपर हमला करके कब्जा न करे। शान्ति का वातावरण बना रहे। दूसरी तरफ इन्हीं बातों की चकाचौंध में आकर उनकी बातों के आधार पर हमने यह रखा है। हम रुपये की कमी के कारण उनके सामने देखेंगे, रशिया और कोई दूसरे कंट्री की तरफ देखेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश की नीति यह हो कि दूसरे देश हमारे

[श्री भैरों सिंह]

उपर अंकुश रखें तो यह ज्यादा अच्छा नहीं है। हम मदद ले सकते हैं। मदद देने का काम उनकी तरफ का है। मदद किस प्रकार की कन्डीशन पर है वह काम देखने का उनका नहीं है हमारा है। वह मदद देते हैं; यदी वह कन्डीशनल सहायता देते हैं तो उनके लिए उचित हो सकता है लेकिन जहां किसी कंडीशन पर सहायता का लेने मामला है. यदि वह स्थिति बनती है तो इस प्रकार की सहायता लेना अनुचित होगा। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के आंकड़ों के आधार पर जो पंचवर्षीय योजना बनी है उस पंचवर्षीय योजना में हमें यह देखना पड़ेगा कि आगे चलकर हम किस प्राकार से इन आंकड़ों के आधार पर काम करने में समर्थ हो सकेंगे।

अब माननीय उपाध्यक्ष, इस बात के अलावा टेक्सेशन का प्रश्न आता है। टेक्सेशन के बारे में इस सदन में पहले भी काफी चर्चा हुई है। लोगों का ऐसा खयाल है कि टेक्सेशन इंक्वायरी कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी कि जो नेशनल इनकम देते हैं उसमें ७ परसेंट का हम टेक्स दे रहे हैं। हम टेक्स को बढ़ा कर नेशनल इनकम का २५ परसेंट तक का टेक्स नहीं देते हैं और योजना चल रही है उस वक्त तक स्कोप है टेक्स की मात्रा को बढ़ाने का। मैं मानता हूँ कि इस चीज के लिए टेक्स बढ़ाये जांय, लेकिन टेक्स बढ़ाने का आधार आर्थिक स्टेंडर्स से करना उचित होगा। लोगों के पास धन हो हम इस बात की चेष्टा करें। ज्यों ज्यों धन बढ़ता है उस धन के आधार पर टेक्स इम्पोज करें तो एक प्रकार से उचित व्यवस्था होगी, लेकिन हमारा इकानामिक स्टेंडर्ड नीचे गिरता जाय और टेक्स लगाने के आधार को सामने रखकर कि २५ पर सेंट तक लगा सकते हैं इसलिए टेक्स लगायें तो पंचवर्षीय योजना में काफी मदद मिलेगी और टेक्स बढ़ता रहे तो मैं समझता हूं कि वह एक प्रकार से अनुचित होगा। हमने पांच वर्षों में लोगों का २५ पर सेंट स्टेंडर्ड बढ़ाने की एक योजना बनाई है तो एक साल में ५ परसेंट हमारा स्टेंडर्ड बढ़ेगा और इस तरह से पूरे ५ ५ वर्षों में वह २५ परसेंट होगा। लेकिन आज यह सोचें कि हमारा यह स्टेंडर्ड अभी ५ वर्ष तो बीत गये और दूसरे पांच वर्ष आ रहे हैं इन दस वर्षों में अच्छा बन गया हो इस तरह की चीज मुझे जंचती नहीं है। मैं समझता हूँ कि दूसरों से लेकर यदि इसी तरह से स्टेंडर्ड को बढ़ायें तो ब्रिटेन के लोगों का जिस प्रकार का स्टेंडर्ड है उस स्टेंडर्ड को लाने में एक सदी लगेगी। इन सारी चीजों को दूर करने के लिए योजना बनायें तो योजना में रेपिड चेंजेज करना पड़ेगा जिन रेपिड चेंजेज के कारण देश को जो समृद्धशाली बनाना है, देश के लोग लोगों का स्तर ऊंचा करना है, तो स्तर ऊंचा करने में हमारे सामने किसी बहुमत का नाम आता है तो उसको छोड़ा जाय। यदि कोई नराजगी का प्रश्न आता है तो उस नाराजगी को छोड़ा जाय। इन सारी चीजों को सामने रखकर हमें काम करना पड़ेगा।

इस योजना को बनाने में ४ मूल बातें बताई गई हैं। पहली बात है कि लोगों का स्टेंडर्ड आफ लिविंग ऊंचा करना है। मैं समझता हूँ कि मूल में इसी बात में कमी है, एक जबरदस्त खामी है। पूज्य महात्मा गांधी ने इस बात का उल्लेख किया था। उनका हरिजन सेवक में इस बात का लेख था कि लोगों का लिविंग स्टेंडर्ड ऊंचा नहीं करना है, बल्कि स्टेंडर्ड आफ लाईफ

[श्री भैरू सिंह]

ऊंचा करना है। लिविंग और लाइफ में इन दोनों में पूज्य महात्मा गांधी के कथन के अनुसार एक विशेष प्रकार का अंतर है। लिविंग के साथ साथ लोगों को भौतिकवाद की ओर की लेजाना है। केवल मकान, कपड़ा, खाना, पीना, अच्छे भवन, सड़कें आदि से ही हम यह सोचें कि लोगों की आवश्यकताओं कि, उनके लिविंग की पूर्ति हो गई, तो मैं समझता हूँ कि वह एक प्रकार का अनुचित प्रयोग होगा। मनुष्य के अंदर मनुष्यता के लक्षण पैदा करें और उन लक्षणों के द्वारा मनुष्यता का स्टैंडर्ड पैदा करें तो वह उचित चीज होगी। मूल में ही इस बात की खामी रखी गई है, और स्टैंडर्ड आफ लिविंग को ऊंचा करने की जो चेष्टा की है वह मैं समझता हूं कि भारतीय संस्कृति और भारतीय परम्परा इन दोनों के प्रतिकूल है। जितने देश के बड़े बड़े नेता थे जिन्होंने आजादी की ज्योति इस देश के अंदर जगा रखी है उसके प्रतिकूल होगा।

तीसरा सिद्धान्त, माननीय उपाध्यक्ष, इसमें रखा है कि 'a large expansion of employment opportunities' मैं समझता हूँ कि हमारे विधान में इस बात का अधिकार दिया गया है कि हम बोल सकते हैं। हैं हम अपनी राय जाहिर कर सकते हैं पत्रों के द्वारा कर सकते या बोलकर कर सकते हैं, लेकिन इस विधान के अन्दर, जबरदस्त खामी रही है जिस खामी की ओर एक बार नहीं जनता के कई माननीय लोगों का ध्यान दिलाया था उसकी ओर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कमी नजर आती है। इसमें लिखी है, large expanison की बात। मैं मानता हूं कि भारतवर्ष जैसे देश में जो कि कर्मभूमि है इस देश में एक सिद्धान्त होना चाहिए कि हरेक को काम मिले जो सरकार भारत वर्ष की है वह नागरिकों को काम नहीं दे सकती है। सरकार चाहे कोई योजना बनाये, खुले तौर से हमारा मूलभूत सिद्धान्त किसी योजना का यह होना चाहिये। ५ वर्ष चले गये और अगले ५ वर्ष आ रहे हैं। भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी धन्धे पर पहुंचाया जाय, इस बात को सामने रख कर इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए चारों तरफ के रिसोर्सेज को जुटाकर लोगों को काम धन्धे पर पहुँचायें। तो उस योजना में आवश्यकताओं की पूर्ति की चीजों को पैदा करना है, सड़कें बनानी हैं, स्कूल के भवन का निर्माण करना है, इन चीजों के करने का जो तरीका है उनसे लोग बेकार रहें, भूखे रहें, नंगे फिरें और उनको कोई धन्धा नहीं मिले तो इन चीजों से भय है कि वह योजना पूरी निश्चित रुफल नहीं होने वाली है। उससे लोगों के अन्दर योजना और सरकार के प्रति कोई श्रद्धा पैदा नहीं होने वाली है। ८० लाख लोगों को धन्धा देने की बात इसमें कही गई है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी श्रीमन्नारायण अग्रवाल का एक लेख मैंने देखा था। उसमें इस बात का संकेत किया है कि कोई भी देश या भारतवर्ष जिसकी द्वितीय पंचवर्षीय में योजना में ८० लाख आदमियों को धन्धा देने की बात चल रही है उसी देश में ५ वर्ष के अन्दर एक करोड़ आदमी और पैदा हो जायेंगे। उन एक करोड़ आदमियों को धन्धा देना पड़ेगा। आज ३१ मार्च, १९५६, के पहले के जितने भी बेकार हैं उन बेकारों को धन्धे की कोई बात नहीं है। आज के दिन से इस योजना के अन्तिम दिनों तक नये बेकार एक करोड़ की संख्या में पैदा होने वाले हैं। हम उन ८० लाख लोगों को धन्धा दे सकें तो उसका मतलब यह है कि ५ वर्षों के अन्दर २० लाख बेकार

[श्री भैरूंसिंह]

और पैदा किये। पहले के थे वे तो थे ही, इन २० लाख लोगों का एडिशन और कराया तो उस योजना का मतलब क्या ? उस योजना का कोई मतलब नहीं है, जब तक उस योजना से सब लोगों को धन्धा नहीं देते हैं तब तक वह योजना सर्वांश में नहीं है। जो उल्लेख है कि लोगों को राहत दें वह इस योजना के द्वारा करना है। बहुत मुमकिन है कि कुछ लोगों को एम्प्लायमेंट मिले। भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को इस प्रकार से धन्धा मिल जाय उसका इसमें कहीं उल्लेख नहीं है।

इसके अलावा सबसे बाद के इसके सिद्धान्त पर आ रहा हूँ कि लोगों की असमानता को दूर करने के लिए, असमानता के बारे में जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातों का उल्लेख किया था। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इतना संकेत और करना चाहता हूं कि जहां हम इन्इक्वीलटीज को दूर करना चाहते हैं हमें उसमें मजबूत होना पड़ेगा। किसी के लिहाज मुलाइजे की जरूरत हो उनको सब को समाप्त करना पड़ेगा। उसमें जिन लोगों का इस प्रकार से एक्स्प्लायटेशन होता है उन बड़े बड़े लोगों की जिनके करने की ऐसी बात बनी हुई थी उन लोगों का एक्स्प्लायटेशन तुरन्त बन्द करके चाहे किसी सूरत में हो हम यह कर सकते हैं। तब तक इन्इक्वीलिटीज का नारा बेकार रहेगा और पूरा नहीं हो सकेगा।

पहले भी लोग इस प्रकार का नारा लगाते थे, यह नारा था कि ऊंच नीच का भेद नहीं रहेगा, उनका रिपीटिशन इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में है। पिछले पांच वर्षों में तरक्की की उसको देखें, लेन्ड रिफोर्म्स को देखें। जागीरें समाप्त की, राजाओं के राज्य समाप्त किये और जमीनें देने का सिद्धान्त बनाया, उसमें भी देखें इक्वलिटी नहीं है, बड़े बड़े ही बने रहे और गरीब २ ही। राजस्थान लेंड रिफोर्म्स की ओर संकेत करते हुए मैं कहूँगा कि राजस्थान में जो छोटे छोटे भू-स्वामी हैं, उनको चाहे छोटे जागीरदार कह दीजिये, उनको चाहे भोमिया कह दीजिये उनको जागीर रिजम्पशन एक्ट द्वारा गरीब से गरीब बनाने की कोशिश की है और उसी जगह में, सीकर जैसे हैं खेतड़ी जैसे हैं उनको करोड़पति बनाने की कोशिश की। हम दावा नहीं कर सकते कि पांच वर्षों में इनइक्वलिटी को दूर कर दिया और आगे के लिए यह पर्याप्त हो सकेगा, इसलिए इन इक्वेलिटी को दूर करने का स्लोगन स्लोगन मात्र ही न रह जाय लेकिन अगले पांच वर्षों में बता दें कि इक्वेलिटी का जो मुख्य सिद्धान्त था उसको पूरा किया है।

इस योजना में इस बात का भी संकेत है कि इसका मुख्य रूप कृषि है और प्रथम पंच वर्षीय योजना में कृषि की ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें करने में, कृषि द्वारा अनाज का उत्पादन बढ़ाने में केन्द्र ने धन राशि दी और उसके मुकाबले में इस योजना में कमी की गई है और इन्डस्ट्रीज डेवलमेन्ट में ज्यादा धन राशि उसने स्वीकार की है। ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार ही नहीं परन्तु भारत सरकार ने भी सोच लिया कि एग्रीकल्चर में किसी प्रकार की तरक्की करना बाकी नहीं है और

[श्री मैरूसिंह]

जो सूचना रखी है राजस्थान सरकार के प्लानिंग डिपार्टमेंट ने, "राजस्थान प्लानिंग डिपार्टमेंट" को इसको कुछ देखने का अवसर मिला है उसमें है पहली योजना कृषि और ग्राम विकास उसके आंकड़ों को देखने से पता चला कि:

१९५०-५१.	४८. ३७० टन आयात
१९५१-५२.	१, ०८, २६७ टन आयत
१९५२-५३.	१, १५, ००० टन आयत्त
१९५३-५४.	१, ००, ०००, टन आयत
१९५४-५५.	१, २०, ००० टन निर्यात हुआ।

निर्यात हुआ इस चीज को लेकर हमारी सरकार ने संतोष कर लिया कि कृषि की हालत ठीक हो गई है। मैं समझता हूँ कि यह सोचना ही गलती की पहले होल्डिंग की प्रवृति चल रही थी और किसी काश्तकार, साहुकार और जागीरदार को जाकर देखते तो अनाज की कमी नहीं थी। उस अनाज को इकट्ठा कर लेते थे, डिस्ट्रिब्यूशन करने से, अगर अनाज तकसीम कर दिया तो आयन्दा हम उसकी पूर्ति नहीं कर सकेंगे और वह होल्डिंग की मेन्टेलिटी कन्ट्रोल के कारण बनी हुई थी किन्तु कन्ट्रोल हटने के बाद उस मनोवृत्ति का परित्याग करना पड़ा और जो आयात करना पड़ा था वह इसी कारण था और जब कन्ट्रोल हटा और ५३. ५४ में जब कि आयात हुआ १ लाख टन अनाज तो ५३. ५४ को निर्यात आंकड़ा के आधार पर निर्यात माना तो कहने लग गये कि निर्यात कर रहे हैं। अगर इन आंकड़ा के आधार पर ही कृषि के सम्बन्ध में नीति निर्धारित करते हैं तो वह अच्छी नहीं है।

दूसरी बात जो है, मुझे हंसी आती है वह यह है, कि इसमें लिखा है कि भारत सरकार के स्टेटिस्टिकल एडवाइजर प्रो० माहोलानोबिस के अनुसार उत्तर पश्चिमी भारतमें, जिसका कि राजस्थान भी एक अंग है, खाद्यान्नों की खपत प्रति प्रौढ़ पुरुष ७ मन वार्षिक है, तो इन्होंने यह अन्दाज लगाया कि एक आदमी की ७ मन वार्षिक अनाज की खपत है। हमने एक लाख टन का निर्यात किया है और बा अनाज है उसको इस पर इस ढंग से मल्टीपलाई करें कि वास्तव में आगे जाकर बता दें कि निर्यात किया है। अगर आयात और निर्यात पर निश्चित योजना बनायी है कि इतना पैदा हुआ अनाज, इतना आयात और निर्यात किया गया, तो मैं स्पष्ट कहूंगा कि ये फीगर्स की चकाचौंध है वह गलत है और जनता को धोखे में डालने की है। फसल का अन्दाज पटवारियों से होता है, पटवारी गांव २ की पैदावार का पता लगा सकते हैं, गेंहू इतना पैदा हुआ, जौ इतना पैदा हुआ, चना इतना पैदा हुआ अगर उस पैदावार को प्रति आदमी ७ मन वार्षिक की खपत से मल्टीप्लाई करें तो लाखों का अन्तर आयगा। और पटवारी के आंकड़े के आधार पर है, गांवों में बैठा हुआ है. एक नक्शा रहता है, पूछ लेता है कि कितना पैदा हुआ, गेंहू कितना पैदा हुआ और जौ कितना पैदा हुआ, बाजरा कितना पैदा हुआ, मक्का कितना पैदा हुआ और जैसे चाहे लिखा

[श्री भैंरू सिंह]

देते हैं जो कि सही तौर पर आधारित किसी योजना बद्ध नहीं है, इस प्रकार के आंकड़ों के भूलावे में आकर करेंगे तो एक जबरदस्त गलती करेंगे और मूल भूत में उनको छोड़ दिया और आंकड़ों के आडम्बर में आकर यह कहेंगे कि कृषि की उन्नति हो चुकी है, मैं समझता हूँ कि अतिशयोक्ति होगी।

कृषि के संबन्ध में कई योजनायें बनायी, सिंचाई के साधनों के लिए योजनायें बनायीं, कुए बनाये, बीज और खाद का वितरण कराया, जो खाद के लिए फेक्टरी है, फरटीलाइजर है उस पर बल दिया और उस कारण जो दिक्कते हैं, भूमि के नाम पर होती हैं एक बीघा में जितनी पैदावार की शक्ति थी उनमें कम-से-कम पचास प्रतिशत ही हो पायी। मैंने अपने गांव का एक नक्शा तैयार किया है जहां मेरे गांव में पांच साल पहले जो पैदावार थी उसको आज की पैदावार से मिला कर देखें तो वह नहीं है। लोगों को ज्यादा जमीनें जरूर मिल गई है लेकिन जितनी जोत सकते थे जोती और कुछ में कैमिकल्स की आवश्यकता थी उनको वे केमिकल्स नहीं मिले, उनकी आवश्यकता को पूरी नहीं कर सके और जमीनों की पैदावार बढ़ सकती थी वह सारी की सारी शक्ति क्षीण हो गई और हमें यह कहा गया कि हम यह फरटीलाइजर तकसीम कर रहे हैं, फलां खाद से यह होगा, मूल में गलती है। आप चाहे तो एक्सपर्ट्स को बिठा दें राजस्थान की भूमि में ये जितने फरटीलाइजर्स हैं एक साल, दो साल या तीन साल कामयाब हो सकते हैं लेकिन चौथे साल में पैदावार कम होती है, राजस्थान के लिए तो सब से बडा खाद वही है जो पशुओं से होता है। पशुओं के कारण राजस्थान के लोगों का आर्थिक विकास होता था उस प्रश्न को दरगुजर किया गया और उस पोइन्ट को नहीं देखा गया। राजस्थान से गायें, भेड-बकरिये और जितने और जानवर है, जिनके आधार पर काम चलता था उनका कुल निकास हो रहा है और सरकार ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। राजस्थान के किसानों के पास असली खाद नहीं मिला और पैदावार छिन गई। माननीय उपाध्यक्ष, पशु खेती के लिए आवश्यक है, यह पशुपालन, खेती के साथ साथ मुख्य धंधा है, जिस पर खेती आधारित है वह है जानवरों की रक्षा का। मैं समझता हूँ कि राजस्थान बडा बदकिस्मत है। आज से पांच वर्ष पूर्व राजस्थान का कोई घर ऐसा नहीं था जहां राजस्थान के किसानों के पास पशुओं के चरने के लिए स्थान, जमीन न हो। लेकिन जितनी २ जमीनों पर कब्जा हुआ, जानवरों की चरने की चारागाह की जमीन पर भी कब्जा कर लिया गया और पशु रखने वाले जो व्यक्ति थे उनको चराने का स्थान न होने से वे पशुअ से पिन्ड छुडाने लगे। राजस्थान के अन्दर अच्छी गायें और सांड मिलते थे, राजस्थान के अन्दर अच्छे २ भेड और बकरी मिलते थे, ऊंट मिलते थे, लेकिन आज राजस्थान पशुओं को पैदा करने के लिए उन्नत नहीं रहा लेकिन उनको दूसरी जगह से लाने पड़ते हैं, आज वह इस स्थिति में आगया। जिन लोगों को जिन जमीनों के खातेदारी के अधिकार मिल गये हैं उनमें कोई आदमी अपने जानवर चरा नहीं सकता है और जब सब को खातेदारी के हकूक मिल गये है, चरागाह की जमीनों के खातेदारी के हकूक मिल गये है और जिनके पास चरागाह नहीं रहा है वे सब के

[श्री भैरूसिंह]

सब यह चाहेंगे कि हमको पशुओं को चराने के लिए जगह मिले लेकिन नहीं मिलती है और खातेदारी के हक प्राप्त करने वाला काहे को इस प्रकार कर सकता है। तो इस प्रकार से जो समस्या बनी हुई है उसके लिए अगर सरकार खेती के द्वारा उत्पादन बढ़ाना चाहती है, फरटीलाइजर्स के लिए जो हमारा पशुधन है न होने का कारण बना हुआ है उसको समाप्त करें और इससे गांवों में अच्छे २ सांडों की व्यवस्था करे।

गांवों में अच्छे से अच्छे बीज की व्यवस्था करें, अच्छी से अच्छी गायों की व्यवस्था करें, गोशालाएं बनावें, पिंजरापोल बनावें। सरकार की ओर से आज जितना बीज दकसीम होता है, जितना कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, नेशनल एक्सटेन्शन विन्लॉक्स के अंतरगत कूए खुदवाते हैं वहां पर एक कूए के मुकाबले में यदि एक सांड छोड़ दिया जाता है तो उससे पशुधन की काफी उन्नति हो सकती है और वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है। एक कूए से तो एक ही काश्तकार को फायदा हो सकता है या उसका और कोई साझीदार होता है तो उसको फायदा हो सकता है लेकिन पशुओं की नसल सुधारने से सब को फायदा हो सकता है। नेश्नल एक्सटेन्शन ब्लोक्स और कम्युनिटि प्रोजेक्ट्स खोले हैं उनको मैंने देखा है। उनके खर्च के लिये १ करोड़ २७ लाख रुपयों की व्यवस्था है। हमें आज कमी के कारण इस टेक्सेशन के युग में इन चीजों की ओर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिये एक इन्क्वायरी बैठानी चाहिये जो निर्देशित करे कि पंचवर्षीय योजना के आधार पर जो अनुभव हुए है उनके अनुसार जो जो त्रुटियें, कमियें रही हैं उनको ठीक तरह से विशलेषण करके यदि हम इस मद के लिये धन स्वीकार करें तो ज्यादा अच्छा होगा। कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स और नेश्नल एक्सटेन्शन ब्लॉक्स के काम के बारे में यदि आप जनता से पूछें तो एक ही तरह की आवाज सब तरफ से मिलेगी, मैं राजस्थान की बात करता हूँ, जनता में इसके प्रति कोई प्रेरणा नहीं है। जिस व्यक्ति ने इसके द्वारा काम कराया या जिनका काम हुआ उनके खिलाफ सारी जनता होगी और कहती है कि नेश्नल धन का दुरूपयोग हो रहा है और जिन चीजों की कमी होती है उनकी पूर्ति नहीं होती। मैं अपनी इस बात की पुष्टि में इकोनोमिक रिव्यू का उदाहरण दूंगा जिसमें श्रीमन्नारायणजी अग्रवाल ने लिखा है कि इससे उन लोगों को सहायता मिलती है जिनको नहीं मिलनी चाहिये और जिन लोगों को सहायता मिलनी चाहिये उनको नहीं मिलती हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जहां हम मोटी रकमें देने के लिये रखते हैं वहां हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे पास काम करने का एक्सपीरियेन्स कितना है, किस प्रकार की सफलता मिली है और किस प्रकार आगे बढ़े हैं, इन सब बातों को हमें देखना पड़ेगा।

अब मैं निवेदन करूंगा कि इस में लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाया जाय इसके बारे में मैं निवेदन करूं कि हमने छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को बढ़ाने की व्यवस्था भी की है और उसमें हम जो अब तक इस इकोनोमिक रिव्यू के आधार पर आगे बढ़ते हैं तो १२७ करोड़ रुपयों की व्यवस्था है। इन १२७ करोड़ रुपयों में से इस इकोनोमिक रिव्यू के आधार पर निवेदन

[श्री भैंरू सिंह]

करता हूं कि ६७ करोड़ रुपयों को अंबर चर्खे के लिये लगाया जायगा। मेरी समझ में नहीं आया कि जब कि हमने इतनी कोटेज इंडस्ट्रीज बनाई, मारकेटिंग फेसिलिटीज देने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी ओर हम अंबर चर्खे के रूप में छोटे २ धंधों पर कुठाराघात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि कुटीर उद्योगों के मूल सिद्धान्तों को ही आप भुला रहे हैं। अंबर चर्खे का आप प्रयोग करें लेकिन आधा पैसा ही आप उसमें लगादें यह उचित नहीं है। अंबर चर्खे का जहां प्रयोग हुआ है वहां इसके कारण बाहर गांवों की बूढ़ी औरतों का धंधा छिन गया है। बूढ़ी औरतें गांव में कताई का काम करती थीं उनका धंधा छीना जा कर उन व्यक्तियों के पास चला जायगा जो अंबर चर्खे के मालिक होंगे। ऐसी सूरत में हमें धंधों का विकेन्द्रीकरण करना है। कुटीर उद्योगों का भी विकेन्द्रीय करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति की ओर आगे बढ़ना है केन्द्रीयकरण की ओर आगे नहीं बढ़ना चाहिये।

अब मैं यह अर्ज करूंगा कि राजस्थान में आज तक जितनी भी सुधार के नाम पर कार्यवाही हुई हैं उनमें और भारतवर्ष में जो सुधार हुये हैं उन दोनों को तुलनात्मक दृष्टि से जांच करें तो हमको अमुक प्रकार की नई चीज मिलेगी। मेरे एक मित्र ने कुछ दिन पहले बताया था कि राजस्थान में ही नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष में यदि कोई सुधार हुआ है और लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक हुई है तो उसका पता बैंकों मे लगेगा। बैंकों में आजकल कौन लोग रुपये ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, किस हद तक लोग रुपये वहां जमा करते हैं। सन् ४५ तक ब्लेक मार्केटिंग के जरिये से लोग रुपया कमाते थे और उन लोगों से पास खूब पैसा था। जितना रुपया उस समय ब्लेक मार्केट करने वालों के पास था उसी प्रकार आज बाहर के लोग जो कमाते नहीं हैं, खेती नहीं करते हैं, कोई धंधा नहीं करते हैं और जो पंचवर्षीय योजना का काम करते हैं और जनता के सुधार का बाना पहने हुये हैं उनको देखें तो पता लगेगा कि उनका इन्वेस्टमेन्ट पहले के उन ब्लेक मार्केटीयर्स से कम नहीं है, बल्कि उनसे २५ परसेन्ट ज्यादा ही लोगों के अकाउन्टस बैंकों में है। ऐसे लोगों की सुधार की मनोवृत्ति नहीं है बल्कि स्वयं का सुधार करने की मनोवृत्ति है। मैं समझता हूं यह एन्टी नेशनल है।

इसी प्रकार की जिम्मेदारी हमारे एज्युकेशन डिपार्टमेन्ट पर है। आज हम लोगों को जो शिक्षा देते हैं वह शिक्षा वही है जिसके कारण हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, मुल्क को गुलाम बनाया, जिसके कारण अन्याय को बर्दाश्त करते रहे। जिसके कारण बेकार होते रहे। जिस शिक्षा के बारे में राष्ट्र के बड़े से बड़े नेताओं ने बताया है कि यह अच्छी नहीं है कुछ लोग प्रोफेसर हुमायुकबीर जैसे ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि कुछ लोगों ने इस शिक्षा को बुरा कहने का पेशा बना लिया है। जो शिक्षा देश के दुश्मन पैदा करने वाली है उस स्थिति से बचने के लिए प्रयत्न करना चाहिये। जिस शिक्षा से लोगों का नैतिक उत्थान न हो उस शिक्षा को फैलाने में कोई सहयोग नहीं मिल सकता! इस सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान में भी एजुकेशन के लिये काफी रखा गया है। इस में यह भी बताया गया है कि इतने मल्टी परपज हाई स्कूल खुलेंगे, सेकन्डरी हाई स्कूल्स खोले जायेंगे। मैं समझता हूँ इस

[श्री भैंरूसिंह]

प्रकार की पढ़ाई ने हमारी स्वतंत्रता पर आघात किया है। बाड़मेर में मल्टी परपज हाई स्कूल खोला गया है। वहां पर चमड़े का काम सिखाने की योजना बनाई गई है। राजपूत भी इस काम को सीखना चाहे तो वह सीख सकते हैं लेकिन हमारे यहां कुछ पाबन्दी है, ब्राह्मण, बनिये जनेऊ पहनने वाले चमड़े का काम नहीं कर सकते। यदि वे बाड़मेर में चमड़े का काम नहीं सीखना चाहते हैं तो उनको दूसरी पढ़ाई करने के लिये जोधपुर जाना पड़ेगा। तो शिक्षा के लिए पहले जो स्वतंत्रता थी उसके लिए एक बंधन खड़ा कर दिया गया, एक ऐसा खोटा बंधन डाल दिया गया कि या तो चमड़े का काम सीखो, या खाती का काम सीखो या किसी दूसरी जगह दर्जी का काम सिखाया जाता है तो वहां दर्जी का काम सीखो। बाहर गावों में शिक्षा के लिए यह व्यवस्था की गई है और उधर शहरों में जहां धनवान लोग बसते हैं उनके लिए यह व्यवस्था है कि वे बी. ए., एम. ए. पढ़ सकते हैं और बाद में एम्बेसेडर, आई. ए. एस, आई. पी. एस. आदि बन सकते हैं उनको ट्रेनिंग दिलाने की सुविधा हो सकती है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—क्षमा करेंगे बीच में बोलने के लिए। सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान पर वाद विवाद चल रहा है, इसके बीच में बाड़मेर और दूसरी जगहों की बातें क्यों लाना चाहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर—प्लेटफार्म पर बोलने जैसी स्पीच हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष—स्ट्रिक्टली रिलेवेन्ट होनी चाहिये।

श्री भैरूसिंह—(जारी रखते हुये) मैंने तो केवल उदाहरण आपके सामने रखा था। यह मामूली बात नहीं है। बाहर गांवों वालों को तो खाती का काम और चमार का काम सिखायेंगे और शहर में रहने वाले धनवानों के लिए आई. ए. एस. आदि के लिये सुविधा है। जिस शिक्षा में शहर और गांव वालों के लिए डिस्पेरिटी हो वह शिक्षा नहीं है बल्कि ऐसा करने के लिये ही यह योजना बनाई है और इसको कार्यरूप में परिणत कर रहे हैं।

लेकिन आज की इस मौजूदा शिक्षा प्रणाली के कारण अनैतिकता बढ़ी है, इसको रोकने का एक ही तरीका है कि सिन्सियरली मिनिस्टरी किस तरह लोगों को सुधारे इस प्रकार की शिक्षा दें तो ठीक है वरना न तो दुनियां को संतोष होगा और न सरकार को संतोष होगा और एक दिन ऐसा आयेगा कि जब इस असंतोष के कारण यह दुनियां किसी गड्ढे खड्डे में चली जाय। नैतिक शिक्षा देनी है तो धार्मिक शिक्षा के जरिये नैतिक शिक्षा दें। द्वितीय पंच वर्षीय योजना को इस दृष्टि से देखेंगे तो चाहे विरोध हो सारे के सारे राष्ट्र के निर्माण कार्य में हर एक जिम्मेदार व्यक्ति इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने की चेष्टा करेगा। परन्तु जब तक यह भाव नहीं तो मैं स्पष्ट रूप से अर्ज करूंगा कि जनता के दिलों में उत्साह पूर्ण प्रेरणा नहीं है तो वह सफल नहीं हो सकेगी।

[श्री भैंरूसिंह]

इस योजना में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की दो बातें रखी हैं। पब्लिक सेक्टर को उत्साहित करने की योजना ज्यादा रखी है ताकि पिछली योजना में प्राइवेट सेक्टर से कराने की कोशिश की थी, उस प्राइवेट सेक्टर की कमी को पूरा कर सके।

हमें ऐसी व्यवस्था करनी है कि लोगों का एक्सप्लोइटेशन न हो और एक के श्रम का फायदा दूसरा न उठा सके। प्राइवेट सेक्टर को हम उत्साह नहीं देते हैं तो जिन लोगों के पास मनी ह्रोप हो जायगा उसको निकालने के लिये क्या किया जायगा? इसमें पब्लिक सेक्टर को प्रोत्साहन दिया है और काम दिया है इसलिये कि जनता का एक्सप्लोइटेशन न हो, पर साथ ही यह व्यवस्था भी होनी चाहिये कि ब्लेक मार्केट के दिनों में अनाज और कपड़ा होर्ड हुआ था उसी तरह सेठों के पास मनी भी होर्ड हो कर पड़ा हुआ है उसको निकालने का तरीका इस्तेमाल में लाइये। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा रूल बनाइये जिससे एक्सप्लोइटेशन न हो आज रूल्स में खामी है, मजदूरों को उनके द्वारा की हुई पैदावार में हिस्सा कम मिलता है केवल इसलिये कि एक्सप्लोइ-टेशन को रोकने का प्रबन्ध नहीं कर रखा है। इसके लिये अगर प्राइवेट सेक्टर को एक तरफ छोड़ कर नागवार कर दें तो ऐसा करके आप पैसे को एक कोने में रखे रहने देने की व्यवस्था करते हैं। इस प्राइवेट सेक्टर की मनी को किस प्रकार पब्लिक के फायदे के लिये किस प्रकार एक कोने में से निकाल कर इस्तेमाल में लाया जाय, इस साधन का इस ड्राफ्ट आउट लाइन में अभाव है, हमें इस ब्लोक हुए रुपये को बाहर लाने का प्रयत्न करना है।

अब लोगों को धंधा देने का प्रश्न आता है, इसके लिये लोगों के दिलों में कोओपरेटिव फीलिंग पैदा करना है। राजस्थान में गिनती की दृष्टि से कोई भी मंत्री या जिम्मेदार व्यक्ति कह सकता है कि हमने इतनी कोओपरेटिव सोसायटीज खोली दी हैं। खोली हैं पर फीलिंग हम निर्माण चाहते हैं वह नहीं कर पाये हैं।

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि अगर आंख मींच कर किसी व्यक्ति पर निगाह डालूं तो शक होगा, उसी तरह मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान में जितनी भी कोओपरेटिव सोसायटीज बनी हुई हैं उनमें से किसी पर आंख मींच कर हाथ रख दें, आपको उसमें गड़बड़ी मिलेगी। सीकर डिस्ट्रिक्ट में तो जितनी कोओपरेटिव सोसायटीज बनी हुई हैं वे सब की सब घाटे में हैं, उनका कोई हिसाब किताब नहीं, पैसे का कहीं कोई हिसाब किताब नहीं। इसका जबरदस्त कारण जो मैं खोज पाया हूं वह यह है इन सारी कोओपरेटिव सोसायटीज के कारण बाहर के छोटे छोटे दूकानदारों का धंधा चौपट होता है, छोटे छोटे जो बाहर बनिये हैं उनका काम बन्द होता है, इसलिये वे कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह इन कोओपरेटिव सोसायटीज को नहीं चलने दें। बाहर गांवों में कोओपरेटिव सोसायटीज बनते ही वहां के महाजन लोग कोशिश करते हैं कि इन्हें किसी तरह नाकामयाब बनाया जाय, ये लोग अपने आदमियों को इनमें डाल देते हैं, कोई सेक्रेटरी बन जाता है कोई मेम्बर बन जाता है और इन पर कब्जा करके हर प्रकार की

[श्री भैंरूसिंह]

कोशिस करके इन्हें नाकामयाब बनाते हैं। हमारी सरकार कहती है कि वह कोओपरेटिव सोसायटीज के आधार पर कोओपरेशन की भावना पैदा करती है पर जिनका धंधा छीना जाता है उन्हें इसी प्रकार का दूसरा धंधा नहीं देते हैं गावों में जो यह व्यवस्था बनी हुई है उसके लिये हम ठोस कदम नहीं उठाते तब तक कोई सफलता नहीं मिलेगी।

लोगों को कोओपरेटिव सोसायटीज से वास्तविक रूप में सहायता मिलती रहे, अगर सरकार ऐसा चाहती है तो कोओपरेटिव सोसायटीज के बारे में निर्णय दे इससे पहले एक्सपर्टस की कमेटी बैठाये जो सरकार के सामने सब बातें रखे और बताये कि कोओपरेटिव सोसायटीज का काम किस तरह चल सकता है।

इसके अलावा मेडिकल, स्वास्थ्य, चिकित्सा सम्बन्धी जिक्र दिया है, सड़कों के लिये धन राशि दी है, राजस्थान सरकार ने कहा है कि सिवाय कुछ तहसीलों के सब तहसीलों को सड़कों से जोड़ दिया जायगा। बिल्डिंग्स बनाने के लिये बहुत सी धन राशि रखी गई है इसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस पर एक मुश्त राशि खर्च करें यह उचित नहीं होगा, गांवों में, जागीरदारों के, सेठों के बहुत से मकान मिलेंगे, वे लोग चाहते हैं कि सरकार हमारे मकानों को खरीदे पर हमारी सरकार की यह नीति रहती है कि हम मकान बनालें ऐसा न करके बाहर गांवों में जो मकान बने हुए हैं वे किसी को कम्पेन्सेशन देने से या कम कीमत देने से मिल सकते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय अध्यक्ष, यह किस चेप्टर पर बहस हो रही है?

श्री भैंरूसिंह (जारी रखते हुये)—मकानोंके ऊपर इस खर्च को करने के चेप्टर के ऊपर बहस हो रही है जो सरकार ने बिल्डिंग्स वैगरह बनाने के ऊपर रखा है उसके ऊपर बहस हो रही है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि बाहर जो मकानात बने हुए हैं उनको खरीद लें तो बहुत अच्छा होगा।

अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि कर्ज के रूप में शामिल सेवाओं के रूप में, अनकवर्ड गैप है उसको साफ कर के जो काम करें, उसमें हमारा दृष्टिकोण यह हो कि उस पैसे का किसी प्रकार दुरुपयोग न होने दें।

इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संबंध में पैसे के दुरुपयोग की शिकायत आती है तो वहां पार्टी पालिटिक्स, दलबंदी के रूप में विचार न करें, और उस व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा सजा दें। इतना कह कर मैं माननीय चीफ मिनिस्टर को इस बात के लिये निवेदन करूंगा कि जहां तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना का संबंध है, यदि उन्होंने विरोधी दल के सदस्यों से इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में सहयोग लिया तो समय समय पर उनकी तरफ से सहयोग मिलता रहेगा, लेकिन उनकी तरफ से भी राजस्थान की जनता

[श्री भैरोंसिंह]

को यह आश्वासन मिलना चाहिये कि इसके लिए वे सारे राजस्थान को डिस्ट्रिक्ट लेवल, पंचायत और तहसील पंचायत व डिस्ट्रिक्टवाइज ब्रेक अप करेंगे और वहां के लोगों की सलाह से काम होगा। यह कहना कि हमने कमेटी बना दी है और वह डिस्ट्रिक्ट कमेटी अपनी राय देती है उसकी राय पर काम होता है, तो मैं यह कहूँगा कि उस कमेटी के डेवलपमेंट को किसी तरह से अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपने अपने पक्ष के लोगों की कमेटी बनादी वे अपना भला सोचते हैं। इसलिये मैं अन्त में यह निवेदन करूंगा कि जहां तक हो सके हम डिस्ट्रिक्टवाइज ब्रेक अप को लेकर कार्य करें। इससे पंचायतों से लेकर ऊपर तक सभी लोगों का हमको सहयोग मिलेगा। उनकी राय उसमें होती ही है। मैं आशा करता हूँ कि आप भी पब्लिक को आश्वासन देंगे और पब्लिक भी इस कार्य में अवश्य सहयोग प्रदान करेगी।

श्री द्वारकादास पुरोहित—माननीय उपाध्यक्ष, मैं राजस्थान सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज सदन में इस बात का मौका दिया कि हमारे इस प्रजातंत्र में जिस प्रकार की नींव पड़ी है और खड़ी करनी है इस बात पर सदन चर्चा करे।

मैं यह जरूरी समझता था कि जिस वक्त यह सदन इस मसले पर और खास मुद्दों के मसलों पर बहस करे उस वक्त हमारे सामने प्रथम पंचवर्षीय योजना के इम्प्लीमेंटेशन की रिपोर्ट होगी राजस्थान की और भारत की तो हम जो कुछ काम हम प्रथम पंचवर्षीय योजना में कर पाये हैं और जो कुछ काम आगे करने जा रहे हैं उसके लिये हमारे सामने एक साफ नक्शा होता और सदन के सदस्य इस बात पर अपनी राय बना सकें कि जो कुछ कार्य किया गया है उसमें हमको कहां और किस हद तक कामयाबी मिली है। लेकिन वह मुकम्मिल रिपोर्ट हमारे सामने नहीं होने से जो कुछ भी चर्चाएं होंगी वह दूसरी आम रिपोर्ट जो हमारे सामने आई हैं उनके आधार पर करनी पड़ती है।

मैं पंच वर्षीय योजना के बारे में आपके द्वारा माननीय अध्यक्ष, सदन को कहना चाहता हूं कि ये पांच वर्ष हमारी जिन्दगी के खास उद्देश्य और आधार हैं और इस पंचवर्षीय योजना को लागू करने में, इम्प्लीमेंट करने में, बनाने में और कामयाब बनाने में एक वातावरण की आवश्यकता है जो वातावरण हमारे यहां के किसानों, मजदूरों और पढ़े लिखे लोगों में यानि सब तरह के तबके के लोगों में होना चाहिये। गवर्नमेंट तो एक न्यूक्लेस के रूप में आनी चाहिये और लोगों को चाहिये कि सब लोग इस काम में सहयोग दें और इसी से काम हो सकता है। लेकिन पहले पांच वर्ष गुजरे उन पांच वर्षों की तरफ अपना दृष्टिकोण फेंके तो मालूम होगा कि इस तरह का वातावरण हम अपने मुल्क में बना नहीं पाये। अगर उस तरह का वातावरण बनाया जाता तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का नक्शा है उसको बनाने में बहुत सहायता मिलती। मैं मानता हूं कि कहने के लिए डेवलपमेंट कमेटी कुछ मसलों पर सरकार को सजेशन देती है। लेकिन मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि वह अच्छे सजेशन्स नहीं देती है क्योंकि इसमें बहुत से एम. एल. ए. होते

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

है, दूसरे अधिकारी भी होते हैं। मगर इसके लिए यह बहुत बहतर होता अगर पंचवर्षीय योजना में तहसीलवार कमेटी बनाते और तहसीलवार ही नहीं एक नायब तहसीलवार कमेटी बनाते जिसमें ५० या १०० गांवों का एक युनिट मान कर बोर्ड बनाते औरवह बोर्ड अपने यहां को हालत को आपके सामने रखता। उसके बाद पंच और दूसरे लोग व एम. एल. ए. को साथ लेकर उन ५० या १०० गांवों को योजना पेश करते और उस पर हम अमल करते, उसको जांच कराते और कायदे से काम होता तो आज जो नकशा हम देखते हैं वह दूसरा ही होता। वरना यह होता है कि जो शख्स जिसको जैसा मौका मिलता है, उसने जैसा मौका मिला, मौके का फायदा उठा लेते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा रकम लग जाती है और दूसरे में जहां पर जरूरत होती है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। इसलिये यह बहतर होता अगर इस तरह से काम किया जाता जिस तरह से बताया गया। मैं आशा करता हूँ कि सरकार इस सम्बन्ध में एक मूवमेंट चलाएगी जिससे वातावरण ऐसा बने जिससे सब लोग योजना को सफल बनाने के लिये सक्रिय भाग लें और कदम उठावें। गांव वालों में इस बात का उत्साह बने और लोग काम करें और उनको किसी प्रकार की शिकायत नहीं रहे काम उस जगह हो गया और इस आधार पर हो गया कि फलां व्यक्ति सरकार की मर्जी में है इसलिये उसके डिस्ट्रिक्ट में काम हो गया और हमारे गांव और जिले में कुछ काम नहीं हुआ। इस तरह की अनुमन शिकायत हमारे सामने है। इस तरह की शिकायत जब हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में काम करें तो नहीं होनी चाहिये। अगर ऐसा होगा तो मैं यह उम्मीद कर सकता हूं कि सब लोग सरकार को सहयोग देंगे और जनता का सहयोग एक बहुत बड़ी बुनियादी चीज है, किसी भी योजना को सफल बनाने के लिये।

दूसरी जो बहुत जरूरी चीज है वह है एफिशियेन्सी और इकोनोमी। काम को कार्यान्वित करने में एफिशियेन्सी और काबलियत से काम को करना चाहिये और उसमें जितनी इकोनोमी बरती जा सके बरतनी चाहिये ताकि पैसे का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो सके। अगर हम प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो काम हुए हैं उनमें से बहुत से कामों की तरफ जावें तो मालूम होगा कि पैसों का बहुत दुरुपयोग हुआ। भाकरा नागल जिसके लिये योजना में जितने पैसे थे उससे डबल कर दिये गये। उसमें कई स्केन्डल हुए, कई मुकदमें भी चले और अभी चल रहे हैं ऐसी व्यवस्था हुई है। वही मिसाल बड़े पैमाने पर हमारे सामने है और छोटों में देखे तो उसमें भी इसी तरह की बात मौजूद है। जो काम ५ या ६ हजार रुपयों में हो सकता था उसको १० हजार में किया जाता है, इसको जांच नहीं होती कि काम किस तरह से होता है, कितने अर्से तक चल सकेगा और फिर गड़बड़ होती है।

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

इसके लिये जांच की कोई मशीनरी सरकार के पास इस वक्त नहीं है। इसके लिये सब से बड़ी चीज यह है कि एफीशियेन्सी और इकोनोमी से काम हो रहा है या नहीं, इसके लिये सरकार को अपनी नजर हर वक्त इन कार्यों की ओर रखने की आवश्यकता है ताकि लोगों से लिया जाना वाला पैसा ठीक तरह से उपयोग में आ रहा है या नहीं यह पता चल सके उस। जनता के पैसे की पाई पाई का ठीक प्रकार से इस्तेमाल होना आवश्यक है। मैंने जैसा कि पहले कहा अगर इम्पलीमेन्टेशन की रिपोर्ट हमारे सामने होती तो बहुत कुछ बातों को सही स्थिति में हम रख सकते।

इसी सम्बन्ध में बोलते हुए एक माननीय सदस्य ने यह भी जिक्र किया कि प्रथम पंच वर्षीय योजना के पिछले दो सालों में बैंकों के पास ऐसे लोगों के हाथों से पैसा आया है जो उनके पहले के बैलेन्स से २५ परसेन्ट ज्यादा है। उन्होंने जो बात कही, उससे इत्तफाक न रखते हुए भी मैं यह जरूर कह देना चाहता हूं कि इस बारे में इन्क्वायरी करें। जो कुछ रेकार्डस मिला है बैंक्स के बारे में और जो कुछ मैं देख सका हूँ इससे यह मालूम हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति के बैंक बेलेन्स में २५ प्रतिशत वृद्धि हुई हो, यह बात नहीं लेकिन यह अवश्य है कि २५ प्रतिशत बैंक डिपोजिट बढ़ा है और इन पिछले दो सालों में बढ़ा है। हर जगह कोमर्शियल बैंकों में २५ प्रतिशत डिपोजिट बढ़ा है। आज के दिनों में हम इस बात की आशा नहीं कर सकते कि लोग इतने प्रगतिशील हो गये या जागरुक हो गये कि वे पैसा जो कुछ भी बचाते हैं बैंक्स में डिपोजिट की तौर पर जमा करा देते हों, मैं यह मानने को तैयार नहीं कि आजकल स्थिति इस हद तक पहुंच गई हो कि किसानों के पास धन हो गया हो या हमारे किसानों की हालत इतनी अच्छी हो गई हो जिससे वे अपनी बचत का पैसा बैंकों जमा करवा सकें, यह मानने लायक बात नहीं है लेकिन जो धन इन बैंकों में जमा है वह धन वह नहीं है मगर कोमर्शियल बैंकों में जो डील विद करते हैं, जो इस बात को समझते हैं बिजिनेस कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके डिपोजिट खास तौर से बढ़े हैं, यह सोचने का मसला है; यह पैसा किस तरह से उनके पास पहुंचा ?

The first five years plan was mainly directed to words agricultural development. इस वजह से खास तौर से यह सोचने की बात है।

हमारे एक माननीय सदस्य जो जोधपुर बी से आये हुए हैं उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि सरकार ने जो डेफीसिट फाईनेन्सिंग जो बताया है उससे इन्फ्लेमेशन होगा जो उनके ख्यालसे मुल्क के लिये हानिकारक हो सकता है। मेरे ख्याल से उनको इस चीज का ज्ञान नहीं है केवल डेफीसिट फाइनेन्सिग के नाम से यह कह देना कि इन्फ्लेमशन बढ़ेगा बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा ऐसा ख्याल कि जो १२०० करोड़ रुपये डेफीसिट फाईनेन्सिंग किया गया है इससे जो इन्फ्लेमेशन का भय है वह बिल्कुल गलत साबित होगा। यह रुपया जो योजनाओं में खर्च किया जायगा इससे इन्फ्लेमेशन नहीं बल्कि क्रेडिट फाइनेसिंग है जो हम आज इनवेस्ट कर रहे हैं या जिस काम के लिये वह रुपया लगाया

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

जा रहा है। उसका बैलेन्स्ड १२०० करोड़ रुपया उसकी एवज में है। यह जो इनफ्लेमेशन हो रहा है जिससे कीमतों पर किसी प्रकार का असर पड़ने वाला नहीं यह तो उसकी एवज में है। इस लिये प्लान्ड इकोनोमी के ढंग से चलें और जैसी कि उम्मीद की जा सकती है हमारे काबिल फाइनेन्स मिनिस्टर और प्लानिंग मिनिस्टर से कि वे इसी प्रकार चलेंगे तो हमें आशा करनी चाहिये कि हमारे यहां किसी किस्म की कमी आने वाली नहीं है। १२०० करोड़ रुपये की कमी की वजह से किसी प्रकार भी इनफ्लेमेशन नहीं होने वाला है। ऐसी मेरी मान्यता है कि इसमें किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिये। यह एक पूंजी लगाने जैसा काम है। जिस प्रकार पूंजी लगाने वाले लोग पूंजी से कितना व्यापार कर लेते हैं जितनी पूंजी होती है उससे कई गुना बढ़ा चढ़ा कर व्यापार कर लेते हैं यह मिसाल इसी तरह की तो नहीं बल्कि मिसाल करीब करीब वैसी ही है उसी के नजदीक आती है। क्रेडिट फाइनेन्सिंग के १२०० करोड़ से किसी प्रकार से इनफ्लेमेशन नहीं होगा। इससे हमारे प्लान को किसी प्रकार हानि पहुंच सकती है, यह बात कदापि नहीं बल्कि यह तो हमारी प्लान के लिये फायदेमन्द होगा।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके जरिये सदन को यह बता देना चाहता हूं कि यह प्लान सारे भारतवर्ष का प्लान है जिस प्लान में सबकी आर्थिक स्थिति और जो हमारी सोसाइटी का आर्डर है उसमें परिवर्तन लाकर हम समाजवादी समाज की रचना की ओर अग्रसर होने वाले हैं, इन सब बातों की आधार शिला हमारा यह प्लान है। जब हम राजस्थान के नक्शे को इस प्लान के अन्दर देखते हैं तो हमें कहीं यह नजर नहीं आता कि बेसिक बातें जो हमारे द्वारा कही गई जिस बेसिक इन्डस्ट्रीज के लिये हमने जोर दिया। यह मानी हुई बात है कि बिना बेसिक इन्डस्ट्री के देश का उत्थान नहीं हो सकता। जब मैंने इस प्लान को इस दृष्टि से देखा तो मुझे मालूम हुआ कि राजस्थान में कौन कौन सी बेसिकइन्डस्ट्रीज लगने वाली हैं ? इस प्लान में जरूर कुछ इस बारे में मिला, उसमें से एक है वूल इन्डस्ट्री का उल्लेख। वूल इन्डस्ट्री कहां और किस तरह की रहेगी यह साफ नहीं है। वूलन मिल के लिये हमारे रा मेटीरियल ज्यादा है। वूल फैक्टरी अगर यह लागू की जाती है तो वह फुल फ्लेज्ड लागू की जानी चाहिये इस पैमाने पर लागू की जानी चाहिये जिस पैमाने पर मुल्क की रिक्वायरमेन्ट्स हों, उसकी जरूरियात हों उसकी पूरी की जा सकें। इस बात को देखते हुए अगर हम यहां वूल मील लागू करते हैं तो हमें कुछ संतोष होगा। केवल वूलन मिल के खोल देने से ही काम नहीं चल सकता। हमारे यहां आप सांभरलेक की ओर ध्यान दीजिये। इस लेक में इतने केमिकल्स हैं जिनका फायदा हमें उठाना चाहिये। पहले भी मैं इन केमिकल्स के बारे में कह चुका हूं लेकिन जहां मैं इस प्लान को देखता हूं इन केमिकल्स के लिये किसी भी प्रकार की कोई योजना नहीं है। इसमें कास्टिक सोडा, सोडा बाई एशतथ और भी दूसरी दूसरी प्रकार के केमिक्लस के प्राप्त होने की गुंजाइश है जो बहुत बड़े पैमाने पर इसमें मिल सकते हैं। मैं नहीं समझता कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को भी इस बारे में कुछ गुंजाइश दी गई या नहीं। मेरे ख्याल से पब्लिक सेक्टर के मातहत इसको रखना चाहिए। इसके लिये राजस्थान सरकार को स्थान देना चाहिये लेकिन मैं देखता हूं कि इस प्लान में इन बातों का कोई जिक्र नहीं आता है। केमिकल्स के बारे में कोई भी

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

योजना इस प्लान में नजर नहीं आती है कि कौनसे केमिकल्स पब्लिक सेक्टर में रहेंगे और कौन २ से केमिकल्स प्राइवेट सेक्टर में, कहीं इस बात का जिक्र नहीं आता है जो होना बहुत आवश्यक है। केमिकल्स बहुत बड़ी बेसिक इन्डस्ट्री है। जिस बेसिक इन्डस्ट्री को कायम करने में हम सबको सहयोग देना चाहिए और भारत सरकार से इस बात की मांग की जानी चाहिए कि इसको कार्यान्वित किया जाय इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है क्योंकि राजस्थान में रॉमेटीरियल बहुतायत से मिलता है।

मैं आपको याद दिलाऊं, केमिकल इंडस्ट्री के बारे में हमें अफसोस है कि इन सात सालों में कुछ नहीं हुआ। जिस वक्त पहली पंच वर्षीय योजना बनी थी उस वक्त नेशनल प्लानिंग कमेटी के चेयरमेन द्वारा जो रिपोर्ट तैयार हुई उसमें इस बात का जिक्र है कि हमारे यहां केमिकल्स की बेसिक इन्डस्ट्रीज हों। इनको डेवलप करने में जल्दी से जल्दी काम शुरू करना चाहिए। इस चीज की बहुत बड़ी कमी रही है। मुझे इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना है कि राजस्थान सरकार को तत्परता से इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसको लेना चाहिए। आप उस रिपोर्ट को देखें जिसमें के. डी. शाह मौजूद थे उन्होंने अपनी राय दी है कि केमिकल्स की इन्डस्ट्री यहां पर जरूर कायम होनी चाहिये, इसमें दो राय नहीं हो सकती। यदि यहां इस प्रकार की इन्डस्ट्रीज़ कायम की गई तो यहां कुछ हद तक अनएम्प्लॉयमेन्ट की समस्या भी हल हो सकती है और इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता हमारे राष्ट्र के लिए भी हो सकती है। इसलिए मैं माननीय उपाध्यक्ष, सदन के सामने यह रखता हूँ, इस संबंध में हमें ज्यादा से ज्यादा जोर भारत सरकार को देना चाहिये और इस प्रकार की इन्डस्ट्रीज़ को इसी दूसरी पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित करवाना चाहिये।

दूसरा हमारे यहां फरटीलाइजर फेक्टरी का प्रश्न था। इसके बारे में बहुत कुछ सुना था कि यह प्रथम योजना के अन्तर्गत हनुमानगढ़ में खुल रही है पर वहां नहीं खुली। इसका यह मतलब नहीं कि अगर वह उपयुक्त स्थान खोलने के लिये नहीं समझा गया तो और जगह भी नहीं लगे। इसके लिये भी हमें कोशिश करना चाहिये ताकि जहां उपयुक्त स्थान समझा जावे वहां वह फैक्टरी लग सके। रॉ मेटीरियल हमारे यहां इतने होते हुए भी अगर ये काम नहीं होते तो यह हमारी कमजोरी है कि हम अपने मसले भारत सरकार के सामने ठीक तरह से पेश नहीं करते और उनको नहीं मनवा सकते। माननीय मुख्य मंत्रीजी कहा करते हैं कि इस योजना के सिलसिले में काफी धनराशि वहां से स्वीकृत करा लाये।

बहुत अच्छा है, इसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। पहली योजना की धनराशि को देखें तो वह ३१ करोड़ रुपया था उससे ढाई गुना तो इस योजना में मिलना ही था क्योंकि पहली योजना से यह योजना वैसे ही ढाई तीन गुनी है और फिर वहां पर एक बात थी कि जो एरिया बैकवर्ड है उसमें भी काम शुरू करने के लिए धनराशि उपयुक्त होनी ही चाहिये ताकि वह एरिया भी और

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

एरियाज़ के बराबर प्रगति में आ सके और यह प्रिन्सिपल प्लानिंग कमीशन ने ले डाउन भी कर दिया था और इसके आधार पर यह राशि तो हमें मिलनी ही चाहिए थी। पर ये काम जो होने चाहिये वे करवाने के लिये माननीय मुख्य मन्त्री जी को और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए और धन राशि प्राप्त करने की। और ये जो रा मैटीरियल हमारे यहां अवेलेबल हैं जिनसे बडी २ थे इन्डस्ट्रीज़ हमारे यहां पनप सकती हैं अगर वे इन्डस्ट्रीज़ इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी नहीं बन सकीं तो यह नाकामयाबी का टीका हमारे सिर पर लगेगा और इस प्रकार जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी ठीक तरह से नहीं निभा सकेंगे।

मैं और बताऊं हमारे यहां डाईज (रंग) की इन्डस्ट्रीज भी लग सकती है। इसे कैमिकल का बाई प्रोडक्ट समझिये, इसकी गुंजाइश भी बहुत है। इस पर भी हमने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। यह बद किस्मती की बात है। राजस्थान में इसकी बहुत बड़ी गुंजाइश है और अलवर जयपुर में इसकी शुरुआत भी हुई थी पर कामयाब नहीं हो सके। इसके बहुत से भिन्न भिन्न कारण हैं। हमें उनमें जाना चाहिये और उनका हल करने की कोशिश करनी चाहिये।

पेट्रोल हमारे यहां निकल सकता है। अभी पिछले दिनों रशियन एक्सपर्टस भी हमारे यहां आये थे। उनकी राय उत्साहवर्धक है। पिछले सात सालों से और उससे भी पहले से हम इसके बारे में सोचते थे। पर अब तक भी काम शुरु नहीं हुआ। अब आशा है शुरु होगा। सुनाई तो दिया जा रहा है, पर अब भी कब होगा यह मालूम नहीं।

कोल के बारे में राजस्थान में गुंजाइश होते हुए भी रिसर्च अभी तक पूरी न हो पाई और हम इस काम को शुरु भी नहीं कर पाये, यह भी शर्म की बात हमारे लिये है, इतना मिनरल होते हुये भी हम कामयाब नहीं हो सकते। कोल से सिंथेटिक पेट्रोल बनने की बात भी सुन रहे हैं। सुनने भर की बात रह गई है, करने के लिये कोई चीज सामने नहीं आई।

ये इतने महत्वपूर्ण मसले हैं जिनको करने के लिये सबसे ज्यादा ध्यान सरकार का जाना चाहिये था और अगर सरकार इन सब बातों में जागरूक होती तो बहुत हद तक आज तक कामयाबी नजर आती, पर अफसोस यह है कि हम इन मुद्दों की बातों पर भी कोई कामयाबी अभी तक हासिल नहीं कर सके। यह हमारे लिये बड़ी दिक्कत है, यह बड़ा मसला है कि हम जनता के सामने पंच-वर्षीय योजनाओं का इतना बड़ा हल्ला गुल्ला करते हैं, इतना बड़ा दावा करते हैं कि ये योजनाएं उनकी आर्थिक स्थिति में आमूल चूल परिवर्तन लावेंगी। पर जब हम अपनी ओर देखते हैं अपने कहने और करने की ओर देखते हैं तो साफ मालूम पड़ता है कि हम कहते ही कहते रहे हैं, करने धरने के माने में हम बहुत पीछे हैं। तो इस पर जनता कहां तक विश्वास करे, यह सोचने की बात है।

[श्री द्वारकादास पुरोहित)

इसके अलावा मैं और एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे यहां ग्लास बनाने का अच्छे से अच्छा रॉमेटीरियल है। इतना सब होने के बाद भी यहां कोई ग्लास फेक्ट्री नहीं पनप सकी। कई जगह ग्लास फेक्ट्रियाँ खुलीं पर वे सब बन्द हो गई और कोई काम उनमें एप्रीशियेबल नहीं हो सका। सरकार का ध्यान भी कई फेक्ट्रीज़ ने आकर्षित किया पर सब बेकार गया। नतीजा यह हुआ कि जो पैसा उनमें लगा वह गरीब लोगों का शेयर के रूप में अधिक था, और वह बेकार गया, बरबाद हुआ। वे आज भी बन्द पड़ी हैं।

इस सिलसिले में यह भी बता दूं कि जोधपुर में जो ग्लास फैक्ट्री थी जिसको कि सेन्ट्रल फाइनेन्शियल कॉरपोरेशन ने सहायता दी उसमें बहुत बड़ा स्केन्डल हुआ। वह आज भी बन्द पड़ी है। ऐसे कन्सर्न्स में जहां इतने स्केन्डल हो जाते हैं सरकार कोई ध्यान नहीं रखती। जो लोग इस तरह के चालाक और होशियार हैं वे किसी तरह से सरकार से पैसा ले सकते हैं और उन्हीं को मिल सकता है चाहे वे कितने ही बड़े पैमाने पर फिर स्कैन्डल करें। पर जहां जिनको मदद देकर सही माने में खड़ा किया जा सकता है वहां वह पैसा नहीं लगता। सही आदमियों को मदद नहीं दी जाती। इसलिये इस बात पर भी खास तौर से ध्यान देने की जरूरत है।

लाइम स्टोन हमारे यहां मौजूद है, इससे बनने वाली शीट ग्लास फैक्ट्री की भी बड़ी गुंजाइश है हमारे यहां।

इसी तरह से बहुत सी चीजें यहां हो सकती हैं जिनकी तरफ सरकार का ध्यान देना बहुत जरूरी है और मैं समझता हूं कि इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम उन सब बातों को ध्यान में रखकर इन्डस्ट्रीज़ को यहां पनपावेंगे और इसके लिए प्रयत्नशील होंगे। हम सदन के मेम्बरों को भी इस बात पर जोर देना चाहिये कि भारत सरकार इन चीजों को अपने ध्यान में ले, ताकि हमारे यहां के लोगों की पिछड़ी हुई आर्थिक स्थिति समुन्नत हो। इससे राष्ट्रीय धन के बढ़ने में अवश्य मदद मिलेगी। ऐसी सूरत में इन कामों को करना निहायत जरूरी है और इन बातों को हाथ में लेना चाहिये।

एक और बात कहूँ, मैं इस प्लान में नहीं पाता हूँ पर जो बहुत ही आवश्यक है, जिसे इसमें अवश्य शामिल किया जाना चाहिये था वह है आयुर्वेद, यूनानी और होमियोपैथी चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहन और समुन्नत बनाने की दिशा में उत्साह और प्रयत्न का किया जाना। इस दिशा में कोई प्रशंसनीय काम जो होना चाहिये नहीं हो रहा है। इस देश में इन तीनों चिकित्सा पद्धतियों का बहुत बड़ा स्थान है। सरकार ड्रग्स, केमिकल्स वगैरह में और ऐलोपैथी दवाइयों वगैरह में लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। पर यह जो सबसे बड़ी खामी रह गई है इस ओर भी ध्यान देना सबसे जरूरी है। जिस आयुर्वेद पद्धति ने हजारों लाखों वर्षों से इस देश में यहां के लोगों की तन्दुरुस्ती की रक्षा की और जिस सफलता से उसने

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

यहां के लोगों के स्वास्थय को बनाये रखना उसके मुकाबले में आज का यह एलोपैथी सिस्टम कुछ भी नहीं है, जिस पर आज करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है। फिर भी बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं, लोगों का स्वास्थ्य का स्तर भी पहले के मुकाबले में बहुत गिरता जा रहा है। शारीरिक गठन भी लोगों का पहले के मुकाबले में कुछ नहीं रह गया है तो इन तीनों हेतु हमारे यहां की देशी चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना में काफी पैसा रखवाना चाहिये ताकि रिसर्च की जाकर वे चीजें जो पुराने जमाने में काम में लाई जाती थीं वे अब भी अच्छी तरह से काम में लाई जा सकें और हमारे यहां की पैदा हुई जड़ी बूटियों का हमारे यहां की जल वायु में पले लोगों के स्वास्थ्य के लिये काफी अच्छा उपयोग किया जा सके। यही हमारे लिये उपयुक्त भी होगा, नहीं तो हमारे यहां के जलवायु के प्रतिकूल किसी भी विदेशी चिकित्सा पद्धति पर आप भले ही करोड़ों रुपया खर्च करें उससे उतना लाभ नहीं होने वाला है जितना यहां की जलवायु में पनपी हुई जडी बूटियों पर आधारित चिकित्सा पद्धति से हो सकता है। अगर ये पद्धतियां पनप गई तो हमें आज जो लाखों करोड़ों रुपयों की दवाइयां बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ रही हैं वे भी बन्द हो सकेंगी और यह पैसा हमारा बच जावेगा। ये सारी पद्धतियां प्रगति करने के काबिल हैं। इनमें प्रगति होनी चाहिये।

बांधों में और उनके निर्माण में करोड़ों रुपया भारत सरकार का खर्च किया गया। हमारे यहां भी खर्चा हुआ। चम्बल और भाखरा में हो रहा है, इसमें जवाई को भी जोड़ते हैं। हालां कि मैं इसको नहीं मानता कि यह भी कोई बड़ी स्कीम है। यह बहुत छोटी स्कीम है और सन् ४६ में ही यह शुरू हो गई थी। पर फिगर्स बताने के लिए यह भी इनमें जोड़ दी जाती है। फिर भी बांधों का काम हुआ है यहां। इसके अतिरिक्त हमारे यहां अगर रिसर्च करें हम, तो पुराने जमाने के बने हुए कई बांध कई जगह हमें मिलेंगे और जो किसी न किसी कारण से रुके पड़े हैं, जिनसे कोई फायदा जनता को नहीं मिल रहा है। उनकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए। यह अत्यन्त जरूरी है। मैं मिसाल दूं जैसे कि जयपुर जिले में एक बेचारा कहो, या बिचारा कहो नाम का बांध है जो तीस साल पहले अपने बूते से भी बाहर रकम खर्च करके उस वक्त की रियासत ने बनाया था पर उस वक्त जागीरदारों और भोमियों की महरबानी से उसमें से नहरें नहीं निकल सकीं। आज उसकी हालत यह है कि इसमें रेत जमा हो गई है और इसमें चार-पांच गांव का पानी आज भी जरूर आता है, पर अगर इसको ठीक करा लिया जाय तो पूरी तहसील के तीन चौथाई हिस्से को यह पानी दे सकता है।

लेकिन उसमें वह रेत हटवाकर, केनाल्स बनवा कर यह काम वह पूरा नहीं कर सकते हैं ऐसी की ऐसी एक बात है, जोधपुर में बिलाडा के पिचयाक बांध में रेत जमा हो गई है और उसके बारे में कई एक झगड़े हुए हैं। इस तरह के छोटे बड़े काम हमारे यहां पर मौजूद हैं जो कि सरकार के ध्यान देने के मात्र से और थोड़ी धनराशि लगाने से ठीक हो सकते हैं। मगर उस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए। इन चीजों का झगड़ा हमारे घर की बात है। हम उसको ठीक तरीके से कर सकते हैं।

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

अब एक और बात, माननीय अध्यक्ष, आपके जरिये से सदन के सामने रखना चाहता हूं, वह यह है कि हमारे राजस्थान प्रान्त में रेलवे लाइन्स का डेवलपमेंट जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है और कुछ गुंजायश भी नहीं मालूम हुई है इस प्लान में। वह हम कहां तक कर सकेंगे इन अगले पांच वर्षों में भी। अभी तक तो जो यह बहुत इम्पोर्टेन्ट लाइन हैं अहमदाबाद से दिल्ली के लिए वह भी ब्रोड गेज नहीं हो रही है। इसकी ब्रोड गेज लाइन बनाना अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए भी प्रोवीजन होना चाहिए। मैं यह कहता हूँ कि जोधपुर से एक गाड़ी चलती है दिल्ली मेल, वैसी की वैसी ही जोधपुर से आगरा फोर्ट चलने लगे तो हम जयपुर से ७ घन्टे में पहुँच सकते हैं और आज जयपुर पहुँचने में १०, १२ घन्टे लगते हैं। इसी तरीके से आगे जैसलमेर और और एरियाज जो हमारे पड़े हुए हैं जिनके बारे में कोई रिसर्च (सर्वे) करके भारत सरकार के सामने पेश नहीं किया है। हमारे यहां की रेल्वे लाइन्स पहले से किसी भी हद तक ज्यादा नहीं हुई है। इनसे हमारी काफी आमदनी थी वह आमदनी भारत सरकार को है। वे उस आमदनी के प्रोफिट से इन रेल्वे लाइन्स में इन्वेस्ट करते रहते तो हमारा बहुत सा मसला हल होता। इसलिए उसको हल करने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए।

इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष, मैं दो बातें और कहना चाहता हूँ, और वह इस सिलसिले में है कि जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था कि हमको एक वातावरण पंचवर्षीय योजना के इम्प्लीमेन्टेशन के लिए बनाना चाहिए कि जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से काम करने के लिए लोग सारे के सारे इसमें आगे आकर मदद दें। ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है। हमारी गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ, अभी तक इस काम में सफल नहीं हुई है, तो यों समझा जाय कि इस हद तक जैसा कि कदम बढ़ाना चाहिए था वह नहीं बढ़ पाया है और मैं मानता हूं कि बहुत सी जगहों से इस बात की मांग आई है कि आदिवासियों में अब तक जो काम होना चाहिए था वह नहीं हुआ है मैं यह मानता हूं कि आदिवासियों, हरिजन, शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों में चमार तथा दूसरी जातियों के बहुत सारे लोग हैं वे हर जगह, राजस्थान के हर गांव, हर तहसील और हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं, और उन सब पर उतना ही ध्यान देने की आवश्यकता है जितना और जगह पर है। उन पर ध्यान देने से मतलब यह है कि उन लोगों को काम धन्धे की सहूलियत करना है। अगर हर डिस्ट्रिक्ट के आंकड़े देखें, हर डिस्ट्रिक्ट में जो काम हुआ है पहली पंचवर्षीय योजना में उन कामों की तरफ देखें, आदिवासियों के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में क्या २ काम इस मुताल्लिक हुए हैं, उन पिछड़ी हुई जातियों को आगे लाने के, उनमें धन्धा बढ़ाने के, तो मालूमात होगा कि खास एप्रिशियेबल काम नहीं हुआ है। इसको मैं आपको एक मिसाल देकर कह सकता हूँ कि एप्रिशियेबल काम अधिक से अधिक करने के लिए हम ध्यान दें। सरकार के विभाग बहुत ज्यादा परचेजेज करते हैं और मैं उसको तफसील में कह दूं। परचेजेज में बड़ी मशीनों की परचेजेज भी शामिल है और छोटी परचेजेज भी शामिल हैं। कई छोटी चीजें यहां पर पैदा हो सकती है। स्टेशनरी का सामान, पुलिस के लिए बेजेज, बटन्स और भी ऐसी हजारों छोटी छोटी

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

चीजें हैं जिनकी अगर एक लिस्ट बनाई जाय तो वह एक बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती है। उनकी जो लिस्ट है उसके मुताबिक उन लोगों की कोआपरेटिव सोसाइटी बनाकर सरकार उनको एलॉट कर दे कि ऐसी ऐसी चीजें तुमको बनानी चाहिए और उनके लिए ट्रेनीज मुकर्रर कर दें, और वह वहां पर उन लोगों को रोजमर्रा ट्रेन करके वे चीजें बनवायें, और जब चीजें बन कर आयें तो हम लोग उनको खरीदें। कम्पीटिशन में हम उन चीजों को नहीं डाल कर करते तो मेरा ख्याल है कि आज इस मामले में बहुत बड़ी प्रगति होगी। आज सरकार खुद एक बहुत बड़ा मारकेट है। कम्पीटिटिव प्राइसेज में न पड़ कर, उस झगड़े में न पड़ कर, जो एजेन्ट्स मिडिल मैन की तरह से, एक्सप्लाइटेशन करते है और सरकार का पैसा ज्यादा खर्च होता है और गरीब लोगों को एम्प्लाइमेंट नहीं मिल सकता है, वैसी हालत में सही मायने में यह बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लान के साथ अपनी रिक्वायरमेंट्स को जिनको यहां बनवाकर कोआपरेटिव बेसिस पर यह चीजें एलॉट करके कि फलां कोआपरेटिव सोसाइटी से इतनी चीजें ली जायगी और इतनी से कम नहीं ली जायगीं, इस कोआपरेटिव सोसाइटी में इतने बटन तैयार कराये जायेंगें, इतने पुलिस के बेजेज तैयार कराये जायेंगे, इतनी हेन्डलूम फेक्ट्रीज से इतनी पुलिस की वर्दी का कपड़ा तैयार कराया जायगा, इससे बहुत सी जरूरियात छोटी बड़ी हैं उन जरूरियात को कन्सेन्ट्रेट करके यहीं से पूरा करें। इस तरह से प्लानिंग के लिए जो पैसा मिलता है, उसके मारफत परचेजेज के लिए जो पैसा एलॉट होता है उसको ठीक तौर से काम में लायेंगे तो वह मसला हम हल कर सकेंगें जिसकी शिकायत हर वक्त बनी रहती है, यह शिकायत रहती है कि इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो गया और उस डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल ही नहीं किया गया है।

इस पंचवर्षीय योजना में एक और बात सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। वह-यह है कि बड़ी बड़ी बेसिक इन्डस्ट्रीज बनाई जायं तो उनका डिस्ट्रिक्टवाइज एक तरह से एलोकेशन होना चाहिए। हमने देखा है कि सड़कों के निर्माण में पी. डब्लू. डी. मिनिस्टर ने हमको कॉन्फीडेन्स में लिया और पूछा कि क्या क्या सड़कें बननी चाहिए तो हमने जाकर देखा और देखने से मालूम हुआ कि जो एलोटमेंट सड़कों के बारे में हुआ है उस एलोटमेंट में बहुत बड़ा अन्तर है एक डिविजन से दूसरे डिविजन के बीच में। एक डिस्ट्रिक्ट और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बीच में थोड़ा बहुत अन्तर है लेकिन एक डिविजन और दूसरे डिविजन के बीचमें बहुत बड़ा अन्तर है। यह उनके सोचने की चीज है कि हमें सभी जगह निर्माण करना है और निर्माण करने में पोपुलेशन बेसिस पर कपिटा एलाट करना चाहिए। और बड़ी चीजों को छोड़ कर दूसरी चीजों में तो सब तरफ से बहुत बड़ी सहूलियत देनी चाहिए सब को। हम बातें करना चाहते हैं इनइक्वीलिटीज को मिटाने की और हम पैदा कर देते हैं इनइक्विलिटीज। यह हमारे खुद की पोलिसी है। हमको ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम इनइक्विलिटीज पैदा न करें क्योंकि यह विचार बढ़कर घोर बादल होते हैं उस एटमास्फियर को बनाने में जिस एटमोस्फियर की आज बहुत जरूरत है इस योजना को कामयाब बनाने के लिए। इसलिए मैं आपसे यह अर्ज करूंगा कि योजना में पैसे को एलोट करते वक्त आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। करीब २ जो कि कुल एलाट हो वह सब डिस्ट्रिक्ट

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

में हो और डिस्ट्रिक्ट के जरिये फिर तहसीलों में, ताकि इसमें इस तरह का वातावरण नहीं बनें और सब लोग इसको कामयाब बनाने में जुट जायं।

एक और बात महत्वपूर्ण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वह यह है कि भारत सरकार की दूसरे विदेशी मुल्क हैं जैसे रशिया है और भी दूसरे मुल्क हैं, जिनके साथ में हमारी ट्रिटीज़ हुई हैं। इस तरह की जनरल ट्रिटीज़ में दूसरे आर्टीकल्स लिये हैं जैसे माइका और दूसरे मिनरल प्रोडक्ट्स हैं उनको वे खरीदेंगे और उसके एवज में मशीनें दे सकेंगे। (समय समाप्ति सूचक घंटी) रशिया से हुआ है जैकोस्लोवाकिया से हुआ है और कई दूसरे मुल्कों से हुआ है कि हमारे यहां पर यह प्रोडक्ट्स बहुतायत से होती हैं उन प्रोडक्ट्स के लिए ट्रिटीज़ और एलायन्स करके मशीनें वगैरह ले सरकार, तो मेरे खयाल से बहुत बड़ा फायदा होगा।

लेकिन वह तब ही हो सकता है कि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन स्टार्ट करें। इस वक्त उसकी शुरूआत कर देना, जब कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना को लागू कर रहे हैं, मेरे खयाल से गलत नहीं होगा, जो काम करने वाले हैं उनको फायदा होगा। पहले बीच में मौका आया था यह सुनने का कि माइका प्रोड्यूस करने वालों को बडा धक्का लगा, इंगलैंड ने माइका को इकट्ठा कर लिया था और वह बिक नहीं सकी थी। उनको ऐसे धक्कों से बचावेंगे। जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कार्यरूप में देखें तो पता चलेगा कि हम कितना दे सकते है और कितनी मशीनें और सामान मंगवा सकते है। आप इस मसले पर विचार कर रहे हैं और स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन को खोलने का मौका है। और उसको हाथ से नही खोना चाहिए और उसके लिए एफर्ट्स करने चाहिये ताकि यह यहां खुल सके।

इस योजना में जो आउट लाइन पेश हुई है, जिसमें बहुत बडा अन्तर नजर आता है वह अन्तर है सीलिंग के बारे में। सीलिंग ३० टाइम्स बेसिकली रखी है। ग्रामीण जनता या एग्रीकल्चर से जीवन निर्वाह करते हैं उनको १२००) रुपया नेट इनकम का प्रोपोजल दिया है और ३० टाइम्स टेक्स पे करने के बाद में, जो दूसरे तरीकों से इनकम पैदा करते हैं, बिजनेस मैन हैं या सर्विस क्लास के हैं और जो एग्रीकल्चर के ढंग से पैदा करते हैं उनके और इनके बीच में ३० टाइम्स का डिफरेन्स रखा है। यह जिस वक्त में हम समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं और योजना बना रहे हैं यह डिफरेन्स बहुत ज्यादा मालूम पडता है। इसके लिए एक कमेटी सेट अप करने की जरूरत है; एक्स्प्लोर करें कि १२०० रुपया और उससे ३० टाइम्स में इतना बडा अन्तर सीलिंग के लिए रख सकते है और उसमें भी लिखा है कि स्टेजेज़ से कदम उठायें। यह बहुत बडा अन्तर मालूम पडता है और जो समाजवादी समाज की रचना करने जा रहे हैं वह इसमें ठीक कर सकें। इस सदन में पिछली दफा बजट और श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर बहस के दौरान में कि फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स और दूसरे जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहों में कितना बडा अन्तर है, सदन ने राय जाहिर की और नाराजगी जाहिर की कि इतना बडा अन्तर है। यह बहुत बडा मसला है। प्राइवेट सेक्टर की मिसाल भी सामने आती है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सोचने की जरूरत है कि सीलिंग किस तरह फिक्स करें कि जिससे प्राइवेट इनकम और एग्रीकल्चर इनकम में ज्यादा अन्तर न हो।

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

अन्त में मैं सिर्फ यह बात कह देना चाहता हूं कि हमें इस पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के लिये, एक जरूरी वातावरण बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए और वह वातावरण बन गया तो हमारी यह योजना बहुत सक्सेसफुल होगी। प्रथम फाइव इयर प्लान की कितनी सक्सेस हुई है, उसकी रिपोर्ट हमारे सामने अभी आई नहीं है। एग्रीकल्चर के बारे में जरा यह कहा जाता है कि हम टारजेट से आगे बढ़ गये हैं। कुछ तो बढ़े हैं, इतने बांधों का निर्माण हुआ। एक हमारे यहां कंट्रोल की पोलिसी चली थी, स्वर्गीय श्री रफी अहमद किदवई की पोलिसी से बडा फायदा हुआ; होर्डिंग की जो आदत थी। सारा स्टोक बाहर आया उससे कितना फायदा हुआ। पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में जब रिपोर्ट आयगी तो कितनी सक्सेस मिली है इसका पता चलेगा। सेकन्ड फाइव इयर प्लान के बारे में सबको मिल कर एक वातावरण बनाना चाहिए जिससे इस योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए सही दिशा में किस तरह से आगे ला सके और एक वातावरण पैदा कर सके।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय अध्यक्ष,......

(घंटी)

श्री नाथूराम मिर्धा—आज कुछ टाइम और कर दें। बोलना भी है, उत्तर भी देंगे।

("कल रख दीजिये" इस प्रकार की आवाज)

श्री मोहनलाल सुखाडिया—एस. आर. सी की रिपोर्ट यदि कल समाप्त हो जाती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा—राजस्थान के बारे में कोई ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।

राजा श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—इसमें विचार प्रकट करने का सवाल है, उत्तर की तो कोई आवश्यकता होती नहीं। चीफ मिनिस्टर को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

(बाधायें)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अगर आप लोग छः बजे तक बैठने के लिए तैयार हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा—हम तो बैठने के लिए तैयार हैं साहब।

("नहीं साहब, नहीं साहब" कई सदस्यों द्वारा इस प्रकार की आवाज)

श्री द्वारकादास पुरोहित—छः बजे तक यह क्या कर रहे है ? कल रख लीजिये साहब।

श्री मुक्तिलाल मोदी—मुझे तो बोलने का टाइम नहीं मिला।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—आप ये ही नहीं सुबह से।

श्री मुक्तिलाल मोदी—अध्यक्ष महोदय, मैं........

(घंटी)

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय अध्यक्ष, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर यह ड्राफ्ट् आउट लाइन की पुस्तक इस सदन के जरिये हमको चन्द रोज पहले मिली। इन पिछले कुछ दिनों में मैंने इस पुस्तक के प्रकरण १४ को काफी गंभीरतापूर्वक पढ़ने की कोशिश की और में जो जो विचार इस प्लान को पढ़ने के बाद में जो बने है उसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि इस पुस्तक मैं, पिछला जो प्लान तैयार किया गया था, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पहला प्लान हमारे सामने आया था, उसको देखकर प्लानिंग कमीशन ने इस प्लान को रखा है। जिस समय हमारे देश में पहली पंच-वर्षीय योजना तैयार की गई थी उस समय बहुत से मुद्दों पर जितने स्टेटिस्टिकल फीगर्स हमारे सामने होने चाहिए थे उन आंकडों में बहुत सी कमियां थीं, इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना को बनाने के पहले क्योंकि इसका पहले ही ध्यान था कि लगातार आने वाले वर्षों में मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की आर्थिक अवस्था को सुधारने के लिए, मुल्क के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए लगातार कुछ योजनायें आगे आने वाले वर्षों में बनानी पड़ेगीं। पहला फाइव ईयर प्लान बना, जिन आकडों की जरूरत पडी उनको तैयार किया गया। इन आकड़ो की तैयारी की वजह से जो टारगेट्स पहले प्लान में मुकर्रर किये थे उनको हमने किसी हद तक पूरा किया है; आने वाले पांच वर्षों में हमको किन किन टारगेट्स पर पहुँचना है, उनके बारे में क्या टारगेट्स मुकर्रर किये जाते हैं ?

माननीय अध्यक्ष, अभी जोधपुर से आने वाले माननीय एक सदस्य ने वाद-विवाद में यह बात कही थी कि हमारे पास पहली पंच वर्षीय योजना में क्या क्या काम हुआ और उसमें कितनी सक्सेस अचीव की उसकी मुक्कमिल रिपोर्ट नहीं है। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में इस तरह की रिपोर्ट आज तक हमारे सामने नहीं है लेकिन इस पुस्तक को पढ़ने से ज्ञात होगा कि इसमें अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बातों के मुद्दों पर चर्चा की गई है, इन

[श्री नाथूराम मिर्धा]

अलग अलग प्रकरणों में अलग अलग रूप से प्रथम पंचवर्षिय योजना में हमने किस हद तक टारजेट को पूरा किया है उसका जिक्र इस पुस्तक में मौजूद है और मैंने दो तीन चेप्टर्स के सिवाय जितने चेप्टर्स अध्यक्ष महोदय, पढ़े हैं, मुझे करीब करीब ऐसा लगा कि पहली पंचवर्षिय योजना में जो टारजेट्स हमने अचीव करने की चर्चा की थी वह करीब करीब उन सब मदों में टारजेट्स अचीव किये हैं, ऐसा प्लानिंग कमीशन का मानना है और इसकी चर्चा द्वितीय पंचवर्षिय योजना की पुस्तक में की गई है।

अध्यक्ष महोदय, द्वितीय पंचवर्षिय योजना का जो ड्राफ्ट हमारे सामने आया है उसको पढ़ने से डेफीनिटली जो पहली पंचवर्षिय योजना में हमने कुछ मुद्दों पर जोर दिया था उससे ज्यादा जोर हमने इस आने वाली द्वितीय पंचवर्षिय योजना में दिया है। हमारे मुल्क को आगे बढ़ाने में हम क्या कर रहे हैं, यह रोशन होगा आपको इसे देखने से। हमारी प्रथम पंचवर्षिय योजना कुल मिलाकर २३५६ करोड़ रुपयों की बनी थी और द्वितीय योजना ४८०० करोड़ रुपयों की है। इस में माननीय अध्यक्ष, १००० करोड रुपये प्राइवेट सेक्टर से और ३८०० करोड़ रुपये पब्लिक सेक्टर से लगने हैं। २३५६ करोड़ और ४८०० करोड़ रुपये करीब करीब दुगुने हैं, दुगुना फर्क है। हम पहली पंचवर्षिय योजना से दूने विस्तार से मुल्क की अर्थ व्यवस्था को तरक्की पर लगाने की योजना रखते हैं।

इसमें अलग अलग मुद्दों पर जो खर्चा करने की व्यवस्था की गई है वह खेती पर पहली पंचवर्षीय योजना में हमने ३७२ करोड़ का खर्चा रखा था, लेकिन इस योजना में हम ५६५ करोड़ रुपये खर्च करना चाहते हैं। सिंचाई में हमने पहले ३६५ करोड़ रूपये खर्च किये थे और इस द्वितीय पंचवर्षिय योजना में ४५८ करोड़ रुपये खर्च करना चाहते हैं। इन्डस्ट्रीज और मिनरल्स पर पहली पंचवर्षिय योजना में १७८ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की थी और द्वितीय पंचवर्षिय योजना में ८९१ करोड़ रुपये खर्च करना चाहते हैं। पहली पंचवर्षिय योजना में बिजली पर २२६ करोड़ रुपये खर्च करने की व्यवस्था की और इस प्लान में ४४० करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। इसी तरह ट्रान्सपोर्ट और कम्युनिकेशन्स पर पहली योजना में ५५६ करोड़ रुपयों की व्यवस्था थी और इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १३८४ करोड़ रुपयों की व्यवस्था रख छोड़ी है। अध्यक्ष महोदय, इन आंकडों से हमें यह पता लगेगा कि आने वाले पांच वर्षों में हम मुल्क में ज्यादा जोर इन्डस्ट्रीज और मिनरल्स को बढ़ाने के लिये, तरक्की देने के लिये देना चाहते हैं और इसलिये इन पर ज्यादा रुपये खर्च करना चाहते हैं क्योंके दूसरे जो आंकड़े हैं उनको देखने से ऐसा पता लगा कि सिवाय इंडस्ट्रीज, मिनिरल्स, ट्रान्सपोर्ट और कम्युनिकेशन्स को छोड़कर जिन पर हमें दुगुने से ज्यादा रुपये इन मुद्दों पर खर्च करने हैं, आनेवाले ५ वर्षों में जो जोर इंन्डस्ट्रीज को तरक्की पर दिया है अध्यक्ष महोदय, उसमें खास तौर से हमने वह इंडस्ट्रीज जो पहले पांच वर्षोंमें कायम की हैं उनको और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए और उनका एक्सटेंशन करने की व्यवस्था कीहै। इसके अलावा कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जो बहुत जरूरी है और जो बेसिक इंडस्टीज हैं जिनके बिना मुल्क की

तरक्की नहीं हो सकती, उनको कायम करने की भी इसमें व्यवस्था है। स्टील और लोहे के कारखाने खोलने का निश्चय किया है और जिनके जरिये बड़ी २ मशीनें तैयार करना चाहते हैं। जिनके लिये पहले प्लान में भी व्यवस्था थी। वास्तव में किसी मुल्क को तरक्की करना है तो ज्यादा से ज्यादा तादाद में मशीनें हमको खुद को तैयार करनी पड़ेंगी। अगर ये मशीनें हम पैदा करेंगे तो उनके जरिये से आगे आने वाले जमाने में जो कंज़्युमर्स गुडस हमें पैदा करने चाहिये जिसे ज्यादा लोग लें और अपना जीवन स्तर बढ़ावें। बड़ी मशीनरी से वे चीजें पैदा होती हैं जिनका इस मुल्क में पैदा करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके साथ साथ जो व्यवस्था बेसिक इंडस्ट्रीज़ के अलावा की गई है जिसके जरिये मिनरल्स की उन्नति करना है। किन्हीं इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने से पहले रॉमेटीरियल पैदा करना जरूरी है। जैसे कोयला और लोहा कच्चे रूप में खानों से निकलते हैं उनका विस्तार करना पड़ेगा। बड़ी खुशी की बात है, मैंने रिपोर्ट में देखा कि कोयले की ज्यादा तरक्की होगी। प्राइवेट सेक्टर में ही आने वाले पांच वर्षों में कोयले को डेवलप करना चाहते हैं। आगे जिसकी ज्यादा जरूरत है उसका ज्यादा हिस्सा पब्लिक सेक्टर में रखा है। उसके जरिये हम कोयले की खदान की तरक्की करना चाहते हैं और नया इन्डस्ट्रिलाइजेशन करके इन खानों को नेशनल तरीके से पब्लिक सेक्टर से डेवलप करके ज्यादा से ज्यादा तरक्की करना चाहते हैं। माइन्स को डेवलप करके इन्डस्ट्रीज को डेवलप करने की व्यवस्था सही और सुन्दर है जिसके जरिये मुल्क की तरक्की का मौका मिलता है और मैं आशा करता हूँ कि वह बढ़ेगी।

इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, जो व्यवस्था सिंचाई के लिये आने वाले पांच में वर्षों में की गई है उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि पहले पांच वर्षों में जो योजनाएं चालू की गई थीं वे योजनाएं ज्यादातर बहुत बड़ी योजनाएं थीं। उनकी कीमत ज्यादातर ३० करोड़ से लेकर ४० करोड़ या इससे ऊपर की कई योजनाएं पिछले पांच वर्षों में चालू की गई थीं। अध्यक्ष महोदय, आने वाले पांच वर्षों में जो योजनाएं हमने चालू करने का इरादा किया है वे कुल १८८ योजनाएं हैं। इनमें से १३६ योजनाएं ऐसी हैं जो एक करोड़ रुपयों से कम खर्च की हैं। ३४ योजनाएं ऐसी हैं जो १ करोड़ से ५ करोड़ तक के खर्च की हैं। ८ योजनाएं ऐसी हैं जो ५ करोड़ और १० करोड़ के बीच की हैं। ६ योजनाएं ऐसी है जो १० करोड़ से लेकर ३० करोड़ की हैं। २ योजनाएं सिर्फ ऐसी हैं जो ३० करोड़ से ज्यादा खर्च की योजनाएं हैं। तो इसका मतलब यह हुआ अध्यक्ष महोदय, कि इनमें से बहुत सी योजनाएं इस आइडिया से शुरु की गई थीं कि इसी पंचवर्षीय योजना के समय में खत्म हो जायेंगी और उसके बाद कुछ योजनाओं का रिटर्न इस योजना में मिलना शुरु हो जायगा। ऐसा यदि नहीं किया जाता तो ठीक नहीं होता और बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं पहली पंचवर्षीय योजना में चालू की गई थीं उनका रिटर्न द्वितीय योजना में भी नहीं मिल सकता। कुछ योजनाओं का रिटर्न तृतीय योजना में मिलने वाला है। तो यह जो व्यवस्था एग्रीकल्चर और सिंचाई की व्यवस्था को लेकर की गई है वह बिल्कुल सही और अच्छी है। इससे हमारे मुल्क में हम जो डेवलपमेन्ट, तरक्की सिंचाई के जरिये किसानों को पैदावार में करना चाहते हैं उसे सही तरीके से हम कर पायेंगे।

[श्री नाथूराम मिर्धा]

इसके अलावा बिजली के डेवलपमेंट के लिए जो खर्चा रखा गया है उसमें हमारे मुल्क के प्लानिंग कमीशन के लोग हैं उनका इरादा यहां तक है कि करीब करीब ५,००० की आबादी के ऊपर के सारे कस्बे हिन्दुस्तान के हैं उनमें से चंद जगहों को छोड़कर सबको बिजली से कवर कर दिया जाय और बड़ी इन्डस्ट्रीज़ के डेवलमेंट के साथ और खाद्यान्नों के डेवलपमेंट के साथ साथ इस चीज को महसूस किया है कि गांवों में बसने वाले अनएम्प्लायड हैं या अन्डर एम्प्लायड हैं उनकी तरक्की के लिये बड़ी इन्डस्ट्रीज के अलावा छोटी कोटेज इन्डस्ट्रीज़ की व्यवस्था करना लाजिमी है और अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सदन के माननीय सदस्यों को सूचना करता हूँ कि इसके लिये काफी अच्छी रकम इस द्वितीय पंच वर्षीय योजना में रखी गई है, करीब २०० करोड़ रुपया इन छोटी मोटी कोटेज इन्डस्ट्रीज़ के लिये, खादी के रूप में, घाणी के तेल के रूप में, छः छोटे मोटे उत्पादनों के रूप में रखी गई है। गांवों में बसने वाले लोगों को अपनी तरक्की के लिये काम करने का मौका इन योजनाओं के जरिये मिलेगा।

इन छोटी मोटी योजनाओं को ठीक व्यवस्थित रूप से चलाने के लिये हमारे मुल्क में अच्छे ट्रेन्ड आदमियों की जरूरत है। इस काम की व्यवस्था करने के लिये कितने ही आदमी ट्रेन्ड होकर ५ वर्षों में उपलब्ध होंगे, इसकी व्यवस्था किस प्रकार होगी, इसका जिक्र इस योजना में किया गया है।

इस द्वितीय पंच वर्षीय योजना में कितना जोर कोओपरेशन पर दिया गया है और किस तरह इस कोओपरेशन के जरिए गांवों की समस्याएं, जिनको आज तक हल नहीं कर पायेंगे, उनका हल कर पायेंगे इन बातों पर इसमें काफी चर्चा की है। कोओपरेशन के लिए इन विगत ५ वर्षों में रिज़र्व बैंक ने प्रयत्न किये थे, इसके प्रयत्न स्वरुप कुछ बैंक्स हमारी स्टेट में हुए थे और भी ज्यादा एग्रीकलचर क्रेडिट लोगों को किस तरह दिया जाय, इसकी व्यवस्था इसमें की है और जितनी व्यवस्था सुचारू रूप में होनी चाहिये थी उतनी इन ५ वर्षों में नहीं कर सके। आने वाले ५ वर्षों में इस पुस्तिका में इस योजना के जरिये कोओपरेशन का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करने का इरादा है। इसको डिटेल्स में, आउटलाइन्स में दिया हुआ है।

एग्रीकल्चर क्रेडिट के अलावा दूसरे छोटी मोटी सोसाइटीज़ बना कर जो लोग अन्डर एम्प्लोयड हैं, उनको किस तरह की फाइनेन्सेज़ की दिक्कत होती है, उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, इस पर इसमें विचार किया गया है। दूसरी सोसायटीज जिनके जरिये कोटेज इन्डस्ट्रीज़ को पनपाया जा सकता है, और उनको फाइनेन्सेज़ की जरूरत है तो रिज़र्व बैंक इसके लिए रूपया देने को तैयार है, इसका जिक्र इस पुस्तिका में है। हमारे गांवों के लोगों के ऐसे मुद्दों का, जिनको आज तक डवलप करने का नहीं सोचा था, इस पुस्तिका में उनका जिक्र है।

माननीय अध्यक्ष, इस प्लान को पूरा करने के लिए आज जो साधन हमारे सामने उपलब्ध हैं, उन सारे साधनों का व्यौरा इस पुस्तिका में दिया हुआ है। इससे मालूम होगा कि अब तक जो रुपया हमें उपलब्ध है, उसमें से ३५० करोड़ रुपया मौजूदा हमारे टैक्सेज़ का लेवल

[श्री नाथूराम मिर्धा]

है, इससे सरप्लस है। बाकी का रुपया ४८०० करोड़ बनाने के लिए, जो मिलना है वह सारा रुपया इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे मुल्क के प्रतिभा सम्पन्न लोगों ने जिस हिम्मत के साथ इस योजना को लोगों के सामने रखा है, उसमें हमारे मुल्क के लोगों का भी बड़ा जिम्मा है, आगे वह यह मान कर चलते हैं कि ४५० करोड़ के नये टैक्सेज लगाने पड़ेंगे।

जो भावनाएं हमें जगह जगह देखने को मिलती हैं वह यह रहती हैं कि टैक्स लग जायंगे तो लोगों पर भार ज्यादा बढ़ेगा। उधर बैठने वाले, जोधपुर से आने वाले माननीय साथी ने कहा कि उन लोगों पर टैक्स बिल्कुल नहीं लगाने चाहिये जो दे नहीं सकते। माननीय अध्यक्ष, आज मुल्क में जिनके पास पैसा कम है उनको कम पैसा टैक्स के रूप में देना चाहिये और जिनके पास ज्यादा पैसा है, उन्हें ज्यादा देना चाहिये, जिनकी ज्यादा देने की हैसियत है उन पर ज्यादा टैक्स लगाया गया है और लगाया जायगा, क्योंकि टैक्सेज के जरिये ४५० करोड़ की पूर्ति करनी है। अल्प बचत की योजना है, वह रकम भी इस मुल्क को देखते हुए बड़ी नहीं है, जब हम आम लोगों में प्रचार करेंगे, और पैसा इकट्ठा करेंगे तब यह रकम इकट्ठी हो सकती है, और इस बात का जिम्मा मुल्क के हर जिम्मेदार व्यक्ति पर है।

इसके बाद मार्केट लोन्स का काम है, भारत सरकार और स्टेट सरकारों ने इस तरह के लोन्स लिए हैं और यह लोन्स मिलने की पूरी उम्मीद है।

१२०० करोड़ का डेफिसिट फाइनेन्सिंग का है। इसके बारे में उधर बैठने वाले माननीय मित्रों ने कहा कि ज्यादा डेफिसिट होने से मुल्क में इन्फ्लेशन का खतरा पैदा हो सकता है।

प्लानिंग कमिशन के बड़े बड़े माननीय मेम्बर्स ने इस बारे में जिक्र किया है। जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान एक बार पेश कर चुके हैं, उसके बाद, बार के बाद में जो इकोनोमिक ट्रेन्ड्स रहे, ऐसी इकोनोमी में १२०० करोड़ रुपये का डेफिसिट का खतरा देखते हैं तो वह कोई विशेष खतरा नहीं है

इसके अलावा जिस बड़ी बात पर जो खर्चा इस द्वितीय पंच वर्षीय योजना में किया जाने वाला है वह बेकारी के सवाल को लेकर है।

माननीय अध्यक्ष, हमारे मुल्क के नेताओं ने और प्लानिंग कमीशन ने इस बात कम कुबूल किया है कि इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम जो बेकारी की समस्या को लेकर चलते हैं, इस समस्या को आने वाले ५ वर्षों तक पूरा कर पायेंगे, यह कहने का हम दावा नहीं करते।

परन्तु इससे एम्पलोयमेंट अवश्य बढ़ेगा। पढ़े लिखे लोगों को एम्पलोयमेंट मिलेगा और इसके साथ साथ बहुत से अनपढ़ लोगों को भी काम मिलेगा। आज कितने ही गांवों में रहने वाले

[श्री नाथूराम मिर्धा]

लोगों को जिनको पूरा काम नहीं मिलता है उनको भी कुछ न कुछ काम अवश्य मिलेगा। गांवों में खेती पर निर्भर रहने वाले लोग हैं उनकी आय में भी कम से कम १७ या १८ प्रतिशत उन्नति अवश्य होगी। इससे उनको काफी सहारा मिलेगा और काम में भी तरक्की होगी।

दूसरा दावा इस पंचवर्षीय योजना में बेकारी को दूर करने का किया गया है और इसको दूर करने के बारे में कहा गया है कि आज जितनी बेकारी है वह आनेवाले पांच वर्षों में यदि कम नहीं होगी तो कम से कम उसी स्टेज पर तो कायम रहेगी और बढ़ेगी तो नहीं क्योंकि पांच वर्षों में कुछ न कुछ तो अनएम्पलोयमेंट बढ़ेगा। मगर इस पंचवर्षीय योजना में इतने लोगों को तो एम्पलोयमेंट मिल सकेगा जिससे बेकारी बढ़ने वाली है वह न बढ़ पाएगी।

तीसरा दावा यह किया गया है कि छोटे मोटे उद्योग धन्धे गांवों में इन पांच वर्षों में खुलेंगे और उद्योग धन्धे खुलने से गांव वालों को जिनके पास कोई काम नहीं रहता उनको काम मिल जायगा और काम करने का मौका मिलेगा जिससे उनकी आय बढ़ेगी और राहत मिलेगी।

माननीय अध्यक्ष, हमारी पंच वर्षीय योजना में जो जो योजनाएं हमारे मुल्क के वैज्ञानिकों ने बनाई है और उसको पूरा करने के लिये हमारे सामने रखी हैं उनको पूरा करने के लिए हमारा बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। हमको चाहिये कि इन पांच वर्षों में किसी तरह से जनता के साथ सहयोग दे कर धन और साधन इस योजना को पूरा करने में जुटावें और किन किन मुद्दों में काम करना है और क्या काम करना है, कैसे काम करना है और इसके लिये जिस तरह का वातावरण तैयार करना हो, उसको तैयार करें।

इसके लिये हमको अल्प बचत की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए और हर पब्लिक के आदमी को यह समझ कर कर चलना चाहिये कि कुछ पैसा अपनी आमदनी में से बचा कर मुल्क की उन्नति के लिये उसको अवश्य लगा देना चाहिये।

(घंटी)

इसी तरह से टैक्सों के बारे में भी हमारे मुल्क के बेटरमेंट के लिये कुछ कदम उठाना चाहिये और वातावरण बनाना चाहिये। इसकी तरफ भी यह एक प्रकार से इशारा हमको देता है। इसके अलावा कोओपरेटिव सोशाइटीज द्वारा गांवों में जो काम होने वाला है उसमें अच्छे अच्छे आदमियों को रखने और डालने की व्यवस्था करनी चाहिये जिससे काम अच्छी तरह से हो और लोगों का उत्साह बढ़े कि काम हो रहा है। इसलिये जो डिस्ट्रिक्टवाइज़ काम हो उसमें हमको भी अच्छे अच्छे व्यक्तियों को लेकर कोओपरेटिव सोसाइटीज को उत्साह देना चाहिये।

अब मैं आपके द्वारा खास तौर से लैंड रिकार्ड के चेपटर के बारे में जो प्लानिंग के सदस्यों ने इसमें रखा है उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें पर्सनल कल्टीवेशन के बारे में

[श्री नाथूराम मिर्धा]

बताया गया है। अभी हमने सदन के जरिये पर्सनल कल्टीवेशन के लिये रूल्स फ्रेम किये हैं। इसमें ऐसे लोग आने चाहिये जो कुछ न कुछ श्रम अपने शरीर के जरिये अवश्य करें वह कितना हो इसकी तादाद भी बताई गई है। अगर कोई आदमी या उसके खानदान में से कोई आदमी या उसका कोई रिश्तेदार कुछ न कुछ काम खेती में नहीं करता हो तो वह पर्सनल कल्टीवेशन की डेफिनेशन में नहीं आवेगा, इस बात का नया संकेत हमें इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आता है और इस आइडिया को इम्पलीमेंट करना है ऐसा संकेत किया गया है।

दूसरी बात खेतीबाड़ी के संबन्ध में सीलिंग को तय करने के बारे में है। इस संबन्ध में जोधपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने यह बताया कि ५ आदमीयों के फेमिली के लिये लेन्ड रिफार्म पेनल की कमेटी ने यह तय किया है कि उनके लिये इतना जमीन का एरिया होना चाहिये जो उनको १६०० रुपया सालाना की आमदनी या नेट इनकम जिसमें से फेमिली लेबर निकाल कर १२०० रुपया सालाना की आमदनी दे सके उसके तीन गुने से ज्यादा नहीं होना चाहिये। दूसरी जगह क्या चर्चा है। यहां पर हम देखते हैं कि १०० रूपये माहवार के हिसाब से इनकम मानी है। या तो ग्रोस इनकम का तिगुना या नेट इन्कम का तिगुना। अगर हम ग्रोस इन्कम का तिगुना लेते हैं तो वह ४८०० रूपये होते हैं और नेट इन्कम का तिगुना लेते हैं तो ३६०० रू० होता है। यह नया संकेत इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमें मिलता है, मैं माननीय अध्यक्ष, यह निवेदन करना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर के अलावा ३६०० रूपयों से नीचे की आमदनी पर कुछ भी टेक्स नहीं लगता और न किसी को देना होता है। अगर आमदनी ३६०० से ज्यादा होगी तो उसके लिये लोगों को कुछ न टैक्स के रूप में लोगों को देना होता है। लेकिन खेती की आय में इस बात का ध्यान नहीं रखा गया है। हमको जमीन का टैक्स भी देना पड़ता है और फिर दूसरा टैक्स भी····

(घंटी)

माननीय अध्यक्ष, हम उम्मीद करते थे कि ३६०० रू० से कम आमदनी के खेती करने वाले लोगों से सरकार कोई लगान जमीन का नहीं लेगी। मगर वह लेती है। लेकिन जब हम इसके लिये कहते हैं तो सरकार कहती है कि लेन्ड रेवेन्यू हमारे मुल्क की आय का सबसे बड़ा जरिया है। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि बहुत सी रियासतों के लैन्ड रेवेन्यू की वजह से ही बजट बैलैन्स पूरा होता है। इसके अलावा बहुत से कस्टम उठ जाने जाने से भी घाटा हुआ है और रेवन्यू के हटाने से बहुत सा घाटा सरकार को हो सकता है, परन्तु यह एक विषय माननीय अध्यक्ष, सोचने का है कि जब दूसरों से टैक्स उतनी आमदनी पर नहीं लिया जाता है तो फिर एग्रीकल्चर या खेती से आय पर क्यों लिया जावे। आने वाले जमाने में क्या हो इसके लिये मैंने आपके जरिये निवेदन किया है। अब मैं ज्यादा समय न लेकर बैठ जाता हूं।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—अध्यक्ष महोदय, यह जो सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान सेन्टर द्वारा तैयार हुआ है उसकी ड्राफट आउटलाइन हमारे सामने आयी है मैं भी उसके ऊपर अपने

[श्री हिम्मत सिंह अटरू]

विचार प्रकट करना चाहता हूं। वास्तव में देखा जावे तो अधिक तर हिन्दुस्तान की पोपूलेशन ८० फीसदी पोपूलेशन गांवों में रहती है अगर हमारा यह प्लान ८० फीसदी जनता को सेटिसफाइ कर सकता है.तो हम यह समझ सकते हैं कि हमारा यह सेकिंड फाइव ईयर प्लान किसी हद तक सक्सेजफुल और कामयाब मानी जा सकती है। लेकिन जब हम इस ड्राफ्ट आउट लाइन को देखते हैं तो हमें यही पता चलता है जिस प्रकार पहला फाइव ईयर प्लान गुजर गया उसी प्रकार यह भी गुजर जायगा। जो फायदा हम गांव वालों को पहुंचाना चाहते हैं, ८० फीसदी जनता को पहुंचना चाहते हैं, वह नहीं पहुंचने वाला है। मुझे इसमें बड़ी भारी गलती दिखाई दी है यह जो प्लान है उसके अन्दर नेशनल एक्सटेन्शन ब्लॉक और कम्युनिटी डेवलपमेन्ट के लिये ३६५ करोड रुपये का प्रोवीजन रखा है यह बिल्कुल इनएडीक्वेट है। आखिरकार हमारा ध्येय है क्या; यह हमको पता नहीं। प्लानिंग बनाने वालों ने यह डेवलमेन्ट ब्लाक और कम्युनिटी डेवलमेन्ट ब्लॉक बनाने में उनका क्या लक्ष्य रहा है। हमें खासतौर से नेशनल एस्टेन्शन ब्लाक और कम्युनिटी डेवलमेन्ट ब्लाक के ऊपर जाना है। इसके बारे में मेरा यह निवेदन है कि कम्पलीटली आइडिया ठीक किया जाय तभी यह मोस्ट सक्सेजफुल साबित हो सकता है गावों के अपलिफ्ट के लिये और वहां के निवासियों के लिये। इस ओर कतई ध्यान इस प्लान में नहीं दिया गया है अगर कम्युनिटी डेवलमेन्ट को पूरी तरह से बनाना है तो हमें यह देखना होगा कि हमें कितना रूपया खर्च करना है, सरकार ने अगर इसी एक चीज पर भी ध्यान दिया होता तो बहुत कुछ तकलीफें गांव वालों को हैं वह भी दूर होजाती और उनका स्टेंडर्ड ऑफ लिविंग भी ऊंचा हो सकता था। विलेज यूनिट तक तो यह चलता है लेकिन इसमें मंडी की जनता तक कुछ नहीं, तहसील की जनता के लिये कुछ नहीं, इस तरह से विलेज यूनिट को हम समाप्त कर देते हैं। जहांतक मेरा खयाल है यह कम्युनिटी डेवलपमेन्ट की कतई मन्शा नहीं है। कम्युनिटी डेवलपमेन्ट का वर्क बहुत आगे चलने को है बजाय इस ३६५ करोड रुपये को जो कम्युनिटी डेवलपमेन्ट के लिये लगाया है इससे चार गुना ज्यादा लगाया जाता तो यह ज्यादा सक्सेजफुल होता ज्यादा लोगों को राहत पहुंचती यह ध्येय रखकर ही हमें प्लान रखना चाहिये। मैं यह सजेस्ट करूंगा कि जैसे गांवों के लिये स्माल स्केल इन्डस्ट्री के लिये २०० करोड़ रुपया लगाया गया है वह कम्युनिटी डेवलपमेन्ट ब्लॉक के अन्दर वह आजाती उसके लिये सेपरेट रकम लगाने की जरूरत नहीं। वह ३६५ करोड में सब शामिल होना चाहिये। इसी तरह से एज्यूकेशन के लिये ३२० करोड रूपया रखा गया है। वैसे एज्यूकेशन के लिये हम रकम प्रोवाइड करते ही हैं इसी तरह से यह रकम भी डेवलपमेन्ट ब्लॉक में चली जानी चाहिये। इसी तरह से लेबर वेलफेयर के लिये और शिड्यूल ट्राइब्ज के लिये २६०करोड रूपया रखा गया है वह भी कम्युनिटी डेवलपमेन्ट के अन्दर जानी चाहिये। मुझे समझ में नहीं आता कम्युनिटी डेवलपमेन्ट ब्लॉक हर तहसील के अन्दर हर कस्बे और गांवों में क्यों न रखे जाय। गवर्नमेन्ट की अगर वास्तव में यही मन्शा है हरेक जगह की उन्नति हो तो पहले जो एक चीज ले रहे हैं उसमें पहले पूरी कामयाबी हासिल करनी चाहिये। इस तरह से अलग अलग जगह खोलकर हम खामखां उलझने पैदा कर रहे हैं। ये सब जो बातें हैं वे सब कम्युनिटी डेवलपमेन्ट के अन्दर आजाती है। अगर सरकार इसी बात पर ध्यान देवे तो मेरा विश्वास है लोगों को ज्यादा राहत मिल सकती है बजाय इनको अलग अलग स्प्लिट करने के।

[श्री हिम्मत सिंह जी]

२६७ करोड़ रुपया लेबर वेलफेयर और बैक वर्ड क्लास के लिये रकम प्रोवाइड की गई है। जिस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य के जमाने में पठानों को रुपया दिया जाता था उसी तरह हम इन बैकवर्ड क्लास को दे रहे हैं। मैं तो यह समझता हूँ यह भी किसी मतलब से दिया जा रहा है। अगर आप उनको फायदा ही पहुँचाना चाहते हैं तो डेवलपमेंट ब्लॉक के थ्रू फायदा पहुँचा सकते है फिर भी मैं नहीं समझता यह सीरणी क्यों बांटी जाती है? अगर इसमें कोई खास रहस्य है तो वह हमारी सरकार ही जाने....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—भारत सरकार को पूछना पड़ेगा।

राज श्री हिम्मतसिंह—आप भी तो उसमें शामिल हैं।

९० करोड़ रुपया हमने रिहेबिलिटेशन के लिये रखा है। जो लोग सिन्ध से भाग कर आये हैं वे तो हमारे महमान हैं उनको तो हमें बसाना पड़ेगा। लेकिन जो हाउसिंग के लिये १२० करोड़ रुपया रखा गया है वह ठीक नहीं है, हाउसिंग भी एक तरह से डेवलपमेंट ब्लॉक में चला जाता है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि हम यह अलग अलग काम क्यों कर रहे हैं, यह रकम स्प्लिट नहीं करनी चाहिये और एक ही के अन्दर लगानी चाहिये।

अब मैं थोडी बातें लैन्ड रिफार्म के बारे में अर्ज करना चाहूंगा। लैन्ड रिफार्म के बारे में जो कुछ इसमें लिखा गया है उसको पढ़ने से मालूम देता है यह केवल आउट लाइन है प्लान बाद में जाकर बनेगा।

" The detailed programme of land reform to be implemented during the second plan will be drawn up after the panel has considered the reports of its committees and made its recommendations. "

अभी तो इसके बनने में देर है मोटी मोटी बातें जो हमारे सामने आई हैं उनमें जो खास बात रखी गई है वह है सीलिंग की। जैसा कि हमारे मित्र ने कहा उनको अब इसके बारे में दर्द होने लगा है, पहले नहीं होता था दूसरों की जागीरें छिनने में उनको दर्द नहीं होता था अब जबकि उनसे लिया जाने वाला है तो दर्द होने लगा....

श्री नाथूराम मिर्धा—मुझे तो सीलिंग मुकर्रर होने में कोई दर्द नहीं। मैं तो कहता हूँ कि सीलिंग होना चाहिये आमदनी पर रेन्ट नहीं होना चाहिये।

राज श्री हिम्मतसिंह—(जारी रखते हुए)—

अब मेरे माननीय मित्र रेन्ट से बचना चाहते हैं। जैसा कि इसमें कहा गया है ३६०० रुपये की आमदनी तक सीलिंग मुकर्रर किया गया है ज्यादा आमदनी पर ज्यादा यूनिटी नहीं रह सकती।

[श्री हिम्मत सिंह अटरू]

इसका मतलब यह हुआ कि ३६०० रुपये से ज्यादा जिसकी आमदनी है उसके ऊपर तो सीलिंग मुकर्रर होगा, इसका मतलब यह हुआ कि जो ८० फीसदी जनता है वह भीख मांगती रहे क्या यही हमारा डेवलपमेन्ट है ? इसी तरह से क्या हम लोगों का स्टेंडर्ड आफ लाविंग बढ़ाना चाहते हैं; क्या इसी तरह से सोशलिस्टिक पेटर्न आफ सोसाइटी कायम करना चाहते हैं क्या आप इसी तरह की समानता करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ इसमें किसी प्रकार की समानता नहीं, एक व्यक्ति तो महलों में आराम करेगा और दूसरे व्यक्ति को झोपड़े में रहना भी नसीब नहीं होगा, इस तरह से असमानता किस प्रकार दूर हो सकती है ? इस लिए गवर्नमेंट को यह विचार करना चाहिये कि जो सिलिंग हम मुकर्रर कर रहे हैं क्या वह वाजिब है ?

हेवी इन्डस्ट्रीज़ बनायी जा रही है। इस हेवी इन्डस्ट्रीज में इतनी सारी पोपूलेशन इन्डस्ट्रीज की तरफ चली जायगी कि जमीन पडत रह जायगी उस पर खेती करने वाला कोई नहीं मिलेगा। सिलिंग हमें हटाना पड़ेगा हमें लोगों का ध्यान मेकेनिकल फार्मिंग की ओर दिलाना होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कलेक्टिव फार्मिंग की ओर ध्यान दिलाना होगा।

राजा श्री हिम्मतसिंह—कलेक्टिव फार्मिंग हिन्दुस्तान में हो नहीं सकता। हिन्दुस्तान में कलेक्टिव फार्मिंग का नामोनिशान नहीं। हमारा देश हमेशा से धर्म प्रधान रहा है हम यहां कलेक्टिव फार्मिंग नहीं करना चाहते। और मेरा जहां तक खयाल है कोई कलेक्टिव फार्मिंग के लिये तैयार भी नहीं होगा। यहां एक फेमिली यूनिट फार्मिंग चल सकता है। जहां अपने बेटे पोतों के लिए कुछ नहीं करना पडता ऐसे देशों में यह कलेक्टिव फार्मिंग चल सकता है जिनका केवल पांच दस बीघे से सन्तोष हो सकता है।

दूसरी बात यह है कि एग्रीकलचर रिफोर्म के अन्दर हमने इस बात का अनुभव किया कि हमने जागीरदारों को डिसलोज किया उसका क्या परिणाम निकला। कितना अनएम्प्लोयमेंट बढ़ गया। यह ठीक है जागीरों से हमें कोई मतलब नहीं, जागीरों को हमने आगे होकर छोड दी आप जागीरें भोगिये, लेकिन यह जरूर हुआ है कि इससे अन एम्प्लोयमेंट हो गया है लोग भूखे मर रहे हैं, जागीरदार नहीं लेकिन जो डिपेन्डेन्टस थे, उनके गरीब आश्रित थे, उनके लीविंग का कोई इन्तजाम नहीं। मेरा यही निवेदन है कि हम हेस्टी लेन्ड रिफोर्म न करें जैसा कि हम सिलिंग के मुकर्रर करने के बारे में कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस डेमोक्रेटिक सेटअप में और और सोशिलिस्टिक पेटर्न ऑफ सोसाइटी में आज हर बेचारे काश्तकार को दस बीघा जमीन काश्त करने के लिये देना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका जीवन स्तर ऊपर उठे। आप उनसे लगान ले रहे हैं

[राज श्री हिम्मतसिंह]

उस भूमि का भी आपको लगान लेने का हक क्या है ? इन्कम टैक्स आप लगाते हैं तीन चार हजार पर और एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स आपने रक्खा है दो हजार की इन्कम पर और उधर वह पचास रुपया नहीं कमाता है और आप उससे लगान ले लेते हैं। क्या यह सोशलिस्टिक पैटर्न आफ स्टेट है ? आप छोड़िये ऐसे लागान को। ऐसे आदमी को खाने दीजिये। उसे भूखों मत मारिये। कुछ उनके पेट में भी तो पडने दीजिये, जिन्दा तो उनको भी रहने दीजिये। उनके मुंह की कोर आप मत छीनिये वैसे फिर अगर फसल खराब हो गई, ऋतु बिगड़ गई, ओले पड़ गई, टिड्डी आ गई तब भी आप तो लगान लेंगे ही, चाहे पैदावार का नाम निशान भी न हो। कोई जाकर देखता नहीं; न कलक्टर देखता है न तहसीलदार न पटवारी। किसी ने साहस किया किसी की सिफारिश पहुँच गई तो यह हो गया कि लगान उसका सस्पेन्ड हो गया अगले साल ले लेंगे इस साल छोड़ा तो। तो काश्तकार आखिर कैसे गुजर करेगा ?

अपनी पर्सनल कल्टीवेशन पर जिक्र करते हुए भी मिर्धाजी ने कहा था कि पर्सनल कल्टीशन तो उसी का गिना जावेगा जिसमें वह लेबर करे। लेबर करने वाले हैं और वे करेंगे भी। और वे आजकल तो मेकेनिकल फार्मिंग हो गया है ट्रेक्टर उठाकर चाला लेंगे और पर्सनल कल्टीवेशन हो जावेगा। अगर आप इसी तरह से जमीन छोड़ते रहेंगे तो आप और हम सब ट्रेक्टर चलाकर फार्म करने लगे जावेंगे।

श्री अध्यक्ष—टाइम हो गया।

श्री हिम्मतसिंह—टाइम तो ज्यादा नहीं लूंगा अब मैं।

(जारी रखते हुए) एक बात और कह दूं। सरकार की जितनी प्लानें हैं वे हैं बडी सुन्दर। देखने में कागज भी अच्छा है, किताब भी अच्छी बनी है। पर उनके चलाने का क्या इन्तजाम है ? वही भ्रष्टाचारी मशीनरी है। जिसके कारनामे हमने इन पांच सालों में देखे हैं; जहां देखो उधर ही भ्रष्टाचार और स्कैन्डल। मेरी समझ में नहीं आता कि इस दूसरी पंचवर्षीय योजना का क्या हाल होगा, इसका क्या नतीजा निकलेगा ? अगर इसी करप्ट मशीनरी के द्वारा यह योजना भी चलाई गई तो उसका भी वही हाल होगा जो पहली का हुआ। सारा पैसा इन भ्रष्ट अधिकारियों की जेब में या इन ठेकेदारों की जेब में जायगा तो इससे तो बहतर यह होगा कि बजाय इस पैसे को इस तरह से बहाने के किसी जगह इस सारी रकम को जमा करा दें और उसके ब्याज से कुछ लोगों का काम कर सकें तो करिये।

श्री अध्यक्ष—This is the nutshell of the speech

श्री हिम्मतसिंह—(जारी) करप्शन की बात मैं कहता हूं। एक अखबार सरकार का निकलता है उसमें भी पढ़ने को मिला एक लेख एक एम. पी ने लिखा है कि जो ये एक्सटेन्शन ब्लॉक्स और कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स डवलपमेन्ट ब्लॉक्स बने हैं वे जिस मंशा और ध्येय से बने थे वह पूरा नहीं हो रहा है। उनमें बहुत कसर है। उनमें ओवर हैड चार्जेज ज्यादा हैं और असली रिलीफ जो जनता को मिलनी चाहिये वह नहीं मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में जो पैसा जनता के हित के लिये खर्च किया जाता है वह जनता का हित साधन नहीं कर रहा है बल्कि यह कुछ ठेकेदार और इन्जीनियरों की जेब में जावेगा। गरीबों को क्या मिलेगा? इसलिये पहले तो अपनी मशीनरी को आप ठीक करिये, अगर आपकी यह मशीनरी भ्रष्ट रही तो बेकार है आपका कोई काम नहीं चलेगा। यथा राजा तथा प्रजा। तो जरा आप मिनिस्टर लोग भी समझें, आप भी जोर लगावें खाली उद्घाटनों, उद्घाटन भाषणों और पार्टियों में ही मत रहिये, जरा सरकारी काम भी देखें, अगर यह भी नहीं देखेंगे तो क्या काम के आप? आप भी थोड़ा बहुत जोर लगावें। गांवों में जाकर देखें तो सही कि क्या हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—आखिरी बात यही रह गई थी कहने की?

(हंसी)

श्री हिम्मतसिंह—(जारी) मैं कहता हूं साहब कि यह भ्रष्टाचार थोड़ा ऊपर से मिटे तो नीचे से मिटेगा। मिनिस्टर साहब अपने में व्याप्त भ्रष्टाचार को पहले मिटावें तो नीचे भी मिटेगा। आज यह हालत है कि लोग-बाग कहते हैं कि मिनिस्टर साहब हमारे यहां आते हैं पर उनके दर्शन तक हमको नहीं होते। उनकी पार्टीवाले उनको घेरे रहते हैं। यहां तक कि अफसर लोगभी उनके दर्शन नहीं कर पाते और वापिस रवाना हो जाते हैं। करेप्शन अगर इसके बाद कोई अफसर करता है तो उसके कान मसिलिये, पूरी पूरी सजा उसे दीजिये। तब तो मशीनरी ठीक चलेगी। बाकी इसी तरह की ढ़िलाई रही तो बेकार है करोड़ों रुपया खर्च करना। यह सारा पैसा यों ही भ्रष्टाचारियों के हाथों बह जावेगा। यह हमारी पिछले पांच सालों का अनुभव है। अब ज्यादा समय नही लेना चाहता और उम्मीद करता हूं कि मेरे सुझावों पर चीफ मिनिस्टर साहब ध्यान देंगे और सेन्टर में भी इस बात को कहेंगे कि इस तरह की प्लान नहीं बनावें, कोई अच्छी प्लान बनावें।

मौलाना श्री मोहम्मद इब्राहीम—दस मिनिट का समय मुझे भी दीजिए साहब।

श्री अध्यक्ष—Order; Order. श्री मोहनलाल सुखाड़िया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री)—सेकंड फाइव इयर प्लान पर वाद विवाद सुबह से अब तक हुआ और मैं समझता हूँ कि अंत में जो भाषण हुआ वह इसके बारे में सबसे ज्यादा प्रकाश डालने वाला था। आपने इस प्लान के संबंध में सेंटर को अपनी राय भेजने को कहा जैसा डी ब्लॉक और एक्सटेंशन ब्लॉक्स में ही आगई है।

श्री अध्यक्ष—This is the result of having debates in the zero hour.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह कहा गया कि ये अलग अलग रखने की क्या आवश्यकता है। मैं निवेदन करूं कि माननीय सदस्य को पता होगा कि कुल एक्सटेंशन ब्लॉकों में ४० परसेंट सी. डी. पी. में कनवर्ट किये जावेंगे। बाकी ६० परसेंट एक्सटेंशन ब्लॉक रहेंगे इस सेकंड फाइव ईयर प्लान में भी। और इसके बाद जितने खर्चे हैं वे काम काज जो चल रहे हैं उनके लिए हैं और ये काम काज अब भी आवश्यक होंगे इस ख्याल से सारी योजनाएं बनाई गई हैं।

मैं अब शुरुआत से चलना चाहता हूं। सदन में बहुत से माननीय सदस्यों ने इन बातों पर जोर दिया कि जो प्लान बनाई गई है उस प्लान के अन्दर जब काम किये जावें तो उनको जिलेवार बांट कर किया जावें। मैंने शुरू में निवेदन किया था कि कुछ काम इस प्रकार के हैं जो जिले के आधार पर बांटे जा सकते हैं और कुछ काम आम तौर पर ऐसे होंगे जो कि स्टेट बेसिस पर ही किये जा सकते हैं जो कि बड़े काम काज हैं। लेकिन जिले के बेसिस पर लोगो में उत्साह पैदा करने की दृष्टि से उन कामों को बांटा जाना मैं उचित समझता हूँ और हम इस प्रयत्न में हैं जल्दी से जल्दी सदन के समक्ष एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाकर उपस्थित करें जिससे आपको अन्दाज हो सके कि हम किस तरह से काम करना चाहते हैं।

ये डिस्ट्रिक्ट प्लान्स जब आवेंगे तब और भी बहुत सी बातें मालूम हो जावेंगी पर एक बात जो कही गई कि बहुत से माननीय सदस्यों की राय प्लान बनाने में नहीं ली गई उसके लिए मैं समझता हूं कि जितने भी प्लान्स यहां पर कन्सीडर किये गये गवर्नमेंट की तरफ से आम तौर से उनको जिले की डवलपमेंट कमेटियों ने बनाकर भेजा है। और उन कमेटियों में संबंधित जिले प्रत्येक एम. एल. ए. को अवसर प्राप्त होता रहा है अपनी राय देने का, एम. पी. को भी अवसर प्राप्त होता रहा है अपनी राय देने का और वे सभी मिला कर अपनी डिस्ट्रिक्ट प्लान भेजते हैं। अब वे शायद यह शिकायत कर सकते हैं कि उन्होंने बहुत से सुझाव दिये वे इसमें नहीं हैं। यह सही है। मैं इन सारे सुझावों की जोड़ आपको बताऊं वह करीब करीब जहां तक मेरी जानकारी है हजार करोड़ के आसपास की होती थी जो अलग जिलों से आई, जब कि हमारी प्लान १०३ करोड़ के आसपास की है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सी चीजें अगर इसमें नज़र नहीं आवे तो यह स्वाभाविक है। इनकी जोड़ों को देखते हुए और हमारी प्लान की रकम को देखते हुए तो ९० प्रतिशत वैसे ही कम हो ही गई है। इसलिए इन चीजों का अधिकतर यहां न दिखाना स्वाभाविक बात है।

लेकिन उनकी राय का, उनकी विचारधारा का, समावेश जब यह प्लान बनाया गया था उस समय वे सारी चीजें सामने रखी गई थीं और उसी आधार पर इन चीजों को पूरा किया है। आज भी इस बात पर चर्चा रखने का खास कारण यह था कि हम लोग सारे भारत के प्लान के बारे में जो अपने विचार रखते हों वह यहां पर व्यक्त करें। बहुत से माननीय सदस्यों ने इसमें

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

अपने विचार व्यक्त किये। बहुत से माननीय सदस्य विचार व्यक्त करके इस समय यहां उपस्थित नहीं है जिससे मुझे उन लोगों को कोई बात कहने में आये तो कह सकूं लेकिन वे अपने विचार व्यक्त करके चले जाना ही उपयुक्त समझते थे तो मैं ज्यादा क्या अर्ज करूं। इस प्लान की चर्चा के दौरान में देश के अन्दर चर्चा चलती है और जिसके बारे में गम्भीरता के साथ दो राय भी हो सकती हैं।

रिसोर्सेज के बारे में जोधपुर से आने वाले एक माननीय सदस्य ने इस बात को रखा कि हम रिसोर्सेज के अन्दर जो गरीब आदमियों पर टेक्स लगाता है वह उचित नहीं है अगर उसके बजाय प्रिंसिपलेज, कम्पेन्सेशन और बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज के ऊपर हमें वह टेक्स लगाना चाहिए और उसी प्रकार शायद उन्होंने या किसी और ने टैक्स के नेशनेलाइजेशन की बात कही। अब कुछ चीजें ऐसी हैं इनमें से जो मैं समझता हूं कि इस सदन के दायरे के बाहर की हैं। इस संबंध में मैं अपनी राय जाहिर करूं तो उचित नहीं होगा। वह भारत सरकार के स्वयं के करने की बात हो सकती है। वह अखिल भारतीय नीति का हिस्सा हो सकता है.... :

श्री हरिकृष्ण व्यास—सुझाव तो दे सकते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जो आप लोगों ने सुझाव दिये हैं वे उन तक पहुँचेंगे ही। मैं अपने सुझाव की बात कहता हूं कि जहां पर यह काम है सुझाव दे सकता हूं। इस स्थान पर मेरा सुझाव देना भी उचित नहीं होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं न पक्ष में हूं और न विपक्ष में हूँ। कोई राय जाहिर करने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। वह चीज यह है कि उसका बेसिस तय होना चाहिये और वास्तव में सिद्धान्ततः तो यह बात ठीक है कि अधिक उनको टेक्स किया जाना चाहिये कि जिनके पास अधिक हो। इसके अन्दर दो राय नहीं हो सकती। जिसके पास कम हो उसको अधिक टेक्स करना वाजिब नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज को स्पष्ट करने की आवश्यकता समझता हूँ कि जो टेक्सेज की बात की कि ४५०० करोड़ है और १५०० करोड़ रेलवे के जरिये से आवें तो उसकी ज्यादा से ज्यादा चर्चा करते हैं; वहां हमको स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि टेक्सेशन का भार जो अब तक रहा है उससे पर केपिटा बढ़ा देने की बात नहीं हैं, बल्कि मूल में इस बात का ख्याल किया जाता है देश की जो नेशनल इन्कम है उस पर ७ परसेंट के एक करीब एवरेज टेक्सेशन है। अब जो एवरेज ७ परसेंट का टेक्स इस वक्त है उसको इस वक्त पर केपिटा इन्कम नेशनल इन्कम के अन्दर इन्क्रीज होना चाहिए फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में और सेकन्ड फाइव ईयर प्लान के दौरान में और जो इन्क्रीज होगा उस इन्क्रीज के अंदर उस हद तक ये टेक्स लगायेंगे, उस हद तक एडजस्ट टे

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

करेंगे कि जिससे ७ परसेंट के आसपास टेक्सेशन का भार रहे, और जो इंक्रीज रहता है, जो स्टेंडर्ड आफ लिविंग के बढ़ने के अंदर जो पर केपिटा इन्क्रीज होना चाहिए देश के अन्दर उसका कुछ लाभ मिले, वापिस देश के डेवलप्मेंट के पूल में आये, इस प्रकार के टेक्सेशन की कल्पना की गई है। सारे का सारा वापिस नहीं आये बल्कि कुछ हिस्सा डेवलप्मेंट के पूल में अगर वापिस आयेगा और स्टेन्डर्ड आफ लिविंग के बढ़ाने के अन्दर उस रुपये को लगाया जाय तो यह बिल्कुल उस बिजीनेस मेन की तरह है जैसे कि एक व्यापारी काम करता है उसकी अधिक इन्कम होती है तो उसका कुछ हिस्सा अपने स्टेन्डर्ड को बनाने के काम में लाये और कुछ हिस्सा जनरल डेवलप्मेंट के अन्दर उसको यूज करे तो उसी दृष्टि को लेकर हम आज चलते हैं। उसमें यह ठीक है कि आज कहा जा सकता है कि जो स्टेंडर्ड आफ लिविंग की कल्पना करके चलते हैं कि अमुक स्टेज पर नहीं पहुँच पाया है तो क्यों लिया जाय, यदि देश को आगे बढ़ाना है तो हर एक पर उसकी स्थिति के अनुकूल कुछ न कुछ भार तो डालना ही होगा। वह इस लिए डालना चाहते हैं कि हम तेजी के साथ आगे बढ़ सकें और आगे बढ़कर उसका लाभ जो होगा वह देश को प्राप्त हो सके। आज टेक्सेशन की बात जो कहते हैं उसके अन्दर उन लोगों से लेना चाहते हैं जो कि इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जो मैंने बात कही है वह इस प्रकार का आधार है जिसको यदि नेशनल इन्टरेस्ट की दृष्टि से यदि देखेंगे तो गलत नहीं है। और कुछ समय लगेगा जब तक कि हम अपने यहां स्टेंडर्ड आफ लिविंग को ज्यादा ऊंचा कर पायें। फस्टफाइव ईयर प्लान के अन्दर हमने ऐसा तय किया था कि ११ परसेंट के करीब हमारे यहां की नेशनल इन्कम इंक्रीज होगी उसके बजाय १८ परसेन्ट नेशनल इनकम के अंदर इंक्रीज हुआ। सेकंड फाइव-ईयर प्लान में जहां २५ परसेंट नेशनल इन्कम के इन्क्रीज की कल्पना की है तो बहुत संभव है कि पूरा प्रयत्न करने पर उस में कुछ ज्यादा ही हो पाये। जहां नेशनल इनकम, पर केपिटा इनकम बढ़ती है तो बढ़ने के साथ में कुछ पोर्शन डेवलपमेंट के पूल के अंदर सभी लोगों से आता है तो मैं समझता हूं कि उसे गलत नहीं कहा जा सकता है, बल्कि देश के हित के अंदर उसे आवश्यक समझ कर हम चलें तो उचित है।

उसी प्रकार स्माल सेविंग्स और दूसरी चीजों के अंदर बहुत ही अधिक एमाउंट रखा है, लेकिन वह अधिक एमाउंट हम ऐसा समझते हैं कि पिछले ५ सालों के अन्दर भी धीरे धीरे टेम्पो बढ़ता हुआ चला गया है। देश प्लान-माइन्डेड जितना पिछले दो वर्षों में हुआ है उतना पहले तीन साल में नहीं था। हम राजस्थान का उदाहरण लेकर चल सकते हैं जहां पर १५,२० लाख एक साल के अंदर इकट्ठा हुआ वहां सन् ५५,५६ में डेढ़ दो करोड़ के आस पास स्माल सेविंग्स में इकट्ठे हम राजस्थान में कर पाये और राजस्थान ने क्रेडिट लिया हुआ प्लान के अंदर साढ़े सात करोड़ स्माल सेविंग्स का। आज हम कल्पना करके चलते हैं वह कल्पना गलत नहीं है। दरअसल देश के अन्दर टोकन इंक्रीज हुआ है। लोगों में भावना पैदा हुई है हमारे अपने विकास के लिए। विकास के लिए जो स्माल सेविंग्स के रुपये लिये जाते हैं वह ऐसी शर्तों पर हैं कि जिसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है और देश के

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

लिए वह रूपया विकास के काम में आता है। मेरे खयाल से जो रिसोर्सेज के लिए प्रयत्न किया जा रहा है देश के अंदर उस प्रयत्न के अंदर अधिक से अधिक हाथ मिला कर कोशिश करनी होगी।

फॉरेन एड के बारे में जैसी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति है उसके अनुसार हम वास्तव में बहुत हद तक उस पर निर्भर रहकर नहीं चल सकते हैं कि जो एमाउन्ट इसनें रखा गया है उसमें से कितना पूरा होगा? लेकिन संभव हो सकता है कि आने वाले वर्षों में कैश के तौर पर या मेटीरियल के तौर पर उसकी प्राप्ति कुछ हद तक है। लेकिन देश की हर परिस्थिति के लिए जैसा कि बीच में फाइनेन्स मिनिस्टर जो कि गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के हैं तथा और दूसरे लोगों ने कहा है कि हमें अपने पांव पर खड़े होकर चाहे मुसीबत ही उठानी पड़े देश को संगठित करना है, उसको विकसित करना है, तो उस प्रयत्न की ओर अधिक से अधिक विचार करना होगा। मैं अध्यक्ष महोदय, समझता हूं कि सब से ज्यादा आवश्यकता जो हमारे सामने है; वह वास्तव में प्लान माइंडेड और प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए आवश्यक वातावरण बनाने और आवश्यक प्रयत्न करने के लिए यदि मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। उसको करने की तैयारी की आवश्यकता है। हम पग पग पर जरा जरा सी टेक्सेज की बातों को लेकर इस मामले को इस तरह से सोचेंगें तो मैं समझता हूं कि जो हम आज आशा रखकर चलते हैं उसमें बहुत सी बाधाएं उपस्थित हो सकती हैं यह हम नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार के टेक्सेज हों कि जिस के भार को लोग उठा न पायें। लेकिन जिस चीज को उठा सकते हैं, जिस चीज को एक हद तक कर सकते हैं उसको करने के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करना चाहिए।

एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के बारे में अधिक जोर दिया जाना चाहिए था मुकाबले बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के, मैं समझता हूँ कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जो कि कार्वे कमेटी सेट अप की गई थी और उसमें मेरे खयाल से २६७ करोड़ रुपये मांगे थे; उसमें से २०० करोड़ के करीब प्लानिंग कमीशन ने एप्रूव किये हैं अगर २६७ करोड़ के अंदर जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा होता वह भी शरीक था और अब इस २०० करोड़ में वह शरीक नहीं है। उसमें जितनी आवश्कता है उतना रुपया खर्च कर सकते हैं; जिसके पूर्ण रूप में उसकी पूर्ति करने का प्रयत्न किया गया है। उसके बाद अगर हम देश का वास्तव में प्लान करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि कोई भी देश प्लानिंग की बात करता है तो प्लानिंग की बात के साथ बेसिक इन्डस्ट्री और बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज का सवाल जुड़ा हुआ है। उसके बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता है और आत्म निर्भर हो नहीं सकता है और जो देश आत्मनिर्भर नहीं होता है वह अपनी स्वतन्त्रता को नहीं टिका सकता। इस तरह से बड़ी बड़ी चेन्जेज हुई हैं और सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान में बड़ी इन्डस्ट्रीज को स्थान दिया गया है एक माननीय सदस्य ने कहा कि जो प्लान फ्रेम था उसमें और इसमें पब्लिक सेक्टर का परसेन्टेज कम कर दिया गया, परसेन्टेज, अध्यक्ष मोहोदय, कम हुआ है, उस परसेन्टेज के कम होने के कारण

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

हैं ट्रान्सपोर्ट और कम्युनिकेशन में अधिक लगाना, इन्डस्ट्रीज सेक्टर के अन्दर जितना रुपया दिया गया और जितने ट्रान्सपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए दिया गया इन दोनों को मिला कर प्लान फ्रेम में लिए ज. ४८ परसेन्ट था और ड्राफ्ट आउटलाइन में उनको मिलाकर ४८ परसेन्ट है और उस चीज की आवश्यकता इस खयाल से ज्यादा की गई कि जो हमारे यहां सामान तैयार हो, एक्सपेन्डेड इनकम के रूप में उसका वितरण नहीं होता है, कन्जम्शन नहीं होता है, तो एक तरह बोटल—नेक हो जायगा और उसका रिजल्ट उल्टा हो जायगा। इसलिए मीन्स ओफ कम्युनिकेशन्स साइड बाइ साइड डेवलप करना आवश्यक है ताकि उत्पादन जो हो उसको यातायात की सुविधा मिल सके। जब हम यह विचार करते हैं तो रेलवेज के डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के लिए आज यह अनुभव करते हैं कि कम रखा है। राजस्थान के लिए विचार करके चलें तो जो सम्भव था उसमें परिवर्तन किया गया वरना किसी के फायदे या नुकसान के लिए परिवर्तन करने का सवाल नहीं। जिन्होंने प्लान तैयार किया था उन सब ने मिल कर इन चेन्जेज को किया है और दूसरे दृष्टिकोण से किस प्रकार का किया गया है ऐसा मैं जानता हूँ नहीं हुआ।

दूसरा प्लान फ्रेम के अन्दर और जरा सी चेन्ज हुई है और वह है सोशल सर्विस पर, कुछ परसेन्टेज सोशल सर्विस पर बढ़ाने के लिए अन्त तक काफी रहा। जैसे एजुकेशन, मेडीकल है उसमें ज्यादा आवश्यकता होते हुए भी केवल जो प्लान फ्रेम था और अब जो ड्राफ्ट फ्रेम है उसमें ३ परसेन्ट का अन्तर हुआ और सोशल सर्विस की आवश्यकता देश को है उसका खयाल रख कर ही किया गया। मैं समझता हूँ कि प्लान फ्रेम के उसूलों में परिवर्तन करनेकी दृष्टि से या दृष्टिकोण का भेद था ऐसी बात नहीं, उसको आम तौर पर स्वीकार करते वक्त, डिटेल्स में किया गया तो उसके परिणाम स्वरुप ये रद्दोबदली हुई।

अभी हमारे सदन के अन्दर लैंड रिफार्म्स पोलिसी के सम्बन्ध में एक चेप्टर है उसके बारे में चर्चा की गई और उस चर्चा के सम्बन्ध में अलग अलग प्रकार की राय जाहिर की गई। खास तौर पर सीलिंग के सम्बन्ध में अधिक चर्चा हुई थी। मैं समझता हूँ अध्यक्ष महोदय, यहां के माननीय सदस्य हैं वे सब जानते हैं कि एक हमारे यहां सीलिंग कमेटी मुकर्रर है जो इस पर विचार कर रही है और मैं समझता हूँ कि एक आधा महीने में अन्तीम निर्णय हो जायगा और वह रिपोर्ट सदन के समक्ष आवेगी और उस पर विचार करने का अवसर होगा। जो सीलिंग के बारे हमें फिगर्स दिये गये हैं उनमें काफी राय का मतभेद भी हो सकता है। सीलिंग का जो लेवल रखा गया है उस पर नहीं लेकिन मैं समझता हूँ कि एक्जम्शनस की जो लिस्ट है, वह काफी बड़ी है और जिस पर चर्चा सदन के अन्दर जानकारी या अनजाने में नहीं हुई है, वह लिस्ट काफी बड़ी है, वेल ओर्गनाइज्ड फार्म्स, आदि हैं। डिटेल्स की बातें हैं। जब सिलींग कमेटी की रिपोर्ट आवे उस वक्त सदन को विचार करने में मदद मिलेगी। इजेक्टमेन्ट के बारे में सदन की पोलिसी रही है, जो टेन्योर ओफ लैंड है और जो इस सम्बन्ध में कानून पास हुए हैं, मुझे याद है कि टिनेन्सी एक्ट में भी इस प्रकार का प्रोविजन किया है कि बीच के अर्से में ऐसी बात हुई हो तो उस पर विचार हो सकता है

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

और सारे अधिकार और दूसरी चीज दी हैं। जब पहले प्लान पार्लियामेन्ट से होकर आजाता है तो उसको इफेक्ट करने के लिए राजस्थान के लिए और देश के दूसरे अलग अलग भागों के लिए अलग अलग पोलिसीज नहीं होती हैं किन्तु एकसी होती हैं और जब देश की पार्लियामेन्ट एक पोलिसी तय कर देती हैं तो वह हर हिस्से पर एक ही तरह से लागू होती है। पार्लियामेन्ट की चर्चा के बाद में नहीं जानता कि एक माननीय सदस्य ने सीलिंग का और सोशलिस्टिक स्टेट का मिलान किया, सीलिंग लग जायगी तो सोशलिस्टक स्टेट कैसे रहेगी। यह बात मेरी समझ में कम आई कि सिलिंग लग जाने सोशलिस्टक स्टेट नहीं रहेगा। जमीनों के बारे में एक कल्पना हमारे सामने रही है कि जमीनों से एक्स्प्लोइटेशन का साधन नहीं हो सकता है। जमीन एक व्यक्त के निर्वाह का साधन होता है उसके जरीये एक्स्प्लोइटेशन की बात करें तो ठीक नहीं ठहरती है। और उस बैकग्राउन्ड पर सोच कर चले तो बहुत से कान्फिलिक्ट्स अपने आप दूर हो सकते हैं। इस प्रश्न पर विचार कर सकते हैं। आपने कहा कि ट्रैक्टर पर बैठ कर खेती करें, लेबर पूरी तरह नहीं करता है, अगर ट्रैक्टर पर भी नहीं बैठे और खेती पर भी न जायें तो माननीय सदस्य समझ सकते हैं कि वह क्या हो सकता है। (हंसी) इस तरह से कई बातें जुड़ती हैं।

एडमिनिस्ट्रेटिव सेट अप के बारे में भी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था कि प्लान तो तय कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे शासन का ढांचा है वह क्या इस प्रकार के प्लान का इम्प्लीमेंट करने के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। यह एक बडा बुनियादी सवाल है। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है। मैं स्वयं भी इस प्रश्न पर कई बार विचार किया करता हूं; दर असल इस बारे में क्या कोई ऐसी स्थिति हो सकती है कि हम ज्यादा साकार रूप इसको दे सकें और ज्यादा लोगों से मेल जोल, प्लान के लिए चेतना और लोग खुद इम्पलीमेन्ट करें इस प्रकार की भावना उनमें पैदा हो। मैं समझता हूं कि कुछ पंचायतें होंगी, डिस्ट्रिक्ट बोर्डस होंगे और कुछ और आर्गेनाइजेशन्स हो सकते हैं, उनके जरीये कुछ चीजें हर एक चीजें, ऐसी नहीं हो सकती हैं, एक टेक्निकल वर्क है, इरीगेशन का है, पी. डब्ल्यु. डी का काम हो सकता है और कई प्रकार के काम हो सकते हैं और जिनको हम चाहे कि उन बड़े बड़े कामों को हम इस प्रकार से पूरा करा लें तो वह नहीं हो सकते हैं, कुछ काम ऐसे हैं जिनको आज भी लोग मिल जुल कर काम करते हैं और उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, जैसे कम्युनिटी प्रोजेक्टस हैं। कुछ मित्रों ने कहा कि पैसों का दुरुपयोग होगा और लोगों को संतोष नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं कि आमतौर पर कम्युनिटि प्रोजेक्ट्स है वहां के जीवन में बड़ा अन्तर आगया हैं, कुछ ऐसे स्थानों को छोड़ सकते है जहां इस प्रकार का बैकग्राउन्ड न हो, नोन ओफिशियल बैक ग्राउन्ड न हो कुछ अफसर ऐसे पहुँच जायें कि जो खुद एक्टिव न हो, आम तौर पर ऐसा होता है यह बात छोड़ दीजिये।

लेकिन आम तौर से जहां पर एक्सटेन्शन ब्लॉक्स हैं या कम्युनिटी डेवलपमेन्ट सेन्टर्स हैं वहां पर लोगों में एक नई जागृति और स्फूर्ति आई है और इस जागृति और स्फूर्ति का स्पष्ट सबूत है। १५ रोज में ५० लाख रुपयों का श्रमदान जहां हो सकता है वहां यह काम बिना स्फूर्ति के हो नहीं सकता। इससे बढ़कर किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है। यह निश्चित तौर से हमारे सामने

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

काम पड़ा है। जो काम हुए हैं वे दर असल में किस प्रकार के हुए हैं इस पर विचार करना चाहिये, यह कहा गया। ठीक है, अध्यक्ष महोदय, हम स्वयं इस पर विचार कर रहे हैं कि एक प्रकार से इन कामों को इवेल्यूट करने के लिए टाइम-टाइम पर रिव्यू करने के लिए एक्सपर्ट्स की एक कमेटी हो। जो काम काज हुआ उन पर राय दें कि क्या क्या परिवर्तन हुआ या नहीं। एक सदस्य महोदय तो और भी आगे बढ़े और कहा कि फूड सिचुएशन में इम्प्रूवमेन्ट हुआ वह केवल हार्डिंग नहीं हो रहा है इस वजह से हुआ है। मैं समझता हूँ कि इस बात को सभी जानते हैं कि राजस्थान नहीं बना उससे पहले भी कई स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें एक्सपोर्ट्स होते रहे। आज यदि अनाज का एक्सपोर्ट होता है राजस्थान में या देश में तो उससे मालूम होता है कि देश में उत्पादन में अन्तर पड़ा है। यह कई फेक्टर्स से मालूम हो सकता है। लैंड पहले से ज्यादा कल्टीवेशन में आई है, पहले से ज्यादा इरिगेशन के साधन हुए हैं, फर्टिलाइजर्स का ज्यादा उपयोग हुआ है, बीज का अच्छा वितरण हुआ है। इन सब के परिणाम को सामने देखते हैं या इस बेसिस पर इन्क्वायरी करते हैं तो यह नहीं कहा जा सकता कि हम आगे नहीं बढ़े।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि गवर्नमेन्ट को क्या राइट है कि आने वाले पांच वर्षों के लिये प्लान या योजना बनावे। जब कि इस डेमोक्रेसी के युग में आगामी इलेक्शन आने वाले हैं और उनके परिणाम स्वरूप गवर्नमेंट बदल सकती है। मैं निवेदन करूं कि प्लान बनाना उचित नहीं है यह जिस आधार पर प्लान बनाया जा रहा है उसमें फ्लेक्जिबिलिटी है, यह सोचने की गुंजाइश है, इसमें समय समय पर परिवर्तन हो सकता है। देश में यदि परिवर्तन हुआ और हकूमत बदलेगी तो प्लान भी आवश्यकतानुसार बदल सकता है। लेकिन जो भी हकूमत होगी वह पहले की गवर्नमेंट की जानकारी से फायदा उठा सकती है। एक गवर्नमेंट यदि जानकारी बनाती है तो मैं समझता हूं, गलत नहीं है। कई स्टेटिक्स, कई फेक्टस होते हैं उनके आधार पर काम करने में ज्यादा सहूलियत होती है बजाय ब्लेन्क छोड़ने के। तो डेमोक्रेटिक प्लान्स में तब भी इसका महत्व है। हमारे सामने एक नक्शा रख कर चलना चाहिये, यह ज्यादा लाभप्रद होगा। यह प्लान सारे देश के लिए है और आप यह मान कर चलें। कुछ मित्र ज्यादा जोर दे रहे हैं आने वाली पंचवर्षीय योजना हमें नहीं बनानी चाहिये। लेकिन उनको यह मानकर चलना चाहिये कि यह योजना तो चलने वाली है, इस में कोई अन्तर नहीं होने वाला है। इस तरह प्लान पर विचार करते हैं तो खास मुद्दों पर चर्चा करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्स इसको इम्प्लीमेंट करता है या वाइ इम्पलीमेंट करता है।

अध्यक्ष महोदय, वैसी बहुत सी चीजें स्थानीय भी चर्चा के दौरान में लाई गईं। प्राइवेट सेक्टर में छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज की भी चर्चा आई जैसे ग्लास वर्क्स कैसे चल रहा है आदि। मैं समझता हूं ये बातें इस प्लान से सम्बन्धित नहीं हैं।

लोकल डेवलपमेंट्स के लिए ज्यादा रुपये हों इस बारे में कहा गया कि अधिक रुपये हों

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

तो अधिक कार्य हो सकता है। आप की यह राय आगे पहुंचाई जायगी। इसमें परिवर्तन हो सकेगा तो बहुत अच्छा होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा और कुछ इस बारे में नहीं कहना चाहता इस लिए कि एक २ प्रश्न पर जवाब देकर कट मोशन्स को विद्ड्रा कराने का प्रश्न नहीं है। हमारे सामने दरअसल में बड़ी बड़ी बातों पर विचार व्यक्त करना चाहते हैं वैसी बातों को सदन की दृष्टि से, राजस्थान की दृष्टि से और सारे प्लान की दृष्टि से जो बातें थीं उनको नोट कर लिया गया है और ये बातें भारत सरकार के सामने रखी जायेंगी और जो बातें यहां पर विचार करने की हैं उन पर यहां विचार किया जायगा। मैं अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इसमें रुचि ली वह सराहनीय है। बहुत से दृष्टिकोण सदन के सम्मुख आये और आगे भी प्लान इम्प्लीमेंट होगा तो ये विचार ज्यादा लाभप्रद होंगे।

श्री अध्यक्ष—सदन की कार्यवाही कल प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लिस्ट ऑफ बिजनेस जो माननीय सदस्यों को सर्कुलेट की गई है उसमें ११ बजे का टाइम दिया गया है। लेकिन कल प्रातः ८ बजे से सभा की बैठक प्रारम्भ होगी।

(तत्पश्चात सदन की बैठक ६ बज कर ५ मिनट पर दिनांक ३ अप्रैल, १९५६ को प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर।
दिनांक २ अप्रैल. १९५६.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

Page No.122

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या २४१ का उत्तर देखिये)

क—राजस्थान में राष्ट्रीयकरण की गई निम्नलिखित पुस्तकें चालू हैं—

(१)	सरल विज्ञान	कक्षा ६	लेखक श्री वी० वी० गुप्ता
(२)	,, ,,	कक्षा ७	,, ,,
(३)	,, ,,	कक्षा ८	,, ,,
(४)	आधुनिक सामान्य विज्ञान	कक्षा ६	लेखक श्री दयाशंकर
(५)	,, ,, ,,	कक्षा ७	,, ,,
(६)	,, ,, ,,	कक्षा ८	,, ,,
(७)	सामाजिक विज्ञान	कक्षा ७	लेखक श्री श्रीलाल औदिच्य
(८)	आदर्श ललित कला	कक्षा ६	लेखक श्री ईश्वरलाल वर्मा
(९)	,, ,,	कक्षा ७	,, ,,
(१०)	,, ,,	कक्षा ८	,, ,,
(११)	राजस्थान रीडर	कक्षा ६	लेखक श्री जी० एस० जैमन.
(१२)	संगीत चन्द्रिका	कक्षा ६	लेखक श्री ब्रह्मानन्द गोस्वामी.
(१३)	,, ,,	कक्षा ७	,, ,,
(१४)	,, ,,	कक्षा ८	,, ,,

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या २४३ का उत्तर देखिये)

खालसा की हुई जागीरों को जिलेवार सूचि

नाम जिला	जागीर संख्या	नाम जिला	जागीर संख्या
उदयपुर	१०७७	सीकर	५३
चितोड़	८५६	झुनझुनु	७२
भीलवाड़ा	६१०	सवाई माधोपुर	१६०
डूंगरपुर	१६१	अलवर	६
बांसवाड़ा	१५८	भरतपुर	३१
कोटा	४८२	जोधपुर	६
बूंदी	१२३	पाली	७६
झालावाड़	२४३	नागोर	१६८
टोंक	१२३	सिरोही	२
जयपुर	५४०	बाड़मेर	१२
		जालोर	१६६
		बीकानेर	४३
		चुरू	१२४
		गंगानगर	५५

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या २४८ का उत्तर देखिये)

समाज कल्याण विभाग—स्वीकृत संस्कार केन्द्र की सूची

क्रमांक	संस्कार केंद्र
	उदयपुर सर्किल
(१)	डूंगरपुर
(२)	बांसवाड़ा
(३)	चित्तोड़गढ़
(४)	भीलवाड़ा
(५)	राजसमन्द
(६)	उदयपुर
	जोधपुर सर्किल
(७)	जालौर
(८)	बाड़मेर
(९)	नागोर
(१०)	सिरोही
(११)	पाली
(१२)	जैसलमेर
(१३)	जोधपुर
	बीकानेर सर्किल
(१४)	चुरू
(१५)	गंगानगर
(१६)	बीकनेर
	जयपुर सर्किल
(१७)	टौंक
(१८)	सीकर
(१९)	झुन्झनू
(२०)	किशनगढ़
(२१)	तिजारा—अलवर

(२२)	राजगढ़—अलवर
(२३]	दौसा—जयपुर
(२४)	जयपुर—प्रोपर
(२५)	जयपुर
(२६)	अलवर

भरतपुर सर्किल

(२७)	झालावाड़
(२८)	बूंदी
(२९)	सवाई माधोपुर
(३०)	करोली—सवाई माधोपुर
(३१)	डीग—भरतपुर
(३२)	धोलपुर—भरतपुर
(३३)	भरतपुर
(३४)	कोटा

क्रम सं०	संस्कार केन्द्र	स्थान व मौहल्ला	कार्यकर्ता	किस तारीख
१.	२.	३.	४.	५.
१.	किशनगढ़	हरिजनों की स्थाई हरिजन मौहल्ला, किशनगढ़ ।	समाज कल्याण कार्यकर्ता (श्री गणपतसिंह)	ता: २४ ११ ५५
२,	,,	,,	,, श्री दिक्षित नारायन माथुर	ता; १६.१.५६. से २२. १०.५६.
		रघराना मदन, किशनगढ़	श्री सुगनलाल	ता: २३. १. ५६.

परीशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या २५२ का उत्तर देखिये)

LIST OF THE PARTIES TO WHOM LOAN AMOUNT HAS NOT YET BEEN PAID.

S. NO.	Name of the Party.	Amount of loan granted.
1.	2.	3.
1.	M/s Indian wollen Carpet Factory, Jaipur.	10,000/-
2.	M/s Crafts Mans Engineering Works, Udaipur.	5,000/-
3.	Shri Aladin, Chaksu.	3,000/-
4.	Shrimati Kalavati Devi, Alwar.	3,000/-
5.	Vaidya Kunj Behari Lal, Singara.	3.000/-
6.	Shri Baal Prashad Saini, Alwar.	5,000/-
7.	Shri Bhandwasia Bahudhandhi Sahakari Samitti, Ltd., Badwasia.	5,000/-
8.	M/s Modern Automobiles & Mechanical Engineers, Udaiper.	5,000/-
9.	Shri Sukhsampat Raj Bhansali, Merta City.	3000/-
10.	Shri Ram ji Lal Sharma, Sanganer.	3,000/-
11.	M/s Kailash Handloom Factory, Madanganj Kishangarh.	2500/-
12.	M/s Chabra Handloom Factory, Madanganj	2,000/-
13.	Shri Banshi Dhar Gupta, jaipur.	3,000/-
14.	Shri Mohamad Safi, Kishangarh.	1,000/-
15.	Shri Chotu Chinppa, Kishangarh.	1,000/-
16.	Shri Roop Chand Patni, Madanagnj, Kiahangarh.	3,000/-
17.	M/s Calico Printers Cooperative Society, Sanganer.	5,000/-
18.	M/s National Weaving Industry, Jodhpur.	10,000/-
19.	M/s Janaluddin Fais Mohd. Jaipur.	5,000/-
20.	Shri Ramashwar Lal Mantri, Parwatsar.	15,000/-

1.	2.	3.
21.	Shri Krishan Narain Ramloo, prop. National Printers, Jodhpur.	5,000/-
22.	Hind Ayurvedic Pharmacy Ltd., Jaipur.	5,000/-
23.	Shri Mitha Lal Jain, prop. Calcutta Store, Udaip ur.	5,000/-
24.	Shri Jagan Nath, Prop. Jagdish Cast Iron Factory, Jaipur.	5,000/-
25.	Shri Bansi Dhar Mishra, Alwar,	5,000/-
26.	Shri Gauri Shanker Mittal, Prop. Servodaya Press, Bharatpur.	5,000/-
27.	M/s Agricultural & Mechanical Labour Contractor & Transport Cooporative Society Ltd., Jodhpur.	7,200/-
28.	Shri Nand Lal Sharma, Bharatpur.	3,000/-
29.	Udaipur Kashtha Kala Utpadan Sahkari Samiti Ltd., Udaipur.	10,000/-
30.	Had Udyog Sahkari Samiti Ltd. Ballabhnagar.	4,000/-
31.	Shri Nathumal Nagota, Pachpahar, (Jhalawar)	5,000/-
32.	Bikaner Zila Kharia & Utpadak Sahkari Samiti, Ltd., Bikaner.	10,000/-
33.	Shri Ganga Bishan Char, Madanganj, Kishangarh	4,000/-
34.	Sarna Bahudhandi Sahkari Samiti Ltd. Sarna (Jalore)	10,000/-
35.	Ranigaon Maltipurpose Cooperative Society Ltd., Ranigaon.	5,000/-
36,	Shri Niranjan Lal, prop. Vishwas-Karma Wood Industry, Rajgarh.	3,000/-
37.	Shri Bhagi Rath Prashad Morda, Churu,	5,000/-
38.	Shri Hira Lal Bhagwanji Nathdwara	3,000/-
39.	Mewar Bone Mill, Cosunda, (Udaipur)	5,000/-

1.	2.	3.
40.	Shri Kamruddin Razabaili prop. Safty Tin Factory, Rani (Esurf)	6,000/-
41.	Shri Pukhraj s/o Fojmal, Rani (Desuri)	4,000/-
42.	Shri Rang Behari Lal, prop. Arya Press, Alwar	3,000/-
43.	Shri Mohanmed Yasin s/o Mohd. Ismail, V. Modi (Teh. Bakani)	3,000/-
44.	Shri Abdul Sakoor s/o Suleman, V. Modi (Tah. Bakani)	3,000/-
45.	Shri Kazi Noor Mohd. s/o Ramzani V. Modi (Tah. Bakani)	3,000/-
46.	Shri Laxmi Lal Bagixieha prop. Ginning Factory, Ballabhnagar.	5,000/-
47.	Shri Kundan Lal Gulabchand Mehta, Rani (Desuri)	3,000/-
48.	Shri Daulatram S/o Kishanlal, Udaipur.	2,500/-
49.	Shri Popot Lal S/o Dayallal, Banswara.	2.500/-
50.	Shri Puran Chand Mittan Lal Motor Engineering works, Jaipur.	4,000/-
51	Shri Umaidmal Nahata, prop. Jain printing press, Kotha.	5,000/-
52.	Kuchaman Regaron Charam Utpadak Sahkari Samiti Ltd., Kuchaman City.	10,000/-
53	Badi Khatu Regaron Charam Utpadak Sahkari Samiti, Badi Khatu.	7,200/-
54.	Shri Jas Raj S/o Nawalaji Lohar, Rani (Desuri)	5,000/-
55.	Hakori Sheep Breeding Co-operative Society Ltd. Hakori.	7, 000/-
56.	Nagaur Sheep Breeding Co-op. Society, Nagour	5, 000/-
57.	Balotra Kansara Utpadak Sahkari S. Ltd. Balota	1o, 000/-
58.	Shri Mool Chand S/o Panjimal Prop. Biscuit Mfg. Co: Jaipur.	5, 000/-

1.	2.	3.
59.	Shri Nathu lal S/o Ganga Sharan Lodha, Gangapur [Bhilwara]	5. 000/-
60.	Shri Tulsi Ram Mittal prop. Agrawal Printing Press, Bharatpur.	4, 000/-
61.	Shri Ram Bharose Lal Verma, Bharatpur	3,000/-
62	Shri Baluiki Bohudhandhi Sahkari S. Ltd., Jodhpur	3,000/-
63.	Emery Stone Mfg. Co;Udaipur.	3, 000/-
64.	Zamidar Krashrikal Karkhana, Bharatpur.	3, 000/-
65.	Shri Hakim Mohd. Ibrahim, Jaipur.	1, 500/-
66.	Shri Gajadhar Chejara S/o Laduram Chejara, Laxmangarh,	5, 000/-
67.	Chhoti Utpadak Sahkari Samiti Ltd. V. Chak 2E (Ganganagar)	2, 500/-
68.	Shri Khyali lal S/o Roop lal, Prop. Premier Metal Industries, Udaipur.	5, 000/-
69.	Shri Aunil Chandra Mukerji, Prop. Mukerji & Co, Ltd Jaipur.	5, 000/-
70.	Rajasthan Electric Products, Ltd, Jaipur.	15, 000/-
71.	Shri Noor Mohamnd. S/o Nulla Yamin, V. Modi (Tah. Bakani)	3, 000/-
	Total	Rs. 3, 57, 500/-

परिशिष्ट ५

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि संबंधित प्रश्न कर्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मंत्री महोदयों की अनुमति है)

प्रश्न संख्या २४६

राव राजा श्री सरदारसिंह, एम. एल, ए., डिविजन नम्बर १३७—क्या राजस्व मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तहसील उनियारा के ग्राम पागंड़ी, नाहरा वगैरह में काश्तकारों को रबी, की खड़ी फसल कटवाई जा रही है ?

(ख) यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा और क्यों ?

(ग) क्या यह सच है कि खरीफ की फसल उनको खेतों में नहीं बोने दी गई है ?

(घ) क्या यह भी सच है कि खरीफ का लगान काश्तकारों से वसूल कर लिया गया है ?

उत्तर

(क) तहसील उनियारा के ग्राम पाठडी नाहदा की भूमि जो गलवा प्रोजेक्ट में है इसका कार्य पहले ही प्रारम्भ हो गया था अतः रबी की खड़ी फसल कटवाने का प्रश्न नहीं उठता।

ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां जो भूमि गलवा प्रोजेक्ट में आ गई थी उसमें फसल नहीं बोने की मनाही कर दी गई थी।

(घ) इस सम्बन्ध में जांच कराई जा रही है।

२५४. (५५। आर. एम.) श्री सोहनलाल भटनागर, एम. एल., ए. डिविजन नम्बर १४५: —क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सलूम्बर तहसील में कई जागीरदारों द्वारा दिये गये पट्टों में सेंक्शन्ड रेंट रेट्स से कई गुना अधिक लगान दर्ज है ?

(ख) क्या ठिकाने जब्त होने व काश्तकारी कानून के अमल में आने के बाद भी तहसील द्वारा पट्टों में दर्ज शुदा लगान ही वसूल किया जा रहा है ?

उत्तर

(क) जी हां लगान सैटलमेंट की रेट से अधिक दर्ज है।

(ख) जी नहीं, जहां जहां से काश्तकारों के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हो रहे हैं जांच के पश्चात उनके लगान में कमी की कार्यवाही की जा रही है।

256. (58/RM) Shri Sajjan Singh, M. L. A., Division No. 132.— Will the Revenue Minister be please to state:

(1) How much area is under Cotton and sugarcane cultivation in the districts of Kotah, Bundi and Jhalawar respectively ?

(2) What is the percentage of these two crops to the total irrigated areas of these districts ?

उत्तर

(१) सम्बन्धित सूचना इस प्रकार है :—

१९५४।५५

	सिंचित : एकड़ :	असिंचित : एकड़ :
कपास		
बूंदी	४२५	४८४०
झालावाड़	६२	६३३५३
कोटा	१६७	६५०४
	६८४	१०५६९७
गन्ना		
बूंदी	४१८४	....
झालावाड़	२०४८	....
कोटा	१८८६	३
	८११६	३

(२) इसका परसन्टेज सिंचित क्षेत्रफल से निम्न प्रकार है :—

कपास बूंदी=७

झालावाड़=३

कोटा=२

गन्ना बूंदी=७ प्रतिशत

झालावाड़=५ प्रतिशत

कोटा=३ प्रतिशत

२५८ (८६ सी. एम.) श्री राव राजा सरदार सिंह, एम. एल. ए. (वि० सं. १३७) क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) राजस्थान में सार्वजनिक पुस्तकालय कहां कहां स्थापित हैं और उनकी वार्षिक आय और व्यय कितना कितना है ?

(ख) सरकार की ओर से इन पुस्तकालयों को क्या आर्थिक सहायता मिलती है ?

(ग) टोंक डिस्ट्रिक्ट में कहां कहां पुस्तकालय हैं ?

(उत्तर अनुपलब्ध)